IAS BABA

One Stop Destination For UPSC/IAS Preparation

March 2022
Baba's Monthly
CURRENT AFFAIRS MAGAZINE

हिंदी

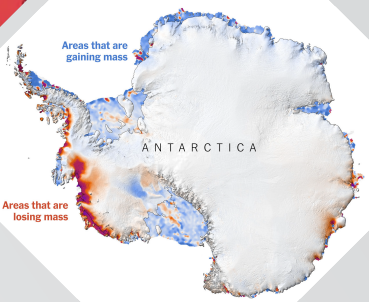

IN NEW AVATAR

Revamped With Revolutionary Aspects

- Easy To Remember Tabular Format
- Practice Mcq's At The End
- Top Editorial Summaries Of The Month
- A Comprehensive Compendium Of News Sourced From More Than 5 Reputed Sources

IAS BABA

Integrated Learning Program (ILP) – 2023

Your Road To Mussoorie...

Available in English & हिन्दी

- Micro Planning - 365 Day Plan
- VAN (Daily Notes)
- Daily Prelims & Mains Tests
- Babapedia – One Stop Destination for Current Affairs (Prelims & Mains)
- Progress Bar – To Track your Progress & Performance
- Strategy Videos for every Subject
- Detailed coverage of NCERTs & Standard Books
- 72 Prelims Tests & 50 Mains Tests

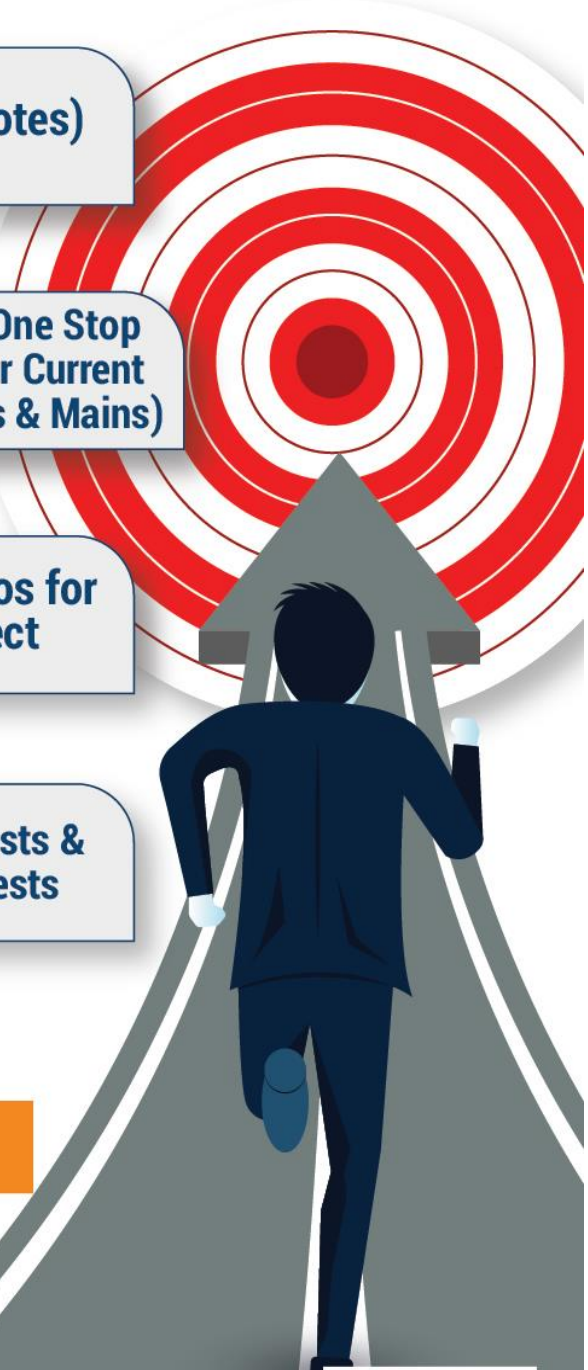

Add-Ons : Current Affairs Videos | Mentorship

Dedicated App for the 1st Time!

REGISTER NOW

Scan Here to Know More

विषय वस्तु

राज्यव्यवस्था एवं शासन

- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)
- कौमी वक्फ बोर्ड तारकक़ियाती योजना
- जल जीवन मिशन
- महिलाओं के लिए समर्थ पहल
- राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन
- वैश्विक उद्यमिता अनुश्रवक (जीईएम)
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
- पद्म पुरस्कार
- नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी)
- प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) की उप-योजना के रूप में किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (एआरएचसी)
- राष्ट्रीय समझ और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत)
- प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना
- लॉटरी कर पर राज्य क्षेत्राधिकार : सुप्रीम कोर्ट
- अनुच्छेद 355
- सीबीआई से सामान्य सहमति वापस लेना
- DIGs की प्रतिनियुक्ति: प्रस्तावित परिवर्तन
- अमरावती पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का फैसला

अर्थव्यवस्था

- भारत के व्यापार घाटे में वृद्धि
- ग्लोबल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (वैश्विक योज्य निर्माण)
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
- राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (NLMC)
- आरबीआई का $5 बिलियन डॉलर-रुपये का स्वैप
- माइक्रोफाइनेंस संस्थान अब निर्धारित कर सकते हैं ब्याज दरें
- पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल 'पीएम-डिवाइन'
- मनरेगा में बाधा डालने वाले मुद्दे
- जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य
- भारत का निर्यात $400 बिलियन डॉलर के पार पहुंचा
- राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन
- निर्यात तैयारी सूचकांक 2021
- भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था
- रूबल मुद्रा (Rouble currency)
- सागर परिक्रमा (Sagar Parikrama)
- UPI भुगतानों के लिए 'टैप टू पे'

पर्यावरण

- जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी)

- नॉर्दन रिवर टेरापिन (Northern River Terrapin)
- जैविक और विष हथियार सम्मेलन (BTWC)
- चिल्का झील
- 19,000 करोड़ रुपये की वनरोपण योजना शुरू
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण (Protection of Great Indian Bustards)
- इलेक्ट्रिक वाहन (EVs)
- असम में कुछ हिमालयन ग्रिफॉन की संदिग्ध विषाक्तता के कारण मृत्यु
- हाथियों की मौत की जांच के लिए स्थाई समन्वय समिति का गठन
- समुद्री घास (Seagrass) पर कार्यक्रम
- काजीरंगा में गैंडों की आबादी 200 बढ़ी

भूगोल और समाचारों में स्थान

- वेडेल सागर (Weddell Sea)
- सोलोमन द्वीप
- जोजिला सुरंग
- डारलोंग समुदाय (Darlong community)

इतिहास औरसंस्कृति

- करकट्टम नृत्य
- वीर योद्धा अहोम लचित बोरफुकन
- नरसिंहपेट्टई नागस्वरम के लिए जीआई टैग

विज्ञान प्रौद्योगिकी

- COVID-19 वैक्सीन प्रभावकारिता की भविष्यवाणी करने के लिए गणित मॉडल
- सीएपीएफ के लिए आधुनिकीकरण योजना- IV
- टोही उपग्रह या खुफिया उपग्रह (Reconnaissance satellite)
- श्रीलंका - भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास 'स्लाइनेक्स'
- प्लाज्मा के जेट के पीछे का विज्ञान
- चंद्रयान-2 ने किया पहला अवलोकन
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी)
- कार्बन कैप्चर और उपयोग
- कोरोनल मास इजेक्शन (Coronal Mass Ejections)
- प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)
- मसौदा राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022
- एक्सोमार्स (ExoMars) मिशन निलंबित
- डीप ओशन मिशन (DOM)
- भारत की आर्कटिक नीति
- विश्व क्षय रोग दिवस
- हाइपरसोनिक मिसाइल
- आईएनएस वलसुरा को "प्रेसिडेंटस कलर" प्रदान किया
- ई संजीवनी (eSanjeevani)

- डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन (जीसीटीएम): भारत (जामनगर, गुजरात में)

अंतरराष्ट्रीयसंबंध

- ऑपरेशन गंगा
- चर्चा में स्थान: ज़ापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र (Zaporizhzhia Nuclear Power Plant)
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना
- उत्तर अटलांटिक संधि संगठन
- कोर कमांडर वार्ता का 15वां दौर
- सफेद फास्फोरस के गोले / युद्ध सामग्री
- भारत ने श्रीलंका को एक अरब डॉलर का ऋण दिया
- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
- भारत की आर्कटिक नीति का विमोचन
- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी)
- फिनलैंडीकरण (Finlandizatio)
- बिम्सटेक
- भारत, संयुक्त अरब अमीरात व्यापार समझौता
- हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी

विविध

- बोल्ट्जमैन मेडल (Boltzmann Medal)
- शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (UDISE+) 2020-21 पर रिपोर्ट
- व्यायाम धर्म संरक्षक-2022
- भारत का मातृ मृत्यु अनुपात (MMR)
- राष्ट्रीय ई-विधान आवेदन (नेवा): 'एक राष्ट्र - एक आवेदन'
- एबेल पुरस्कार 2022: अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन हुए सम्मानित
- युद्धाभ्यास डस्टलिक

मुख्य फोकस (MAINS)

राज्यव्यवस्था औरशासन

- मणिपुर में कुकी विद्रोह (Kuki Insurgency in Manipur)
- समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की जरुरत
- मैनुअल स्कैवेंजिंग (Manual Scavenging)
- हिजाब प्रतिबंध: कर्नाटक
- कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET)
- कृषि कानूनों पर SC पैनल की रिपोर्ट
- इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS)
- युद्ध के भीतर एक और 'युद्ध': जंग के हथियार के रूप में यौन हिंसा (A war within a war: Sexual violence as a weapon of war)
- प्रवासी नागरिकों का मतदान: इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली
- आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022

अर्थव्यवस्था

- क्रिप्टो प्रश्न (The Crypto Question)
- तेल की बढ़ती कीमतें और मुद्रास्फीतिजनित मंदी
- देखभाल सेवाओं में निवेश 2035 तक महिलाओं के लिए 234 मिलियन रोजगार पैदा कर सकता है
- फीचर फोन के लिए नए UPI123Pay
- परमाणु ऊर्जा: गुमराह नीति (Nuclear Energy: Misguided Policy)
- रुपया-रूबल व्यापार व्यवस्था
- करों का भुगतान करने के लिए नागरिकों की अनिच्छा को समझना
- राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम
- बेरोजगारी लाभ ढूँढना (Finding Unemployment Benefits)
- वैश्विक अनिश्चितताएं, भारत की विकास संभावनाएं
- राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी)
- $400 बिलियन डॉलर का निर्यात
- क्रिप्टोकरंसी
- भारत में किफायती स्वास्थ्य सेवा की ओर: 'जन औषधि' से 'जन उपयोगी' तक
- सीए, सीडब्ल्यूए और सीएस (संशोधन विधेयक), 2021

पर्यावरण

- डाउन टू अर्थ की स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2022 रिपोर्ट
- नो वाइल्ड, नो लाइफ (No Wild, No Life)
- भारत की सौर क्षमता: महत्त्वपूर्ण उपलब्धि और चुनौतियाँ
- प्लास्टिक प्रदूषण पर प्रस्तावित वैश्विक संधि
- मुंबई जलवायु कार्य योजना (एमसीएपी)

भूगोल

- जल प्रबंधन को एक जल-सामाजिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है
- अमेज़न वर्षावन का 75% से अधिक एक अस्थिर बिंदु (टिपिंग पॉइंट) के पास, शुष्क सवाना में बदल सकता है: अध्ययन

विज्ञान औरप्रौद्योगिकी

- प्रसवोत्तर रक्तस्राव केरल में मातृ मृत्यु का प्रमुख कारण बना हुआ है: रिपोर्ट
- मैन-पोर्टेबल एयर-डिफेंस सिस्टम (MANPADS)
- भारत की मसौदा चिकित्सा उपकरण नीति
- सौर तूफान
- COVID की तरह, TB एक महामारी है और इसे एक आपात स्थिति के रूप में माना जाना चाहिए
- पहली बार मानव रक्त में मिला माइक्रोप्लास्टिक

अंतरराष्ट्रीय संबंध

- मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन (MCC): नेपाल, यूएसए और इंडो-पैसिफिक
- बालाकोट हवाई हमला

- भारत और यूएनएससी ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण पर मतदान किया (India and UNSC Vote over Russia's Invasion of Ukraine)
- ऑस्ट्रेलिया-भारत द्विपक्षीय संबंधों में 'नया अध्याय' लिख रहे हैं
- 'मानवीय गलियारे'(Humanitarian Corridors)
- भारत-चीन संबंधों और नई वैश्विक धाराओं पर: स्पष्ट संकेत
- यूक्रेन युद्ध में तुर्की का दांव (Turkey's Stakes in Ukraine War)
- रूस-यूक्रेन संघर्ष वैश्विक खाद्य संकट को जन्म दे सकता है
- रक्षा कूटनीति के क्षेत्र में भारत के बढ़ते क़दम और उसके पदचिन्ह
- नई यूएस इंडो-पैसिफिक स्ट्रैटेजी: नए और विकसित पर्यावरण के साथ निरंतरता को संतुलित करना
- वन रैंक वन पेंशन केस
- रूस-यूक्रेन संघर्ष: आईसीजे की भूमिका
- अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन
- नाटो के ब्लंडर्स से क्वाड क्या सीख सकता है (What Quad can learn from NATO's Blunders)
- भारत-जापान संबंध
- भारत और इज़राइल, एक स्थिर रिश्ते की परिपक्वता
- श्रीलंका की बिगड़ती अर्थव्यवस्था
- यूरोपीय संघ का डिजिटल बाजार अधिनियम (डीएमए)
- श्रीलंका का आर्थिक संकट

प्रैक्टिस MCQs

उत्तरकुंजी

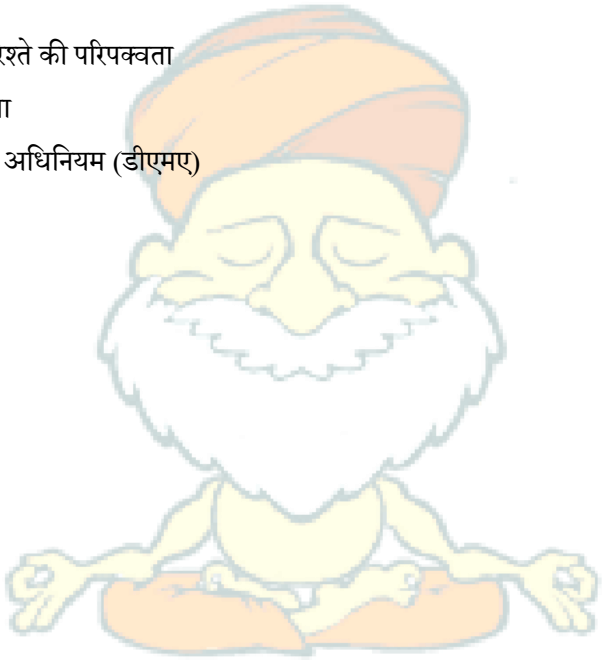

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)	**संदर्भ:** सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने सूचित किया है कि वह निवास/पहचान के प्रमाण पत्र पर जोर दिए बिना यौनकर्मियों (Prostitute) को आधार कार्ड जारी करने को तैयार है। • लेकिन उन्हें राज्यों के स्वास्थ्य विभागों के राजपत्रित अधिकारी या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) के किसी अधिकारी से प्रमाण पत्र लेना होगा। • मालूम हो कि NACO केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Health and Family Welfare Ministry) के अधीन काम करता है और उसके पास यौनकर्मियों के सारे आंकड़े उपलब्ध हैं। • अदालत इस बारे में दलीलें सुन रही है कि कैसे अधिकारी और समुदाय आधारित संगठन यौनकर्मियों तक पहुंच कर उन्हें उनकी पहचान बताए बिना राशन कार्ड, मतदाता कार्ड और आधार कार्ड प्रदान करते हैं। • सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है और यौनकर्मियों के पास एड्रेस प्रूफ नहीं होता। ऐसे में उन्हें किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। **यूआईडीएआई के बारे में** • यूआईडीएआई (UIDAI) को भारत के सभी निवासियों को 'आधार' नाम से विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) जारी करने के उद्देश्य से बनाया गया था: ○ डुप्लीकेट और नकली पहचान को खत्म करने के लिए ○ इसे आसान और लागत प्रभावी तरीके से सत्यापित और प्रमाणित किया जा सकता है। • भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) सरकार द्वारा 12 जुलाई 2016 को आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाएं लक्षित लक्ष्य) अधिनियम, 2016 ("आधार अधिनियम 2016") के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकारी है। • एक सांविधिक प्राधिकरण के रूप में अपनी स्थापना से पहले, यूआईडीएआई तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) के एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा था। • आधार अधिनियम 2016 के तहत, यूआईडीएआई इसके लिए जिम्मेदार है ○ आधार नामांकन और प्रमाणीकरण, आधार जीवन चक्र के सभी चरणों के संचालन और प्रबंधन सहित ○ व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली का विकास करना ○ प्रमाणीकरण करना ○ व्यक्तियों की पहचान की जानकारी और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करना। • यह इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
कौमी वक्फ बोर्ड तारकक़ियाती योजना	**संदर्भ:** अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय (MoMA) ने कौमी वक्फ बोर्ड तारकक़ियाती योजना (वक्फ संपत्तियों को जियोटैगिंग) के लिए मार्च 2022 से नवंबर 2023 तक की समय सीमा बढ़ा दी है। **महत्वपूर्ण तथ्य** • योजना के तहत, सभी वक्फ संपत्तियों को जियोटैग किया जाना है। • इस परियोजना की शुरुआत 2017 में 'कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना' के तहत की गई थी। • **मंत्रालय:** केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय • पूर्व में संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर इस योजना की परिकल्पना की गई थी। • इस योजना के तहत, सरकार वक्फ बोर्डों के तहत अचल संपत्तियों का उचित उपयोग और मुद्रीकरण सुनिश्चित करने के लिए उनका नक्शा बनाना चाहती थी। • इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि ये संपत्तियां अतिक्रमणों और अन्य प्रतिस्वामित्व दावों से सुरक्षित रहे। • अनुमान के मुताबिक, छह लाख से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। इसमें से 2 लाख संपत्तियों को पिछले पांच साल में जियोटैग किया गया है।

	अन्य संबंधित तथ्य • एक वक्फ (जिसे वक्फ या पति के रूप में भी जाना जाता है) इस्लामी कानून के तहत एक अविभाज्य धर्मार्थ बंदोबस्ती है। • इसमें आम तौर पर मुस्लिम धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के इरादे से एक इमारत, भूमि का भूखंड या अन्य संपत्ति दान करना शामिल है। • वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 9(1) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों द्वारा राज्य वक्फ बोर्डों की स्थापना की गई थी। • भारत में "बोर्डों के कामकाज और वक्फ के उचित प्रशासन से संबंधित मामलों पर" सरकार को सलाह देने के लिए एक केंद्रीय वक्फ परिषद भी है।
जल जीवन मिशन	**प्रसंग:** जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 1,473 करोड़ रुपए की लागत से पांच जिलों में फैली नौ सौ अठारह बस्तियों में संयुक्त जलापूर्ति योजनाएँ बनने जा रही हैं। • इन सभी योजनाओं पर कार्य दो साल में पूरा होने की उम्मीद है। • इस लागत में केंद्र सरकार का हिस्सा लगभग 581.5 करोड़ रुपए ; राज्य सरकार 884.3 करोड़ रुपए ; और सामुदायिक योगदान 7.4 करोड़ रुपए का है । **जल जीवन मिशन क्या है?** • वर्ष 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। • इसमें 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है। • इसमें स्कूलों, आंगनबाडी केन्द्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केन्द्रों, आरोग्य केन्द्रों और सामुदायिक भवनों के लिए कार्यात्मक नल कनेक्शन भी शामिल है। • यह कार्यक्रम अनिवार्य तत्वों के रूप में स्रोत स्थिरता उपायों को भी लागू करेगा, जैसे कि भूजल प्रबंधन, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन के माध्यम से पुनर्भरण और पुन: उपयोग। • JJM स्थानीय स्तर पर पानी की एकीकृत मांग और आपूर्ति-पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया है। • यह मिशन पानी के प्रति सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है। ○ यह पानी के लिए एक जन आंदोलन बनाना चाहता है, जिससे यह हर किसी की प्राथमिकता बन जाए। • यह नकद, वस्तु और/या श्रम और स्वैच्छिक श्रम में योगदान के माध्यम से स्थानीय समुदायों के बीच स्वैच्छिक स्वामित्व को बढ़ावा देना और सुनिश्चित करता है। • **मंत्रालय:** पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय • **फंडिंग पैटर्न:** केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न हिमालय और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 90:10, अन्य राज्यों के लिए 50:50 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% है। • राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर योजना का चार स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी।
महिलाओं के लिए समर्थ पहल	**संदर्भ:** हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, (MSME) ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान - "समर्थ" शुरू किया, ताकि उन्हें स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर एवं स्वतंत्र होने का अवसर प्रदान किया जा सके। जो प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। **महत्वपूर्ण तथ्य** • इस पहल के माध्यम से,एमएसएमई मंत्रालय महिलाओं को कौशल विकास एवं बाजार विकास सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है • समर्थ अभियान के तहत मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रमों में 20 प्रतिशत सीटें इच्छुक और मौजूदा महिला उद्यमियों के लिए आवंटित की जाएंगी। • जिसका फायदा 7500 से अधिक महिलाओं को होगा।

	• मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विपणन सहायता के लिए योजनाओं के अंतर्गत घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भेजे गए एमएसएमई व्यापार प्रतिनिधिमंडल का 20% महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई को समर्पित होगा। • मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं में महिलाओं के लिए कई अतिरिक्त लाभ प्रदान करके मंत्रालय महिलाओं के बीच उद्यमिता संस्कृति को विकसित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। • समर्थ योजना के अंतर्गत सिखाई जाने वाले कार्य : तैयार परिधान, भुने हुए कपड़े, धातु हस्तकला, हथकरघा, हस्तकला, कालीन आदि।
राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन	**संदर्भ:** पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन के लिए पर्यटन उद्योग और डोमेन विशेषज्ञों के साथ परामर्श करने, संदर्भ, मिशन, दृष्टि, उद्देश्यों और राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन के समग्र दायरे को परिभाषित करने हेतु एक अंतर-मंत्रालयी टास्क फोर्स का गठन किया था। • **विजन:** राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन का दृष्टिकोण एक डिजिटल राजमार्ग के माध्यम से पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न हितधारकों के बीच मौजूदा सूचना अंतर को दूर करना है। **आवश्कता (The Need)** • राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन देश की तथा राज्य पर्यटन संगठनों, पर्यटन सेवा प्रदाताओं, पर्यटन स्थलों, उत्पादों, अनुभवों और पर्यटकों में फैले पर्यटन क्षेत्र में सूचना एवं सेवाओं के आदान-प्रदान की सुविधा के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में डिजिटलीकरण की पूरी क्षमता का उपयोग करने के उद्देश्य को प्राप्त करने की परिकल्पना करता है। • केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र द्वारा विकसित अधिकांश पर्यटन प्रणालियाँ साइलो में कार्य करती हैं। • परिणामस्वरूप पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र सूचना के आदान-प्रदान के संयुक्त लाभों को प्राप्त करने में असमर्थ है। • डेटा सिस्टम वर्तमान में एक आम भाषा का उपयोग करके एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं, जिससे डेटा एनालिटिक्स और परिणामी नीति-निर्माण में कमी आती है। इसे दूर करने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच निर्बाध मानकीकृत डेटा विनिमय की आवश्यकता है।
वैश्विक उद्यमिता अनुश्रवक (जीईएम)	**संदर्भ:** वैश्विक महामारी एक बार जीवन भर के व्यवधान में है यह विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं में जीवन और आजीविका पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) खंड जैसे सबसे कमजोर और छोटे व्यवसायों के जीवन एवं आजीविका की रक्षा करने के उद्देश्य से कैलिब्रेटेड उपायों की एक श्रृंखला के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। 60,000 से अधिक स्टार्ट-अप के साथ अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप इकोसिस्टम बन गया है। जो अकेले वर्ष 2021 में 42 यूनिकॉर्न बनाए। **वैश्विक उद्यमिता अनुश्रवक (जीईएम)** • यह एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना है जो देशों के उद्यमशीलता परिदृश्य पर सूचना प्रदान करना चाहती है। • GEM संपूर्ण विश्व में उद्यमिता तथा उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र पर सर्वेक्षण-आधारित अनुसंधान करता है एवं इसका नेतृत्व भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद कर रहा है। • हाल ही में जारी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर (GEM) इंडिया रिपोर्ट (21-22) के अनुसार, 2021 में भारत की उद्यमशीलता गतिविधि का विस्तार हुआ। इसकी कुल उद्यमी गतिविधि दर (वयस्कों का प्रतिशत (18-64 आयु वर्ग) जो एक नया व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं अथवा संचालित कर रहे हैं) 2021 में बढ़कर 14.4% हो गई, जो 2020 में 5.3% थी। **मंत्रालय की पहल** • पायलट प्रोजेक्ट, 'महिला उद्यमियों का आर्थिक सशक्तिकरण और महिलाओं द्वारा स्टार्टअप (WEE)' को ड्यूश गेसेलशाफ्टफुर इंटरनेशनेल जुसामेनरबीट (GIZ) जर्मनी के सहयोग से कार्यान्वित है जो महिला सूक्ष्म उद्यमियों के लिए ऊष्मायन (इनक्यूबेशन) एवं त्वरक (एक्सेलरेशन) कार्यक्रमों को पायलट करने के लिए लागू किया जा रहा है, जिससे वे नए व्यवसाय आरंभ कर सकें तथा महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों जैसे राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मौजूदा उद्यमों को बढ़ायें। • औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), पॉलिटेक्निक, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) तथा जन शिक्षण

	संस्थान (जेएसएस) जैसे कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रों और पूर्व छात्रों के लिए उद्यमिता शिक्षा, प्रशिक्षण, पक्षपोषण तथा उद्यमिता नेटवर्क तक आसान पहुंच के माध्यम से एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करने हेतु उद्यमिता विकास पर प्रायोगिक परियोजना (पीएम युवा) नवंबर, 2019 में आरंभ किया गया है। इस योजना में महाराष्ट्र और 2 केंद्र शासित प्रदेशों सहित 10 राज्य शामिल हैं। • छह पवित्र शहरों में उद्यमिता संवर्धन एवं सूक्ष्म तथा लघु व्यवसायों हेतु परामर्श: परियोजना पंढरपुर, पुरी, वाराणसी, हरिद्वार, कोल्लूर एवं बोधगया में उद्यमिता जागरूकता, शिक्षा तथा परामर्श के माध्यम से संभावित एवं वर्तमान उद्यमियों की भागीदारी के माध्यम से स्थानीय उद्यमशीलता गतिविधियों को उत्प्रेरित करना चाहती है। • महिला श्रमिकों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, पीएमकेवीवाई केंद्रों और प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	**संदर्भ:** एक संसदीय समिति ने हाल की एक रिपोर्ट में कहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पिछले चार वर्षों से निष्क्रिय है और उसने संसद (Parliament) को एक भी रिपोर्ट नहीं दी है। आयोग की वेबसाइट के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में इसकी सिर्फ चार बार बैठक हुई है। शिकायतों के समाधान और इसे प्राप्त होने वाले मामलों के लंबित होने की दर 50% के करीब है। **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी)** • राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की स्थापना 19 फरवरी, 2004 से अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 338ए सम्मिलित करके की गई थी। • अत: यह एक संवैधानिक निकाय है। • **शक्तियाँ:** यह संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करना और ऐसे सुरक्षा उपायों के कामकाज का मूल्यांकन करता है। • अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित किसी भी शिकायत की जांच करने पर किसी भी मामले की जांच करते समय आयोग को सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां निहित हैं। • **संरचना:** इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन पूर्णकालिक सदस्य (एक महिला सदस्य सहित) शामिल हैं। ○ सदस्यों में कम-से-कम एक सदस्य महिला होनी चाहिये। ○ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। ○ सदस्य दो से अधिक कार्यकाल के लिए नियुक्ति के पात्र नहीं हैं।
पद्म पुरस्कार	**संदर्भ:** भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत (जिनकी पिछले साल तमिलनाडु में एक हेलिकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई), राजनीतिक नेता गुलाम नबी आजाद, टाटा संस के अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन, पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि और दिवंगत राधेश्याम खेमका शामिल थे। इन 54 प्रमुख हस्तियां को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। • इस समारोह में कुल 128 पुरस्कार प्रदान किए गए। **पद्म पुरस्कारों (Padma awards) के बारे में** • पद्म पुरस्कार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रतिवर्ष घोषित किए जाने वाले भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। • यह पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं: o पद्म विभूषण (असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए)। o पद्म भूषण (उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा) और o पद्म श्री (प्रतिष्ठित सेवा)। • इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। • जाति, व्यवसाय, पद या लैंगिक भेद के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं।

	• यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। • यह पुरस्कार पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर प्रदान किए जाते हैं, जिसका गठन हर साल प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। • इस समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं और इसमें गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और सदस्यों के रूप में चार से छह प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। • समिति की सिफारिशें अनुमोदन के लिए प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती हैं।
नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी)	**लक्ष्य:** नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को- 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में गैर-साक्षर लोगों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने में सहायता करना है। जिसके तहत, 2022-2027 तक की कार्यान्वयन अवधि के दौरान पूरे देश में 5 करोड़ गैर-साक्षरों को कवर किया जाएगा। **प्रमुख घटक :** 1. आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता 2. महत्वपूर्ण जीवन कौशल 3. व्यावसायिक कौशल विकास 4. बुनियादी शिक्षा 5. सतत शिक्षा **एनआईएलपी की मुख्य विशेषताएं हैं:** • स्कूली छात्रों, उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के पूर्व-सेवा छात्रों, स्कूल शिक्षकों, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं, एनवाईकेएस, एनएसएस, एनसीसी स्वयंसेवकों की भागीदारी। • योजना के क्रियान्वयन की इकाई विद्यालय होगा। • 'ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम' (ऑनलाइन शिक्षण, अधिगम तथा मूल्यांकन प्रणाली) के माध्यम से योजना के आईसीटी और ऑनलाइन कार्यान्वयन का उपयोग। • डिजिटल मोड के माध्यम से सामग्री और संसाधन, जैसे टीवी, रेडियो, सेल फोन-आधारित फ्री/ओपन-सोर्स ऐप्स/पोर्टल इत्यादि। • राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्कूलों में आयोजित की जाने वाली मूल्यांकन परीक्षाएं और एनआईओएस/एसआईओएस द्वारा शिक्षार्थियों का मूल्यांकन; ओटीएलएएस के माध्यम से मांग पर मूल्यांकन और ई-प्रमाणपत्रों का निर्माण। • नमूना उपलब्धि सर्वेक्षण • ऑनलाइन एमआईएस
प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) की उप-योजना के रूप में किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (एआरएचसी)	**संदर्भ:** आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने शहरी प्रवासियों / गरीबों को उनके कार्यस्थल के पास सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U) की एक उप-योजना के रूप में किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ARHCs) लॉन्च किया है। यह योजना दो मॉडलों के माध्यम से निम्नानुसार कार्यान्वित की जा रही है: • **मॉडल-1:** जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) और राजीव आवास योजना (आरएवाई) के तहत बनाए गए मौजूदा सरकारी वित्त पोषित खाली घरों का उपयोग सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) या सार्वजनिक एजेंसियों के माध्यम से एआरएचसी में परिवर्तित करने के लिए; • **मॉडल-2:** सार्वजनिक/निजी संस्थाओं द्वारा अपनी उपलब्ध खाली भूमि पर एआरएचसी का निर्माण, संचालन और रखरखाव। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एआरएचसी का वहनीय किराया स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थानीय सर्वेक्षण के आधार पर तय किया जाता है।
राष्ट्रीय समझ और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल	प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने का लक्ष्य और यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे पढ़ने, लिखने और अंकगणित में ग्रेड स्तर की दक्षता प्राप्त करें। • इसका उद्देश्य 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना है।

(निपुण भारत)	• स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा NIPUN को भारत में कार्यान्वित किया जाएगा। • यह ग्रेड 3 तक प्रत्येक बच्चे के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता में दक्षता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्राथमिकताएं एवं कार्रवाई योग्य एजेंडा निर्धारित करता है। • निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश विकसित किए गए हैं जिसमें लक्ष्य या मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के लक्ष्य शामिल हैं जो बालवाटिका से शुरू होकर 9 वर्ष की आयु तक हैं।
प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना	**संदर्भ:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा 2020-21 के दौरान अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग / गैर-अधिसूचित जनजाति और सफाई कर्मचारियों से संबंधित युवाओं (18-45 वर्ष के बीच की आयु) को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। जिसमें कचरा उठाने वाले भी शामिल हैं। • यह प्रशिक्षण नि:शुल्क है और तीन निगमों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (NSFDC), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (NBCFDC) और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC) संबंधित लक्षित समूहों को पूरा करते हैं। • इस योजना का मुख्य उद्देश्य लक्षित युवाओं के कौशल स्तर को दीर्घावधि और अल्पकालिक कौशल प्रदान करके रोजगार / स्वरोजगार में समझौता करना है।
लॉटरी कर पर राज्य क्षेत्राधिकार : सुप्रीम कोर्ट	**चर्चा में क्यों:** हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक राज्य विधायिका को अपने अधिकार क्षेत्र में अन्य राज्यों द्वारा आयोजित लॉटरी पर कर लगाने का अधिकार है। • न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा कि 'लॉटरी' एक 'जुआ गतिविधि' है। और 'सट्टेबाज़ी और जुआ' संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है। • चूंकि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि लॉटरी भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा या राज्य द्वारा अधिकृत है या राज्य सरकार या केंद्र सरकार की किसी एजेंसी या संस्था या किसी निजी अभिकर्त्ता द्वारा संचालित व आयोजित 'सट्टा और जुआ' है और राज्य विधानसभाओं को राज्य सूची की प्रविष्टि 62 के तहत लॉटरी पर कर लगाने का अधिकार है। **सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील** • यह फैसला कर्नाटक और केरल सरकारों द्वारा दायर अपीलों पर अपने संबंधित उच्च न्यायालयों के फैसले के खिलाफ दायर की गई अपीलों पर दिया गया है , जिसमें केरल और कर्नाटक में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर राज्यों द्वारा आयोजित और प्रचारित लॉटरी पर कर लगाने हेतु उनकी विधायिकाओं द्वारा अधिनियमित कानूनों को रद्द करने के लिए थे। • उच्च न्यायालयों ने दोनों राज्यों द्वारा बनाए गए कर कानूनों को अमान्य और असंवैधानिक पाया था और यहां तक कि केरल और कर्नाटक को लॉटरी से कर के रूप में एकत्र किए गए धन को उत्तर-पूर्वी राज्यों को वापस करने का निर्देश दिया था।
अनुच्छेद 355:	• अनुच्छेद 355 संविधान में उस प्रावधान को संदर्भित करता है जिसमें कहा गया है कि "संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करे।" • **पृष्ठभूमि:** 21 मार्च 2022 को, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोगटुई गांव में सत्ताधारी दल के दो समूहों के बीच हिंसक लड़ाई हुई थी। उप प्रधान, श्री भादु शेख की मौत हो गई और जवाबी कार्रवाई में घरों पर हमला किया गया और आग लगा दी गई, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं और बच्चों सहित 12 लोगों की मौत हो गई। सभी सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से हैं।
सीबीआई से सामान्य सहमति वापस लेना	**संदर्भ:** नौ राज्यों ने मामलों की जांच के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो- सीबीआई की सामान्य सहमति वापस ले ली है। • इनमें पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल और पंजाब राज्य शामिल हैं। **केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के बारे में** • सीबीआई भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। • **मंत्रालय:** कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। ○ **भूमिका:** यह मूल रूप से रिश्वतखोरी और सरकारी भ्रष्टाचार की जांच के लिए स्थापित किया गया था। • 1965 में, इसे भारत सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले केंद्रीय कानूनों के उल्लंघन, बहु-राज्य संगठित अपराध,

	बहु-एजेंसी या अंतरराष्ट्रीय मामलों की जांच के लिए विस्तारित अधिकार क्षेत्र प्राप्त हुआ। • सीबीआई को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से छूट प्राप्त है। • सीबीआई इंटरपोल के साथ संपर्क के लिए भारत का आधिकारिक रूप से नामित एकल संपर्क बिंदु है। • सीबीआई मुख्यालय: नई दिल्ली।
DIGs की प्रतिनियुक्ति: प्रस्तावित परिवर्तन	**संदर्भ:** अखिल भारतीय सेवा नियमों में संशोधन के अपने प्रस्ताव के बाद, जो इसे राज्य की सहमति के साथ या बिना केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर किसी भी आईएएस, आईपीएस या आईएफओएस अधिकारी को बुलाने की अनुमति देगा, केंद्र ने उप महानिरीक्षक स्तर के आईपीएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर एक और आदेश जारी किया है जो राज्यों के अनुकूल नहीं हो सकता है। **आदेश क्या है?** • मौजूदा नियमों के अनुसार, डीआईजी-रैंक के आईपीएस अधिकारियों, जिनके पास न्यूनतम 14 साल का कार्य अनुभव है, को केंद्र में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है यदि पुलिस स्थापना बोर्ड उन्हें केंद्र में डीआईजी के रूप में सूचीबद्ध करता है। • बोर्ड, अधिकारियों के कार्यकाल और सतर्कता रिकॉर्ड के आधार पर पैनल में उनका चयन करता है।अभी तक केवल पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को केंद्र के पैनल में शामिल करने की आवश्यकता नहीं होती थी। • कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने 10 फरवरी को जारी आदेश में कहा है कि डीआईजी स्तर पर केंद्र में आने वाले आईपीएस अधिकारियों को अब उस स्तर पर केंद्र सरकार के साथ पैनल में शामिल होने की जरूरत नहीं होगी। • नया आदेश राज्य में डीआईजी स्तर के अधिकारियों के पूरे पूल को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के योग्य बनाता है। **यह आदेश क्यों जारी किया गया है?** • गृह मंत्रालय (एमएचए) के सूत्रों ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य केंद्रीय पुलिस संगठनों (सीपीओ) और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में भारी रिक्तियों की पृष्ठभूमि में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए डीआईजी स्तर के आईपीएस अधिकारियों के पूल को बढ़ाना है। • विभिन्न सीपीओ और सीएपीएफ से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, केंद्र में डीआईजी स्तर पर आईपीएस अधिकारियों के लिए आरक्षित 252 पदों में से 118 (लगभग आधे) रिक्त हैं। IPS अधिकारियों का CPO और CAPF में 40% का कोटा होता है। **यह कदम कैसे मदद करेगा?** • गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया को आसान बनाने का विचार है क्योंकि अभिलेखों के सत्यापन में लंबा समय लगता है (कभी-कभी एक वर्ष तक)। • साथ ही, यह केंद्र के लिए उपलब्ध अधिकारियों के पूल के आकार को बढ़ाता है। • हालांकि, यह स्वतः ही डीआईजी को केंद्र में आने की अनुमति नहीं देगा। अधिकारियों को अभी भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए प्रस्ताव सूची में रखना होगा जो राज्यों और केंद्र द्वारा परामर्श से तय किया जाता है। साथ ही, राज्यों को उन्हें राहत देने के लिए तैयार रहना होगा। **इस आदेश से राज्यों को समस्या क्यों होगी?** • आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर हाल के प्रस्ताव के साथ पढ़ा जाए, तो नए आदेश को कई राज्यों द्वारा नए आदेश को राज्यों में सेवारत अधिकारियों पर अपनी शक्तियों को बढ़ाने हेतु केंद्र सरकार के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। • पहले के प्रस्तावों के तहत, केंद्र के पास एक निर्धारित समय सीमा के अंदर, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए राज्य से अधिकारियों के एक निश्चित कोटा की मांग करने और "जनहित" में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर किसी भी आईएएस अधिकारी को बुलाने का अधिकार होगा। यदि राज्य अधिकारी को कार्यमुक्त करने में विफल रहता है, तो उसे निर्धारित तिथि के बाद कार्यमुक्त माना जाएगा। • एनडीए द्वारा शासित कुछ राज्यों सहित अधिकांश राज्यों ने इस कदम का विरोध किया है। • इसके अलावा, केंद्र में रिक्तियों पर प्रभाव डालने वाली सूची की शर्तों में छूट के बहुत कम सबूत हैं। उदाहरण के

	लिए, एसपी स्तर के पदों के लिए पैनल में शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी रिक्तियां 50% के पास हैं। **राज्य अधिकारियों को राहत क्यों नहीं देते?** • राज्यों में भी अधिकारियों की भारी कमी है। • अटल बिहारी वाजपेयी के शासन के दौरान एक लागत-कटौती कदम में, अन्य सरकारी कर्मचारियों के बीच आईपीएस बैचों का आकार कम कर दिया गया था, बेशक उस समय भी बड़ी रिक्तियां मौजूद थीं। • 80-90 अधिकारियों में से प्रत्येक, आईपीएस बैचों को घटाकर 35-40 अधिकारी कर दिया गया (1999-2002 में, औसत 36 था)। सेवानिवृत्ति के कारण आईपीएस अधिकारियों की औसत सेवानिवृत्ति दर 85 प्रति वर्ष है। • कुछ राज्यों में जिलों की संख्या एक दशक में दोगुनी हो गई है, लेकिन अधिकारियों की उपलब्धता एक तिहाई थी। • वर्ष 2009 में, 4,000 से अधिक आईपीएस अधिकारियों की स्वीकृत संख्या के मुकाबले 1,600 से अधिक रिक्तियां थीं। यूपीए सरकार के दौरान, सरकार ने 150 के रूप में बड़े पैमाने पर आईपीएस बैचों का सेवन (intake) शुरू किया। ○ सरकार ने 2020 सिविल सेवा परीक्षाओं के साथ 200 IPS अधिकारियों को लेने के साथ बैचों के आकार में वृद्धि जारी रखी है। • एमएचए के अनुसार, 1 जनवरी, 2020 तक, स्वीकृत संख्या 4,982 के मुकाबले 908 रिक्तियां थीं। • 1990 के दशक के दौरान कम भर्ती के कारण आईएएस अधिकारियों की मजबूती भी प्रभावित हुई थी। **यह सेवाओं को कैसे प्रभावित किया है?** • आईपीएस भर्ती में विसंगति ने वर्षों से कैडर प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। कुछ स्तरों पर स्वीकृत पदों की तुलना में कम अधिकारी हैं, जबकि अन्य स्तरों पर भरमार है। • एक तरफ, राज्य केंद्र को पर्याप्त डीआईजी या एसपी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ, IPS के कुल कैडर रिजर्व की गणना करने पर केंद्र के पास पर्याप्त पद नहीं हैं। • उत्तर प्रदेश में डीआईजी (DIG) और आईजी(IG) की कमी है, लेकिन एडीजी के स्तर पर बहुत अधिक अधिकारी हैं। • तब जबकि राज्यों को आदर्श रूप से उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार बैचों या इसके कुछ हिस्सों को बढ़ावा देना चाहिए, राजनीतिक बॉस अक्सर एक निश्चित वर्ग को खुश करने के लिए पूरे बैचों को बढ़ावा देते हैं। • कार्यकाल में ठहराव का सामना कर रहे सीएपीएफ अधिकारी आईपीएस अधिकारियों के लिए डीआईजी स्तर के कोटा को हटाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि वे शामिल होने के इच्छुक नहीं हैं, ताकि फोर्स कैडर के अधिकारी इन पदों को भर सकें। • यह अनुमान है कि वर्ष 2025 तक, राज्यों के पास केंद्र के लिए अतिरिक्त डीआईजी स्तर पर अतिरिक्त अधिकारी हो सकते हैं और यदि केंद्र-राज्य संबंध सामान्य रहते हैं, तो समस्या का समाधान हो सकता है।
अमरावती पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का फैसला	**संदर्भ:** हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एपीसीआरडीए अधिनियम 2014 के प्रावधानों के तहत छह महीने के अंदर राज्य की राजधानी अमरावती और राजधानी क्षेत्र के निर्माण एवं विकास करने का निर्देश दिया। **मामले की संक्षिप्त पृष्ठभूमि** • वर्ष 2014 में, अमरावती क्षेत्र को आंध्र प्रदेश की राजधानी के स्थल के रूप में चुना गया था, और तेलंगाना नामक नया राज्य बना। • यद्यपि वर्ष 2019 में शासन परिवर्तन के साथ, जहां नई सरकार ने तीन राजधानियों के साथ विकेंद्रीकृत विकास का प्रस्ताव रखा, वहां काम रोक दिया गया। • आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा 'आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास अधिनियम, 2020 (तीन राजधानियों की स्थापना के उद्देश्य से) विधेयक पारित किया गया था। यह अधिनियम आंध्र प्रदेश राज्य के लिये तीन राजधानियों का मार्ग प्रशस्त करता है- अमरावती में विधायी, विशाखापत्तनम में कार्यकारी राजधानी, और कुरनूल में न्यायिक।

- अनिवार्य रूप से, अमरावती के लगभग 33,000 किसानों ने 2014-15 में राजधानी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए अपनी जमीन छोड़ दी थी।
- यद्यपि वर्ष 2020 में तीन राजधानी शहरों के निर्माण के कानून के साथ, किसानों के पास आजीविका का कोई स्थायी साधन नहीं बचा था। इसलिए उन्होंने इन नए कानून (तीन राजधानियों के प्रस्ताव) को एपी उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
- याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि राजधानी क्षेत्र (अमरावती) में विकास के अचानक रुकने से प्लॉट (plots) के मूल्य में गिरावट आई है इसका मतलब यह हो सकता है कि यदि लेने हेतु पुनः प्लॉट के मूल्य का अनुमान लगाया जाता है तो इन किसानों को सबसे कम कीमतों पर 30,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होगा।
- लेकिन नवंबर 2021 में, राज्य ने इन कानूनों को निरस्त/वापस ले लिया था।

उच्च न्यायालय के फैसले की मुख्य विशेषताएं

- राज्य के उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि वह अमरावती को राजधानी के रूप में विकसित करने की परियोजना को नहीं छोड़ सकता है क्योंकि किसानों द्वारा 33,000 एकड़ से अधिक को छोड़ दिया गया था और ₹15,000 करोड़ विकास व्यय में खर्च हो गए।
- न्यायालय ने कहा है कि तीन राजधानियों के प्रस्ताव के साथ राज्य की कार्रवाई मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 300-ए का उल्लंघन है।
- राज्य विधानमंडल में उच्च न्यायालय सहित सरकार के तीनों अंगों के राजधानी और विभागाध्यक्षों को स्थानांतरित करने, विभाजित करने या विभाजित करने के लिए कोई कानून बनाने की क्षमता का अभाव है।
- उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य उन याचिकाकर्ताओं से अपना वादा निभाने में विफल रहा है जिन्होंने विकसित, पुनर्गठित भूखंडों की उम्मीद में अपनी भूमि छोड़ दी थी क्योंकि राज्य वर्ष 2018 तक अमरावती शहर के निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करने में विफल रहा था।
- राज्य को छह महीने के भीतर अमरावती राजधानी शहर और राजधानी क्षेत्र का निर्माण एवं विकास करने का निर्देश दिया गया है।

फैसले के निहितार्थ

- यदि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर ध्यान नहीं दिया, तो राजधानी को अमरावती से बाहर स्थानांतरित करने के प्रयासों पर विराम लग सकता है।
- फैसले की एक स्वागत योग्य विशेषता यह है कि यह एक शासन को नागरिकों से अपने वादों से पीछे हटने से रोकने के लिए संवैधानिक विश्वास और वचन-बंधन के सिद्धांतों को लागू किया।
    - प्रॉमिसरी एस्टॉपेल अनुबंध कानून में एक सिद्धांत है जो एक व्यक्ति को एक वादे पर वापस जाने से रोकता है, भले ही कोई कानूनी अनुबंध मौजूद न हो।
- यह एक संदेश है कि शासन को राजनीतिक परिवर्तन की हवाओं से प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए या किसी विशेष शासन की सनक (whimsy) के लिए बंधक नहीं बनाया जाना चाहिए।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- राज्यों का पुनर्गठन
- शक्ति का विभाजन

भारत के व्यापार घाटे में वृद्धि	**संदर्भ:** प्रारंभिक विदेशी व्यापार अनुमानों के अनुसार, फरवरी में भारत का व्यापारिक निर्यात 22.3% बढ़कर 33.81 बिलियन डॉलर, जबकि आयात 35% बढ़कर 55 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया, जिससे व्यापार घाटा बढ़कर 21.2 बिलियन डॉलर पहुंच गया। **क्या आप जानते हैं?** एक व्यापार घाटा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक आर्थिक उपाय है जिसमें किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है। ***(व्यापार घाटा = आयात का कुल मूल्य - निर्यात का कुल मूल्य)***
ग्लोबल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (वैश्विक योज्य निर्माण)	**संदर्भ:** इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) का लक्ष्य अगले तीन वर्षों के भीतर वैश्विक योज्य निर्माण में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 5% करना है। • यह भी आशा की जाती है कि उस समय तक यह सकल घरेलू उत्पाद में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर जोड़ सकती है। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • ग्लोबल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हेतु राष्ट्रीय रणनीति के अनुसार, वर्ष 2025 तक भारत कुछ लक्ष्यों को हासिल करने का लक्ष्य रखेगा जैसे: o सामग्री, मशीन और सॉफ्टवेयर के लिए 50 भारत विशिष्ट तकनीकियां, o एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए 100 नए स्टार्टअप, o 500 नए उत्पाद। • कुल मिलाकर, MeitY को उम्मीद है कि ये नए स्टार्टअप और अवसर अगले तीन वर्षों में कम से कम 1 लाख नए कुशल श्रमिकों को रोजगार देंगे। **एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में** • 3डी प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक नई पीढ़ी की तकनीक है जो प्लास्टिक, राल (रेज़िन), थर्मोप्लास्टिक, धातु, फाइबर या मृत्तिका (सिरेमिक) जैसी सामग्रियों की क्रमबद्ध परतों का क्रम स्थापन कर वस्तुओं के प्रोटोटाइप या कार्यात्मक प्रतिरूप (वर्किंग मॉडल) निर्मित करने हेतु कंप्यूटर-एडेड डिज़ाइन का उपयोग करती है। • सॉफ्टवेयर की सहायता से प्रिंट किए जाने वाले मॉडल को पहले कंप्यूटर द्वारा विकसित किया जाता है, जो फिर 3डी प्रिंटर को निर्देश देता है।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	**संदर्भ:** हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के पूर्व प्रबंध निदेशक चित्रा रामकृष्ण को मई 2018 में दर्ज एक मामले में तरजीही पहुंच प्रदान करने के लिए एनएसई को-लोकेशन घोटाला मामले में कथित दुरुपयोग की जांच के लिए गिरफ्तार किया था। • सुश्री रामकृष्णा अप्रैल 2013 से दिसंबर 2016 तक एनएसई की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थीं। **सेबी द्वारा पहले जुर्माना** • 11 फरवरी को, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सुश्री रामकृष्ण, श्री सुब्रमण्यम, और एनएसई के पूर्व एमडी रवि नारायण पर कई उल्लंघनों के लिए दंड लगाया, जिसमें श्री सुब्रमण्यम की मुख्य रणनीतिक सलाहकार के रूप में नियुक्ति में अनियमितताएं शामिल थीं। **भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज** • यह मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित भारत का प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है। • डेरिवेटिव ट्रेड बॉडी फ्यूचर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन (एफआईए) द्वारा बनाए गए आंकड़ों के आधार पर कारोबार किए गए अनुबंधों की संख्या के हिसाब से यह वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज है। • यह कुछ प्रमुख वित्तीय संस्थानों, बैंकों और बीमा कंपनियों के स्वामित्व में है। • एनएसई की स्थापना 1992 में देश में पहले डीमैटरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के रूप में हुई थी।

	• एनएसई एक आधुनिक, पूरी तरह से स्वचालित स्क्रीन-आधारित इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली प्रदान करने वाला देश का पहला एक्सचेंज था जिसने देश के निवेशकों को आसान व्यापारिक सुविधाएं प्रदान कीं।
राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (NLMC)	**संदर्भ:** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (National Land Monetization Corporation-NLMC) की स्थापना को मज़ूरी दी है। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • NLMC की घोषणा 5000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी और 150 करोड़ रुपए की चुकता शेयर पूंजी के साथ की गई है। • सरकार "योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया" के माध्यम से एनएलएमसी के अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी और विशेषज्ञता के साथ निजी क्षेत्र के पेशेवरों को नियुक्त करेगी। • एनएलएमसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के साथ-साथ सरकारी एजेंसियों की अधिशेष भूमि और भवन संपत्ति का मुद्रीकरण करेगा। • नया निगम सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों से संबंधित संपत्तियों के मुद्रीकरण में भी मदद करेगा जो बंद हो गई हैं या रणनीतिक बिक्री के लिए तैयार हैं। • सरकार अप्रयुक्त और कम उपयोग की गई संपत्ति का मुद्रीकरण करके पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम होगी।
आरबीआई का $5 बिलियन डॉलर-रुपये का स्वैप	**संदर्भ:** हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी तरलता प्रबंधन पहल के हिस्से के रूप में $ 5 बिलियन डॉलर-रुपये की स्वैप नीलामी आयोजित की। • इस कदम से डॉलर का प्रवाह मज़बूत होगा और वित्तीय प्रणाली से रुपए की निकासी होगी। • इससे महंगाई कम होगी और रुपए में मजबूती आएगी। **स्वैप नीलामी के दौरान क्या होता है?** • RBI ने बैंकों को 5.135 बिलियन अमेरिकी डा ॅलर बेचे और साथ ही स्वैप निपटान अवधि के अंत में डॉलर को वापस खरीदने के लिये सहमति प्रदान की है। • यहाँ आशय यह है कि केंद्रीय बैंक विक्रेता से डॉलर प्राप्त करता है तथा दो वर्ष की अवधि के लिये संभव न्यूनतम प्रीमियम वसूल करता है। ○ तरलता का अर्थ है बाजार में तरल संपत्ति की उपलब्धता • बाज़ार में डॉलर के प्रवाह से रुपए को मज़बूती मिलेगी जो पहले ही अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 77 के स्तर पर पहुँच चुका है। • जब मुद्रास्फीति में वृद्धि का खतरा होता है तो आरबीआई आमतौर पर सिस्टम में तरलता को कम कर देता है। निम्नलिखित कारकों के कारण मुद्रास्फीति बढ़ना तय है। • आरबीआई तब बाजार से डॉलर खरीदता है और रुपये में बराबर राशि जारी करता है।
माइक्रोफाइनेंस संस्थान अब निर्धारित कर सकते हैं ब्याज दरें	**संदर्भ:** भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (MFI) को उन ब्याज दरों को निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी, जो वे उधारकर्त्ताओं से वसूलते हैं। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • ये दिशा-निर्देश 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होंगे। • 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार को दिये गए संपार्श्विक-मुक्त ऋण को इंगित करने हेतु आरबीआई ने माइक्रोफाइनेंस ऋण की परिभाषा को संशोधित किया। ○ इससे पहले ऊपरी सीमा ग्रामीण कर्जदारों के लिये 1.2 लाख रुपए और शहरी कर्जदारों के लिये 2 लाख रुपए थी। • माइक्रोफाइनेंस ऋणों पर कोई पूर्व भुगतान दंड नहीं होगा। • विलंबित भुगतान के लिये जुर्माना, यदि कोई हो तो वह अतिदेय राशि पर लागू होगा न कि संपूर्ण ऋण राशि पर। **सूक्ष्म वित्त संस्थान** • माइक्रोफाइनेंस छोटे व्यापार मालिकों के लिए एक समाधान प्रदान करता है, जिनके पास बैंकिंग और संबंधित

	सेवाओं तक पहुंच नहीं है। • ये संस्थान बैंक के समान सेवाएं प्रदान करते हैं। • वे ऋण पर ब्याज लेते हैं लेकिन ब्याज दर देश के अधिकांश बैंकों द्वारा वसूले जाने वाले ब्याज से कम है। • वे छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों को सही समय पर धन की पहुंच के साथ बड़े पैमाने पर मदद करते हैं। • उन्होंने वित्तीय समानता पैदा करने के उद्देश्य से एक विकल्प के रूप में काम किया। • भारत में, दो चैनल हैं जिनके माध्यम से माइक्रोफाइनेंस संचालित होता है: ○ SHG - बैंक लिंकेज प्रोग्राम (SBLP) ○ माइक्रोफाइनेंस संस्थान (MFIs)
पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल 'पीएम-डिवाइन'	**संदर्भ:** केंद्रीय बजट 2022-23 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा एक नई "पीएम-डिवाइन योजना" (PM-DevINE Scheme) प्रस्तावित की गई है। • पीएम-डिवाइन को नॉर्थ-ईस्टर्न काउंसिल के जरिए लागू किया जाएगा। • इस नई योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन किया जाएगा। **उद्देश्य:** • यह आवंटन पीएम गतिशक्ति की भावना के अनुरूप बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और पूर्वोत्तर की जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं की फंडिंग के लिए है। • विभिन्न क्षेत्रों में कमियों को पूरा करते हुए युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम बनाना। **पीएम गति शक्ति** • पीएम गति शक्ति मिशन 100 लाख करोड़ रुपये की योजना है। • पीएम गति शक्ति इस परियोजना को गति देने के लिए सरकार द्वारा वित्तपोषित 20,000 करोड़ रुपये के माध्यम से लोगों और सामानों की तेजी से आवाजाही की सुविधा के लिए प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के साथ राज्यों के लिए मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए 7 इंजनों को शामिल करेगी। • लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए - सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, बड़े पैमाने पर परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण। सभी सात इंजन एक साथ अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे • यह वर्ष 2024-25 के लिये सरकार द्वारा निर्धारित महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार और रेलवे एवं जहाजरानी मंत्रालयों द्वारा कार्गो क्षमता बढ़ाना शामिल है। • **महत्व:** वर्तमान में, भारत मेंलॉजिस्टिक कॉस्ट सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 13% है जबकि अन्य विकसित देशों में यह 8% की सीमा तक है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। ○ हमारे विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता ○ किसानों को कीमतों की बेहतर वसूली ○ उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर माल की उपलब्धता
मनरेगा में बाधा डालने वाले मुद्दे	**संदर्भ:** लोकसभा को सौंपी गई संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बाधा डालने वाले मुद्दों में फर्जी जॉब कार्ड, व्यापक भ्रष्टाचार, मस्टर रोल को देर से अपलोड करना और मजदूरी तथा सामग्री के लिए भारी लंबित भुगतान योजना शामिल हैं। • प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के संबंध में, पैनल ने कहा कि जमीनी स्तर की टिप्पणियों ने भ्रष्टाचार को उजागर किया। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • इस समिति को मनरेगा साइट पर काम करने वाले वास्तविक मजदूरों की अनुपलब्धता के बारे में सूचित किया गया था, जबकि कागज पर मजदूरों की संख्या स्थिर (stayed) और भरी हुई थी।

	○ इनकी लंबित मजदूरी रु. 4,060 करोड़ थी। **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) क्या है?** • मज़दूरी दरों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 के तहत अधिसूचित किया गया है। • लक्ष्य - ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा में सुधार करना। • मनरेगा दुनिया के सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। • यह एक सार्वभौमिक योजना है जो मांग व्यक्त करने वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देती है। • इसका उद्देश्य 'काम के अधिकार' की गारंटी देना है। • प्रत्येक पंजीकृत परिवार को अपने पूरे किए गए कार्य को ट्रैक करने के लिए एक जॉब कार्ड (JC) प्राप्त होता है। • इस योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। • मनरेगा की रूपरेखा का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग यह है कि इसके तहत किसी भी ग्रामीण वयस्क को मांग करने के 15 दिनों के भीतर काम पाने की कानूनी रूप से समर्थित गारंटी प्राप्त है, जिसमें विफल होने पर उसे 'बेरोज़गारी भत्ता' प्रदान किया जाता है। • यह आवेदक के निवास स्थान से 5 किमी के के दायरे में रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। • मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी अधिकार है। **प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के बारे में** • **शुरू किया गया:** वर्ष 2022 तक "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) को 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) में पुनर्गठित किया गया था। • **मंत्रालय:** ग्रामीण विकास मंत्रालय • **उद्देश्य:** मार्च 2022 के अंत तक सभी ग्रामीण परिवारों, जो बेघर या कच्चे या गिरे- पड़े घरों में रह रहे हैं, को बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का घर उपलब्ध कराना। • **लाभार्थी:** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग, मुक्त बंधुआ मजदूर और गैर-एससी/एसटी वर्ग, विधवाओं या कार्रवाई में मारे गए रक्षा कर्मियों के परिजन, पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, विकलांग व्यक्ति और अल्पसंख्यक इसके लिए पात्र होंगे। • इकाई (घर) सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60-40 के अनुपात में मैदानी क्षेत्रों में और 90:10 उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी राज्यों के बीच साझा की जानी है।
जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य	**संदर्भ:** कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2022-23 सीजन के लिए रॉ जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार 2022-23 के सीजन के लिए कच्चे जूट (टीडीएन 5 के समरूप टीडीएन 3) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 250 रुपये बढ़ाकर 4,750 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) क्या है?** • न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कृषि उत्पादकों को कृषि कीमतों में किसी भी तेज गिरावट के खिलाफ बीमा करने के लिए भारत सरकार द्वारा बाजार में हस्तक्षेप का एक रूप है। ○ एमएसपी बंपर उत्पादन वर्षों के दौरान किसानों को कीमतों में अत्यधिक गिरावट से बचाने के लिए निर्धारित मूल्य है। • कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर कुछ फसलों के लिए बुवाई के मौसम की शुरुआत में भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। • प्रमुख उद्देश्य किसानों को संकटग्रस्त बिक्री से सहायता करना और सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न की

	खरीद करना है। • सरकार ने 22 अनिवार्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) की घोषणा की। • **ये है :** ○ अनाज (7) - धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी ○ दाल (5) - चना, अरहर/तूर, मूंग, उड़द और मसूर ○ तिलहन (8) - मूंगफली, रेपसीड/सरसों, तोरिया, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल, कुसुम के बीज और नाइजर बीज ○ कच्चा कपास ○ कच्चे जूट ○ खोपरा (Copra) ○ भूसी रहित नारियल ○ गन्ना (उचित और लाभकारी मूल्य) ○ फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया (FCV) तंबाकू
भारत का निर्यात $400 बिलियन डॉलर के पार पहुंचा	• भारत ने वस्तुओं के निर्यात (merchandise exports) में पहली बार 400 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार किया है, इनमें इंजीनियरिंग उत्पादों, परिधान और वस्त्र, रत्न और आभूषण एवं पेट्रोलियम उत्पाद आदि शामिल है। • 2018-19 के पूर्व-महामारी वित्तीय वर्ष में निर्यात 331.02 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। मार्च महीने के दौरान शिपमेंट में अब तक 25.19 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है और 31 मार्च तक कुल आंकड़ा 410 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। • कृषि क्षेत्र ने भी "चावल, समुद्री उत्पाद, गेहूं, मसाले और चीनी" के निर्यात की मदद से 2021-22 के दौरान अपना अब तक का सबसे अधिक निर्यात दर्ज किया था • महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने यह लक्ष्य तय समय से 9 दिन पहले हासिल कर लिया है।
राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन	**संदर्भ:** भारत में स्मार्ट ग्रिड गतिविधियों से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की योजना और निगरानी के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संस्थागत तंत्र है। • भारत सरकार ने 2015 की शुरूआत में राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) को मंजूरी दी थी। • स्मार्ट ग्रिड का प्राथमिक उद्देश्य बिजली नेटवर्क की विश्वसनीयता में सुधार करना और वितरित उत्पादन के माध्यम से ग्रिड को अक्षय ऊर्जा इनपुट के लिए उत्तरदायी बनाना है। • स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट मीटर के साथ बढ़ी हुई क्षमता उपभोक्ताओं को अपनी बिजली की खपत को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने और उनके बिलों को कम करने में मदद करने के लिए सशक्त बनाती है। • एनएसजीएम स्मार्ट ग्रिड के क्षेत्र में वितरण क्षेत्र के कर्मियों के लिए क्षमता निर्माण पहल की भी परिकल्पना करता है।
निर्यात तैयारी सूचकांक 2021	**चर्चा में क्यों:** नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान के साथ साझेदारी में निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआई) 2021 जारी किया। • इसमें भारत की निर्यात उपलब्धियों का व्यापक विश्लेषण है। • सूचकांक का उपयोग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) द्वारा अपने साथियों के खिलाफ अपने प्रदर्शन को बेंचमार्क करने और उप-राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात-आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए बेहतर नीति तंत्र विकसित करने हेतु संभावित चुनौतियों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। • निर्यात तैयारी सूचकांक उप-राष्ट्रीय निर्यात प्रोत्साहन के लिए महत्वपूर्ण मूलभूत क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक डेटा-संचालित प्रयास है। **भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तीन प्रमुख चुनौतियां:** • निर्यात बुनियादी ढांचे में अंतर और अंतर-क्षेत्रीय अंतर

	• राज्यों में कमजोर व्यापार समर्थन और विकास अभिविन्यास • जटिल और अद्वितीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं विकास बुनियादी ढांचे की कमी • EPI राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 मुख्य स्तंभों पर रैंक करता है- **1. नीति:** एक व्यापक व्यापार नीति निर्यात और आयात के लिए एक रणनीतिक दिशा प्रदान करती है। **2. व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र:** एक कुशल व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र निवेश को आकर्षित करने और व्यवसायों के विकास के लिए एक सक्षम बुनियादी ढाँचा बनाने में मदद करता है। **3. निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र:** इस स्तंभ का उद्देश्य कारोबारी माहौल का आकलन करना है, जो निर्यात के लिए विशिष्ट है। **4. निर्यात प्रदर्शन:** यह एकमात्र आउटपुट-आधारित स्तंभ है और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के निर्यात पदचिह्नों की पहुंच की जांच करता है। **11 उप-स्तंभ-** • निर्यात संवर्धन नीति • संस्थागत ढांचा • व्यापारिक वातावरण • आधारभूत संरचना • परिवहन कनेक्टिविटी • वित्त तक पहुंच • निर्यात अवसंरचना • व्यापार सहायता • अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना • निर्यात विविधीकरण • विकास अभिविन्यास निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनकी निर्यात क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए एक अनुकूल निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने हेतु ध्वनि निर्यात-उन्मुख नीतियों की योजना बनाने और उन्हें निष्पादित करने में मदद करेगा।
भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था	**संदर्भ:** तिरुवनंतपुरम में दो प्रमुख अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग ने भारत की "अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था" पर प्रकाश डाला है। • भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के आकार को मापने के अपने तरह के पहले प्रयास में, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज (सीडीएस) और भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसटी) के शोधकर्ता वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 36,794 करोड़ (लगभग $ 5 बिलियन) रुपये के आंकड़े पर पहुंचे। **अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था क्या है?** • अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था सभी उद्योगों (रॉकेट और उपग्रह निर्माण, दूरसंचार, जलवायु परिवर्तन शोधकर्ता, डेटा और वित्त विशेषज्ञ, रक्षा, आदि) से बनी है, जो अंतरिक्ष में ट्रिलियन डॉलर का पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एक साथ आते हैं जो आधुनिक दिन, डिजिटल जीवन को संभव बनाता है। • अगले दशक के अंत तक, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का मूल्य रूढ़िवादी रूप से $4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगा। ○ कुछ अनुमानों के अनुसार वर्ष 2040 तक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था $10T से अधिक हो सकती है। • अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पर्यटन से परे और उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्रों में वस्तु और सेवाओं के लिए जाना जाता है, जो कर्मन (Karman) लाइन (लगभग 100 किलोमीटर ओवरहेड) और सिस्लुनर (Cislunar) स्पेस (भूस्थिर पृथ्वी की कक्षा और चंद्रमा की कक्षा के बीच का आयतन) मानवता के लिए संभावनाओं की एक और दुनिया का निर्माण कर रही है।

रूबल मुद्रा (Rouble currency)	**संदर्भ:** यूक्रेन पर हमलों के लिए रूस के खिलाफ लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के मद्देनजर, रूस ने हाल ही में जोर देकर कहा है कि वह केवल यूरोपीय संघ को रूबल में गैस वितरण के लिए भुगतान स्वीकार करेगा। • G7 मंत्रियों ने इस व्यवस्था को "अस्वीकार्य" कहा। • यूरोपीय संघ अपनी गैस आपूर्ति का लगभग 40% रूस से प्राप्त करता है। अरे क्या आपके पास यह है आप इसे देख सकते हैं हाँ **रूबल के बारे में** • यह रूसी संघ आधिकारिक मुद्रा है। • रूबल रूसी साम्राज्य और सोवियत संघ (सोवियत रूबल के रूप में) की मुद्रा थी। • यद्यपि आज केवल रूस, बेलारूस और ट्रांसनिस्ट्रिया समान नाम वाली मुद्राओं का उपयोग करते हैं। • रूसी रूबल का उपयोग अबकाज़िया, दक्षिण ओसेशिया, डोनेट्स्क और लुहान्स्क के आंशिक रूप से मान्यता प्राप्त चार गणराज्यों में भी अनौपचारिक रूप से किया जाता है। • अप्रैल 2019 तक, रूबल दुनिया में सत्रहवीं सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा है, और एक मुक्त-अस्थायी मुद्रा है। **G7 के बारे में** • G7 दुनिया की सात सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमरीका शामिल हैं। इसे ग्रुप ऑफ़ सेवन भी कहते हैं। • यह समूह स्वयं को "कम्यूनिटी ऑफ़ वैल्यूज" यानी मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय मानता है। स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और क़ानून का शासन और समृद्धि और सतत विकास, इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। • जी-7 का कोई औपचारिक संविधान या कोई निश्चित मुख्यालय नहीं है।
सागर परिक्रमा (Sagar Parikrama)	**द्वारा:** मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। **'सागर परिक्रमा' का उद्देश्य** • मछुआरों, तटीय समुदायों और हितधारकों के साथ बातचीत को सुगम बनाना ताकि सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न मत्स्य पालन संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी का प्रसार किया जा सके। • आत्मानिर्भर भारत की भावना के रूप में सभी मछुआरों, मछली पालने वाले किसानों और इससे संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करना। • राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा और तटीय मछुआरा समुदायों की आजीविका के लिए समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों के उपयोग के बीच स्थायी संतुलन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जिम्मेदार मात्स्यिकी को बढ़ावा देना। • समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण। 'सागर परिक्रमा' कार्यक्रम में चरणबद्ध तरीके से समुद्री राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करने की परिकल्पना की गई है। • तटीय क्षेत्रों में मछुआरों, मछुआरा समुदायों और हितधारकों को सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न लाभार्थी उन्मुख योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता के साथ लाभान्वित होने की संभावना है और उन्हें अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। • मछुआरों और अन्य हितधारकों के मुद्दों को हल करने और भारत सरकार द्वारा लागू की जा रही विभिन्न मत्स्य पालन योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से उनके आर्थिक उत्थान की सुविधा हेतु जैसे 'प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना' (पीएमएमएसवाई) एक प्रमुख योजना है। मात्स्यिकी क्षेत्र में अब तक का सर्वाधिक अनुमानित निवेश रु. 20,050 करोड़ है। **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाई) के बारे में** • भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने के लिए शुरू किया गया। • **लक्ष्य:** अगले 3 से 4 वर्षों में यानी 2024-25 तक मछली निर्यात को दोगुना करना।

	• **उद्देश्य:** मछली उत्पादन और उत्पादकता में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करने के लिए; गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे और प्रबंधन, मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, पता लगाने की क्षमता, एक मजबूत मत्स्य पालन प्रबंधन ढांचे की स्थापना और मछुआरों का कल्याण आदि। ○ एक स्थायी, जिम्मेदार, समावेशी और न्यायसंगत तरीके से मत्स्य पालन क्षमता का दोहन ○ कृषि जीवीए और निर्यात में योगदान बढ़ाना ○ मछुआरों और मछली किसानों के लिए सामाजिक, भौतिक और आर्थिक सुरक्षा; ○ मजबूत मात्स्यिकी प्रबंधन और नियामक ढांचा
UPI भुगतानों के लिए 'टैप टू पे''	**संदर्भ:** गूगल पे ने कस्टमर्स के लिए पेमेंट सर्विस को और बेहतर बनाने के लिए एक नई सुविधा 'टैप टू पे' (Tap to Pay) को लॉन्च की है। इसके लिए गूगल ने पाइन लैब्स (Pine Labs) के साथ साझेदारी की है। अभी तक 'टैप टू पे' सर्विस केवल कार्ड के लिए उपलब्ध थी। **महत्वपूर्ण तथ्य** • पेमेंट करने के लिए कस्टमर्स को अपने फोन को पीओएस (POS) टर्मिनल पर टैप करना होगा। इस टैप सर्विस (Tap to Pay) से पेमेंट और अधिक आसान हो जाएगी। • इसमें आपको अपने का इस्तेमाल करने क्यूआर कोड को स्कैन (QR Code) करना या UPI पिन को दर्ज नहीं करना होगा। • कार्यक्षमता किसी भी यूपीआई उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध होगी जो देश भर में किसी भी पाइन लैब्स एंड्रॉइड पीओएस टर्मिनल का उपयोग करके लेनदेन करने के लिए अपने एनएफसी-सक्षम एंड्रॉइड स्मार्टफोन का उपयोग करना चाहता है। • इसे रिलायंस रिटेल के साथ शुरू किया गया था और अब यह फ्यूचर रिटेल और स्टारबक्स जैसे अन्य बड़े व्यापारियों के लिए उपलब्ध होगा। **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) क्या है?** • UPI भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा अप्रैल 2016 में शुरू की गई एक भुगतान प्रणाली है, जो स्मार्टफोन का उपयोग करके किसी भी दो बैंक खातों के बीच धन हस्तांतरण की अनुमति देती है। • यह ग्राहकों को ग्राहक द्वारा बनाए गए वर्चुअल भुगतान पते का उपयोग करके चौबीसों घंटे भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है। • UPI एक ग्राहक को कार्ड या बैंक विवरण टाइप करने की परेशानी के बिना, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के विभिन्न व्यापारियों को सीधे बैंक खाते से भुगतान करने की अनुमति देता है। • यह "पीयर टू पीयर" संग्रह अनुरोध को भी पूरा करता है जिसे शेड्यूल और आवश्यकता और सुविधा के अनुसार भुगतान किया जा सकता है। • UPI को IMPS इंफ्रास्ट्रक्चर पर बनाया गया है। • वर्ष 2020-21 में भीम यूपीआई ने 41 लाख करोड़ रुपये के 22 अरब लेनदेन को संसाधित किया है।

जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी)	**संदर्भ:** इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया अगले दो दशकों में 1.5 डिग्री सेल्सियस के ग्लोबल वार्मिंग के साथ अपरिहार्य कई जलवायु खतरों का सामना कर रही है।
	• यहां तक कि अस्थायी रूप से इस वार्मिंग स्तर को पार करने का मतलब अतिरिक्त, गंभीर प्रभाव होगा, जिनमें से कुछ अपरिवर्तनीय होंगे।
	इस रिपोर्ट की मुख्य बातें
	• मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन, जिसमें अधिक लगातार और तीव्र चरम घटनाएं शामिल हैं, ने प्रकृति और लोगों को व्यापक प्रतिकूल प्रभाव और क्षति पहुंचाई है।
	• कुछ विकास और अनुकूलन प्रयासों ने भेद्यता को कम किया है।
	• सभी क्षेत्रों में सबसे कमजोर लोगों और प्रणालियों को अनुपातहीन रूप से प्रभावित देखा गया है।
	• मौसम और जलवायु चरम सीमाओं में वृद्धि ने कुछ अपरिवर्तनीय प्रभावों को जन्म दिया है क्योंकि प्राकृतिक और मानव प्रणालियों को अनुकूलन करने की उनकी क्षमता से परे धकेल दिया जाता है।
	'वेट-बल्ब' तापमान क्या है?
	• 'वेट-बल्ब' का तापमान वह न्यूनतम तापमान होता है, जिससे हवा में पानी के वाष्पीकरण द्वारा निरंतर दबाव में हवा को ठंडा किया जा सकता है।
	• रिपोर्ट के अनुसार, अगर उत्सर्जन में वृद्धि जारी रही तो लखनऊ और पटना 35 डिग्री सेल्सियस के 'वेट-बल्ब' तापमान तक पहुंचने की भविष्यवाणी कर रहे हैं।
	• भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, इंदौर और अहमदाबाद को निरंतर उत्सर्जन के साथ 32-34 डिग्री सेल्सियस के 'वेट-बल्ब' तापमान तक पहुंचने के खतरे के रूप में पहचाना जाता है।
	• कुल मिलाकर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब सबसे अधिक प्रभावित होंगे।
	• लेकिन यदि उत्सर्जन बढ़ता रहता है, तो सदी के अंत तक सभी राज्यों में ऐसे क्षेत्र होंगे जो 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक के वेट-बल्ब तापमान का अनुभव करेंगे।
	इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) क्या है?
	• यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा 1988 में नीति निर्माताओं को प्रदान करने के लिए स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है।
	  ○ जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक आधार का नियमित मूल्यांकन
	  ○ जलवायु परिवर्तन से जुड़े प्रभाव और भविष्य के खतरे
	  ○ जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूलन और शमन के विकल्प
	• आईपीसीसी की सदस्यता डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी के सभी सदस्यों के लिए ओपन है।
	• आईपीसीसी आकलन जलवायु संबंधी नीतियों को विकसित करने हेतु सभी स्तरों पर सरकारों के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु वार्ता भी करते हैं।
	• यूएनएफसीसीसी का मुख्य उद्देश्य वातावरण में ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को एक स्तर पर स्थिर करना, जो जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवजनित हस्तक्षेप को रोक सके।

नॉर्दन रिवर टेरापिन (Northern River Terrapin)	**संदर्भ:** हाल ही में, भारतीय सुंदरबन में 'नॉर्दन रिवर टेरापिन'कछुओं पर जीपीएस ट्रांसमीटर लगाए थे। • इस पहल का उद्देश्य प्रजातियों के निवास स्थान, प्रजनन पैटर्न और उनके संचलन का पता लगाना था। • नदी में छोड़े जाने के बाद गंभीर रूप से संकटग्रस्त नॉर्दन रिवर टेरापिन दस की संख्या में से कम से कम तीन ने सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके बांग्लादेश में पहुँच चुके हैं। **नॉर्दन रिवर टेरापिन के बारे में** • नॉर्दन रिवर टेरापिन दक्षिण पूर्व एशिया की नदीय कछुए की एक प्रजाति है।

	• यह भारत और बांग्लादेश (सुंदरबन), म्यांमार, मलेशिया (प्रायद्वीपीय), इंडोनेशिया (सुमात्रा), थाईलैंड और कंबोडिया में पाए जाते है। • यह तटीय मैंग्रोव मुहल्लों और खाड़ियों में रहता है, लेकिन प्रजनन के मौसम के दौरान यह बहुत ऊपर बढ़ जाते है। • **चुनौतियाँ :** o अंडे का शिकार और कटाई। o प्रदूषण और आवास की हानि o अवैध मछली पकड़ने के जाल से डूबना। o लॉगिंग जैसी वाटरशेड गतिविधियों के कारण गाद और अवसादन। • **IUCN:** गंभीर रूप से संकटग्रस्त • **CITES:** परिशिष्ट I
जैविक और विष हथियार सम्मेलन (BTWC)	**संदर्भ:** रूस ने यूक्रेन में जैविक प्रयोगशालाओं के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। • रूस ने यू.एस. द्वारा समर्थित यूक्रेन में रासायनिक और जैविक हथियार प्रयोगशालाओं से किए गए दावों पर चर्चा करने के लिए बैठक का अनुरोध किया था। • भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि जैविक और विषाक्त हथियार सम्मेलन (बीटीडब्ल्यूसी) के तहत दायित्वों से संबंधित किसी भी मामले को संबंधित पक्षों के बीच परामर्श और सहयोग के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए। **जैविक हथियार सम्मेलन** • जैविक हथियार सम्मेलन (बीडब्ल्यूसी), या जैविक और विष हथियार सम्मेलन (बीटीडब्ल्यूसी), एक निरस्त्रीकरण संधि है जो जैविक और विषाक्त हथियारों को उनके विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण, भंडारण और उपयोग पर रोक लगाकर प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करती है। o जैविक हथियार एक जीवाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, परजीवी, कवक, रसायन या विष है जिसे उद्देश्यपूर्ण ढंग से जैव आतंकवाद या जैविक युद्ध में एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। o अब तक 1,200 से अधिक विभिन्न प्रकार के संभावित हथियार बनाने योग्य जैव-एजेंटों का वर्णन और अध्ययन किया जा चुका है। • यह 26 मार्च 1975 को लागू हुआ। • BWC सामूहिक विनाश के हथियारों की एक पूरी श्रेणी के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि थी। • यह सम्मेलन असीमित अवधि का है। • जनवरी 2022 तक, 183 राज्य संधि के पक्षकार बने हैं।
चिल्का झील	**संदर्भ:** उड़ीसा सरकार ने 'चिल्का झील' (Chilika Lake) के मंगलाजोड़ी क्षेत्र में (Mangalajodi area) में मछली पकड़ने वाली मशीनीकृत नौकाओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया है। इसका उद्देश्य पंखों वाले मेहमानों को हर साल छह महीने के लिए एक अबाधित पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना है। • उड़ीसा उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाए। **चिल्का झील के बारे में** • चिल्का एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है, जो ओडिशा में स्थित है। • यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा सर्दियों का मैदान है और पौधों एवं जानवरों की कई संकटग्रस्त प्रजातियों का निवास है। o प्रवासी पक्षी जैसे नार्थन पिनटेल, गडवाल, शोवलर, कॉमन कूट और कई अन्य अतीत में झील का दौरा करते पाए गए हैं। • वर्ष 1981 में, चिल्का झील को रामसर सम्मेलन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया था। • चिल्का में प्रमुख आकर्षण इरावदी डॉल्फ़िन हैं जिन्हें अकसर सतपाड़ा द्वीप से देखा जाता है।

	• लैगून क्षेत्र में लगभग 16 वर्ग किमी. में फैला नलबाना द्वीप (फारेस्ट ऑफ रीडस) को वर्ष 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। • कालिजई मंदिर- यह मंदिर चिल्का झील में एक द्वीप पर स्थित है। **क्या आप जानते हैं?** • मंगलाजोड़ी को पक्षियों के संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण माना जाता है। • प्रवासी पक्षी वहां बसने और घोंसले बनाने के लिए पहुंचते हैं। • हालांकि, उभरती वनस्पतियों के साथ 8.3 वर्ग किमी दलदली भूमि की रक्षा के लिए कोई वैधानिक नियम और कानून नहीं हैं।
19,000 करोड़ रुपये की वनरोपण योजना शुरू	**संदर्भ:** पर्यावरण और जल शक्ति मंत्रालयों के अधिकारियों ने कहा कि केंद्र ने पेड़ लगाकर 13 प्रमुख नदियों को फिर से जीवंत करने के लिए 19,000 करोड़ रुपये की परियोजना की परिकल्पना की है। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदियां राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड द्वारा वित्त पोषित हैं। • इन नदियों और उनकी सहायक नदियों के दोनों किनारों पर पेड़ लगाए जाएंगे। **इस परियोजना का महत्व** • इन 13 नदियों के आसपास के क्षेत्र में संचयी वनावरण में वृद्धि करना। • जलवायु परिवर्तन और सतत विकास से संबंधित राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना। • भूजल पुनर्भरण में मदद करना • अवसादन को कम करना • गैर-लकड़ी और अन्य वन उपज से 449.01 करोड़ रुपये उत्पन्न करना • रोजगार प्रदान करना • कटाव कम करना
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण (Protection of Great Indian Bustards)	ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विश्व में सबसे अधिक वज़न के उड़ने वाले पक्षियों में से एक है, यह पक्षी मुख्यतया भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। इनमें से बमुश्किल 150 पक्षियों के विश्व स्तर पर जीवित रहने का अनुमान है, आज इसकी आबादी ज्यादातर राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है। • **वैज्ञानिक नाम:** अर्देओटिस नाइग्रिसप्स • भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Great Indian Bustard -GIB) को सोन चिरैया के नाम से भी जाना जाता है। • भौतिक विवरण (Physical description) : माथे पर काला मुकुट जो पीली गर्दन और सिर के विपरीत होता है। • वे घास के बीज, टिड्डे और भृंग जैसे कीड़ों, और कभी-कभी छोटे कृन्तकों और सरीसृपों को भी खाते हैं। • **वितरण:** भारत, प्रभावी रूप से बस्टर्ड का एकमात्र घर, आज इसकी आबादी ज्यादातर राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी इनकी आबादी कम मात्रा में पाई जाती है। • यह राजस्थान का राजकीय पक्षी है। जैसलमेर में जीआईबी के लिए चूजों के पालन केंद्र होने के साथ, राजस्थान में सोरसान को उनके पालन के लिए सबसे अनुकूल साइट के रूप में पहचाना गया है, क्योंकि वहाँ घास के मैदानों की उपलब्धता, सड़कों तक पहुंच और अच्छी तरह से अनुकूल जलवायु परिस्थितियां है। • जीआईबी घास के मैदान की एक प्रमुख प्रजाति है; यह घास के मैदानों के स्वास्थ्य को निर्धारित करता है, जिस पर पक्षियों और जानवरों की कई अन्य प्रजातियां और यहां तक कि डेयरी उद्योग भी निर्भर है। **मुद्दे:** • घास के मैदानों पर पवन चक्कियों और बिजली स्टेशनों की निर्बाध चराई और स्थापना, जिससे जीआईबी के प्रजनन और सर्दियों के मैदान पर अतिक्रमण हो रहा है। • चरागाह के बड़े भाग को कृषि भूमि में परिवर्तित होना।

	• बदलते कृषि पैटर्न जो पारंपरिक फसलों से दूर होते जा रहे हैं, इसका एक और कारण है। पारंपरिक बाजरा और ज्वार की फसलें, जिनके उप-उत्पाद चारे के रूप में इस्तेमाल होते थे, वे गायब होने के साथ उनके भोजन में गिरावट आना। • कुत्तों और लोमड़ियों के हमले • अवैध शिकार • उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों की उपस्थिति • **संरक्षण की स्थिति:** o द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची- 1 में सूचीबद्ध o CITES के परिशिष्ट I में सूचीबद्ध o IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध
इलेक्ट्रिक वाहन (EVs)	**संदर्भ:** हाल ही में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत में वर्ष 2022 के अंत तक इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बिक्री में 10 गुना वृद्धि होना तय है। • केंद्रीय मंत्री ने हाइड्रोजन को "भविष्य के लिए ईंधन" कहा है। **इलेक्ट्रिक वाहन (ईवीएस) के बारे में** • एक इलेक्ट्रिक वाहन प्रणोदन के लिए एक या एक से अधिक इलेक्ट्रिक मोटर या ट्रैक्शन मोटर्स का उपयोग करता है। • ईंधन को बिजली में बदलने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन को बैटरी, सोलर पैनल या इलेक्ट्रिक जनरेटर से चलाया जाता है। • भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की आवश्यकता o जलवायु परिवर्तन o तेजी से शहरीकरण o ऊर्जा सुरक्षा o नवाचार o रोजगार • भारत सरकार ने देश में ईवी पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं जैसे: • इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण (FAME II) योजना को फिर से तैयार करना। • आपूर्तिकर्ता पक्ष के लिए उन्नत रसायन विज्ञान प्रकोष्ठ (एसीसी) के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना। • इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माताओं के लिए ऑटो और ऑटोमोटिव घटकों के लिए हाल ही में शुरू की गई पीएलआई योजना।
असम में कुछ हिमालयन ग्रिफॉन की संदिग्ध विषाक्तता के कारण मृत्यु	**संदर्भ:** असम में कम से कम 100 गिद्धों (सभी हिमालयी ग्रिफॉन) की संदिग्ध विषाक्तता से मृत्यु हो गई। ऐसी घटनाएं कई सालों से हो रही हैं। **हिमालयन ग्रिफॉन** • हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर (जिप्स हिमालयेंसिस) एसीपीट्रिडी (Accipitridae) परिवार से संबंधित है, जिसमें ईगल, बुलबुल और बाज भी शामिल हैं। • यह यूरोपियन ग्रिफॉन वल्चर जी फुलवस (G. Fulvus) से संबंधित है। • इसके पंख काफी बड़े होते हैं और इसकी पूंछ छोटी होती है। इसकी गर्दन सफेद पीले रंग की होती है। • हिमालयी गिद्ध ज़्यादातर तिब्बती पठार (भारत, नेपाल और भूटान, मध्य चीन और मंगोलिया) पर हिमालय में पाए जाते हैं। • यह मध्य एशियाई पहाड़ों (पश्चिम में कज़ाखस्तान और अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पश्चिमी चीन तथा मंगोलिया तक) में भी पाया जाता है। • इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) की रेड लिस्ट में इस गिद्ध को "संकटापन्न" (Near Threatened या NT) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

	• 1990 के दशक में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और अन्य संगठनों द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि भारत और नेपाल में जिप्स समूह की आबादी केवल दो दशकों में लगभग 40 मिलियन से 99.9% कम हो गई। • हिमालयन ग्रिफॉन, सफेद पीठ वाले और पतले चोंच इसके सदस्यों में से हैं।
हाथियों की मौत की जांच के लिए स्थाई समन्वय समिति का गठन	**संदर्भ:** केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने रेल पटरियों पर हाथियों की मौत को रोकने के लिए एक 'स्थायी' समन्वय समिति का गठन किया है, जिसमें रेल और पर्यावरण मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं। • मंत्रालय ने कहा कि 2018-19 में रेलवे ट्रैक पर देशभर में 19, 2019-20 में 14 और 2020-21 में 12 हाथियों की मौत हुई। **उठाए गए आवश्यक कदम** • हाथियों की मौत की संख्या को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए। इसमे शामिल है: ○ चिन्हित किए गए हाथी गलियारों और आवासों में स्थायी और अस्थायी गति (स्पीड) प्रतिबंध लगाना; ○ चिन्हित स्थानों पर हाथियों की आवाजाही के लिए अंडरपास और रैंप बनाना; ○ चयनित स्थानों पर बाड़ लगाना, ○ चिन्हित किए गए हाथी गलियारों के बारे में ट्रेन चालकों को चेतावनी देने के लिए साइनेज (संकेतक) लगाना; ○ हाथियों के साथ ट्रेन की टक्कर से बचने के लिए ट्रेन के चालक दल और स्टेशन मास्टरों को संवेदनशील बनाना; और ○ रेलवे भूमि के भीतर ट्रैक के किनारों पर झाड़ी आदि को साफ करना। • भारतीय वन्यजीव संस्थान, पर्यावरण मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और विश्व बैंक समूह के परामर्श से "इको" नामक एक दस्तावेज प्रकाशित किया है। मानव-पशु संघर्ष को कम करने के लिए रेलवे लाइनों सहित रैखिक बुनियादी ढांचे को डिजाइन करने में परियोजना एजेंसियों की सहायता हेतु रैखिक बुनियादी ढांचे के प्रभावों को कम करने के लिए अनुकूल उपाय। **एशियाई हाथी:** • एशियाई हाथी की तीन उप-प्रजातियां हैं जो भारतीय, सुमात्राण और श्रीलंकाई हैं। • वैश्विक जनसंख्या: अनुमानित 20,000 से 40,000 तक। • विश्व की 60% से अधिक हाथी आबादी भारत में है। • आईयूसीएन रेड लिस्ट स्थिति: संकटापन्न। • वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I
समुद्री घास (Seagrass) पर कार्यक्रम	**समुद्री घास (Seagrass) के बारे में** • ये पुष्पी पौधे होते हैं जो खारे और लैगून जैसे उथले समुद्री जल में डूबे हुए उगते हैं। • इनमें छोटे फूल और पट्टा जैसे या अंडाकार पत्ते होते हैं। • समुद्री घास स्थलीय पौधों से विकसित हुई, जिन्होंने लगभग 70-100 मिलियन वर्ष पहले समुद्र को फिर से बसाया था। • समुद्री घास प्रकाश संश्लेषण द्वारा भी भोजन का उत्पादन करती है। • कुछ महत्वपूर्ण समुद्री घास: ○ सी काउ ग्रास (सीमोडोसेया सेरुलता) ○ थ्रीड सी ग्रास (सिमोडोशिया रोटंडेटा) ○ नीडल सी ग्रास (सीरिंगोडियम आइसोइटिफोलियम) ○ फ्लैट-टैप्ड सी ग्रास (हालोड्यूल यूनिनर्विस) आदि। • **स्थान :** ये दलदल (muddy) और रेतीले सबस्ट्रेट्स में पाए जाते हैं। ये हमारे पूर्वी तट मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी क्षेत्रों, पश्चिमी तट पर कच्छ क्षेत्र की खाड़ी, अरब सागर में लक्षद्वीप में द्वीपों के लैगून और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं।

	• **महत्व:**
	  ○ वे कई पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करते हैं।
	  ○ इन्हें 'समुद्र के फेफड़े' भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा पानी में ऑक्सीजन छोड़ते हैं
	  ○ समुद्र में दबे कार्बनिक कार्बन का 11% तक सीक्वेंसर (Sequesters)
	  ○ उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में समुद्री-घास वातावरण से 35 गुना अधिक तेज़ी से कार्बन का पृथक्करण कर सकती है।
	  ○ पानी की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करना
	  ○ भूमि आधारित उद्योगों से निकलने वाले पोषक तत्वों को फिल्टर करना
	  ○ मिट्टी के कटाव को रोकना
	  ○ मछलियों, ऑक्टोपस, झींगा, नीले केकड़ों, कस्तूरी आदि के लिए भोजन के साथ-साथ आवास प्रदान करना शामिल है।
	  ○ समुद्री-घास में 2-5 % प्रतिवर्ष की दर से गिरावट हो रही है।
	  ○ हाल के दशक में लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर समुद्री-घास की कमी हुई है।
	• **खतरे:** चराई, तूफान, बर्फ की परत (ग्लेशियर द्वारा समुद्र तल का घर्षण और क्षरण), अवसादों का बढ़ना, आवास का यांत्रिक विनाश, मत्स्य ट्रोलिंग, तटीय इंजीनियरिंग निर्माण आदि।
	• क्षेत्रीय सर्वेक्षण और उपग्रह डेटा के आधार पर, राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र ने भारत में समुद्री घास पारिस्थितिकी तंत्र की कुल सीमा 516.59 वर्ग किमी होने का अनुमान लगाया है। समुद्री घास पारिस्थितिकी तंत्र की CO2 अनुक्रम दर 434.9 टन / वर्गकिमी / वर्ष तक अनुमानित है, जिसमें 517 वर्ग किमी के क्षेत्र के लिए 0.75 मिलियन टन की वार्षिक शुद्ध CO2 सिंक है।
	कुछ कार्यक्रम
	• सरकार ने 130.269 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल लागत पर भारत के तटीय समुदायों की जलवायु लचीलापन बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा राज्यों में एक परियोजना शुरू की है जिसमें ग्लोबल क्लाइमेट फंड (जीसीएफ) द्वारा 43.419 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान शामिल है।
	• इन चयनित राज्यों में 24 पारिस्थितिक तंत्रों को कवर करना है, जिसका उद्देश्य भारत के प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जैसे मैंग्रोव और समुद्री घास की रक्षा एवं पुनर्स्थापित करके तटीय समुदायों की जलवायु लचीलापन को मजबूत करना है।

काजीरंगा में गैंडों की आबादी 200 बढ़ी	**संदर्भ:** हाल ही में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में एक-सींग वाले या भारतीय गैंडों की आबादी में चार वर्षों में 200 की वृद्धि हुई है।
	• वर्ष 2018 में हुई पिछली पशुगणना में गैंडों की आबादी 2,413 दर्ज की गई थी।
	• इस साल की गणना में पहली बार 26 उद्यान खंडों की पुन: जांच के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया था, जहां नमूना सर्वेक्षण किया गया था।
	• इससे पहले मार्च में असम के दो और गैंडों के आवासों में इसी तरह की जनगणना की गई थी। ओरंग नेशनल पार्क ने वर्ष 2018 में 101 के आंकड़े से 24 गैंडों की वृद्धि दर्ज की।
	  ○ पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य ने वर्ष 2018 की तुलना में पांच अधिक गैंडों को दर्ज किया।
	बड़ा एक सींग वाला गैंडा (Greater One-Horned Rhinoceros)
	• इस भारतीय गैंडे के रूप में भी जाना जाता है, यह राइनो प्रजातियों में सबसे बड़ा है।
	• भारत दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में एक सींग वाले गैंडे का घर है।
	  ○ वर्तमान में, भारत में लगभग 2,600 भारतीय गैंडे हैं, जिनकी 90% से अधिक आबादी असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में है।
	• **आवास:** यह प्रजाति इंडो-नेपाल के तराई क्षेत्र, उत्तरी पश्चिम बंगाल और असम तक सीमित है।
	• भारत में गैंडे मुख्य रूप से पाए जाते हैं-
	  ○ असम में काजीरंगा एनपी, पोबितोरा डब्ल्यूएलएस, ओरंग एनपी, मानस एनपी

	○ पश्चिम बंगाल में जलदापारा एनपी और गोरुमारा एनपी ○ उत्तर प्रदेश में दुधवा टीआर • **खतरा:** ○ सींगों के लिये अवैध शिकार ○ पर्यावास की हानि ○ जनसंख्या घनत्व ○ घटती जेनेटिक विविधता • **सुरक्षा की स्थिति:** ○ IUCN की रेड लिस्ट: सुभेद्य (Vulnerable)। ○ CITES: परिशिष्ट-I ○ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची-I

वेडेल सागर (Weddell Sea)	**संदर्भ:** वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने ध्रुवीय खोजकर्ता अर्नेस्ट शेकलटन के जहाज एंड्योरेंस के डूबे हुए मलबे को ढूंढ लिया है, जो अंटार्कटिक की बर्फ में खो जाने के एक सदी से भी अधिक समय बाद मिला है। • यह जहाज वेडेल सागर की सतह से 3,000 मीटर नीचे है। **वेडेल सागर के बारे में** • वेडेल सागर दक्षिणी महासागर का हिस्सा है और इसमें वेडेल गायरे शामिल हैं। इसकी भूमि सीमाओं को कोट भूमि और अंटार्कटिक प्रायद्वीप के तटों से बनने वाली खाड़ी द्वारा परिभाषित किया गया है। • समुद्र का अधिकांश दक्षिणी भाग एक स्थायी, विशाल बर्फ शेल्फ क्षेत्र, फिल्चनर-रोने आइस शेल्फ़ से आच्छादित है। • अंटार्कटिक प्रायद्वीप के पूर्व की ओर कुछ बर्फ की अलमारियां, जो पहले वेडेल सागर के लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर (3,900 वर्ग मील) को कवर करती थीं, 2002 तक पूरी तरह से गायब हो गई थीं। • वैज्ञानिकों द्वारा वेडेल सागर को किसी भी समुद्र का सबसे साफ पानी माना गया है।
सोलोमन द्वीप	**संदर्भ:** सोलोमन द्वीप ने चीन के साथ एक सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और एक व्यापक सुरक्षा समझौते का प्रस्ताव अपने मंत्रिमंडल को विचार के लिए भेजेगा। • सोलोमन द्वीप समूह ने वर्ष 2019 में राजनयिक संबंधों को ताइवान से बीजिंग में बदल दिया। • ऑस्ट्रेलिया ने सोलोमन द्वीप समूह को ऐतिहासिक रूप से सुरक्षा सहायता प्रदान की है। • सोलोमन द्वीप एक संप्रभु देश है जिसमें छह प्रमुख द्वीप हैं और ओशिनिया में 900 से अधिक छोटे द्वीप शामिल हैं जो पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में और वानुअतु के उत्तर-पश्चिम में स्थित हैं। • इसकी राजधानी होनियारा है जो वहाँ के सबसे बड़े द्वीप ग्वाडलकैनाल पर स्थित है। देश का नाम सोलोमन द्वीप द्वीपसमूह से लिया गया है, जो मेलानेशियन द्वीपों का एक संग्रह है। • यह दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है।

जोजिला सुरंग

संदर्भ: लद्दाख में चीनी सैनिकों के टकराव के साथ पिछले दो वर्षों में पुरुषों और मशीनरी की लामबंदी पर अतिरिक्त दबाव डालने के कारण लगभग 1,000 श्रमिकों ने जोजिला सुरंग की समय सीमा को दो साल आगे बढ़ाने के लिए मध्य कश्मीर में बर्फ से ढके सोनमर्ग में काम करना जारी रखा।

- पहले इसे 2026 तक पूरा किया जाना था।

जोजिला सुरंग के बारे में

- यह सुरंग एनएच-1 पर श्रीनगर घाटी और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क मुहैया कराएगी और जम्मू-कश्मीर का चौतरफा आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक एकीकरण करेगी।
- इसके साथ ही जोजिला दर्रे को पार करने में लगने वाला साढ़े 3 घंटे का सफर सिर्फ 15 मिनट में ही पूरा हो जाएगा
- कश्मीर घाटी में हिमालय की पर्वत श्रेणियों के बीच तैयार हो रही यह जोजिला टनल (Zojila Tunnel) है।
- जोजिला टनल (Zojila Tunnel) समुद्र तल से 11 हजार वर्ग मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर बनने वाली एशिया की सबसे लंबी सुरंग है।
- जोजिला टनल (Zojila Tunnel) को बनाने में स्टेट ऑफ आर्ट तकनीक का उपयोग किया गया है।
- सुरंग में हीट डिटेक्शन सिस्टम, सीसीटीवी, एलईडी स्क्रीन और लाइटिंग होगी।
- 14.15 किलोमीटर लंबी यह सुरंग एशिया की सबसे लंबी द्वि-दिशात्मक सुरंग होगी।

डारलोंग समुदाय (Darlong community)

संदर्भ: लोकसभा ने पिछले दिनों डारलोंग समुदाय को त्रिपुरा की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुकी जनजाति की उप-जनजाति के रूप में शामिल करने के लिए एक विधेयक पारित किया।

डार्लोंग समुदाय

- डारलोंग त्रिपुरा का एक आदिवासी समुदाय है, जिसकी आबादी 11,000 है।

	• समुदाय में शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों का उच्च प्रसार है तथा समुदाय के सदस्य स्थानीय प्रशासन में वरिष्ठ पदों पर कार्यरत हैं। • परंपरागत रूप से, डारलोंग समुदाय झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि (Slash and Burn Cultivation) प्रणाली का अनुसरण करते हैं • वर्तमान समय में अधिकांश ने गीले चावल (wet rice) की खेती और मौसमी सब्जियों की खेती के अलावा कृषि वानिकी और बागवानी वृक्षारोपण या बाग विकास को अपनी मुख्य आजीविका के रूप में लिया है। • डार्लोंग्स के पास उन्हें नियंत्रित करने और अपने मामलों को निपटाने के लिए प्रथागत कानून और प्रथाएं हैं।

इतिहास और संस्कृति

करकट्टम नृत्य	**संदर्भ:** हाल ही में, केरल नट्टुकला क्षेम सभा (केएनकेएस), एक संगठन जो राज्य में स्थानीय कलाकृतियों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, ने मांग की है कि काराकट्टम नृत्य को केरल के कृषि कला रूप के रूप में मान्यता दी जाए। **नृत्य के बारे में** • करकट्टम त्योहारों, सम्मेलनों, रोड शो और मुख्य रूप से मरिअम्मन (बारिश की देवी) त्योहारों पर किया जाने वाला लोक नृत्य है। • काराकट्टम और कृषि का एक संबंध है, क्योंकि केरल में मकरकोयथु (फसल के मौसम) के बाद, मरियम्मन पूजा मेदम महीने में होती है और मरियम्मन को बारिश की देवी माना जाता है। • काराकट्टम के प्रदर्शनों में बहुत सारी हिलती-डुलती हरकतें और हर्षित हंसी-मजाक होते हैं। • कलाकार अपने सिर पर एक बर्तन को संतुलित करते हैं। इसके लिए बहुत अभ्यास और समर्पण की आवश्यकता होती है। • अन्य हाइलाइट्स में आग फूंकना, आंखों में सुइयां डालना, और परफॉर्मर की पीठ पर जमीन के समानांतर एक बोतल रखते हुए संतुलन बनाए रखना शामिल हैं।
वीर योद्धा अहोम लचित बोरफुकन	**संदर्भ:** हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुवाहाटी में 17वीं शताब्दी के एक महान और वीर योद्धा लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह का उद्घाघन किया। • उन्होंने अलाबोई युद्ध स्मारक और महान सेनापति की 150 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा की भी नींव रखी। • लचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य का एक प्रसिद्ध सेनापति था। • उन्हें मुगल सेना के खिलाफ ब्रह्मपुत्र पर 1671 में 'सरायघाट की लड़ाई' में उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता है, जहां उन्होंने मुगल सेना को हराया था। • इससे पहले, अलाबोई की लड़ाई 5 अगस्त, 1669 को अहोम और मुगलों के बीच लड़ी गई थी, जहां मुगलों की जीत हुई थी। **अहोम साम्राज्य के बारे में (1228-1826)** • यह असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में देर से मध्यकालीन साम्राज्य था। • राज्य लगभग 600 वर्षों तक अपनी संप्रभुता बनाए रखने और पूर्वोत्तर भारत में मुगल विस्तार का सफलतापूर्वक विरोध करने के लिए जाना जाता है। • यह मोंग माओ के एक ताई राजकुमार सुकाफा द्वारा स्थापित किया गया था
नरसिंहपेट्टई नागस्वरम के लिए जीआई टैग	**संदर्भ:** तंजावुर जिले के नरसिंहपेट्टई में बने संगीत वाद्ययंत्र नागस्वरम को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग दिया गया है। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • नागस्वरम 'अचा मरम' से बना है, जो एक पेड़ है जो अपनी मजबूत विशेषताओं के लिए जाना जाता है। • आगे का भाग – अनुसू या बढ़ाने वाला – वागई की लकड़ी से बना होता है। ○ सीवली, ईख, एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो कावेरी और कोलिडम के तट पर उगती है।

- यह दक्षिण भारत का एक डबल रीड विंड इंस्ट्रूमेंट है।
- यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में पारंपरिक शास्त्रीय वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है।
- यह उपकरण "दुनिया के सबसे ऊंचे गैर-पीतल ध्वनिक यंत्रों में" है।
- यह एक पवन वाद्य यंत्र है जो आंशिक रूप से उत्तर भारतीय शहनाई के समान है।
- यह यंत्र बेलनाकार होता है और नीचे घंटी के आकार का होता है। इस वाद्य यंत्र में दो भाग होते हैं; शंक्वाकार नली और एक धातु की घंटी। छोर पर नीचे की ओर बढ़ने वाली नली, एक धातु की घंटी से सुसज्जित होती है।
- दक्षिण भारतीय संस्कृति में, इसे बहुत शुभ माना जाता है, और यह दक्षिण भारतीय परंपरा के लगभग सभी हिंदू शादियों और मंदिरों में बजाया जाने वाला एक प्रमुख संगीत वाद्ययंत्र है।

जीआई टैग क्या है?

- GI टैग यानि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ये एक प्रकार का लेबल होता है।
- जिसमें किसी प्रोडक्ट को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है ऐसा प्रोडक्ट जिसकी विशेषता या फिर नाम खास तौर से प्रकृति और मानवीय कारकों पर निर्भर करती है।
- जीआई कानून संसद में 2003 में पास हुआ और भारत की विरासत, समृद्धता (prosperity) और पहचान को बचाने और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध करने में कानूनी कवायद है।
- देश में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला।
- अब तक करीब 325 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है।
- वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटर्नल ट्रेड (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) की ओर से यह टैग दिया जाता है।
- किसी वस्तु को एक बार जीआई टैग मिल जाने के बाद 10 वर्षों तक मान्य होते हैं.
- वस्तु के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 भारत में जीआई माल का पंजीकरण और सुरक्षा प्रदान करता है।
- भारत के लिए भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री चेन्नई में स्थित है।
- एक पंजीकृत जीआई टैग किसी तीसरे पक्ष को ऐसे उत्पादों का उपयोग करने से रोकता है।
- जीआई एक सामूहिक बौद्धिक संपदा अधिकार है और इस प्रकार परिभाषित जीआई क्षेत्र के भीतर सभी उत्पादकों के स्वामित्व में है।
- पेटेंट और ट्रेडमार्क का स्वामित्व किसी व्यक्ति या व्यावसायिक इकाई के पास होता है।

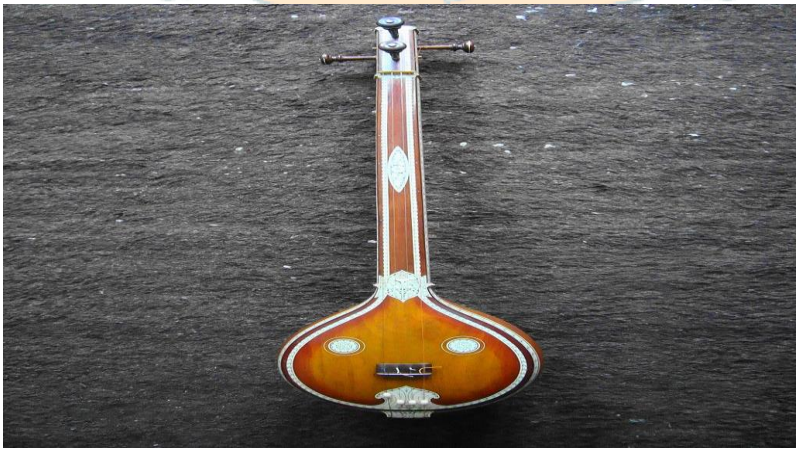

COVID-19 वैक्सीन प्रभावकारिता की भविष्यवाणी करने के लिए गणित मॉडल	**संदर्भ:** ऑस्ट्रेलिया में भारतीय विज्ञान संस्थान और क्वींसलैंड ब्रेन इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने एक गणितीय मॉडल विकसित किया है जो भविष्यवाणी करता है कि कैसे COVID-19 टीकों द्वारा उत्पन्न एंटीबॉडी रोगसूचक संक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। **मुख्य निष्कर्ष** • कई टीके उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिनमें से कुछ नैदानिक परीक्षणों में रोगसूचक संक्रमणों की संख्या को 95% से अधिक कम कर देते हैं। • टीम द्वारा विकसित मॉडल व्यक्ति के एंटीबॉडी 'प्रोफाइल' के आधार पर टीकाकरण के बाद उपलब्ध सुरक्षा के स्तर का अनुमान लगाने में सक्षम था। • सभी प्रमुख अनुमोदित टीकों के लिए नैदानिक परीक्षणों में रिपोर्ट की गई प्रभावशीलता से भविष्यवाणी को निकटता से मेल खाते हुए पाया गया। ○ शोधकर्ताओं ने यह भी देखा कि टीके की प्रभावशीलता एक आसानी से मापने योग्य मीट्रिक से जुड़ी हुई थी जिसे एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रे कहा जाता है। • इससे विस्तृत क्लिनिकल परीक्षण शुरू होने से पहले भविष्य के टीकों की प्रभावशीलता के परीक्षण के लिए ऐसे मॉडलों का उपयोग करने की संभावना खुलती है। • इस औपचारिकता को ओमाइक्रोन सहित नए रूपों पर लागू किया जाना बाकी है। **क्या आप जानते हैं?** • टीके की प्रभावशीलता का अनुमान लगाने का कारण कठिन रहा है क्योंकि इसमें शामिल प्रक्रियाएं जटिल हैं और कई परस्पर स्तरों पर संचालित होती हैं। • टीके कई अलग-अलग एंटीबॉडी को ट्रिगर करते हैं, प्रत्येक शरीर में वायरस के विकास को अलग तरह से प्रभावित करते हैं। • यह, बदले में, संक्रमण की गतिशीलता और संबंधित लक्षणों की गंभीरता को प्रभावित करता है। • इसके अलावा, अलग-अलग व्यक्ति एंटीबॉडी के अलग-अलग संग्रह और अलग-अलग मात्रा में उत्पन्न करते हैं।
सीएपीएफ के लिए आधुनिकीकरण योजना- IV	**ख़बरों में:** सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के लिए आधुनिकीकरण योजना- III के बाद "सीएपीएफ के लिए आधुनिकीकरण योजना- IV " को मंजूरी दे दी है। • कार्यान्वयन द्वारा: गृह मंत्रालय • सीएपीएफ को उन्नत आईटी समाधान भी प्रदान किए जाएंगे। • योजना के कार्यान्वयन से सीएपीएफ को समग्र परिचालन दक्षता/तैयारी में सुधार लाने में मदद मिलेगी, जिससे देश में आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। • यह अंतरराष्ट्रीय सीमा/एलओसी/एलएसी के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों, जैसे वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों, जम्मू और कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेशों, लद्दाख और उग्रवाद से प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारकी क्षमता को मजबूत करेगा।
टोही उपग्रह या खुफिया उपग्रह (Reconnaissance satellite)	**संदर्भ:** उत्तर कोरिया ने जासूसी या टोही उपग्रह विकसित करने के लिए आवश्यक डेटा ट्रांसमिशन और अन्य प्रमुख परीक्षण किए। लगभग एक सप्ताह में यह दूसरा ऐसा परीक्षण है, जो दर्शाता है कि देश जल्द ही प्रतिबंधित लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्च करने का इरादा रखता है। उत्तर कोरिया लगातार बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर रहा है। विशेषज्ञ इसे अपने शस्त्रागार में नई हथियार प्रणालियों को जोड़ने का प्रयास कहते हैं और रुकी हुई कूटनीति के बीच अमेरिका पर रियायतें देने का दबाव बनाते हैं। **टोही उपग्रह**

	• खुफिया उपग्रह, जिसे आमतौर पर जासूसी उपग्रह कहा जाता है, एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह या संचार उपग्रह है जिसे सैन्य या खुफिया अनुप्रयोगों के लिए तैनात किया गया है। • इसके कुछ प्रकार और उनके उपयोग ○ **मिसाइल पूर्व चेतावनी:** बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण का पता लगाकर हमले की चेतावनी प्रदान करता है। सबसे पहले ज्ञात मिसाइल रक्षा अलार्म सिस्टम हैं। ○ **परमाणु विस्फोट का पता लगाना:** अंतरिक्ष से परमाणु विस्फोट का पता लगाता है। मिसाइल रक्षा अलार्म सिस्टम सबसे पहले ज्ञात हैं। ○ **ऑप्टिकल इमेजिंग सर्विलांस:** इसका अर्थ इमेजिंग उपग्रह है। सैटेलाइट इमेज एक सर्वेक्षण या नज़दीकी दिखने वाली टेलीफ़ोटो हो सकती हैं। इससे कोरोना सबसे पहले ज्ञात हुआ। • टोही उपग्रहों का उपयोग उपग्रह प्रहरी परियोजना के माध्यम से मानवाधिकारों को लागू करने के लिए किया गया है, जो सूडान और दक्षिण सूडान में अत्याचारों की निगरानी करता है। • एक टोही उपग्रह को संचालित करने हेतु उत्तर कोरिया को इसे कक्षा में स्थापित करने के लिए एक लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्च करना होगा। ○ लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया द्वारा इस तरह के प्रक्षेपण पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि वह इसे अपनी लंबी दूरी की मिसाइल प्रौद्योगिकी के परीक्षण के लिए एक कवर के रूप में मानता है।
श्रीलंका - भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास 'स्लाइनेक्स'	**भाग :** प्रारंभिक और जीएस-II अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जीएस-III रक्षा और सुरक्षा **संदर्भ:** 7 से 10 मार्च तक, भारतीय और श्रीलंकाई नौसेना के द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास Sri Lanka–India Naval Exercise (SLINEX) का नौवां संस्करण विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। • यह संस्करण विशाखापत्तनम के नौसेना डाकयार्ड और बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ था। • SLINEX का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच बहुआयामी समुद्री संचालन के लिए अंतरसंचालनीयता को बढ़ाना, आपसी समझ में सुधार करना और सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रक्रियाओं का आदान-प्रदान करना है। • यह अभ्यास दो चरणों में आयोजित किया गया। • श्रीलंका नौसेना का प्रतिनिधित्व एसएलएनएस सयूराला द्वारा किया जाएगा, जो एक उन्नत अपतटीय गश्ती पोत है। • भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व आईएनएस किर्च, एक निर्देशित मिसाइल कार्वेट द्वारा किया गया।
प्लाज्मा के जेट के पीछे का विज्ञान	**ख़बरों में:** वैज्ञानिकों ने प्लाज्मा के जेट के पीछे के विज्ञान का पता लगाया है। यह प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है, जिसमें विद्युत रूप से आवेशित कण मौजूद होते हैं और सूर्य के क्रोमोस्फीयर में हर जगह मौजूद रहते हैं। क्रोमोस्फीयर वायुमंडलीय परत है जो कि सूर्य की दिखाई देने वाली सतह के ठीक ऊपर होती है। • ये जेट या स्पिक्यूल्स, पतली घास जैसी प्लाज्मा संरचनाओं के रूप में दिखाई देते हैं जो सतह से लगातार ऊपर उठते रहते हैं और फिर गुरुत्वाकर्षण द्वारा नीचे लाए जाते हैं। • इन स्पिक्यूल्स द्वारा ले जाई जा रही ऊर्जा की मात्रा और गति सौर प्लाज्मा भौतिकी में मौलिक रूचि है। • जिन प्रक्रियाओं द्वारा सौर हवा को प्लाज्मा की आपूर्ति की जाती है और सौर वायु मंडल एक मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है, यह अभी भी एक पहेली बना हुआ है। • दृश्यमान सौर सतह (फोटोस्फीयर) के ठीक नीचे प्लाज़्मा संवहन की स्थिति में होता है और निचली सतह पर किसी बर्तन में उबलते हुए गर्म पानी की तरह लगता है। इसे गर्म-घने कोर में परमाणु ऊर्जा द्वारा संचालित होता है। • यह संवहन लगभग आवधिक होता है, लेकिन यह सौर क्रोमोस्फीयर में प्लाज्मा को मजबूती से उद्दीत करता है। यह क्रोमोस्फीयर दृश्यमान सौर डिस्क के ठीक ऊपर अर्ध-पारदर्शी परत है। क्रोमोस्फीयर फोटोस्फीयर में प्लाज्मा की तुलना में 500 गुना हल्का है। इसलिए तल से उठने वाले ये मजबूत किक, घडियाल के आर्तनाद के विपरीत नहीं है, जो पतले कॉलम या स्पिक्यूल्स के रूप में अल्ट्रासोनिक गति से क्रोमोस्फेरिक प्लाज्मा को बाहर की ओर शूट करते हैं। • स्पिक्यूल्स सभी आकारों और गति में आते हैं। सौर समुदाय में मौजूदा सर्वसम्मति यह रही है कि छोटे स्पिक्यूल्स के पीछे की भौतिकी लम्बे और तेज़ स्पिक्यूल्स के मुकाबले अलग है।

चंद्रयान-2 ने किया पहला अवलोकन	**संदर्भ:** भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अनुसार, चंद्रयान-2 मिशन पर स्थित स्पेक्ट्रोमीटर चंद्र वातावरण संयोजन अन्वेषक-2 (चेस-2) ने चंद्रमा के वातावरण की बाहरी पतली परत में आर्गन-40 के वैश्विक वितरण का अब तक का पहला अवलोकन किया है। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • ये पर्यवेक्षण चंद्रमा के बाहरी वातावरण (एक्जोफियर) के गतिविज्ञान और चंद्रमा की सतह के नीचे शुरुआती कुछ मीटर में रेडियोधर्मी गतिविधियों पर रोशनी डालते हैं। ○ 'एक्जोफियर' किसी खगोलीय पिंड के ऊपरी वातावरण का सबसे बाहरी क्षेत्र है जहां घटक अणु और कण दुर्लभ तरीके से ही एक दूसरे से टकराते हैं। • CHACE-2 अवलोकन चंद्रमा के भूमध्यरेखीय और मध्य अक्षांश क्षेत्रों को कवर करते हुए Ar-40 की दैनिक और स्थानिक भिन्नता प्रदान करते हैं। • नोबल गैसें सतह-एक्सोस्फीयर इंटरैक्शन की प्रक्रियाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण ट्रेसर के रूप में काम करती हैं। ○ आर्गन-40 (Ar-40) चंद्र एक्सोस्फेरिक प्रजातियों की गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रेसर परमाणु है। • Ar-40 चंद्र सतह के नीचे मौजूद पोटेशियम-40 (K-40) के रेडियोधर्मी विघटन से उत्पन्न होता है। • एक बार बनने के बाद, यह अंतर-दानेदार स्थान के माध्यम से फैलता है और सीपेज और दोषों के माध्यम से चंद्र एक्सोस्फीयर तक पहुंच जाता है। **महत्वपूर्ण अवलोकन** • नासा के अपोलो-17 और LADEE मिशनों ने चंद्रमा के निकट-भूमध्यरेखीय क्षेत्र तक सीमित चंद्र बाह्यमंडल में Ar-40 की उपस्थिति का पता लगाया है। • चंद्र सतह का एक तीव्र अक्षांशीय तापमान प्रवणता है, यह अब तक चंद्र बाह्यमंडलीय प्रजातियों की वैश्विक गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए एक अंतराल क्षेत्र था, जो एक तापमान-संचालित प्रक्रिया है। • CHACE-2 जहाज पर अवलोकन मध्य-अक्षांश क्षेत्रों (-60^{o} से $+60^{o}$) तक के अवलोकन ज्ञान में अंतर को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। **चंद्रयान-2** • यह चंद्रमा के लिए भारत का दूसरा मिशन है और चंद्र सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में विफल रहा था। • लैंडर और रोवर अंतिम क्षणों में खराब होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। • विफल होने के बावजूद, मिशन का ऑर्बिटर और अन्य भाग सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं, और वहाँ की जानकारी एकत्र कर रहे हैं। **क्या आप जानते हैं?** • 'एक्सोस्फीयर' एक आकाशीय पिंड के ऊपरी वायुमंडल का सबसे बाहरी क्षेत्र है जहां घटक परमाणु और अणु शायद ही कभी एक दूसरे से टकराते हैं और अंतरिक्ष में हट सकते हैं।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी)	**संदर्भ:** हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (स्नातक) [NEET-UG] में भाग लेने के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा को हटा दिया है। **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी)** • राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में कुल 33 सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति एक विशेष समिति की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। • यह 25 सितंबर 2020 को भारतीय चिकित्सा परिषद का स्थान लिया। • चार स्वायत्त बोर्ड इस आयोग के तहत काम करेंगे। वे इस प्रकार हैं : ○ अंडरग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड ○ चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड ○ स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड

	○ नैतिक और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड **राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के बारे में** • राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (स्नातक) या एनईईटी (यूजी), पूर्व में अखिल भारतीय प्री-मेडिकल टेस्ट (एआईपीएमटी), उन छात्रों के लिए एक अखिल भारतीय प्री-मेडिकल प्रवेश परीक्षा है जो स्नातक चिकित्सा (एमबीबीएस), दंत चिकित्सा (एमबीबीएस) कोर्स करना चाहते हैं। • भारत में सरकारी और निजी संस्थानों में बीडीएस और आयुष (बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, आदि) पाठ्यक्रम और विदेशों में प्राथमिक चिकित्सा योग्यता हासिल करने के इच्छुक लोगों के लिए भी। • परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित की जाती है।
कार्बन कैप्चर और उपयोग	**संदर्भ:** भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाईऑक्साइड (CO_2) के अवशोषण और उसका उपयोग करने के लिए नए ठोस अवशोषक (एडजौर्बेन्ट्स) को संश्लेषित करने की रणनीति की खोज की है। आईआईएसईआर-कोलकाता के प्रो. बनर्जी के समूह ने विशेष प्रकार के नैनोकणों या माइक्रोपार्टिकल्स की खोज की है जो अपने सूक्ष्म और मेसोपोरस रिक्त स्थानों में कार्बन डाईऑक्साइड का भंडारण कर सकते हैं। • कार्बन के अवशोषण (कैप्चर) और उसका उपयोग, कार्बन डाईऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुसंधान के बढ़ते क्षेत्र हैं। • हालांकि इस बारे में बहुत सी औद्योगिक प्रविधियां पहले ही सामने आ चुकी हैं, किन्तु कोई भी तकनीक अब तक आर्थिक रूप से व्यवहार्य और पूर्ण कार्बन डाई ऑक्साइड के अवशोषण (कैप्चर) और उसके उपयोग समाधान प्रदान नहीं कर सकी हैं। इसलिए, अनूठे ठोस अवशोषक पर मौलिक शोध कार्बन डाईऑक्साइड के अवशोषण कैप्चर और उसके उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री की पेशकश कर सकता है।
कोरोनल मास इजेक्शन (Coronal Mass Ejections)	**ख़बरों में:** भारतीय शोधकर्ताओं ने सौर कोलोना की निरंतर पृष्ठभूमि को अलग करने और गतिशील कोरोना को प्रकट करने की एक सरल तकनीक विकसित की है। • सूर्य एक अत्यंत सक्रिय निकाय है, जहाँ कई हिंसक और विनाशकारी घटनाओं के ज़रिये भारी मात्रा में गैस और प्लाज़्मा बाहर निकालता है। • 'कोरोनल मास इजेक्शन' सौरमंडल में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोट हैं। **विकास का महत्व** • निरंतर पृष्ठभूमि को घटाने का सरल दृष्टिकोण कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई) की पहचान की दक्षता में सुधार कर सकता है – ऐसी घटनाएं जिनमें सौर कोरोना से अंतरिक्ष में ऊर्जावान और अत्यधिक चुंबकीय प्लाज्मा का एक बड़ा बादल फट जाता है, जिससे पृथ्वी पर रेडियो और चुंबकीय गड़बड़ी होती है। • यह सीएमई की विशेषताओं की स्पष्ट तस्वीर भी दे सकता है और उनके अध्ययन को बना सकता है। • कोरोनल मास इजेक्शन (सीएमई) सौर कोरोना में गतिशील संरचनाएं हैं और पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष में अंतरिक्ष मौसम को चला सकते हैं। • सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत का घनत्व - कोरोना - रेडियल रूप से बाहर की ओर दूरी के साथ घटता जाता है। • चूंकि सफेद रोशनी में देखे गए कोरोना की तीव्रता वातावरण में कणों के घनत्व पर निर्भर करती है, यह तेजी से घटती है। • यदि निरंतर कोरोना और क्षणिक सीएमई के बीच अंतर अधिक नहीं है, तो सीएमई का पता लगाना एक चुनौती बन जाता है।
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)	**संदर्भ:** प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) केंद्रों ने अपने ग्राहकों के लिए प्रोटीन पाउडर और बार, माल्ट-आधारित खाद्य पूरक और इम्युनिटी बार सहित न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों को जोड़ा है। **प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)** • यह औषधि विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है • विजन: "सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं" प्रदान करके भारत के प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य देखभाल बजट को कम करना।

	• प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र योजना के तहत खोला गया एक मेडिकल आउटलेट है जो सभी के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराता है। ○ वर्तमान में, पीएमबीजेपी केंद्र नागरिकों को सुलभ, मानकीकृत और सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। ○ पीएमबीजेपी केंद्रों के उत्पाद समूह में वर्तमान में 1,451 दवाएं और 240 सर्जिकल उपकरण शामिल हैं। ○ सरकार ने मार्च 2025 के अंत तक इनकी संख्या को बढ़ाकर 10,500 करने का भी लक्ष्य रखा है। • प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन "जनऔषधि सुगम" जनता को अपनी उंगलियों की नोक पर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करके सुविधा प्रदान करता है। • पीएमबीजेपी के तहत, एक दवा की कीमत उक्त दवा के शीर्ष तीन ब्रांडों के औसत मूल्य के अधिकतम 50% के सिद्धांत पर होती है। • इस प्रकार, जन औषधि दवाओं की कीमतें कम से कम 50% और कुछ मामलों में, ब्रांडेड दवाओं के बाजार मूल्य के 80% से 90% तक सस्ती हैं। • भारत में, फार्मास्युटिकल विभाग के तहत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण सभी दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करता है, चाहे वह ब्रांडेड हो या जेनेरिक। o यह औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसूचित दवाओं की अधिकतम कीमत तय करता है। o गैर-अनुसूचित दवाओं के मामले में, निर्माता दवा का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। **पौष्टिक-औषध (न्यूट्रास्युटिकल) क्या हैं?** • पौष्टिक-औषध (न्यूट्रास्युटिकल), जो "न्यूट्रिशन" (पोषण) और "फार्मास्युटिकल" (दवा/औषध) शब्दों से मिलकर बना है, एक खाद्य या खाद्य उत्पाद है जो बीमारी की रोकथाम एवं उपचार सहित स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय लाभ प्रदान करता है। • न्यूट्रास्युटिकल खाद्य स्रोतों से प्राप्त उत्पाद हैं जिन्हें खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले मूल पोषण मूल्य के अतिरिक्त अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए होते है। • **आलोचना:** चूंकि न्यूट्रास्युटिकल्स और बायोसेयूटिकल्स बड़े पैमाने पर अनियमित हैं, ये पूरक वास्तविक नैदानिक परीक्षण की तुलना में अधिक विपणन प्रचार का विषय हैं, और कई लोगों के लिए, यह अभी तक ज्ञात नहीं है कि क्या वे उपभोक्ताओं के लिए जोखिम से अधिक लाभ प्रदान करते हैं या नहीं।
मसौदा राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2022	**संदर्भ:** चिकित्सा उपकरण उद्योग के पहलुओं को बढ़ावा देने की जरूरत के अनुरूप, फार्मास्युटिकल विभाग ने चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के विकास में तेजी लाने और इसकी क्षमता का पता लगाने के लिए एक समग्र नीति की आवश्यकता को महसूस करते हुए हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद इस दृष्टिकोण पत्र को प्रकाशित किया है। चिकित्सा उपकरणों के इस उभरते क्षेत्र को लोकप्रिय रूप से मेडटेक सेक्टर कहा जाता है। वर्ष 2025 तक इस क्षेत्र के बाजार आकार के मौजूदा 11 बिलियन अमरीकी डालर से 50 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ने की उम्मीद है। **मुख्य विशेषताएं** • मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिये वैश्विक मानकों के साथ सामंजस्य के साथ-साथ व्यापार करने में आसानी के लिये नियामक प्रक्रियाओं और एजेंसियों की बहुलता को अनुकूलित करने हेतु नियामकों को सुव्यवस्थित करना। • वैश्विक मानकों के अनुरूप उपभोक्ताओं को सुरक्षित उपकरण उपलब्ध कराने के लिए गुणवत्ता मानकों और उपकरणों की सुरक्षा। • निजी क्षेत्र के निवेश के साथ स्थानीय विनिर्माण परितंत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय और वित्तीय सहायता के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता का निर्माण। • लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार और घरेलू निर्माताओं के आकर्षण को बढ़ाने के लिये परीक्षण केंद्रों जैसी सामान्य सुविधाओं के साथ चिकित्सा उपकरण पार्क सहित सर्वश्रेष्ठ भौतिक आधार उपलब्ध कराने के लिये

	बुनियादी ढाँचा विकास करना। • अकादमिक पाठ्यक्रम और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच की खाई को कम करने के लिये नवाचार एवं अनुसंधान व विकास परियोजनाओं, वैश्विक भागीदारी और प्रमुख हितधारकों के बीच संयुक्त उद्यमों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुसंधान तथा विकास और नवाचार की सुविधा प्रदान करना। • उच्च शिक्षा स्तर पर प्रासंगिक पाठ्यक्रम सुनिश्चित करने के लिये मानव संसाधन विकास, विभिन्न हितधारकों का कौशल विकास, नवाचार मूल्य शृंखला में आवश्यक कौशल के साथ भविष्य के लिये तैयार मानव संसाधन का निर्माण करना। • "मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" पहल के एक हिस्से के रूप में भारत को चिकित्सा उपकरणों के निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिये जागरूकता का सृजन और ब्रांड स्थापित करना। **नीति में इस बात का अनुमान लगाया गया है कि 2047 तक, भारत** • "राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान" (NIPERs) की तर्ज पर कुछ राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईएमईआर) होंगे। • मेडटेक (मेडिकल टेक्नोलॉजी) में 25 हाई-एंड फ्यूचरिस्टिक तकनीकों का प्रवर्तन करना। • वैश्विक बाज़ार हिस्सेदारी के 10-12% के साथ 100-300 बिलियन अमेरिकी डॉलर आकार का एक मेडटेक उद्योग होगा।
एक्सोमार्स (ExoMars) मिशन निलंबित	**संदर्भ:** यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) ने अपने €1bn (£844m) एक्सोमार्स मिशन को निलंबित कर दिया है, जो रूस के साथ एक संयुक्त परियोजना है। • यह सितंबर में रोबोटिक रोवर लॉन्च करने वाला था। • ईएसए के सदस्य देशों ने हाल ही में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के कारण प्रक्षेपण को रद्द करने के लिए वोट किया। **इस मिशन के बारे में** • एक्सोमार्स (ExoMars) का नाम रोसैलिंड फ्रैंकलिन (Rosalind Franklin) रखा गया है। इसकी असेंबली यूके में हो रही है। ○ रोसालिंड फ्रैंकलिन संयुक्त यूरोपीय-रूसी मिशन का दूसरा चरण है। ○ पहला भाग, ट्रेस गैस ऑर्बिटर नामक एक उपग्रह, 2016 में लॉन्च किया गया था और यह ग्रह के वातावरण का अध्ययन कर रहा है। ○ रोवर के आने पर इसे रोसैलिंड फ्रैंकलिन के लिए एक दूरसंचार रिले के रूप में भी काम करना चाहिए था। • पृथ्वी और मंगल के संरेखण पर आधारित अगली उपलब्ध लॉन्च विंडो 2024 होगी, लेकिन तकनीकी और राजनीतिक मुद्दों को हल करने में इससे अधिक समय लग सकता है। • ईएसए ने रोस्कोस्मोस (रूसी अंतरिक्ष एजेंसी) की भागीदारी के बिना एक्सोमार्स को जमीन से बाहर निकालने का एक व्यवहार्यता अध्ययन शुरू किया है। • नासा के साथ काम करना एक विकल्प है और इसने मिशन को "समर्थन करने की प्रबल इच्छा" व्यक्त की थी।
डीप ओशन मिशन (DOM)	**संदर्भ:** भारत जल्द ही जीवन की उत्पत्ति के रहस्यों को जानने के लिए समुद्र तल की खोज करेगा क्योंकि वैज्ञानिक एक गहरे समुद्र मिशन के तहत समुद्र तल से 6,000 मीटर नीचे यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं। • **मंत्रालय:** पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • प्रारंभ में रु. 4,077 करोड़ रुपये का मिशन वैज्ञानिकों को अज्ञात में उतरने से पहले इस उद्देश्य के लिए विकसित की जा रही विभिन्न तकनीकों का परीक्षण करने के लिए 500 मीटर की गहराई तक यात्रा करने के लिए मजबूर करेगा। • डीप ओशन मिशन भारत को समुद्र तल का नक्शा बनाने में भी मदद करेगा, जो धातुओं और खनिजों का एक समृद्ध स्रोत है। • यह मिशन वैज्ञानिकों को संसाधन संपन्न क्षेत्रों की पहचान करने और उनका सीमांकन करने में मदद करेगा

	जिनका बाद में दोहन किया जा सकता है जब गहरे समुद्र में खनन के लिए उपयुक्त तकनीक उपलब्ध होंगी। • खनिजों के अन्वेषण अध्ययन से निकट भविष्य में वाणिज्यिक दोहन का मार्ग प्रशस्त होगा, जब अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण द्वारा इस तरह का कोड विकसित किया जाएगा। • यह मिशन समुद्री जीव विज्ञान में विकास की दिशा में भी निर्देशित है जो भारतीय उद्योगों में रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
भारत की आर्कटिक नीति	**संदर्भ:** भारत के आर्कटिक नीति दस्तावेज के अनुसार, भारत आर्कटिक क्षेत्र में स्थायी उपस्थिति, अधिक शोध केंद्र और सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन स्थापित करने की इच्छा रखता है। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** • भारत में अब एक अकेला स्टेशन, हिमाद्री, Ny-Alesund, स्वालबार्ड, नॉर्वेजियन द्वीपसमूह में है, जहां अनुसंधान कर्मी आमतौर पर 180 दिनों के लिए मौजूद रहते हैं। • भारत एक बर्फ तोड़ने वाला अनुसंधान पोत प्राप्त करने की प्रक्रिया में है जो इस क्षेत्र में नेविगेट कर सकता है। • अपने मौजूदा उपग्रहों के माध्यम से, भारत "आर्कटिक क्षेत्र के विकास में सहायता" करने के लिए अधिक विस्तृत छवियों को कैप्चर करने की इच्छा रखता है। • भारत, आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा रखने वाले 13 देशों में से एक है। • आर्कटिक परिषद में आठ राज्य हैं जिनमें कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, रूस, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। ○ भारत वर्तमान में आर्कटिक परिषद में एक पर्यवेक्षक सदस्य है। हाल ही में, सरकार ने भारत के आर्कटिक नीति दस्तावेज का अनावरण किया। • आर्कटिक मौसम भारतीय मानसून को प्रभावित करता है और इसलिए दशकों से भारतीय शोधकर्ताओं के लिए रुचिकर रहा है। जलवायु परिवर्तन और बर्फ की चोटियों के पिघलने से आर्कटिक मौसम में परिवर्तन होता है।
विश्व क्षय रोग दिवस	**संदर्भ:** केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री, डॉ. मनसुख मांडविया विश्व टीबी दिवस (24 मार्च 2022) के अवसर पर नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में स्टेप-अप टू एंड टीबी – वर्ल्ड टीबी डे शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। • इस शिखर सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि होंगी जो वर्चुअली इसमें शामिल होंगी। • दो दिवसीय शिखर सम्मेलन राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की सीखों और सफलताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। **विश्व टीबी दिवस के बारे में** • यह हर साल 24 मार्च को 1882 में डॉ रॉबर्ट कोच द्वारा टीबी बैक्टीरिया की खोज की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। • **उद्देश्य:** तपेदिक (टीबी) की वैश्विक महामारी के बारे में जन जागरूकता का निर्माण करना। • संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2030 को दुनिया भर में टीबी को खत्म करने के वैश्विक लक्ष्य के रूप में चिह्नित किया है। • **पहल:** ○ केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्षय रोग उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना (2017-2025) का उद्देश्य 2025 तक टीबी के प्रसार को समाप्त करना है। ○ टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिये अप्रैल 2018 में निक्षय पोषण योजना (Nikshay Poshan Yojana), एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना की शुरुआत की गई है। ○ इस योजना के तहत टीबी रोगियों को उपचार की पूरी अवधि के लिये प्रतिमाह 500 रुपए मिलते हैं। ○ एनपीवाई राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ○ 'टीबी हारेगा देश जीतेगा' अभियान सितंबर 2019 में शुरू किया गया था जिसमें अभियान में तीन स्तंभ हैं - नैदानिक दृष्टिकोण, सार्वजनिक स्वास्थ्य घटक और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी। ये वर्ष 2025 तक टीबी को खत्म करने की रणनीति के एक भाग के रूप में थे। **टीबी क्या है?**

	• टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, जो लगभग 200 सदस्यों वाले माइकोबैक्टीरियासी परिवार से संबंधित है। • मनुष्यों में, टीबी सबसे अधिक फेफड़ों (फुफ्फुसीय टीबी) को प्रभावित करता है, लेकिन यह अन्य अंगों (अतिरिक्त-फुफ्फुसीय टीबी) को भी प्रभावित कर सकता है। • टीबी रोग का इलाज अब उपलब्ध है। • **संचरण:** टीबी हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ○ जब फेफड़े की टीबी से पीड़ित लोग खांसते, छींकते या थूकते हैं, तो वे टीबी के कीटाणुओं को हवा में फैला देते हैं। • टीबी सबसे ज्यादा फेफड़ों को प्रभावित करता है जिसकी वजह से इसके शुरुआती लक्षण खांसी के रूप में दिखाई देते हैं। टीबी हो जाने पर सबसे पहले सूखी खांसी आती है और बाद में बलगम के साथ साथ खून भी आने लगता है। • आठ देशों में टीबी के नए मामलों का दो तिहाई हिस्सा है: ○ भारत, इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका। • मल्टीड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस (एमडीआर-टीबी) टीबी का एक प्रकार है जिसका इलाज दो सबसे शक्तिशाली प्रथम-पंक्ति उपचार एंटी-टीबी दवाओं के साथ नहीं किया जा सकता है। • एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस (एक्सडीआर-टीबी) टीबी का एक रूप है जो बैक्टीरिया के कारण होता है जो कई सबसे प्रभावी एंटी-टीबी दवाओं के प्रतिरोधी होते हैं। • टीबी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले टीके: बीसीजी वैक्सीन।
हाइपरसोनिक मिसाइल	**संदर्भ:** रूसी रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि उसने यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। **हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है?** • हाइपरसोनिक मिसाइल एक हथियार प्रणाली है जो कम से कम मैक 5 की गति से अधिक गति से उड़ान भरती है यानी ध्वनि की गति से पांच गुना, और युद्धाभ्यास योग्य होती है। • हाइपरसोनिक मिसाइल की गतिशीलता इसे एक बैलिस्टिक मिसाइल से अलग करती है क्योंकि यह बाद में बैलिस्टिक प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करती है। • इस प्रकार बैलिस्टिक मिसाइलों के विपरीत, हाइपरसोनिक मिसाइलें बैलिस्टिक प्रक्षेपवक्र का पालन नहीं करती हैं तथा उन्हें इच्छित लक्ष्य तक ले जाया जा सकता है। • दो प्रकार की हाइपरसोनिक हथियार प्रणालियों में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल (Hypersonic Glide Vehicles- HGV) और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल (Hypersonic Cruise Missiles) शामिल हैं। • ये मिसाइलें लक्ष्य की ओर लॉन्च होने से पूर्व एक पारंपरिक रॉकेट के माध्यम से पहले वायुमंडल में जाती हैं, जबकि हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुँचने से पहले वायु की मदद से उच्च गति इंजन या 'स्क्रैमजेट' द्वारा संचालित होती है। ○ अमेरिका, रूस और चीन हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रमों के उन्नत चरणों में हैं। • भारत, फ्रांस, जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी हाइपरसोनिक हथियार विकसित कर रहे हैं।
आईएनएस वलसुरा को "प्रेसिडेंटस कलर" प्रदान किया	**संदर्भ:** भारतीय राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने नौसेना के प्रमुख तकनीकी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान आईएनएस वलसुरा को "प्रेसिडेंटस कलर" प्रदान किया। • शांतिकाल में और युद्ध के दौरान भी राष्ट्र को दी गई असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को राष्ट्रपति का रंग प्रदान किया जाता है। • आईएनएस वलसुरा बोर्ड युद्धपोतों पर परिष्कृत और तकनीकी रूप से उन्नत उपकरणों के संचालन और रखरखाव पर अधिकारियों और पुरुषों को प्रशिक्षित करता है। • 1942 में अंग्रेजों के अधीन 30 एकड़ भूमि पर टारपीडो स्कूल के रूप में शुरू हुआ आईएनएस वलसुरा, आज

	600 एकड़ में फैले देश के अग्रणी तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों में से एक बन गया है।
ई संजीवनी (eSanjeevani)	**संदर्भ:** भारत ने अपनी ई-हेल्थ यात्रा में युगांतकारी मील के पत्थर को पार कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ई-संजीवनी टेलिमेडिसिन सेवा टेलीकन्सलटेशन (टेलीपरामर्श) 2,26,72,187 को पार कर गई है। **ई संजीवनी के बारे में** • यह एक राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है जो टेली-परामर्श प्रदान करती है यह सेवा न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाती है बल्कि समय और धन की बचत करने के अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करती है। • ई-संजीवनी के दो संस्करण हैं जो पूरे भारत में दूरस्थ चिकित्सा परामर्श प्रदान कर रहे हैं। इनमें- डॉक्टर से डॉक्टर (ई-संजीवनीएबी-एचडब्ल्यूसी) और रोगी से डॉक्टर (ई-संजीवनीओपीडी) शामिल हैं। • पूर्व को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (AB-HWCs) कार्यक्रम के तहत लागू किया जा रहा है। • टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म 40 से अधिक ऑनलाइन ओपीडी की मेजबानी कर रहा है, इनमें से आधे से अधिक विशेष ओपीडी हैं जिनमें स्त्री रोग, मनोरोग, त्वचा विज्ञान, ईएनटी, नेत्र विज्ञान, एड्स / एचआईवी रोगियों के लिए एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी), गैर-संचारी रोग (एनसीडी) आदि शामिल हैं। **टिप्पणी:** • ई-संजीवनीओपीडी अब आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (ABHA) बनाने में सक्षम बनाता है, जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के अनुसार भाग लेने वाले स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और लाभार्थियों के साथ, लाभार्थी की सहमति से स्वास्थ्य डेटा की पहुंच और साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा। • ई-संजीवनी 'मेक इन इंडिया' पहल का एक उदाहरण है क्योंकि इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है।
डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन (जीसीटीएम): भारत (जामनगर, गुजरात में)	• आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए। • विश्वभर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र वैश्विक केंद्र (कार्यालय)। • यह पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और उत्पादों पर नीतियों तथा मानकों के लिए ठोस सबूत आधार बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा और देशों को इसे अपनी स्वास्थ्य प्रणालियों में उचित रूप से एकीकृत करने और इष्टतम एवं टिकाऊ प्रभाव के लिए इसकी गुणवत्ता और सुरक्षा को विनियमित करने में मदद करेगा। • जीसीटीएम का प्राथमिक उद्देश्य आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से दुनिया भर से पारंपरिक चिकित्सा की क्षमता का दोहन करना और दुनिया भर के समुदायों के समग्र स्वास्थ्य में सुधार करना है।

ऑपरेशन गंगा

संदर्भ: ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू की गई पहल है।

कुछ अन्य हालिया ऑपरेशन

- ऑपरेशन ऑल आउट (2015): इस ऑपरेशन में सेना के साथ सीआरपीएफ, बीएफएफ और आईबी साथ मिलकर काम कर रहे थे। इस ऑपरेशन का मकसद राज्य में मौजूद लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिद्दीन और अल-बदर को खत्म करना था।
- 2015 में भारतीय आतंकवाद विरोधी अभियान म्यांमार में: भारतीय सेना ने उग्रवादी संगठन एनएससीएन(खापलांग) के कैंप पर हमला करने के लिए म्यांमार सीमा में प्रवेश किया।
- जम्मू और कश्मीर में ऑपरेशन ऑपरेशन काम डाउन (2016)
- जम्मू और कश्मीर में ऑपरेशन रंदोरी बेहक (Randori Behak) (2020)
- पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, अफगानिस्तान में ऑपरेशन देवी शक्ति (2021): अफगानिस्तान से हिंदुओं और सिखों को भगाने में मदद के लिए।

चर्चा में स्थान: ज़ापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र (Zaporizhzhia Nuclear Power Plant)

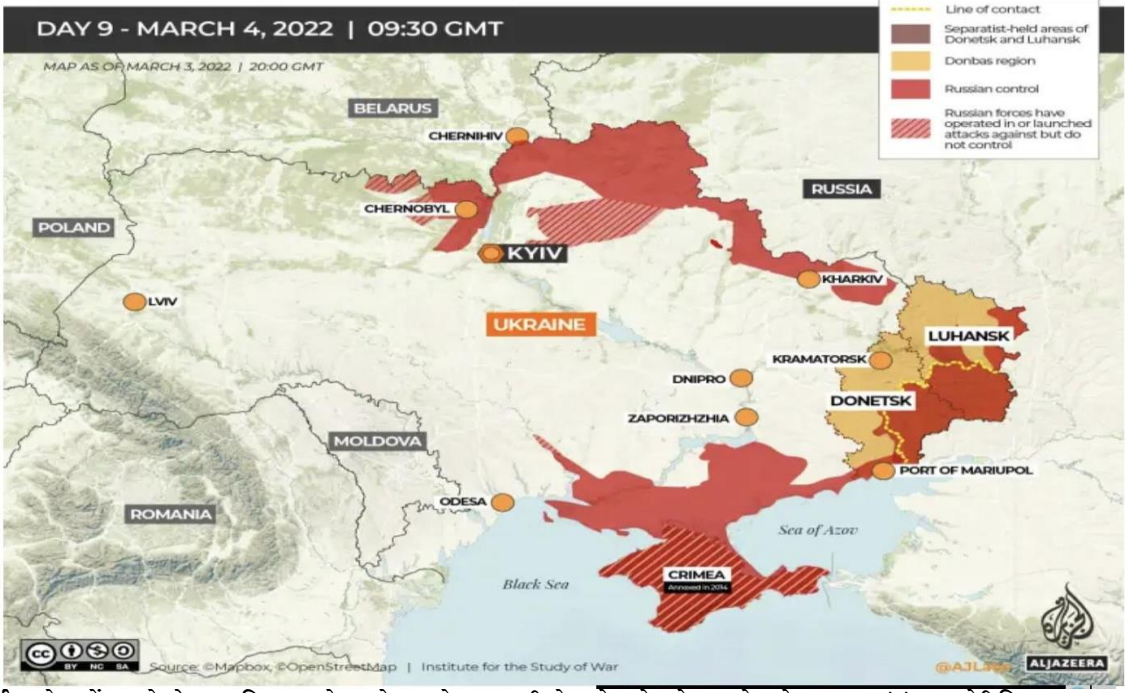

संदर्भ: यूक्रेन में अपने सैन्य अभियान को आगे बढ़ाते हुए रूसी सेना ने यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र ज़ापोरिज्जिया पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन में यह एक प्रमुख बिजली आपूर्तिकर्ता है।

- यह संयंत्र 40-42 बिलियन kWh उत्पन्न करता है जो यूक्रेन में औसत वार्षिक बिजली उत्पादन का पांचवां हिस्सा है।
- इस संयंत्र से यूक्रेन की जरूरत की 20 प्रतिशत बिजली की आपूर्ति होती है।
- ज़पोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूक्रेन में स्थित चार ऑपरेटिंग एनपीपी में से एक है और वर्ष 1984 से कार्यरत है।

प्रमुख तथ्य

- रूस ने पहले ही यूक्रेन की राजधानी कीव के उत्तर में लगभग 100 किलोमीटर (62 मील) उत्तर में मृत चेरनोबिल संयंत्र पर कब्जा कर लिया है।
- इसी के तहत हाल में खेरसोन पर कब्जा किया गया है और मारीपोल पर भीषण हमले हो रहे हैं।
- मीकोलईव यूक्रेन के महानगरों में शुमार है और वहां पर पानी के जहाज बनते हैं।
- अज़ोव सागर क्रीमिया के पूर्व में और यूक्रेन के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तरी किनारों पर यूक्रेन के दो बंदरगाह हैं, बर्डयांस्क और मेरीपोल है।
- उत्तरपूर्वी शहर खार्किव पर आक्रमण शुरू होने के बाद से ही हमले हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना	**संदर्भ:** केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के तहत किसी भी नागरिक को एक असंगठित श्रमिक की ओर से प्रीमियम राशि का भुगतान करने की अनुमति देने वाली 'डोनेट-ए-पेंशन' (Donate-a-Pension) स्कीम की शुरुआत की। **महत्वपूर्ण तथ्य** • इस स्कीम के तहत नागरिक घरेलू कामगारों, ड्राइवरों, घरेलू नौकरों सहित कर्मचारियों के लिए प्रीमियम का दान कर सकते हैं। • दाता कम से कम एक वर्ष के लिए योगदान का भुगतान कर सकता है, जिसकी राशि रु. 660 से रु. 2,400 प्रति वर्ष, लाभार्थी की आयु पर निर्भर करता है। **प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के बारे में** • यह पेंशन योजना 2019 में शुरू की गई थी। • इस स्कीम के तहत अगर 18-40 आयु वाले असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिक रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उन्हें साल के न्यूनतम 660 से 2400 रूपए जमा कराने होंगे। • जो उनके लिए कोई और भी जमा करा सकता है, पैसा जमा होने के बाद उनके आयु वर्ग के हिसाब से 60 साल के बाद 3,000 रुपये उन्हें पेंशन के रूप में दिए जाएंगे, जिससे बुढापे में उन्हें अपनी जीवन बस करने में काफी मदद मिलेगी। • इस योजना का लाभार्थी असंहठित क्षेत्र का कोई भी श्रमिक उठा सकता है. घर पर काम करने वाले या फिर स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा कामगार, मोची, कूड़ा वाला, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, मजदूर, निर्माण मजदूर, बीड़ी मजदूर के अलावा भी कई लोग इसका फायदा उठा सकते हैं।
उत्तर अटलांटिक संधि संगठन	**संदर्भ:** यूक्रेन अब नाटो सदस्यता के लिए दबाव नहीं बना रहा है। नाटो एक उत्कृष्ट मुद्दा (delicate issue) रहा है जो यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस के बताए गए कारणों में से एक था यह पश्चिमी समर्थक है। **उत्तर अटलांटिक संधि संगठन क्या है?** • यह सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल, 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि (जिसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है) द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। • इस संधि के एक प्रमुख प्रावधान को अनुच्छेद 5 कहा जाता है। • इसमें कहा गया है कि अगर यूरोप या उत्तरी अमेरिका में गठबंधन के एक सदस्य पर हमला किया जाता है, तो इसे सभी सदस्यों पर हमला माना जाना चाहिए। ○ यह पश्चिमी यूरोप को अमेरिका के "परमाणु छत्र" के तहत प्रभावी रूप से डाल दिया। • इसमें 30 स्वतंत्र सदस्य देश शामिल हैं।
कोर कमांडर वार्ता का 15वां दौर	**संदर्भ:** भारत व चीन के बीच लद्दाख में तनाव खत्म करने के लिए सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता का 15 वां दौर शुरू हुआ। दोनों देशों के सैन्य कमांडर एलएसी के समीप चुशुल मोल्डो के भारतीय क्षेत्र में बैठक कर रहे हैं। • चर्चा का मुख्य विषय हॉट स्प्रिंग्स पाइंट (Patrolling Point-15) से सेना की वापसी की रुकी प्रक्रिया को पूरा करना रहेगा। • मई 2020 में गतिरोध शुरू होने के बाद से, दोनों पक्षों ने अब तक पैंगोंग त्सो (झील), पीपी17 के दोनों किनारों पर 14 दौर की बातचीत की है। • पीपी15, डेमचोक और देपसांग अन्य क्षेत्रों का समाधान किया जाना बाकी है। **पेट्रोलिंग प्वाइंट 15 और 17ए:** • भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ, भारतीय सेना को कुछ ऐसे स्थान दिए गए हैं जहां उसके सैनिकों की पहुंच उसके नियंत्रण वाले क्षेत्र में गश्त करने के लिए है। • इन बिंदुओं को गश्त बिंदु या पीपी के रूप में जाना जाता है, और चीन अध्ययन समूह (सीएसजी) द्वारा तय किया जाता है।

	• PP15 और PP17A एलएसी के साथ लद्दाख में 65 गश्ती बिंदुओं में से दो हैं। • LAC वह सीमांकन है जो भारतीय-नियंत्रित क्षेत्र को चीनी-नियंत्रित क्षेत्र से अलग करता है। • PP15 हॉट स्प्रिंग्स नामक क्षेत्र में स्थित है, जबकि PP17A गोगरा पोस्ट नामक क्षेत्र के पास है। **हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट का स्थान** • हॉट स्प्रिंग्स चांग चेन्मो नदी के उत्तर में है और गोगरा पोस्ट उस बिंदु के पूर्व में है जहां यह नदी गलवान घाटी से दक्षिण-पूर्व में आकर दक्षिण-पश्चिम की ओर मुड़ती है। **अन्य संबंधित तथ्य** • **पैंगोंग त्सो झील:** पैंगोंग झील केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। पैंगोंग झील का एक तिहाई हिस्सा भारत में और दूसरा दो तिहाई चीन में है। • **गलवान घाटी:** यह घाटी उस भूमि को संदर्भित करती है जो गलवान नदी को बहने वाले खड़े पहाड़ों के बीच स्थित है। इस नदी का स्रोत अक्साई चिन में है। • **चांग चेनमो नदी:** यह श्योक नदी की एक सहायक नदी है।
सफेद फास्फोरस के गोले / युद्ध सामग्री	**संदर्भ:** हाल ही में रूसी सेना पर लुगांस्क के पूर्वी क्षेत्र में फास्फोरस बम हमले शुरू करने का आरोप लगाया गया था। • अंतर्राष्ट्रीय कानून भारी आबादी वाले नागरिक क्षेत्रों में सफेद फास्फोरस के गोले के उपयोग पर रोक लगाता है, लेकिन उन्हें खुले स्थानों में सैनिकों के लिए कवर के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। **सफेद फास्फोरस युद्ध सामग्री** • सफेद फास्फोरस एक मोम जैसा रासायनिक पदार्थ होता है, जो पीला या रंगहीन होता है। • ये लहसुन की तरह महकता है। • ये पाउडर ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर आग पकड़ता है। • ये ब्लास्ट होने पर एक खास तरह का पाउडर बन जाता है और वातावरण में फैल जाता है। • जलते हुए फॉस्फोरस का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका इस्तेमाल रिहायशी इलाकों में प्रतिबंधित है। • हथियारों में इसका प्राथमिक कार्य जलना, तेज और चमकीला होना है। इसका उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया भर के उग्रवादियों द्वारा युद्धों में किया जाता रहा है। **फास्फोरस के उपयोग का ऐतिहासिक रिकॉर्ड** • फॉस्फोरस गोला-बारूद का इस्तेमाल पूरे इतिहास में और आधुनिक युद्धों जैसे इराक युद्ध, अरब-इजरायल संघर्ष में भी किया गया है। • दो घटनाएँ नीचे सूचीबद्ध हैं: ○ माना जाता है कि सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल पहली बार 19वीं शताब्दी में फेनियन (आयरिश राष्ट्रवादी) आगजनी करने वालों द्वारा किया गया था। ○ ब्रिटिश सेना ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1916 के अंत में कारखाने में निर्मित पहला सफेद फास्फोरस ग्रेनेड प्रस्तुत किया।
भारत ने श्रीलंका को एक अरब डॉलर का ऋण दिया	**संदर्भ:** हाल ही में भारत सरकार ने पड़ोसी मुल्क की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया और इसके तहत पिछले दिनों श्रीलंका को भोजन, दवा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए एक अरब डॉलर का कर्ज देने पर सहमति बनी। • इस आशय के एक समझौते पर भारतीय स्टेट बैंक और श्रीलंका सरकार के बीच हस्ताक्षर किए गए। **महत्वपूर्ण तथ्य** • वर्ष 2022 में, भारत ने अब तक $400 मिलियन आरबीआई मुद्रा विनिमय के माध्यम से श्रीलंका को 1.4 बिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है, 0.5 बिलियन डॉलर के ऋण को स्थगित कर दिया है और देश के लिए आवश्यक ईंधन आयात को बनाए रखने के लिए ऋण की एक पंक्ति के रूप में आधा बिलियन डॉलर का योगदान दिया है। **श्रीलंका में क्या है स्थिति** • श्रीलंका अपने सबसे खराब वित्तीय संकट का सामना कर रहा है, और अगस्त 2021 में विदेशी मुद्रा संकट के कारण

	आपातकाल की घोषणा की थी। • राष्ट्र अभी भी महत्वपूर्ण ईंधन और गैस की कमी, और आवश्यक वस्तुओं में उच्च मुद्रास्फीति का सामना कर रहा है। • वहाँ कि स्थिति ने श्रीलंका में राजनीतिक विपक्ष और नागरिक समूहों द्वारा विरोध शुरू कर दिया है। • इस संकट का मूल कारण 10 अरब डॉलर के बड़े व्यापार घाटे के कारण विदेशी मुद्रा की कमी थी। • भोजन, दवाओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए डॉलर की लगातार कमी के बीच श्रीलंका को इस वर्ष लगभग 7 बिलियन डॉलर का विदेशी ऋण चुकाना है। ○ इसने अपने कुल विदेशी ऋण के 10% के बराबर अपने ऋणों के पुनर्गठन के लिए पहले ही चीन से मदद मांगी है। **क्रेडिट सुविधा क्या है?** • क्रेडिट सुविधा एक प्रकार का ऋण है। • यह उधार लेने वाले पक्ष को हर बार धन की आवश्यकता होने पर ऋण के लिए पुन: आवेदन करने के बजाय विस्तारित अवधि में धन निकालने की अनुमति देता है। **लाइन ऑफ क्रेडिट (LOC) क्या है?** • लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी) एक पूर्व निर्धारित उधार सीमा है जिसे किसी भी समय टैप किया जा सकता है। • उधारकर्ता अपनी आवश्यकतानुसार धन निकाल सकता है जब तक कि अधिकतम सीमा तक न पहुंच जाए और जब धन का पुनर्भुगतान हो जाए तो किसी ओपन एलओसी के मामले में इसे फिर से उधार लिया जा सकता है। • एलओसी किसी वित्तीय संस्थान-आम तौर पर एक बैंक और एक ग्राहक के बीच एक प्रकार की व्यवस्था है जो उस अधिकतम ऋण राशि को स्थापित करता है जो ग्राहक उधार ले सकता है। • उधारकर्ता किसी भी समय एलओसी से फंड की सुविधा प्राप्त कर सकता है जबतक कि वे समझौते में निर्धारित अधिकतम राशि (या क्रेडिट सीमा) से अधिक न हो जाए। ○ एलओसी एक पूर्व निर्धारित उधारी सीमा है जिसका लाभ उधारकर्ता कभी भी उठा सकता है। ○ क्रेडिट लाइन के प्रकारों में पर्सनल, बिजनेस, होम इक्विटी आदि शामिल हैं। ○ एलओसी में अंतर्निहित लचीलापन होता है जो इसका मुख्य लाभ है। ○ संभावित नुकसानों में उच्च ब्याज दर, लेट पेमेंट के लिए सख्त आर्थिक दंड और अधिक व्यय की आशंका शामिल है।
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन	**संदर्भ:** आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने अनुमान लगाया है कि यूक्रेन संकट इस साल वैश्विक विकास दर में एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज कर सकता है और मुद्रास्फीति में ढाई प्रतिशत अंक जोड़ सकता है। • यह प्रत्युत्तर में लक्षित सरकारी खर्च बढ़ाने का आह्वान किया है। • जीडीपी के 0.5% के क्रम में ओईसीडी देशों द्वारा सरकारी खर्च में अच्छी तरह से लक्षित वृद्धि, मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय वृद्धि किए बिना युद्ध के आर्थिक प्रभाव को लगभग आधा कर सकती है। **आर्थिक सहयोग और विकास संगठन** • ओईसीडी एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है, जिसकी स्थापना आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। • अधिकांश ओईसीडी सदस्य उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनका मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) बहुत अधिक है और उन्हें विकसित देश माना जाता है। • स्थापित: 1961 • मुख्यालय: पेरिस (फ्रांस) • कुल सदस्य: 38 देश • भारत एक सदस्य नहीं है, बल्कि एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है। • ओईसीडी द्वारा रिपोर्ट और सूचकांक ○ सरकार की एक नज़र 2017 की रिपोर्ट पर

	○ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक ○ ओईसीडी बेहतर जीवन सूचकांक
भारत की आर्कटिक नीति का विमोचन	**संदर्भ:** भारत की आर्कटिक नीति जिसका शीर्षक 'इंडिया एंड द आर्कटिक: बिल्डिंग ए पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' है, में छह स्तंभ हैं: 1. भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग को मजबूत करना 2. जलवायु और पर्यावरण संरक्षण 3. आर्थिक और मानव विकास 4. परिवहन और कनेक्टिविटी 5. शासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग 6. आर्कटिक क्षेत्र में राष्ट्रीय क्षमता निर्माण भारत की आर्कटिक नीति को लागू करने में अकादमिक, अनुसंधान समुदाय, व्यवसाय और उद्योग सहित कई हितधारक शामिल होंगे। ● आर्कटिक में भारत की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। यह आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा रखने वाले 13 देशों में से एक है, जो एक उच्च स्तरीय अंतरसरकारी मंच है जो आर्कटिक सरकार और आर्कटिक के स्वदेशी लोगों के सामने आने वाले मुद्दों को संबोधित करता है। ● आर्कटिक क्षेत्र के साथ भारत का जुड़ाव सुसंगत और बहुआयामी रहा है। देश का कहना है कि सभी मानवीय गतिविधि टिकाऊ, जिम्मेदार, पारदर्शी और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर आधारित होनी चाहिए। भारत की आर्कटिक नीति का उद्देश्य निम्नलिखित एजेंडे को बढ़ावा देना है- 1. आर्कटिक क्षेत्र के साथ विज्ञान और अन्वेषण, जलवायु और पर्यावरण संरक्षण, समुद्री और आर्थिक सहयोग में राष्ट्रीय क्षमताओं और दक्षताओं को मजबूत करना। सरकार और शैक्षणिक, अनुसंधान और व्यावसायिक संस्थानों के भीतर संस्थागत और मानव संसाधन क्षमताओं को मजबूत किया जाएगा। 2. आर्कटिक में भारत के हितों की खोज में अंतर-मंत्रालयी समन्वय। 3. भारत की जलवायु, आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा पर आर्कटिक में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की समझ को बढ़ाना। 4. वैश्विक नौवहन मार्गों, ऊर्जा सुरक्षा और खनिज संपदा के दोहन से संबंधित भारत के आर्थिक, सैन्य और सामरिक हितों पर आर्कटिक में बर्फ पिघलने के प्रभावों पर बेहतर विश्लेषण, भविष्यवाणी और समन्वित नीति निर्माण में योगदान देना। 5. ध्रुवीय क्षेत्रों और हिमालय के बीच संबंधों का अध्ययन करना। 6. वैज्ञानिक और पारंपरिक ज्ञान से विशेषज्ञता हासिल करते हुए विभिन्न आर्कटिक मंचों के तहत भारत और आर्कटिक क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग को गहरा करना। 7. आर्कटिक परिषद में भारत की भागीदारी बढ़ाना और आर्कटिक में जटिल शासन संरचनाओं, प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय कानूनों और क्षेत्र की भू-राजनीति की समझ में सुधार करना। **नोडल संस्थान:** गोवा में राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है।
क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी)	**संदर्भ:** जापान ने अभी भी यह उम्मीद नहीं छोड़ी है कि भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) में शामिल होने पर पुनर्विचार कर सकता है, जिससे उसने 2019 में बाहर होने का विकल्प चुना था। **कुछ महत्वपूर्ण तथ्य** ● क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस (ASEAN) के 10 सदस्य हैं। ○ आसियान के सदस्य ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। ● 15 सदस्य देशों में विश्व की आबादी का लगभग 30% (2.2 बिलियन लोग) और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 30% (29.7 ट्रिलियन डॉलर) है। ● यह इतिहास का सबसे बड़ा व्यापार ब्लॉक है।

	• नवंबर 2020 में हस्ताक्षरित, RCEP एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में पहला FTA है। • यह जनवरी 2022 में लागू हुआ।
फिनलैंडीकरण (Finlandizatio)	**प्रसंग:** रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद, यह स्पष्ट नहीं है कि युद्ध कब और कैसे समाप्त हो सकता है। **Background** • रूस ने आक्रमण के बहाने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की धमकी का आह्वान किया। • राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने अब स्वीकार किया है कि उनका देश निकट भविष्य में अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं होगा। **फ़िनलैंडाइज़ेशन मॉडल** • जिन परिदृश्यों को संभावित रूप से व्यावहारिक रूप में देखा गया है उनमें यूक्रेन का "फिनलैंडीकरण" है। • यह पहले 2014 में प्रस्तावित किया गया था, जिस वर्ष रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और यूक्रेन के पूर्वी डोनबास क्षेत्र में लड़ाई छिड़ गई थी। • 'फिनलैंडाइजेशन' मास्को और पश्चिम के बीच सख्त तटस्थता की नीति को संदर्भित करता है जिसका फिनलैंड ने शीत युद्ध के दशकों के दौरान पालन किया था। ○ तटस्थता का सिद्धांत मित्रता, सहयोग और पारस्परिक सहायता के समझौते में निहित था जिसे फिनलैंड ने अप्रैल 1948 में यूएसएसआर के साथ हस्ताक्षरित किया था। ○ फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी सेंट पीटर्सबर्ग (लेनिनग्राद) से फिनलैंड की खाड़ी के पार स्थित है। ○ संधि ने इसे बाल्टिक और पूर्वी यूरोपीय राज्यों की तरह यूएसएसआर में हमला या शामिल होने से बचाया। ○ इसने देश को महान शक्तियों के बीच संघर्ष से बाहर रहते हुए लोकतंत्र और पूंजीवाद के मार्ग पर चलने की अनुमति दी। ○ इसने उन मामलों पर तटस्थ रुख अपनाया जिन पर सोवियत संघ और पश्चिम असहमत थे। ○ यह नाटो और यूरोपीय सैन्य शक्तियों से अलग रहा, और इस स्थिति का उपयोग मास्को से सोवियत ब्लॉक या वारसॉ संधि का हिस्सा बनने के दबाव को दूर करने के लिए किया। **यूक्रेन और फिनलैंडकरण** • यदि यूक्रेन इस मॉडल से गुजरता है, तो निम्नलिखित परिणाम प्रासंगिक हो सकते हैं: ○ यूक्रेन को यूरोप सहित अपने आर्थिक और राजनीतिक संघों को स्वतंत्र रूप से चुनने का अधिकार होना चाहिए। ○ यूक्रेन को आगे के आक्रमण और हमलों से बचने के लिए नाटो में शामिल नहीं होना चाहिए। ○ यूक्रेन को अपने लोगों की व्यक्त इच्छा के अनुरूप कोई भी सरकार बनाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। • समझदार यूक्रेनी नेता तब अपने देश के विभिन्न हिस्सों के बीच सुलह की नीति का विकल्प चुन सकते हैं। • अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उन्हें फिनलैंड की तुलना में एक मुद्रा का पालन करना चाहिए। ○ फ़िनलैंड अपनी भयंकर स्वतंत्रता के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ता है और अधिकांश क्षेत्रों में पश्चिम के साथ सहयोग करता है लेकिन रूस के प्रति संस्थागत शत्रुता से सावधानी से बचता है।
बिम्सटेक	**संदर्भ:** श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे 28 से 30 मार्च, 2022 तक "हाइब्रिड मोड" में आयोजित होने वाले बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं की मेजबानी करेंगे। • म्यांमार के विदेश मंत्री भी समूह को वस्तुतः संबोधित करेंगे। • इस सप्ताह के शिखर सम्मेलन के मुख्य उद्देश्यों में से एक 'बिम्सटेक चार्टर' को लॉन्च करना और फोरम का नेतृत्व थाईलैंड को सौंपना होगा, जो अगले अध्यक्ष होगा। **बिम्सटेक के बारे में** • बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल/बिम्सटेक (The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation- BIMSTEC) एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है।

- इसके सदस्य बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं, जो एक निकटवर्ती क्षेत्रीय एकता का गठन करते हैं।
- 7 सदस्यों में से पांच दक्षिण एशिया से हैं -
  - o बांग्लादेश
  - o भूटान
  - o भारत
  - o नेपाल
  - o श्रीलंका
- दो दक्षिण पूर्व एशिया से हैं -
  - o म्यांमार
  - o थाईलैंड
- इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है; सामाजिक प्रगति में तेजी लाना; और इस क्षेत्र में साझा हित के मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देना।

भारत, संयुक्त अरब अमीरात व्यापार समझौता

संदर्भ: भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच मुक्त व्यापार समझौता इस साल 1 मई से लागू होने की संभावना है, जिसके तहत कपड़ा, कृषि, सूखे मेवे, रत्न जैसे क्षेत्रों से कम से कम 6,090 वस्तुओं के घरेलू निर्यातक हैं। और आभूषणों को संयुक्त अरब अमीरात के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी।

कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

- व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने फरवरी में हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 60 अरब डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर करना है।
- दोनों देशों ने हस्ताक्षरित समझौते के हिस्से के रूप में निवेश, व्यापार संवर्धन और सुविधा पर एक तकनीकी परिषद स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है।
- यूएई अपने 97% से अधिक उत्पादों पर शुल्क उन्मूलन की पेशकश कर रहा है, जो मूल्य के संदर्भ में यहां 99% भारतीय निर्यात करता है।

भारत और यूएई संबंध

- विदित हो कि 1972 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने राजनयिक संबंध स्थापित किए।
- जब अगस्त 2015 में भारत के प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा ने दोनों देशों के बीच एक नई रणनीतिक

	साझेदारी की शुरुआत को चिह्नित किया, तो द्विपक्षीय संबंधों में और अधिक बल प्राप्त हुआ है। • इसके अलावा, जनवरी 2017 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा के दौरान, यह सहमति हुई थी कि द्विपक्षीय संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया जाना था। • यह भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए वार्ता शुरू करने को गति दी। **संयुक्त अरब अमीरात का आर्थिक महत्व** • यूएई विश्व स्तर पर नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र के रूप में उभरा है। • हालांकि संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाई है, लेकिन सेवाओं और विनिर्माण के बाद हाइड्रोकार्बन क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है।
हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी	**संदर्भ:** हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (Indian Ocean Naval Symposium - IONS) समुद्री अभ्यास 2022 (आईएमईएक्स-22) का पहला संस्करण 26 से 30 मार्च, 2022 तक गोवा और अरब सागर में आयोजित किया गया था। • आईओएनएस के 25 सदस्य देशों में से 15 देशों की नौसेनाओं ने अभ्यास में भाग लिया। • इस अभ्यास को क्षेत्रीय नौसेनाओं के लिए क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के लिए सामूहिक रूप से सहयोग करने और प्रतिक्रिया देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है और क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करता है। **हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (आईओएनएस) के बारे में** • हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (आईओएनएस) समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने, क्षेत्रीय समुद्री मुद्दों पर चर्चा करने और सदस्य देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय राज्यों के बीच द्विवार्षिक बैठकों की एक श्रृंखला है। • फोरम की स्थापना 2007 में हुई थी। • यह प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ एक प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र और मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) विकसित करने का भी कार्य करता है। • IONS में 24 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं जो IOR के भीतर स्पर्श करते हैं या झूठ बोलते हैं, और 8 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। • सदस्यों को भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित चार उप-क्षेत्रों में बांटा गया है: ○ दक्षिण एशियाई समुद्र तट: बांग्लादेश, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, सेशेल्स, श्रीलंका और यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र) ○ पश्चिम एशियाई समुद्रतट: ईरान, ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ○ पूर्वी अफ्रीकी लिटोरल्स: फ्रांस (रीयूनियन), केन्या, मॉरीशस, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया। ○ दक्षिण पूर्व एशियाई और ऑस्ट्रेलियाई समुद्रतट: ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड और तिमोर-लेस्ते। • भारत के लिए महत्व: आईओएनएस इस क्षेत्र में भारत की तीन गुना। • महत्वाकांक्षाओं में फिट बैठता है: ○ हिंद महासागर के तटवर्ती राज्यों के साथ संबंधों को मजबूत और गहरा करना ○ नेट-सुरक्षा प्रदाता होने की अपनी नेतृत्व क्षमता और आकांक्षाओं को स्थापित करना, और ○ IOR में नियम-आधारित और स्थिर समुद्री व्यवस्था के भारत के दृष्टिकोण को पूरा करना

विविध

बोल्ट्जमैन मेडल (Boltzmann Medal)	**संदर्भ:** भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर)- पुणे के भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर दीपक धर को प्रतिष्ठित बोल्ट्जमैन पदक-2022 के लिये चुना गया है। • वह यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। • वे यह पुरस्कार अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड (John Hopfield) के साथ संयुक्त रूप से प्राप्त करेंगे, जो एक सहयोगी तंत्रिका नेटवर्क के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं, जिसे अब उनके नाम पर रखा गया है। • यह पुरस्कार अगस्त 2022 में जापान के टोक्यो शहर में होने वाले इंटरनेशनल कांफ्रेंस में दिया जाएगा। • प्रो. धर को सांख्यिकीय भौतिकी के क्षेत्र में उनके मौलिक योगदान के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। **बोल्ट्जमैन मेडल के** • स्टैटफिस सम्मेलन में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड फिज़िक्स के सांख्यिकीय भौतिकी (Statistical Physics) पर आयोग द्वारा हर तीन वर्ष में यह पदक प्रदान किया जाता है। • इसकी शुरुआत 1975 में नोबेल पुरस्कार विजेता (1982) के.जी. विल्सन पहले प्राप्तकर्ता थे। • यह पदक सांख्यिकीय भौतिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों का सम्मान करता है। • लुडविग बोल्ट्जमैन के नाम पर भौतिकी के सुप्रसिद्ध विज्ञानियों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह पदक दिया जाता है। • यह पिछले 47 वर्षों में एक या दो व्यक्तियों को तीन साल में एक बार दिया गया है। • यह किसी व्यक्ति को केवल एक बार और इस शर्त पर दिया जाता है कि उस व्यक्ति ने अब तक नोबेल पुरस्कार न जीता हो।
शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (UDISE+) 2020-21 पर रिपोर्ट	• शिक्षा मंत्रालय ने भारत की स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (UDISE+) 2020-21 पर रिपोर्ट जारी की है। • विद्यालयों से ऑनलाइन डेटा संग्रह की यूडाइस+ प्रणाली को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2018-19 में विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य दस्तावेज के प्रारूप में मैनुअल डेटा भरने के पहले के अभ्यास और इसके बाद 2012-13 से संचालित यूडाइस डेटा संग्रह प्रणाली में प्रखंड या जिला स्तर पर कंप्यूटर पर फीडिंग से संबंधित मुद्दों को दूर करना है। • यूडाइस+ प्रणाली में विशेष रूप से डेटा संग्रह, डेटा मानचित्रण और डेटा सत्यापन से संबंधित क्षेत्रों में सुधार किए गए हैं। यूडाइस+ डेटा से संबंधित मौजूदा रिपोर्ट साल 2020-21 के लिए संदर्भित है।
व्यायाम धर्म संरक्षक-2022:	• भारतीय सेना और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच एक वार्षिक अभ्यास है। • जो फरवरी, 2022 को विदेशी प्रशिक्षण नोड, बेलगाम में शुरू हुआ और बारह दिनों के गहन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण के बाद मार्च, 2022 को सफलतापूर्वक समाप्त हुआ।
भारत का मातृ मृत्यु अनुपात (MMR)	• इसमें 10 अंकों की गिरावट हुई। • भारत वर्ष 2030 तक 70/लाख जीवित जन्मों के मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) के एसडीजी लक्ष्य को प्राप्त करने के कगार पर। • केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश द्वारा सूचित एमएमआर में 15% से अधिक की उल्लेखनीय गिरावट आई। • जिन राज्यों ने सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) लक्ष्य हासिल किया है, उन्हें 5 से बढ़ाकर 7 किया गया है।
राष्ट्रीय ई-विधान आवेदन (नेवा): 'एक राष्ट्र - एक आवेदन'	• यह परियोजना वास्तव में पेपरलेस असेंबली या ई-असेंबली की एक अवधारणा है, जिसमें असेंबली के काम को सुविधाजनक बनाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग किया जाएगा। • देश के सभी विधायिकाओं को एक मंच पर लाना, जिससे कई आवेदनों की जटिलता के बिना बड़ा (massive) डेटा डिपॉजिटरी तैयार किया जा सके। • यह लोगों को अच्छी तरह से सूचित और प्रबुद्ध नागरिक बनाकर देश भर में शासन में दूरगामी परिवर्तन लाने के

	लिए है और इस तरह देश में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करता है।
एबेल पुरस्कार 2022: अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन हुए सम्मानित	• उनकी प्रमुख सफलताओं में से एक तर्कसंगत समरूप सिद्धांत को समझने का एक नया तरीका विकसित करना है, जो बीजीय टोपोलॉजी का एक उपक्षेत्र है। • टोपोलॉजी गणित का एक क्षेत्र है, जो उन्नीसवीं शताब्दी में अस्तित्व में आया था और इसका संबंध सतहों के गुणों से है जो विकृत होने पर नहीं बदलते हैं। टोपोलॉजी गणित का बड़ा क्षेत्र है। इसे ज्यामिति के विस्तार के रूप में देखा जाता है। इसमें उन गुणों का अध्ययन किया जाता है जो वस्तुओं को सतत रूप से विकृत करने पर उनमें बने रहे हैं। • टोपोलॉजिकल रूप से, एक वृत्त और एक वर्ग समान होते हैं; इसी तरह, एक डोनट और एक हैंडल के साथ एक कॉफी मग की सतहें टोपोलॉजिकल रूप से समकक्ष होती हैं, हालांकि, एक गोले की सतह और एक कॉफी मग समान नहीं होते हैं।
युद्धाभ्यास डस्टलिक	भारत-उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास "युद्धाभ्यास डस्टलिक" का तीसरा संस्करण मार्च 2022 महीने में उज्बेकिस्तान के यांगियारिक में संपन्न हुआ।

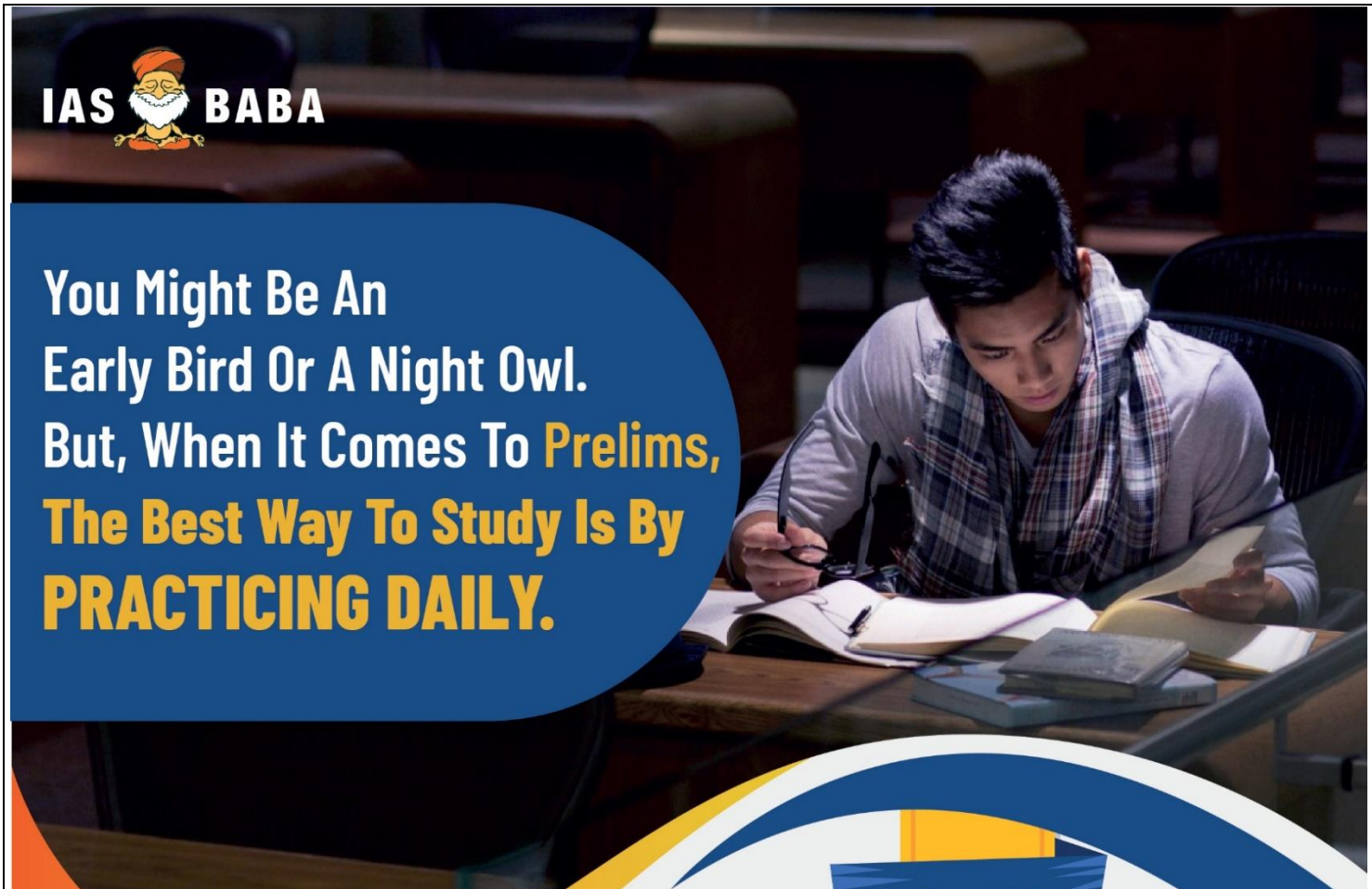

IAS BABA

You Might Be An
Early Bird Or A Night Owl.
But, When It Comes To Prelims,
The Best Way To Study Is By
PRACTICING DAILY.

"No Cost EMI"
Available now!

100+ Hours Of Prelims Focused Classes

100+ Meticulously Prepared Practice Tests

1:1 Mentorship

Prelims Strategy Classes

Prelims Specific & Exclusive Handouts

PRELIMS EXCLUSIVE PROGRAM (PEP) -2022

Crack UPSC Prelims 2022 in a Go!

REGISTER HERE

www.iasbaba.com

pep@iasbaba.com

91691 91888

राजव्यवस्था और शासन

मणिपुर में कुकी विद्रोह (Kuki Insurgency in Manipur)

संदर्भ: 28 फरवरी को मणिपुर में विधानसभा चुनाव के पहले दो चरणों के शुरू होने से ठीक पहले, मणिपुर में कुकी जनजातियों से जुड़े सभी विद्रोही समूहों ने कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को वोट देंगे।

- हाल ही में कुकी के गढ़ चुरचांदपुर में एक रैली में, अमित शाह ने आश्वासन दिया था कि अगर भाजपा दूसरी बार सत्ता में आई तो कुकी विद्रोह की समस्या समाप्त हो जाएगी।
- कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (केएनओ) के अध्यक्ष पीएस हाओकिप ने भाजपा नेतृत्व के साथ बातचीत का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कुकी राजनीतिक आकांक्षाओं के त्वरित समाधान का वादा किया है।

कुकी कौन हैं?

- कुकी एक जातीय समूह है जिसमें मूल रूप से मणिपुर, मिजोरम और असम जैसे भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में रहने वाली कई जनजातियां शामिल हैं; और ये बर्मा (अब म्यांमार), और सिलहट जिले और बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी इलाकों के हिस्से में भी रहते है।
- जबकि कुकी स्वयं जातीय समूह द्वारा बनाया गया शब्द नहीं है, इससे जुड़ी जनजातियों को औपनिवेशिक शासन के तहत सामान्य रूप से कुकी कहा जाने लगा।
- मणिपुर में, मुख्य रूप से पहाड़ियों में रहने वाली विभिन्न कुकी जनजातियां, वर्तमान में राज्य की कुल 28.5 लाख आबादी का 30% हिस्सा हैं।
- मणिपुर की बाकी आबादी मुख्य रूप से दो अन्य जातीय समूहों से बनी है - मैतेई या गैर-आदिवासी, वैष्णव हिंदू जो मणिपुर के घाटी क्षेत्र में और नागा जनजाति राज्य के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं।
- मणिपुर के भौगोलिक क्षेत्र का नौ-दसवां हिस्सा पहाड़ियों का है, और बहुत कम आबादी वाले हैं, इस राज्य की अधिकांश आबादी घाटी में निवास करती है।
    - इंफाल घाटी में मेइतेई समुदाय बहुसंख्यक है, जबकि आसपास के पहाड़ी जिलों में नागा और कुकी रहते हैं।
    - मणिपुर विधानसभा की 60 सीटों में से 40 सीटों पर मैतेइस का कब्जा है और बाकी 20 सीटों पर कुकी और नागाओं का कब्जा है।

मणिपुर में कुकी विद्रोह का कारण क्या था?

- मणिपुर, जो पहले बर्मा के कुछ हिस्सों सहित एक रियासत थी, ने स्वतंत्रता के बाद भारत में (केवल 1972 में एक पूर्ण राज्य बना) आ गया।
- भारत में "जबरदस्ती" शामिल किए जाने पर नाराजगी और राज्य का दर्जा देने में देरी के कारण विभिन्न विद्रोही आंदोलनों का उदय हुआ।
- मणिपुर में स्वतंत्रता के बाद के विद्रोही आंदोलनों, जो घाटी-आधारित समूहों या मैतेईस द्वारा किए गए थे, का पता 1960 के दशक के आसपास लगाया जा सकता है, जब विभिन्न समूहों ने वामपंथी विचारधारा से प्रेरित मणिपुर के लिए आत्मनिर्णय और अलग राज्य की मांग की थी।
- कुकी उग्रवाद की जड़ें जातीय पहचान के संघर्ष में निहित हैं।
- सबसे पहले केवल अपने जातीय ताने-बाने से संबंधित समूहों के लिए आत्मनिर्णय की मांग थी, जिसका अर्थ है एक कुकीलैंड बनाने का सपना जिसमें म्यांमार, मणिपुर, असम और मिजोरम के कुकी बसे हुए क्षेत्र शामिल हैं।
- उग्रवाद का दूसरा कारण मणिपुर में कुकी और नागाओं के बीच अंतर-सामुदायिक संघर्ष है।
    - कुकी-नागा संघर्ष पहचान और भूमि हासिल करने के लिए शुरू किया गया था क्योंकि कुछ कुकी बसे हुए क्षेत्र नागा के बसे हुए क्षेत्रों से मेल खाते थे।
    - उन क्षेत्रों में व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों पर हावी होने की धारणा लिए हुए दोनों समुदाय अकसर हिंसक गतिरोध में लगे रहते हैं।
    - नागा समूहों की "नागालिम" (ग्रेटर नागालैंड) की मांग को मणिपुर की "क्षेत्रीय अखंडता" के लिए "खतरे" के रूप में माना जाता है।

	• 1980 में मणिपुर को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किए जाने के बाद, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत कुकी समस्या तेज हो गई थी, जो सेना को व्यापक अधिकार देता है और और ज्यादतियों का कारण बना है। • जबकि कुछ कुकी उग्रवादी संगठनों ने कुकीलैंड की मांग की, जिसमें कुछ हिस्से भारत में नहीं हैं, और कुछ भारत भाग के अंदर है। • वर्तमान में, भारतीय संविधान के अंतर्गत एक स्वतंत्र जिला-कुकिलैंड प्रादेशिक परिषद के गठन की मांग आई है, जो बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद की मॉडलिंग करती है, जिसका गठन संविधान की छठी अनुसूची के तहत किया गया था। **आज कुकी कहाँ खड़ी हैं?** • कुकी विद्रोही समूह वर्ष 2005 से ऑपरेशन के निलंबन (एसओओ) के अधीन हैं, जब उन्होंने भारतीय सेना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। • वर्ष 2008 में, समूहों ने मणिपुर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया, ताकि अस्थायी रूप से अपने कार्यों को निलंबित कर दिया जाए और राजनीतिक संवाद को एक मौका दिया जा सके। • कुकीज को किसी प्रकार का आत्मनिर्णय देने के बारे में राजनीतिक संवाद शुरू करने के लिए अस्थायी एसओओ समझौते किए गए थे, लेकिन यूपीए या एनडीए दोनों सरकारों के तहत ऐसा नहीं हुआ है। • सरकार द्वारा वर्ष 2008 से लगभग हर साल एसओओ का विस्तार किया गया है, कुकी संगठनों ने फिर से हथियार उठाकर और सरकार का बहिष्कार करके समझौते का उल्लंघन करने की धमकी दी है। ○ वर्ष 2012 में, समूहों ने अपने क्षेत्र के चारों ओर राजमार्गों की लगभग आठ महीने लंबी नाकेबंदी की, जिससे सरकार को प्रतिदिन दो करोड़ का नुकसान हुआ।
समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की जरुरत	**संदर्भ:** अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day - IWD) हर साल 8 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। 2022 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय "एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता" है। भारत की महिला अनौपचारिक कार्यबल के लिए लैंगिक समानता अभी भी दूर की कौड़ी है। • अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के वर्ष 2018 के एक अध्ययन के अनुसार, भारत की 95% से अधिक कामकाजी महिलाएँ अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, जो बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के और कम भुगतान में अत्यधिक श्रमप्रधान कार्य करती हैं। साथ ही, अनौपचारिक क्षेत्र की नौकरियों में अनिश्चितता भी अधिक होती है। • डब्ल्यूएचओ का कहना है कि "महिलाओं का अनौपचारिक कार्य गरीबी के नारीकरण के लिए केंद्रीय है"। • मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के तहत लाभ ज्यादातर औपचारिक क्षेत्र की महिला श्रमिकों द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो महिला कर्मचारियों की संख्या का 5% से कम है। ○ मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अनुसार गर्भवती महिला 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की पात्र होती है। ○ यह 50 या अधिक महिलाओं को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों के लिए क्रेच सुविधाओं को अनिवार्य कर दिया। • गुणवत्तापूर्ण चाइल्डकेयर सेवाओं तक पहुँच की कमी के कारण भी महिला श्रमिकों को रोज़गार छोड़ने पर मज़बूर होना पड़ता है, जिससे उनकी आय प्रभावित होती है और उन्हें आर्थिक जोखिम का सामना करना पड़ता है। इससे लिंग एवं वर्ग असमानता में वृद्धि हो सकती है। • महिलाओं को अधिक उत्पादक भुगतान कार्य करने और अपने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने में सक्षम बनाने के लिए यहां तीन उपाय दिए गए हैं: **1. एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) के बुनियादी ढाँचे का विस्तार** • आई.सी.डी.एस. के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों का प्राथमिक कार्य मातृ एवं शिशु पोषण सुरक्षा, स्वच्छ व सुरक्षित वातावरण एवं प्रारंभिक स्तर की शिक्षा प्रदान करना है। इस प्रकार महिलाओं को प्रसव के बाद कार्य पर फिर लौटने को सुगम बनाना है। • हालांकि, आईसीडीएस की दो प्रमुख सीमाएं हैं।

	• सबसे पहले, इसमें तीन वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल नहीं हैं। • दूसरा, यह दिन में केवल कुछ घंटों के लिये कार्य करता है, जिससे कार्य के दौरान बच्चों को भेजने और लाने में असुविधा होती है। • आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को कम आयु में शामिल करने से दोहरा लाभ हो सकता है। इससे माताओं को वैतनिक कार्य के लिये समय मिल सकेगा और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप भी होगा। शिक्षा नीति में 0-6 आयु वर्ग के बच्चों के लिये गुणवत्ता प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा की परिकल्पना की गई है। • आंगनवाड़ी केंद्रों के समय का विस्तार करने से कामकाजी महिलाओं के लिये समय की कमी को भी दूर किया जा सकता है, जिसके लिये बुनियादी ढाँचे के विस्तार की भी आवश्यकता है। **2. क्रेच योजना को पुनर्जीवित करना** • राष्ट्रीय क्रेच योजना जो कि एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे पूर्व में राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना के नाम से जाना जाता था। • राष्ट्रीय क्रेच योजना में कामकाजी महिलाओं के लिये विशिष्ट प्रावधान है, परन्तु इसे सरकारी वित्त में कमी का सामना करना पड़ रहा है। • सार्वजनिक क्रेच को विभिन्न कार्यस्थल समूहों, जैसे- औद्योगिक क्षेत्रों, बाजारों, सघन एवं कम आय वाले आवासीय क्षेत्रों और श्रमिक केंद्रों में संचालित किया जा सकता है। • निर्माण क्षेत्र के मामले में 'बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड' क्रेच संचालन का आदेश देता है। • निर्माण उपकर से एकत्र की गई धनराशि का प्रयोग निर्माण स्थलों पर क्रेच संचालन के लिये किया जा सकता है। **3. मातृत्व लाभ में सुधार** • अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 तक मातृत्व लाभ नहीं मिलता था, जिसके तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को कम से कम ₹6,000 के नकद हस्तांतरण का अधिकार था। • हालाँकि, इस उद्देश्य के लिये प्रारंभ की गई 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' (PMMVY) के तहत यह लाभ पहले जन्म तक सीमित करते हुए प्रदान की जाने वाली राशि को घटाकर 5,000 रूपए कर दिया गया है। • PMMVY के तहत यह राशि मुद्रास्फीति-समायोजित NFSA बेंचमार्क (2022 में लगभग ₹9,400) से मेल नहीं खाती। • विभिन्न राज्यों ने अपनी स्वयं की योजना के साथ कवरेज अंतर को पाटने की कोशिश की है। तमिलनाडु में एक विशाल और महत्वाकांक्षी योजना है जो दो जीवित जन्मों के लिए 18,000 रुपये नकद और वस्तु प्रदान करती है। **निष्कर्ष** • यह अत्यावश्यक है कि हम सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चाइल्डकैअर अवसंरचना को रोजगार से जुड़े लाभ के रूप में और एक सार्वजनिक भलाई के रूप में मानें।
मैनुअल स्कैवेंजिंग (Manual Scavenging)	**मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है?** • मैनुअल स्कैवेंजिंग सीवर या सेप्टिक टैंक से मानव मल को हाथ से हटाने की प्रथा है। • भारत ने 'मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' के तहत इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। • यह अधिनियम किसी भी व्यक्ति के मानव मल को उसके निपटान तक हाथ से साफ करने, ले जाने, निपटाने या अन्यथा किसी भी तरीके से संभालने पर प्रतिबंध लगाता है। • वर्ष 2013 में, सेप्टिक टैंक, गड्ढों या रेलवे ट्रैक को साफ करने के लिए नियोजित लोगों को शामिल करने के लिए मैनुअल स्कैवेंजिंग की परिभाषा को भी विस्तृत किया गया था। • यह अधिनियम मैनुअल स्कैवेंजिंग को 'अमानवीय प्रथा' के रूप में मान्यता देता है और मैनुअल स्कैवेंजर्स द्वारा झेले गए ऐतिहासिक अन्याय और अपमान की क्षतिपूर्ति की आवश्यकता पर बल देता है। **मैनुअल स्कैवेंजिंग**

	• मैला ढोने वालों को जहरीली गैसों के कारण श्वासावरोध से मृत्यु का खतरा होता है और अक्सर हैजा, हेपेटाइटिस, मेनिन्जाइटिस, पीलिया, त्वचा विकार और यहां तक कि हृदय रोगों जैसी बीमारियों के संपर्क में आ जाते हैं। • उनके पास अक्सर उचित सुरक्षा गियर और उपकरण तक पहुंच की कमी होती है। • सावधानियों की कमी, जैसे बड़ी मात्रा में मीथेन गैस के साथ सीवर में लैंप नीचे ले जाना, दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। • यह प्रथा भारत की जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई है, जहां तथाकथित निम्न जातियों को यह काम करने की उम्मीद है। **भारत में अभी भी मैला ढोने का प्रचलन क्यों है?** • अधिनियम के प्रवर्तन की कमी एक कारण है कि यह प्रथा अभी भी भारत में प्रचलित है। जबकि केंद्र सरकार कानून बनाती है, स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधि भी अक्सर न केवल निजी घरों द्वारा हाथ से मैला ढोने पर प्रतिबंध लागू करने में विफल होते हैं, बल्कि इस प्रथा को भी कायम रखते हैं। • विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा 2019 के एक अध्ययन में कहा गया है कि "कमजोर कानूनी सुरक्षा और कानूनों के प्रवर्तन की कमी", साथ ही साथ सफाई कर्मचारियों की खराब वित्तीय स्थिति, अभी भी प्रचलित प्रथा में योगदान करती है। ○ मुंबई नगर निकाय सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए 20,000 रुपये से 30,000 रुपये के बीच कहीं भी शुल्क लेता है। इस बीच, अकुशल मजदूरों को काम पर रखना काफी सस्ता है और ठेकेदार उन्हें 300-500 रुपये के दैनिक वेतन पर अवैध रूप से रोजगार देते हैं। • ह्यूमन राइट्स वॉच की 2014 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, बहुत से जो मैला ढोने वालों के रूप में काम करने से इनकार करते हैं, उन्हें उच्च जातियों के दबाव और धमकियों का सामना करना पड़ता है। • लोग इस भूमिका से इंकार करने के अपने अधिकार से अनजान रहते हैं, और जो लोग मना करते हैं उन्हें भारी सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें अक्सर स्थानीय सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से उनके गांव से हिंसा और निष्कासन की धमकी भी शामिल है। • दिल्ली सहित कुछ राज्यों ने इस उद्देश्य के लिए सीवेज सफाई मशीनों का उपयोग शुरू किया है। हालांकि, वे पूरे देश में व्यापक रूप से उपयोग नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा, संकरी गलियां बड़ी मशीनों तक पहुंच को रोकती हैं जबकि खराब तरीके से डिजाइन किए गए सेप्टिक टैंक मशीनों के काम करने में मुश्किल पैदा करते हैं। **इस अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए किन उपायों की आवश्यकता है?** • उन सभी व्यक्तियों की पहचान करना होगा जो वर्तमान में हाथ से मैला ढोने का काम करते हैं और जो 1993 के अधिनियम के तहत गैरकानूनी घोषित होने के बाद से इस कार्य में लगे हुए हैं। • यह सुनिश्चित करना होगा कि वर्ष 2013 के अधिनियम के तहत पुनर्वास के अधिकार-जिसमें वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, आवास, वैकल्पिक आजीविका सहायता और अन्य महत्वपूर्ण कानूनी और कार्यक्रम संबंधी सहायता शामिल हैं- यह हाथ से मैला उठाने वाले समुदायों के लिए उपलब्ध हैं। • स्थानीय सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कानून को सख्ती से लागू करें जो स्वयं लोगों को हाथ से मैला उठाने वाले के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करते हैं। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** • एससी/एसटी अत्याचार कानून • राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग
हिजाब प्रतिबंध: कर्नाटक	**संदर्भ:** कर्नाटक उच्च न्यायालय, (रेशम बनाम कर्नाटक राज्य में) कर्नाटक राज्य में स्कूली कक्षाओं में छात्रों द्वारा हिजाब के उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा है। • हिजाब मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। **याचिकाकर्ताओं ने क्या दलील दी?** • याचिकाकर्ता कर्नाटक के उडुपी जिले के एक सरकारी कॉलेज के कक्षा में हिजाब पहनने से प्रतिबंधित मुस्लिम

लड़कियों का एक समूह था - उन्होंने विरोध किया, लेकिन कॉलेज नहीं माना, और मामला अदालत में समाप्त हुआ।

- लड़कियों ने तर्क दिया कि हिजाब पर प्रतिबंध लगाना न केवल भेदभावपूर्ण था, बल्कि अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता के उनके अधिकार को भी प्रभावित करता है।
- याचिकाकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि मुस्लिम लड़कियां कम से कम शिक्षित हैं और कक्षाओं में कम प्रतिनिधित्व करती हैं और अगर उन्हें इस तरह से बंद कर दिया जाता है, तो यह उनकी शिक्षा को प्रभावित करेगा।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले की मुख्य विशेषताएं

- अदालत का मानना है कि हिजाब पहनना इस्लाम के अभ्यास के लिए आवश्यक नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ताओं के धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बाधित नहीं होता है;
- अदालत ने कहा कि एक ड्रेस अपने आप में भेदभावपूर्ण नहीं है और, बाद में, उसने सरकारी आदेश को "किसी भी ड्रेस को निर्धारित नहीं किया है, लेकिन केवल एक संरचित तरीके से नुस्खे का प्रावधान करता है।"
- छात्र शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निर्धारित ड्रेस पर आपत्ति नहीं कर सकते। किसी संस्थान में छात्रों के लिए ड्रेस का प्रिस्क्रिप्शन उचित प्रतिबंधों की श्रेणी में आता है।
- अदालत ने माना कि अनुच्छेद 14 और 15 के तहत अन्य बातों के साथ-साथ कोई भेदभाव नहीं है, जब धर्म, भाषा, जेंडर या इस तरह के मामले सभी छात्रों के लिए ड्रेस कोड समान रूप से लागू होता है।
- संस्थागत अनुशासन व्यक्तिगत पसंद पर हावी है।
    - यह पाया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता का कोई वास्तविक अधिकार नहीं है जिसका दावा एक कक्षा के भीतर किया जा सकता है।
    - यह कहा गया है कि स्कूल 'योग्य स्थान (qualified spaces)' हैं और उनकी प्रकृति से यह उनके सामान्य अनुशासन और शिष्टाचार के नुकसान के लिए व्यक्तिगत अधिकारों के दावे को खारिज कर देता है।
- पीठ ने यह भी स्पष्ट किया था कि यह आदेश उन संस्थानों तक ही सीमित है जहां कॉलेज विकास समितियों (सीडीसी) ने छात्र ड्रेस कोड/वर्दी निर्धारित की है।

उपरोक्त निर्णय की आलोचनाएँ क्या हैं?

- कुछ लोगों का तर्क है कि न्यायालय को केवल अनिवार्यता परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एजेंसी के तर्क पर विचार करना चाहिए था।
    - संवैधानिक विशेषज्ञों और कानूनी विद्वानों ने हमेशा आवश्यक धार्मिक सिद्धांत पर सवाल उठाया है जिसके द्वारा न्यायालय धार्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां वकीलों और न्यायाधीशों के बारे में बहुत कम जानकारी है।
- अदालत ने याचिकाकर्ताओं द्वारा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा समानता के अधिकार पर दिए गए तर्कों को दरकिनार कर दिया - उन्हें "व्युत्पन्न अधिकार" के रूप में खारिज कर दिया।
- अदालत ने स्कूलों में छात्रों की तुलना की, जिसे उसने "योग्य सार्वजनिक स्थान" कहा, जेल में बंदियों के साथ जो अपने व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकते।
- बिंदी या मंगलसूत्र पहनना या कलाई पर पवित्र धागे रखना भी कुछ लोगों द्वारा धार्मिक प्रतीकों के रूप में माना जाता है। इसलिए तर्क दिया जाता है कि अगर सरकार वर्दी लागू करती है, तो यह बोर्ड भर में होनी चाहिए
- अदालत ने 'उचित आवास' के पक्ष में तर्क को खारिज कर दिया, जिसके द्वारा एक बहुलवादी समाज छात्रों के बीच समानता की भावना को कम किए बिना कक्षा को सामाजिक विविधता को प्रतिबिंबित करने की अनुमति दे सकता है।
- साथ ही इस बात का भी डर है कि हिजाब प्रतिबंध अब राष्ट्रीय हो जाएगा।

निष्कर्ष

- धर्म की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वतंत्रता महत्वपूर्ण हैं, इसलिए नहीं कि धर्म महत्वपूर्ण हैं।

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET)	**संदर्भ:** शैक्षणिक सत्र 2022-23 से देश के सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) के माध्यम से होगी। भारत में स्नातक स्तर पर कितने छात्र नामांकित हैं? • नामांकन वर्षों से बढ़ रहा है। वर्ष 2015-16 में स्नातक स्तर पर यह 2.74 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में 3.06 करोड़ हो गया है। • अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2019-20 के अनुसार, भारत में उच्च शिक्षा के सभी स्तरों में नामांकित 3.85 करोड़ छात्रों में से ○ 3.06 करोड़, या 79.5%, स्नातक स्तर पर थे, इसके बाद 43.1 लाख छात्रों या 11.2% के साथ स्नातकोत्तर थे। • 2019-20 में पाठ्यक्रमवार के अनुसार ○ 96.56 लाख छात्र (47.1% पुरुष और 52.9% महिला) बीए में ○ 47.55 लाख छात्र (48.7% पुरुष, 51.3% महिला) बीएससी में ○ 41.6 लाख (51.2 फीसदी पुरुष, 48.8% महिलाएं) बीकॉम में ○ 37.27 लाख (70.8 प्रतिशत पुरुष, 29.2% महिला) इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में ○ o 13.5 लाख (41.5 प्रतिशत पुरुष, 59.5% महिला) चिकित्सा पाठ्यक्रमों में थे। • उच्च शिक्षा संस्थानों में विविधता/इक्विटी (2019-20 एआईएसएचई रिपोर्ट) ○ 14.7% अनुसूचित जाति के अंतर्गत ○ 5.6 % अनुसूचित जनजातियों के लिए ○ 37% अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ○ 5.5% मुसलमान जबकि 2.3% अन्य अल्पसंख्यक समूहों के थे। • प्रत्येक वर्ष कक्षा 12 के उम्मीदवारों की संख्या 1 करोड़ से अधिक होती है। **केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थिति** • विदित हो कि वर्ष 2019-20 में 48 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 7.2 लाख छात्र अध्ययन कर रहे हैं, जिनमें से 5.4 लाख स्नातक कार्यक्रम कर रहे थे। • केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इक्विटी ○ 13.73% अनुसूचित जाति ○ 4.5% एसटी ○ 17.9% ओबीसी ○ 8.41% मुसलमान • केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्वीकृत 19,366 संकाय पदों में से 6,558 रिक्त हैं। **क्या सीयूसीईटी नया है?** • CUET नया नहीं है। इसे यूपीए-द्वितीय सरकार के तहत 2010 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीयूसीईटी) के रूप में शुरू किया गया था। • लेकिन यह कर्षण हासिल करने में विफल रहा क्योंकि पिछले साल तक केवल 14 केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने इसे लागू किया था और उनमें से कोई भी फ्रंटलाइन केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं रहा है। • CUET, CUCET का नया रूप है और अब सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए इसे अपनाना अनिवार्य है। • CUCET नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) की घोषणा के बाद आया है, जो विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए एक प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता की सिफारिस करती है। **CUET कौन आयोजित करेगा और परीक्षा का पैटर्न क्या होगा?** • राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए), जो जेईई (मुख्य) और यूजीसी-नेट जैसे प्रवेश परीक्षा आयोजित करती है, यह जुलाई के पहले सप्ताह में सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए सीयूईटी भी आयोजित करेगी।

- यह साढ़े तीन घंटे की कंप्यूटर आधारित परीक्षा है जो दो पालियों में होगी और इसे 13 भाषाओं में लिया जा सकता है।
- इसमें केवल एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों की सामग्री पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे।
- CUET में अनिवार्य रूप से तीन भाग होंगे।
    - पहले भाग में भाषा का परीक्षण होता है जिसमें पढ़ने की समझ, शब्दावली पर प्रश्न शामिल होंगे।
    - CUET का दूसरा भाग उम्मीदवार के डोमेन-विशिष्ट ज्ञान के परीक्षण पर केंद्रित है (प्रस्ताव पर 27 डोमेन, छात्र कम से कम एक और अधिकतम छह चुनता है)।
    - तीसरा भाग सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, सामान्य मानसिक क्षमता, संख्यात्मक क्षमता, मात्रात्मक तर्क पर प्रश्नों के साथ एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगी। इसमें उम्मीदवार केवल तभी उपस्थित होगा जब वह अपनी पसंद के विश्वविद्यालय द्वारा चाहेगा।
- यहां तक कि राज्य, निजी और डीम्ड-टू-बी विश्वविद्यालय भी CUET को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं।
- अभी के लिए, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश किसी भी सामान्य प्रवेश के तहत होना अनिवार्य नहीं है।
- लेकिन जेईई (मेन) के विपरीत, सीयूईटी स्कोर के आधार पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए कोई सामान्य परामर्श नहीं होगा। प्रत्येक विश्वविद्यालय एनटीए द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची के आधार पर अपनी प्रवेश प्रक्रिया को परिभाषित करने के लिए स्वतंत्र है।
    - हालांकि, यूजीसी अध्यक्ष ने भविष्य में संयुक्त परामर्श से इंकार नहीं किया।

कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्यों?

- उच्च शिक्षा के अभ्यर्थियों पर बोझ को कम करने के लिए एक से अधिक प्रवेश परीक्षाओं के स्थान पर एक ही प्रवेश परीक्षा देना।
- छात्र CUET परीक्षा को 13 में से किसी भी भाषा में लिखने का विकल्प चुन सकते हैं, जो उनकी क्षेत्रीय भाषा हो।
- आसमान छूती कट-ऑफ अब इतिहास बनेंगे जो दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे कुछ प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के मामले में था।
- किसी छात्र के कॉलेज या कार्यक्रम में उसके प्रवेश को निर्धारित करने में उसके बोर्ड के अंकों की कोई भूमिका नहीं होगी। यह केवल उसके CUET स्कोर पर आधारित होगा। यह विभिन्न बोर्डों में मूल्यांकन प्रथाओं में अंतर को स्पष्ट करता है।
    - अधिक से अधिक, केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड के रूप में बोर्ड के अंकों का उपयोग कर सकते हैं।
    - संगीत, पेंटिंग, मूर्तिकला और रंगमंच जैसे प्रमुख व्यावहारिक घटकों वाले कौशल-आधारित पाठ्यक्रमों के लिए, विश्वविद्यालयों को CUET के साथ व्यावहारिक परीक्षा या साक्षात्कार आयोजित करने की अनुमति होगी।
    - इंजीनियरिंग और एमबीबीएस जैसे पेशेवर कार्यक्रमों के लिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय क्रमशः प्रवेश परीक्षा जेईई (मुख्य) और एनईईटी के माध्यम से प्रवेश देंगे।

चिंताएं क्या हैं?

- परीक्षण की संरचना, और जिन लक्ष्यों के साथ इसे बनाया गया है, उन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का सुझाव दिया था जो वैचारिक समझ और ज्ञान को लागू करने की क्षमता की जांच करता है और इसका उद्देश्य इन परीक्षाओं के लिए कोचिंग लेने की आवश्यकता को समाप्त करना होगा।
- अनुचित कट-ऑफ को किसी अन्य परीक्षण स्कोर से प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए।
- साथ ही, प्रवेश प्रक्रिया में 12 साल की स्कूली शिक्षा को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सरकार और स्कूल बोर्डों को एक बच्चे के स्कूली शिक्षा करियर को वेटेज देने का एक तरीका खोजना चाहिए।

अंत में, सुधार का एक भी टुकड़ा संकट के बड़े, संरचनात्मक कारणों को अस्पष्ट नहीं करना चाहिए, यानी उच्च शिक्षा में

	समानता और गुणवत्ता की चुनौती को संबोधित करना।
कृषि कानूनों पर SC पैनल की रिपोर्ट	**संदर्भ:** विवादास्पद कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट को पहली बार सार्वजनिक किया गया। **मुद्दे की संक्षिप्त पृष्ठभूमि** ● समिति का गठन नए कृषि कानूनों से संबंधित किसानों की शिकायतों और सरकार के विचारों को सुनने और सिफारिशें करने के उद्देश्य से किया गया था। ● तीन कृषि कानूनों को निरस्त करना दिल्ली की सीमाओं पर इन सुधारों के विरोध में लगभग 40 किसान संघों (संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के बैनर तले) की प्रमुख मांगों में से एक था। ● नवंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र के सुधारों के लाभों के बारे में विरोध करने वाले किसानों को नहीं समझा सकती है। **रिपोर्ट की मुख्य बातें** ● मौजूदा नीति वर्तमान के लिए अनुपयुक्त: रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा कृषि कानूनों और नीतियों को पहले दशकों के खाद्य उत्पादन घाटे और कमी के दौरान उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया था, और यह वर्तमान समय के लिए ठीक नहीं हैं जब भारत ने एक खाद्य अधिशेष देश में छलांग लगाई है। ● **नए कानूनों का उद्देश्य:** तीन नए अधिनियमों का उद्देश्य कृषि बाजारों तक पहुंच बढ़ाना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है। ● **एमएसपी का कानूनी मुद्दा:** समिति ने कानूनों में कई बदलावों का सुझाव दिया, जिसमें राज्यों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रणाली को कानूनी बनाने की स्वतंत्रता देना शामिल है। ● **अधिप्राप्ति की सीमा:** समिति ने सिफारिशों की एक श्रृंखला प्रस्तावित की थी, जिनमें से एक भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा गेहूं और धान की खरीद को सीमित करना था। समिति को लगा कि बड़े पैमाने पर खरीद के बजाय राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन संघ (नेफेड) द्वारा तिलहन और दलहन की खरीद के मामले में अपनाए गए मॉडल को अपनाया जा सकता है। ● **विवाद निपटान:** एक महत्वपूर्ण सिफारिश विवाद निपटान के लिए एक वैकल्पिक तंत्र थी, जिसे सिविल अदालतों या मध्यस्थता तंत्र के माध्यम से हितधारकों को प्रदान किया जा सकता है। ● इन अधिनियमों के कार्यान्वयन में सहकारी प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में कृषि विपणन परिषद का गठन जीएसटी परिषद की तर्ज पर किया जा सकता है। ● सरकारी उपाय- सरकार को इस दिशा में तत्काल कदम उठाने चाहिए ○ कृषि बुनियादी ढांचे को मजबूत करना ○ सहकारी समितियों और एफपीओ के माध्यम से कृषि उपज के एकत्रीकरण, जाँच और गुणवत्ता छँटाई को सक्षम बनाना ● रिपोर्ट से भविष्य में कृषि क्षेत्र के लिए नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट में कहा है कि "इन कानूनों को निरस्त करना या लंबे समय तक निलंबन उन खामोश बहुमत के खिलाफ अनुचित होगा जो कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं।" ○ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 73 किसान संगठनों में से 61 संगठनों (85.7%) ने 3.3 करोड़ से अधिक किसानों का प्रतिनिधित्व करते हुए कानूनों का पूरा समर्थन किया। **समिति के शांत बहुमत के तर्क से क्या सरोकार था?** ● इन कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के बैनर तले प्रदर्शन करने वाले 40 किसान संगठनों ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। उनसे बार-बार अपनी राय या सुझाव देने का आग्रह किया गया था। ● मात्र 51 लाख किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले 13.3 प्रतिशत यानी चार संगठन इसके विरोध में थे। 3.6 लाख किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले सात संगठन इन कानूनों के कुछ प्रविधानों में संशोधन के पक्षधर थे। ● पैनल की बैठकों में भाग लेने वाले कुल 142 प्रतिनिधियों में से सिर्फ 78 किसान संगठनों से थे, जबकि 64 उद्योग निकायों और अन्य संगठनों के थे। लेकिन रिपोर्ट की छानबीन से पता चलता है कि 19,207 प्रतिक्रियाओं में से केवल 5,451 या 28 प्रतिशत किसानों ने सुझाव दिए थे।

	○ इनमें से अधिकतम प्रतिक्रियाएं महाराष्ट्र (2,000-2,500) से थीं, 2,000 राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश से थीं। इन राज्यों में कृषि कानूनों का विरोध भी मामूली हुआ था।
इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS)	**संदर्भ:** राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) स्थापना दिवस पर, केंद्रीय गृह मंत्री ने टिप्पणी की कि इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) परियोजना का दूसरा चरण 2026 तक पूरा होने वाला है। **क्या आप जानते हैं?** ● इंदौर पुलिस आयुक्त ने हाल ही में 'फिंगरप्रिंट आधारित आपराधिक रिकॉर्ड डेटा फ़ेचिंग सिस्टम' का अनावरण किया। चेकिंग पॉइंट्स, सार्वजनिक स्थानों आदि पर उंगलियों के निशान को पकड़ने के लिए छोटे अंगूठे के निशान वाली मशीन को फोन में जोड़ा जा सकता है। ● अगर दर्ज की गई फिंगरप्रिंट पुलिस डेटाबेस से मेल खाती है, तो किसी व्यक्ति के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। इस प्रणाली की सराहना की जा रही है क्योंकि यह जांच के रूप में फिंगरप्रिंट विश्लेषण में ज्यादा समय नही लगेगा। **आईसीजेएस क्या है?** ● ● इंटर-ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) देश में आपराधिक न्याय के वितरण के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य आईटी प्रणाली के एकीकरण को पांच स्तंभों द्वारा सक्षम करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच है: - ○ पुलिस (अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग और नेटवर्क सिस्टम), ○ फोरेंसिक लैब के लिए ई-फोरेंसिक, ○ न्यायालयों के लिए ई-न्यायालय, ○ लोक अभियोजकों के लिए ई-अभियोजन ○ जेलों के लिए ई-जेल ● गृह मंत्रालय (गृह मंत्रालय) की सीसीटीएनएस (अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम) परियोजना के तहत निवेश किया गया, आईसीजेएस देश के सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में पुलिस, जेलों और अदालतों के डेटाबेस पर एक राष्ट्रव्यापी खोज को सक्षम बनाता है। ● यह भविष्य में अपराधों के प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण के लिए क्षेत्र-वार, श्रेणी-वार, और अन्य मापदंडों के आधार पर रिपोर्ट किए गए अपराधों में पूर्वानुमान / भविष्यवाणी के रुझान के लिए डेटा एनालिटिक्स भी प्रदान करता है। ● आईसीजेएस प्रणाली उच्च गति कनेक्टिविटी के साथ एक समर्पित और सुरक्षित क्लाउड-आधारित बुनियादी ढांचे के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। ● राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) जिम्मेदार होगा। ● इस परियोजना को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया जाएगा। ● आईसीजेएस परियोजना के पहले चरण (2018-2022) में, व्यक्तिगत आईटी प्रणालियों को लागू और स्थिर किया गया है; इन प्रणालियों पर अभिलेखों की खोज को भी सक्षम किया गया है। ● चरण- II (2022-26) के तहत, सिस्टम 'एक डेटा एक प्रविष्टि' के सिद्धांत पर बनाया जा रहा है, जिसके तहत डेटा केवल एक बार एक स्तंभ में दर्ज किया जाता है और फिर वही अन्य सभी स्तंभों में उपलब्ध होता है।

. Conceptual diagram of ICJS implementation

आईसीजेएस की खूबियां

- यह आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न स्तंभों के बीच आवश्यक सूचनाओं को साझा करने में लगने वाली त्रुटियों और समय को कम करता है, जिससे आम आदमी को जल्द न्याय मिल जाता है।
- यह प्लेटफॉर्म में इनबिल्ट एनालिटिक्स का लाभ उठाकर जांच गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद करता है।
- आईसीजेएस मंच मामले और अदालत प्रबंधन के लिए एक प्रभावी उपकरण है, क्योंकि किसी मामले की सभी प्रासंगिक जानकारी अदालतों द्वारा उपयोग के लिए रीयल-टाइम में उपलब्ध होगी।
- प्रभावी समय प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए न्यायिक आदेशों और समन का अनुपालन भी शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है।
- प्रिडिक्टिव पुलिसिंग: अपराधों के रोकथाम के लिए प्रिडिक्टिव पुलिसिंग का प्रयोग देश में पहली बार किया जाएगा। आईआईटी कानपुर द्वारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पुलिस को पहले ही बता देगा कि किस जगह गश्त करने से क्राइम को रोका जा सकता है।
    - भविष्य में पुलिस की गाड़ियों को कहां और कब गश्त लगानी है, सॉफ्टवेयर इसका भी समय और जगह बताएगा।
- आईसीजेएस गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह से आपराधिक न्याय प्रणाली की उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है।

पुलिसिंग में प्रौद्योगिकी को लागू करने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- गोपनीयता- केएस पुट्टस्वामी में सुप्रीम कोर्ट ने सूचनात्मक गोपनीयता के मौलिक अधिकार को सर्वोपरि घोषित किया और कहा कि कोई भी उपाय जो जानकारी एकत्र करने या सर्वेक्षण करने की मांग करता है वह कानूनी, आवश्यक और आनुपातिक होना चाहिए।
- बड़े पैमाने पर निगरानी- भविष्य कहनेवाला पुलिसिंग प्रथाओं की सूची में फिंगरप्रिंट-आधारित आपराधिक रिकॉर्ड डेटा लाने वाली प्रणाली को एकीकृत करना बड़े पैमाने पर निगरानी को जन्म देगा।
- गरीब और कमजोर लोगों पर अनुपातहीन प्रभाव- किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल संदेह या प्राथमिकी दर्ज करना पुलिस की विवेकाधीन शक्तियों को ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त है जो उत्पीड़ित समुदायों के खिलाफ दुरुपयोग किया जाता है। पुलिस के अधीन होने वालों में शायद ही कभी संसाधनों वाले प्रभावशाली जाति के व्यक्ति शामिल होते हैं, जिन्हें अपराध का दोषी भी ठहराया जा सकता है।

युद्ध के भीतर एक और 'युद्ध': जंग के हथियार के रूप में यौन हिंसा (A war within a war: Sexual violence as a weapon of war)

प्रसंग: किसी भी युद्ध में महिलाएं और लड़कियां सबसे ज़्यादा असुरक्षित होती हैं। संस्थाओं और सामाजिक तानेबाने के टूटने से महिलाओं और लड़कियों के लिए यौन हिंसा और शोषण के मामले लगातार बढ़ सकते हैं। इतिहास गवाह है कि संघर्ष और हिंसा के दौर में आबादी को अपमानित करने, उसे ग़ुलाम बनाने और आतंकित करने के लिए यौन हिंसा को एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है।

- उदाहरण के लिए, बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन के दौरान 200,000 से 400,000 बंगाली महिलाओं को सिलसिलेवार ढंग से यौन हिंसा का शिकार बनाया गया।

	• वर्ष 1991-2002 के बीच सिएरा लियोन में गृहयुद्ध के दौरान 60,000 से अधिक महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया गया, 1989-2003 के बीच 14 साल तक चले गृह युद्ध के दौरान लाइबेरिया में लगभग 40,000, महिलाओं को, साल 1992-95 के दौरान पूर्व यूगोस्लाविया में लगभग 60,000, वहीं 100,000 से 250,000 महिलाओं को रवांडा नरसंहार के दौरान, और साल 1998 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 200,000 से अधिक महिलाओं को शिकार बनाया गया। **यह कैसे स्थिर रहता है?** युद्ध क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार, यौन दासता, सामूहिक बलात्कार, यौन उत्पीड़न और यातना सहित कई प्रकार की यौन हिंसा को अंजाम दिया गया है। पीड़ितों में बच्चे और गर्भवती महिलाएं तक शामिल हैं, जिनमें से कई को हफ्तों तक यौन गुलामों के रूप में बंदी बनाकर रखा गया था। • एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार, यौन हिंसा के मामलों से उबरने वाले अधिकांश व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं सहित गंभीर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करते हैं, और चिकित्सा या मनोसामाजिक सेवाओं तक उनकी पहुंच लगभग न के बराबर होती है। • अंतरराष्ट्रीय मानवीय क़ानून के प्रावधानों के विपरीत, चिकित्सा सुविधाओं को सशस्त्र समूहों द्वारा जानबूझकर लक्ष्य बनाया जाता है, एम्बुलेंसों को ज़ब्त कर लिया गया है, और ज़्यादातर चिकित्साकर्मी डर के मारे भाग गए हैं। • कुछ युद्धों में, पीड़ितों से जुड़ी अधिकांश रिपोर्ट कहती हैं कि उनकी पहचान के चलते उनके साथ यह बर्बरता की गई और इस क्रूरता का मकसद उन्हें शुद्ध करना था। • एचआईवी, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और सामाजिक कलंक जैसी समस्याओं के अलावा इन संघर्षों के दौरान होने वाली यौन हिंसा का प्रभाव अक्सर संघर्ष समाप्त होने के बाद भी बना रहता है। उदाहरण के लिए, लाइबेरिया में, गृहयुद्ध के सालों के दौरान सामने आई हर दण्ड से मुक्ति की भावना और 'अति पुरुषत्व' की संस्कृति के चलते औपचारिक रूप से संघर्ष खत्म होने के बाद भी यौन हिंसा की दर लगातार बहुत अधिक बनी हुई है। • संघर्ष झेलने वाले और उसके खत्म होने के बाद जीवित बचे समाजों में लोगों को चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक देखभाल प्रदान करने की क्षमता नहीं होती, और ऐसे में न्याय की बात करना बेहद मुश्किल है। **वैश्विक चुप्पी** दुर्भाग्य से, संघर्षों में लिंग आधारित हिंसा के मुद्दे पर लैंगिक समानता की बहस और सतत विकास को लेकर होने वाली चर्चाओं में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। • संघर्ष क्षेत्रों में यौन हिंसा को अक्सर युद्ध के एक कारक के रूप में माना जाता है और हिंसा के अपराधियों को शायद ही कभी दंडित किया जाता है। • युद्ध लैंगिक समानता के वैश्विक लक्ष्य, एसडीजी 5 के संबंध में कुछ मुश्किल प्रश्न उठाता है, जो "सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में महिलाओं और लड़कियों के ख़िलाफ़ हिंसा को ख़त्म करने का आह्वान करते हैं, जिसमें तस्करी और यौन व अन्य प्रकार के शोषण शामिल हैं।" वैश्विक समुदाय के लिए एक प्रश्न पर विचार करना चाहिए: क्या महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा को खत्म करना संभव है यदि देश संघर्ष क्षेत्रों में यौन हिंसा के ख़िलाफ़ सख्त रुख अपनाने से इनकार करते हैं? **निष्कर्ष** यदि किसी राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान और 'आंतरिक' मामलों में हस्तक्षेप, युद्ध के हथियार के रूप में यौन हिंसा के इस्तेमाल से ज़्यादा ज़रूरी कारक बन जाता है, तो लैंगिक समानता क्या एक दूर का लक्ष्य नहीं हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए प्रतिबद्ध दुनिया महिलाओं और लड़कियों के साथ इतने बड़े पैमाने पर होने वाली यौन हिंसा को लेकर चुप नहीं रह सकती। **क्या आप निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं?** 1. क्या हम लैंगिक समानता हासिल कर सकते हैं जबकि यौन हिंसा अभी भी युद्ध का हथियार है? चर्चा कीजिए।
प्रवासी नागरिकों का मतदान: इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक	**संदर्भ:** केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा (Loksabha) में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि केंद्र विदेशों में काम कर रहे भारतीयों को ऑनलाइन मतदान का अधिकार देने पर विचार कर रहा है। • वर्ष 2020 में ही भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने पात्र एनआरआई को डाक मतपत्र की सुविधा का विस्तार

मतपत्र प्रणाली	करने का प्रस्ताव दिया था। डाक मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एनआरआई को भेजा जाना था जिसके बाद वे डाक के माध्यम से अपना उम्मीदवार चुनने के बाद मतपत्र वापस भेजते। **वर्तमान में विदेशी मतदाता भारतीय चुनावों में कैसे मतदान कर सकते हैं?** • वर्ष 2010 से पहले, एक भारतीय नागरिक जो एक पात्र मतदाता है और छह महीने से अधिक समय से विदेश में रह रहा था, वह चुनाव में मतदान नहीं कर सकता था। • ऐसा इसलिए था क्योंकि एनआरआई का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया था यदि वह लगातार छह महीने से अधिक समय तक देश से बाहर रहा। • जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010 के पारित होने के बाद, पात्र एनआरआई जो छह महीने से अधिक समय तक विदेश में रहे थे, वे मतदान करने के लिए पात्र हो गए हैं, लेकिन केवल मतदान केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से जहां उन्हें एक विदेशी मतदाता के रूप में नामांकित किया गया है। • जिस तरह 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी निवासी भारतीय नागरिक उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने के लिए पात्र है जहां वह निवासी है इस तरह से प्रवासी भारतीय नागरिक भी ऐसा करने के लिए पात्र हैं। • विदेशी मतदाताओं के मामले में, पासपोर्ट में उल्लिखित उनके पते को सामान्य निवास स्थान के रूप में लिया जाता है और विदेशी मतदाता के नामांकन के लिए निर्वाचन क्षेत्र के रूप में चुना जाता है। **मौजूदा सुविधा ने अब तक कैसे काम किया है?** • वर्ष 2014 में पंजीकृत केवल 11,846 विदेशी मतदाताओं में से यह संख्या 2019 में एक लाख के करीब पहुंच गई। लेकिन इनमें से अधिकांश मतदाता (लगभग 90%) सिर्फ केरल राज्य के थे। • ऐसे 25,606 मतदाताओं में से, जो वास्तव में आए, 25,534 केरल (ज्यादातर कोझीकोड और मलप्पुरम जिलों से) से थे। • स्पष्ट रूप से, पात्र विदेशी निवासियों का बहुत कम अनुपात वास्तव में पंजीकृत है या मतदान के लिए आया है। • व्यक्तिगत रूप से मतदान केंद्र पर जाने के प्रावधान ने पात्र मतदाताओं को अपने जनादेश का प्रयोग करने से हतोत्साहित किया है। • वर्ष 2017 में संसद के शीतकालीन सत्र में, सरकार ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 20A द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का प्रस्ताव रखा, जिसके लिए उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करने के लिए व्यक्तिगत शारीरिक रूप से उपस्थित होना आवश्यक है। • चुनाव आचरण नियम, 1961 में निर्धारित शर्तों के अधीन, विधेयक विदेशी मतदाताओं को अपनी ओर से वोट डालने के लिये एक प्रॉक्सी नियुक्त करने में सक्षम बनाते हैं। • विधेयक में वर्ष 2018 में पारित किया गया था, लेकिन 16वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही यह समाप्त हो गया। • इसके बाद ईसीआई ने सरकार से संपर्क किया कि एनआरआई को डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी जाए, जो पहले से ही सेवा मतदाताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रणाली के समान है, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रणाली या ईटीपीबीएस है। ○ सेवा मतदाता वे हैं जिनके पास सेवा योग्यता है। कोई व्यक्ति जो या तो संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य है, किसी राज्य का सशस्त्र पुलिस बल है, या कोई व्यक्ति जो केवल भारत सरकार के अधीन कार्यरत है। ○ वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सेवा मतदाताओं के बीच अधिक मतदान के लिए ETPBS पद्धति की अनुमति दी गई। **ईटीपीबीएस क्या है और यह कैसे काम करता है?** • सेवा मतदाताओं को ETPBS का उपयोग करने की अनुमति देने हेतु चुनाव आचरण नियम, 1961 में वर्ष 2016 में संशोधन किया गया था। • इस प्रणाली के तहत, डाक मतपत्र पंजीकृत सेवा मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जाते हैं। • सेवा मतदाता तब ETPB (घोषणा पत्र एवं कवर के साथ) डाउनलोड कर सकते हैं, मतपत्र पर अपना जनादेश दर्ज कर सकते हैं और इसे सामान्य मेल के माध्यम से निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को भेज सकते हैं।

	• इस पोस्ट में एक सत्यापित घोषणा पत्र शामिल होता है (मतदाता द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद एक नियुक्त वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में जो इसे सत्यापित करेगा)। • मतगणना के दिन सुबह 8 बजे तक डाक मतपत्र रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंच जाना चाहिए। • भारत निर्वाचन आयोग ने इस सुविधा को विदेशी मतदाताओं के लिए भी विस्तारित करने का प्रस्ताव किया है। • इसे शुरू करने के लिए, कानून मंत्रालय को चुनाव संचालन नियम, 1961 में संशोधन करना होगा। • एनआरआई मतदाताओं के मामले में, ईटीपीबीएस के माध्यम से मतदान करने के इच्छुक लोगों को चुनाव की अधिसूचना के कम से कम पांच दिन बाद रिटर्निंग ऑफिसर को सूचित करना होगा। • इसके बाद रिटर्निंग अधिकारी ईटीपीबीएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतपत्र भेजेंगे। • एनआरआई मतदाता तब अपने जनादेश को बैलेट प्रिंटआउट पर पंजीकृत कर सकता है और सेवा मतदाता के समान प्रक्रिया में एक सत्यापित घोषणा के साथ इसे वापस भेज सकता है। इस मामले को छोड़कर, वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति एनआरआई के निवासी देश में भारतीय राजनयिक या कांसुलर (consular) प्रतिनिधि द्वारा की जाएगी। • चुनाव आयोग ने यह निर्दिष्ट नहीं किया है कि क्या मतदाता को सामान्य डाक के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी को मतपत्र भेजना चाहिए या इसे भारतीय कांसुलर कार्यालय/दूतावास में छोड़ना चाहिए, जो फिर निर्वाचन अधिकारियों को निर्वाचन क्षेत्र-वार लिफाफे भेज देगा।
आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022	**संदर्भ:** सरकार ने विपक्ष के कड़े विरोध के बीच लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022 पेश किया है। • यह विधेयक कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 की जगह लेता है। • **विधेयक का उद्देश्य:** यह बिल ऐसे व्यक्तियों के शरीर का उचित माप लेने के लिए कानूनी मंजूरी प्रदान करता है, जिन्हें अपराध की जांच को अधिक कुशल और तेज बनाने" के लिए इस तरह के माप देने की आवश्यकता होती है। • यह उंगलियों के निशान, हथेली के निशान और पैरों के निशान, फोटोग्राफ, आईरिस और रेटिना स्कैन, भौतिक और जैविक नमूने और उनके विश्लेषण को शामिल करने के लिए 'माप' को परिभाषित करने का प्रयास करता है। **भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की समस्याएं** • मामलों का धीमी गति से निपटान जिसके कारण बड़े बैकलॉग होते हैं।न्यायपालिका के समक्ष 4.4 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। अधिक संख्या में मामलों का एक कारण आचरण को अपराधीकरण करने की प्रवृत्ति है। • न्याय तंत्र ज्यादातर हाशिए के नागरिकों के वर्गों के लिए दुर्गम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्षमता निर्माण के बजाय संस्था निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। • कुछ हलकों में औपनिवेशिक मानसिकता के जारी रहने के कारण पुलिस द्वारा सत्ता का दुरूपयोग होता है। • अपराध की रोकथाम हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली का काल्पनिक लक्ष्य बना हुआ है। यह अप्रभावी सामुदायिक पुलिस तंत्र और स्थितिजन्य अपराध रोकथाम के कारण है • न्याय के पुनर्वासात्मक स्वरूप पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है। सरकार द्वारा हिरासत में दंड को गैर-हिरासत दंड (विभिन्न विधि आयोग द्वारा अनुशंसित) की तुलना में अधिक प्रभावी उपाय के रूप में देखा जाता है। • विश्वसनीय राज्य प्रायोजित डेटा संग्रह, रखरखाव और विश्लेषण तंत्र की कमी। • आपराधिक न्याय प्रणाली को अपराधों की बदलती प्रकृति के साथ पकड़ना अभी बाकी है। • पुलिस और न्यायिक प्रणाली में अक्षमताओं के कारण कम दोषसिद्धि दर - जिसे नए प्रस्तावित विधेयक द्वारा संबोधित किया जा रहा है। **क्या है प्रस्तावित कानून?** • **दोषियों और अन्य व्यक्तियों के बारे में विवरण:** पहले के अधिनियम में केवल उंगलियों के निशान और पदचिह्नों के संग्रह की अनुमति थी। बिल में आईरिस और रेटिना स्कैन, पाम-प्रिंट इंप्रेशन, सिग्नेचर और हैंडराइटिंग, बायोलॉजिकल सैंपल जैसे ब्लड, सीमेन, हेयर सैंपल और स्वैब और उनके विश्लेषण को शामिल करने के लिए सूची का विस्तार किया गया है। • कवरेज- यह प्रस्ताव करता है कि कानून तीन श्रेणियों के व्यक्तियों पर लागू होता है।

- सभी दोषी व्यक्ति (पहले यह केवल कुछ मामलों के लिए था)
- गिरफ्तार व्यक्ति
- संदिग्ध अपराधी
- किसी भी निवारक निरोध कानून के तहत पकड़े गए व्यक्ति

- **विवरण का प्रतिधारण:** बिल में संग्रह की तारीख से 75 वर्षों तक डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में एकत्र किए गए विवरण को बनाए रखने की आवश्यकता होती है।
- **ब्यौरों को हटाना:** उन व्यक्तियों के मामले में रिकॉर्ड नष्ट किया जा सकता है जो: (i) पहले दोषी नहीं ठहराए गए हैं, और (ii) सभी कानूनी उपायों को समाप्त करने के बाद, बिना मुकदमे के रिहा कर दिए गए हैं, उन्हें बरी कर दिया गया है, या अदालत द्वारा बरी कर दिया गया है।
- हेड कांस्टेबल रैंक तक के पुलिस कर्मियों को माप रिकॉर्ड करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- **विवरण देने का विरोध:** विधेयक के अनुसार, प्रतिरोध या विवरण देने से इनकार करना भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत अपराध माना जाएगा।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की भूमिका: इस विधेयक के तहत एनसीआरबी के कार्यों में शामिल हैं:
  - राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों, या अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों से विधेयक के तहत शामिल व्यक्तियों के बारे में विवरण एकत्र करना
  - राष्ट्रीय स्तर पर निर्दिष्ट व्यक्तियों के बारे में विवरण संग्रहीत करना और नष्ट करना
  - प्रासंगिक आपराधिक रिकॉर्ड के साथ विवरण संसाधित करना, और
  - कानून प्रवर्तन एजेंसियों को विवरण का प्रसार करना।
- **नियम बनाने की शक्ति:** अधिनियम ने केवल राज्य सरकार में नियम बनाने की शक्ति निहित की है। यह बिल केंद्र सरकार को भी इस शक्ति का विस्तार करता है। केंद्र या राज्य सरकार एनसीआरबी द्वारा विवरण के संग्रहण, भंडारण, संरक्षण, विनाश, प्रसार और निपटान के तरीके जैसे विभिन्न मामलों पर नियम बना सकती है।

बिल के खिलाफ क्या चिंताएं व्यक्त की गई हैं?

- **स्पष्टता की कमी:** वस्तुओं का बयान कहता है कि यह "दोषियों और अन्य व्यक्तियों" के लिए माप के संग्रह के लिए प्रदान करता है लेकिन अभिव्यक्ति "अन्य व्यक्तियों" को परिभाषित नहीं किया गया है।
- **मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष:** बिल में जैविक जानकारी के संग्रह में बल का प्रयोग निहित है, जिससे नार्को विश्लेषण और मस्तिष्क मानचित्रण हो सकता है, जिसे अनुच्छेद 20 (3) (आत्म-अपराध के खिलाफ अधिकार) का उल्लंघन माना जाता है। ऐसी भी चिंताएं हैं कि यह अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
- **न्यायिक जांच की संभावना:** बिल में "बढ़ती सजा दर" को भी इसके उद्देश्यों में से एक बताया गया है। अदालत को यह देखना पड़ सकता है कि क्या यह एक वैध उद्देश्य हो सकता है और क्या यह नागरिकों के अधिकारों से आगे निकल सकता है।
- **संघीय चुनौतियाँ:** यह देखते हुए कि पुलिसिंग अभी भी एक राज्य का विषय है, यह देखा जाना बाकी है कि क्या कोई राज्य इस जानकारी को साझा करने से इनकार करता है।
- **बड़े पैमाने पर निगरानी का भय :** प्रस्तावित विधेयक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पुलिस निगरानी के लिए एक कानूनी ढांचा लाता है, विशेषज्ञों को डर है कि इसका विस्तार या दुरुपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए: बिल राजनीतिक विरोध में लगे प्रदर्शनकारियों से भी नमूने एकत्र करने का अधिकार देता है।

क्रिप्टो प्रश्न (The Crypto Question)

संदर्भ: जब बिटकॉइन की शुरुआत 2008 में एक दशक से अधिक समय पहले हुई थी, वर्ष 2017 की शुरुआत में सभी क्रिप्टोकरेंसी का कुल बाजार पूंजीकरण केवल $20 बिलियन था। यह अगले तीन वर्षों में बढ़कर 289 बिलियन डॉलर हो गया और नवंबर 2021 में 2.9 ट्रिलियन डॉलर के शिखर पर पहुंच गया। पिछले तीन महीनों में इसमें फिर से तेज गिरावट देखने को मिली है।

- आज की स्थिति में क्रिप्टो करेंसी की कुल संख्या 17,697 है और क्रिप्टो एक्सचेंजों की कुल संख्या 462 है।
- वर्तमान में, भारत में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग पर कोई विनियमन या कोई प्रतिबंध नहीं है।
- क्रिप्टो लेनदेन का समर्थन करने से बैंकों को प्रतिबंधित करने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश को मार्च 2020 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से उलट दिया गया था।
- जबकि आरबीआई ने क्रिप्टोकरेंसी के खिलाफ अपने मजबूत दृष्टिकोण को बार-बार रेखांकित किया है, यह कहते हुए कि ये देश की व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा हैं, भारत सरकार इस क्षेत्र के नियमन के लिए एक कानून पर काम कर रही है।

बजट 2022

- वित्त मंत्री ने इस साल अपने बजट भाषण में आने वाले वित्तीय वर्ष में एक डिजिटल मुद्रा पेश करने का प्रस्ताव किया है जिसके लिए आरबीआई जल्द ही पायलट के बारे में ध्यान देगा।
- भविष्य में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी निविदा या विनिमय का माध्यम बन जाएगी या नहीं, इस पर सभी संदेहों को दूर करते हुए, बजट ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार क्रिप्टोक्यूरेंसी को एक मुद्रा के रूप में नहीं मानती है, लेकिन इसे एक आभासी डिजिटल संपत्ति के रूप में मानेगी। दूसरे शब्दों में, भारत सरकार क्रिप्टोकुरेंसी को निवेश के रूप में मानेगी।
- केंद्रीय बजट 2022 पेश करते समय सरकार ने आभासी संपत्तियों पर 30 प्रतिशत कर का प्रस्ताव रखा, निजी क्रिप्टोकरेंसी और अपूरणीय टोकन के व्यापार को प्रभावी रूप से वैध बनाया। यह मोटे तौर पर कानूनी निविदा के रूप में निजी आभासी सिक्कों के उपयोग की अनुमति नहीं देते हुए, एक फ़िएट डिजिटल मुद्रा रखने की केंद्र की योजना के अनुरूप है।

क्रिप्टोकरेंसी में कर लेनदेन

कर लगाने की शक्ति अनुच्छेद 246 के तहत निर्धारित है जो संसद के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं को कर लगाने की शक्ति प्रदान करती है। अनुच्छेद 265 में प्रावधान है कि कानून के अधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता है या एकत्र नहीं किया जा सकता है। आज, क्रिप्टोकरेंसी और इसकी अंतर्निहित तकनीक के उजागर होने के साथ, दुनिया एक और ऐसी क्रांति के शीर्ष पर खड़ी है। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी विकेन्द्रीकृत हैं, डिजिटल मुद्राएं एक पीयर-टू-पीयर नेटवर्क पर निर्भर हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक जैसे तीसरे पक्ष के मध्यस्थ की आवश्यकता के बिना संचालित होती हैं। नियामक मार्गदर्शन की कमी के साथ, इसके अद्वितीय तकनीकी पहलू इसके कराधान में भारी जटिलताएं पैदा करते हैं।

- क्रिप्टोकरेंसी अर्थात वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के कराधान के बारे में ये स्पष्टीकरण जैसा कि सरकार चाहती है कि इसे संबोधित किया जाए की यह सही समय पर आएं।
- यह विशेष रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लगभग 10 करोड़ व्यक्तिगत निवेशकों ने विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी में लगभग 6 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है, जैसा कि द ब्लॉकचैन एंड क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार, जो कि इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का एक हिस्सा है।
- 'आभासी डिजिटल संपत्ति' या क्रिप्टो मुद्राओं पर कर लगाने से आयकर विभाग को देश में इस व्यापार की "गहराई" को मापने में मदद मिलेगी।
- आयकर विभाग और आयकर अधिनियम केवल यह देखता है कि आपके द्वारा किए गए लेन-देन के परिणामस्वरूप आय हुई है या नहीं।
- नए कानून के तहत क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाने की कोई वैधता नहीं है।
- जब कोई संस्था डिजिटल व्यापार पर किसी लाभ या अधिशेष की घोषणा करती है, तो उन्हें यह भी कहना होगा कि उन्हें निवेश करने के लिए पैसा कहां से मिला है और यदि निवेश उचित है, तो अधिशेष पर कर लगाया जाएगा।

चुनौतियां:

- स्पष्ट कर प्रावधानों की अनुपस्थिति ने अस्पष्टता और अनिश्चितता को उजागर किया : इस बात की स्पष्टता का अभाव कि क्या क्रिप्टो लेनदेन पर जीएसटी केवल रुपये के लेनदेन पर या यहां तक कि क्रिप्टो मुद्राओं के माध्यम से लेनदेन पर भी लागू होता है।
- सीमा पार लेनदेन के कारण कर लगाना मुश्किल: आमतौर पर, करदाता भारत के बाहर सर्वर पर क्रिप्टोकरेंसी और ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं। ऐसे मामलों में, यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि किस क्षेत्राधिकार के कर कानून लागू होंगे।
- क्रिप्टोकरेंसी के साथ लेनदेन करने वाले करदाताओं की पहचान गुमनाम रहती है और इसलिए उन व्यक्तियों पर नजर रखना काफी मुश्किल हो जाता है जो क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार कर रहे हैं। आमतौर पर, कर चोर अपने काले धन को विदेशों में जमा करने और आपराधिक गतिविधियों, आतंकवाद आदि को निधि देने के लिए क्रिप्टो लेनदेन का उपयोग करते रहे हैं।
- कर चोरों का पता लगाना मुश्किल: आयकर विभाग के हाथ में सबसे कुशल प्रवर्तन साधनों में से एक है आकलनों का CASS या 'कंप्यूटर सहायता प्राप्त जांच चयन', जहां करदाताओं के रिटर्न का चयन अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों जैसे तीसरे पक्ष के मध्यस्थों से एकत्रित जानकारी के आधार पर किया जाता है

क्रिप्टोक्यूरेंसी कैसे काम करती है?

- क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन नामक तकनीक का उपयोग करके काम करती है। ब्लॉकचेन एक विकेन्द्रीकृत तकनीक है जो कई कंप्यूटरों में फैले हुए लेनदेन का प्रबंधन और रिकॉर्ड करती है।
- इसलिए आरबीआई जैसे पारंपरिक वित्तीय संस्थानों पर भरोसा करने के बजाय, जो आपके लेनदेन को सत्यापित और गारंटी देते हैं, क्रिप्टोकुरेंसी लेनदेन को उपयोगकर्ता के कंप्यूटर द्वारा मुद्रा के नेटवर्क में लॉग इन करके सत्यापित किया जाता है।
- क्रिप्टोक्यूरेंसी खनन वह प्रक्रिया है जिसमें उपयोगकर्ताओं के बीच लेनदेन को सत्यापित किया जाता है और ब्लॉकचेन सार्वजनिक खाता बही में जोड़ा जाता है।
- खनन की प्रक्रिया मौजूदा परिसंचारी आपूर्ति में नए सिक्कों को पेश करने के लिए भी जिम्मेदार है और यह उन प्रमुख तत्वों में से एक है जो क्रिप्टोकरेंसी को किसी तीसरे पक्ष के केंद्रीय प्राधिकरण की आवश्यकता के बिना पीयर-टू-पीयर विकेन्द्रीकृत नेटवर्क के रूप में काम करने की अनुमति देता है।

आगे की राह

- स्मार्ट रेगुलेशन बेहतर है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र की तकनीक पर आधारित किसी चीज़ पर प्रतिबंध सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि चीन में क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इंटरनेट को नियंत्रित किया गया है, क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार कम रहा है, लेकिन गायब नहीं हुई है। सरकार को प्रतिबंध के विचार का विरोध करना चाहिए और स्मार्ट विनियमन पर जोर देना चाहिए।
- संक्रमण का पता लगाने के लिए सरकार को एक मौद्रिक सीमा से ऊपर के लेनदेन के स्रोत पर 1 प्रतिशत कर कटौती (टीडीएस) लगानी चाहिए। अमेरिकी सरकार ने सभी करदाताओं और तीसरे पक्ष के बिचौलियों (एक्सचेंज, वॉलेट प्रदाता, खनिक आदि) के लिए क्रिप्टोकुरेंसी से संबंधित सभी लेनदेन का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया है।
- स्पष्ट और स्पष्ट प्रावधानों को आयकर अधिनियम में शामिल किया जाना चाहिए। क्रिप्टो लेनदेन पर जानकारी एकत्र करने और साझा करने में सक्षम बनाने हेतु सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे को मजबूत किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- कर विभाग ऐसे समय में डिजिटल या आभासी संपत्ति पक्ष में पहुंच रहे है जब नीति पर काम किया जा रहा है, इसलिए निश्चित रूप से विभाग के बाजार में प्रवेश करने का यह सही समय है। केवल कानून ही हमें यह जानने में मदद करेगा कि कौन निवेश कर रहा है, कितना निवेश किया जा रहा है, निवेश की गुणवत्ता, निवेश की प्रकृति और लोग लाभ या हानि कमा रहे हैं या नहीं।
- देश को इन लेनदेनों को ऐसे तरीके से विनियमित करना चाहिए जिससे उपभोक्ता सुरक्षा और वैधता के बीच एक उचित संतुलन की अनुमति मिलती है। क्रिप्टो मुद्राओं के लिए एक स्पष्ट, रचनात्मक और अनुकूली नियामक वातावरण के निर्माण में एक सुव्यवस्थित कर व्यवस्था आवश्यक होगी।

	क्या आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं? 1. क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन पर कर लगाने पर हाल की बजट घोषणाओं पर आपके क्या विचार हैं? अपने विचारों की पुष्टि करें। 2. हाल के महीनों में क्रिप्टोकरेंसी के बाजार कैसे विकसित हुए हैं? क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित नियामक चिंताएं क्या हैं? चर्चा करना।
तेल की बढ़ती कीमतें और मुद्रास्फीतिजनित मंदी	**संदर्भ:** कच्चे तेल की कीमतें लगभग 140 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गईं, जो दिसंबर में लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल थी। **तेल की कीमतों में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है?** • वृद्धि के लिए सबसे तात्कालिक ट्रिगर यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में रूसी तेल की खरीद पर प्रतिबंध लगाने का यूएसए का निर्णय है। • रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है अगर प्रतिबंधों के कारण इसके तेल को बाजार से बाहर रखा जाता है, तो इससे न केवल कीमतों में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इसका मतलब यह भी होगा कि वे लंबे समय तक इस तरह बने रहेंगे। **Fig 1. Impact of war on major commodity prices:** 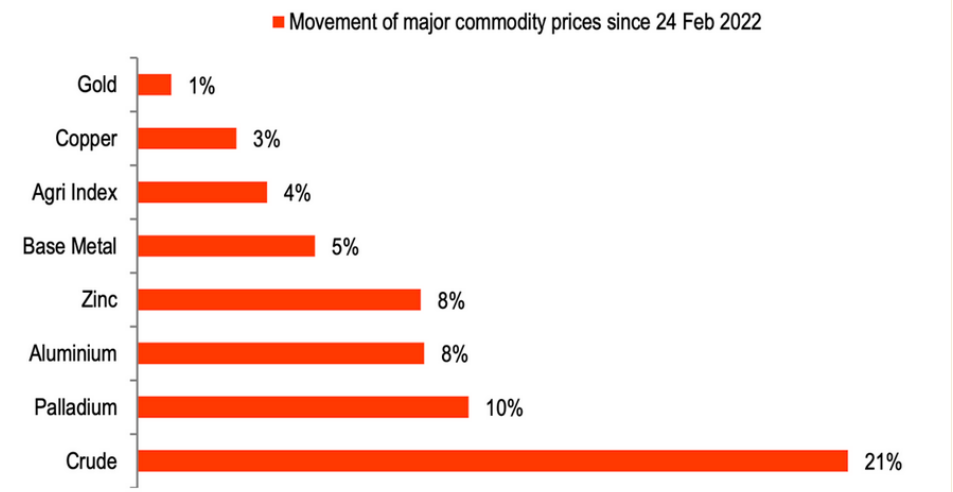 **तेल की बढ़ती कीमतों से भारत पर क्या असर पड़ेगा?** • हालांकि भारत सीधे तौर पर इस संघर्ष में शामिल नहीं है, लेकिन अगर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है और इस तरह बनी रहती है तो यह बुरी तरह प्रभावित होगा। • भारत अपनी कुल तेल मांग का 84% से अधिक आयात करता है और तेल की कीमतों में वृद्धि से हमारे आयात बिल में वृद्धि होगी जिससे चालू खाता घाटा और बढ़ जाएगा। • कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि होगी, अगर सरकार अपने करों में कटौती नहीं करती है। • उच्च पेट्रो और डीजल की कीमतें मुद्रास्फीति को और बढ़ा देंगी और सामान्य मूल्य स्तर (परिवहन लागत में वृद्धि के कारण) को बढ़ा देंगी। कच्चे तेल की कीमतों में 10% की वृद्धि थोक मुद्रास्फीति में 0.9% और खुदरा मुद्रास्फीति में 0.5% की वृद्धि हुई। • उच्च मुद्रास्फीति भारतीयों की क्रय शक्ति को ग्रहण कर सकती है , इस प्रकार उनकी समग्र मांग में कमी आएगी। • निजी उपभोक्ता मांग भारत में विकास का सबसे बड़ा चालक है, जो भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 55% से अधिक है। • वर्तमान में, भारत की जीडीपी वृद्धि कमजोर उपभोक्ता मांग है। ऊंची कीमतें मांग को और कमजोर करेंगी एवं ये हमारी आर्थिक सुधार की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाएंगी। ○ विश्लेषक भारत के लिए अपने पूर्वानुमानों को संशोधित कर रहे हैं - विकास के लिए नीचे (7.9% से

	7.7%) और मुद्रास्फीति के लिए (5.8% से 6.3%)। • इसके अलावा, मांग की जा रही कम वस्तुओं और सेवाओं से व्यवसायों को नई क्षमताओं में निवेश करने से हतोत्साहित किया जाएगा, जो बदले में बेरोजगारी संकट को बढ़ा कर आय को और भी कमकरेगा। • चिंताजनक बात है कि तेल की कीमतों में अचानक और तेज उछाल भारत जैसी अपेक्षाकृत कमजोर अर्थव्यवस्था को गतिरोध में पहुंचा सकता है। **मुद्रास्फीतिजनित मंदी क्या है?** • स्टैगफ्लेशन उस स्थिति को दर्शाता है जब मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दर दोनों ही उच्च रहते हैं। • यह एक देश के लिए आर्थिक रूप से एक मुश्किल स्थिति होती है, चूंकि, इस समय दोनों ही मुद्रास्फीति और आर्थिक अस्थिरता की समस्या एक साथ उत्पन्न होती हैं और कोई भी व्यापक आर्थिक नीति एक ही समय में इन समस्याओं पर एक साथ ध्यान केन्द्रित नहीं कर सकती है। • आमतौर पर, बढ़ती मुद्रास्फीति तब होती है जब कोई अर्थव्यवस्था फलफूल रही होती है - लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे होते हैं, बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं की मांग करते हैं और इसके परिणामस्वरूप कीमतें बढ़ती रहती हैं। • जब रिवर्स लॉजिक से मांग कम हो जाती है, तो कीमतें गिर जाती हैं। • लेकिन मुद्रास्फीतिजनित मंदी एक ऐसी स्थिति है जहां एक अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे खराब स्थिति का अनुभव करती है - विकास दर काफी हद तक स्थिर है (बढ़ती बेरोजगारी के साथ) और मुद्रास्फीति न केवल उच्च है बल्कि लगातार बनी रहती है। • मुद्रास्फीतिजनित मंदी का सबसे प्रसिद्ध मामला वर्ष 1970 के दशक की शुरुआत हुआ था। ओपेक (पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन), जो एक कार्टेल की तरह काम करता है, ने कच्चे तेल की आपूर्ति में कटौती करने का फैसला किया। इसने दुनिया भर में तेल की कीमतों में उछाल पहुचांया जो लगभग 70% ऊपर थे। • इस तरह अचानक तेल की कीमत के झटके ने न केवल हर जगह मुद्रास्फीति बढ़ा दी (विशेष रूप से पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में) बल्कि उत्पादन करने की क्षमता को भी बाधित किया, इस प्रकार आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई। **क्या तेल की बढ़ती कीमतों के कारण भारत में मुद्रास्फीतिजनित मंदी का खतरा है?** • इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि यदि तेल की कीमतें अधिक और लंबे समय तक बनी रहती हैं, तो मुद्रास्फीति की स्थिति काफी खराब हो जाएगी और यह पहले से ही बढ़ी हुई कीमतों और कम आय के दो साल बाद आएगा। • दूसरी आवश्यकता विकास को रोकना है यह एक संकेतक बेरोजगारी है। भारत पिछले पांच दशकों में सबसे तीव्र बेरोजगारी संकट का सामना कर रहा है। • यह तर्क दिया जा सकता है कि हम निकट भविष्य में मुद्रास्फीतिजनित मंदी की ओर देख रहे हैं।
देखभाल सेवाओं में निवेश 2035 तक महिलाओं के लिए 234 मिलियन रोजगार पैदा कर सकता है	**संदर्भ:** इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन (ILO) ने 'केयर एट वर्क: इन्वेस्टिंग इन केयर लीव एंड सर्विसेज फॉर ए मोर जेंडर-इक्वल वर्ल्ड ऑफ वर्क' शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट राष्ट्रीय कानूनों और देखभाल नीतियों, अर्थात् मातृत्व सुरक्षा, पितृत्व, माता-पिता और अन्य देखभाल से संबंधित छुट्टी नीतियों के साथ-साथ चाइल्डकैअर और दीर्घकालिक देखभाल सेवाओं के बारे में एक वैश्विक अवलोकन प्रदान करती है। • संयुक्त राष्ट्र की श्रम एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से 234 मिलियन (78 प्रतिशत) महिलाओं को मिलेगी। • रिपोर्ट के अनुसार, रोजगार दर महिलाओं की संख्या में कुल मिलाकर 10 प्रतिशत अंक की वृद्धि होगी, यूरोप में नौ प्रतिशत अंक और एशिया में निम्न-मध्यम और निम्न-आय वाले देशों से लेकर अरब राज्यों में 12 प्रतिशत अंक तक, पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक। • वर्ष 2035 तक यह रोजगार सृजन क्षमता चाइल्डकैअर में 96 मिलियन प्रत्यक्ष नौकरियों, दीर्घकालिक देखभाल में 136 मिलियन प्रत्यक्ष नौकरियों और गैर-देखभाल क्षेत्रों में 67 मिलियन अप्रत्यक्ष नौकरियों से प्रेरित होगी और इसके लिए $5.4 ट्रिलियन के वार्षिक निवेश की आवश्यकता होगी।

	आईएलओ की रिपोर्ट ● देखभाल सेवाओं और नीतियों में लगातार एवं महत्वपूर्ण अंतर के कारण करोड़ों श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा और समर्थन के बिना पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ छोड़ दिया गया है। ● रिपोर्ट में पाया गया कि प्रजनन आयु की हर दस में से तीन महिलाएं या 649 मिलियन महिलाएं उन 82 देशों में रहती हैं जो ILO कन्वेंशन को पूरा नहीं करते हैं। कन्वेंशन सामाजिक बीमा या सार्वजनिक निधियों द्वारा वित्त पोषित पिछली कमाई के कम से कम दो-तिहाई पर न्यूनतम मातृत्व अवकाश के 14 सप्ताह को अनिवार्य करता है। **मातृत्व अवकाश सुविधा** ● 14 सप्ताह से कम मातृत्व अवकाश अवधि वाले देशों में रहने वाली संभावित माताओं का अनुपात अफ्रीका (23 देशों) में 51.9 प्रतिशत, अमेरिका में 55.8 प्रतिशत (18 देशों) और एशिया और प्रशांत क्षेत्र (15 देशों) में 17.5 प्रतिशत है। ● यूरोप और मध्य एशिया में, सभी संभावित माताएँ कम से कम 14 सप्ताह के मातृत्व अवकाश प्रदान करने वाले देशों में रहती हैं। ● विश्व स्तर पर, 123 देश पूरी तरह से भुगतान किए गए मातृत्व अवकाश की पेशकश करते हैं, इन देशों में रहने वाली 10 में से नौ संभावित माताएं हैं। ● रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अध्ययन के लिए विश्लेषण किए गए 185 देशों में न्यूनतम मातृत्व अवकाश अधिकार प्राप्त करने में कम से कम 46 साल लगेंगे। **दीर्घकालिक देखभाल सेवा सुविधा** गरिमा और स्वतंत्र जीवन में स्वस्थ उम्र बढ़ने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक देखभाल सेवाएं भी आवश्यक हैं। ● विश्व स्तर पर, 179 में से केवल 89 देशों में वृद्ध व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक दीर्घकालिक देखभाल सेवाओं का वैधानिक प्रावधान है। ● रिपोर्ट में सार्वभौमिक पहुंच के आधार पर देखभाल नीतियों का एक परिवर्तनकारी पैकेज बनाने के लिए एक मजबूत निवेश मामला पाया गया जो काम की एक बेहतर और अधिक लैंगिक-समान (gender-equal) दुनिया के निर्माण के लिए एक सफल मार्ग तैयार करेगा। **आगे की राह** ● ज्ञान, डेटा और जागरूकता का निर्माण ● देखभाल नीतियों और सेवाओं को डिजाइन और कार्यान्वित करना ● लागत देखभाल नीतियां और सेवाएं ● प्रतिनिधित्व और सामाजिक संवाद को मजबूत बनाना
फीचर फोन के लिए नए UPI123Pay	**संदर्भ:** 8 मार्च को, भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए 'यूपीआई123पे' (UPI123Pay) नामक एक नया यूपीआई भुगतान समाधान लॉन्च किया। 2016 में लॉन्च किया गया एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई), देश में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों में से एक बन गया है। ● चालू वर्ष में UPI लेनदेन की मात्रा पहले ही ₹76 लाख करोड़ तक पहुंच गई है, जबकि वित्त वर्ष 21 में यह ₹41 लाख करोड़ थी। ● UPI का पूरा नाम एकीकृत भुगतान इंटरफेस (Unified Payments Interface) है। **यूपीआई के बारे में** • UPI एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, यह सिस्टम मोबाइल प्लेटफार्म के द्वारा एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में तुरंत ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। • UPI पेमेंट प्लेटफॉर्म की शुरुआत 2016 में हुई थी। • तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) प्लेटफॉर्म के आधार पर चौबीसों घंटे 24*7 और 365 दिनों में मोबाइल डिवाइस के माध्यम से तत्काल धन हस्तांतरण। • यूपीआई पूरी तरह से इंटरऑपरेबल है और इस तरह यह विश्व में अद्वितीय है, जहां आपके पास 'भेजें' और 'प्राप्त'

पक्ष पर एक इंटरऑपरेबल सिस्टम है।

- **द्वारा विकसित:** भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) आरबीआई के मार्गदर्शन में।

यूपीआई का महत्व

- इसने सभी स्रोतों और धन के प्राप्तकर्ताओं (उपभोक्ताओं, व्यवसायों, फिनटेक, वॉलेट, 140 सदस्य बैंकों) के बीच अंतर-संचालन क्षमता का निर्माण किया।
- फिएट मनी में केंद्रीय बैंक के अंदर तुरंत बसे - उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लिए सुविधा और
- धूमिल डेटा एकाधिकार (Blunted data monopolies) - बड़ी तकनीकी फर्मों के पास मजबूत स्वायत्तता है लेकिन ग्राहक डेटा पर कमजोर प्रत्ययी जिम्मेदारियां हैं)।

यूपीआई की चुनौतियां

- कई संरचनात्मक और तकनीकी चुनौतियों में साइबर-धोखाधड़ी, लेनदेन, संचार अवसंरचना, जागरूकता आदि शामिल हैं।
- वर्तमान में यूपीआई तक प्रभावी पहुंच बड़े पैमाने पर स्मार्टफोन के माध्यम से उपलब्ध है।

नया साधन (UPI123) कैसे काम करता है?

- नई UPI-आधारित सेवा को देश में बड़ी संख्या में फीचर फोन मोबाइल ग्राहकों के लिए डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसकी अनुमानित संख्या 40 करोड़ से अधिक है।
- ऐसे उपयोगकर्ता पहले यूएसएसडी आधारित प्रक्रिया के माध्यम से *99# के शॉर्ट कोड का उपयोग करके डिजिटल लेनदेन प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकते थे, जो कि आरबीआई के अनुसार लोकप्रिय नहीं है।
  - यूएसएसडी-आधारित मोबाइल बैंकिंग का उपयोग फंड ट्रांसफर, अकाउंट बैलेंस चेक करने, बैंक स्टेटमेंट जेनरेट करने आदि के लिए किया जा सकता है।
  - नवोन्मेषी *99# भुगतान सेवा का मुख्य उद्देश्य समाज के कम बैंकिंग सुविधा वाले और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के वित्तीय समावेशन की अनुमति देना एवं उन्हें मुख्यधारा की बैंकिंग में एकीकृत करना है।
- यूएसएसडी-आधारित प्रक्रिया को बोझिल माना जाता है, जिसमें उपयोगकर्ताओं को कई संदेश भेजने होते हैं और इसके लिए शुल्क लिया जाता है, तथा यह सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा समर्थित नहीं होता है।
- फीचर फोन में यूपीआई सुविधा का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को सबसे पहले अपने बैंक खाते को मोबाइल नंबर से लिंक करना होगा। उपभोक्ता को अपने डेबिट कार्ड के विवरण के जरिये अपना यूपीआई पिन जेनरेट करना होगा। इसके बाद ही भुगतान कर सकेंगे।
- एक बार जब वे इस प्रारंभिक प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं, तो उपयोगकर्ता चार अलग-अलग भुगतान विकल्पों में से एक के माध्यम से नई UPI सुविधा का उपयोग करने में सक्षम होंगे, जिसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है।

उपयोगकर्ता इंटरनेट के बिना भुगतान कैसे करेंगे?

- UPI123Pay सेवा उपयोगकर्ताओं के लिए सेवाओं को शुरू करने और निष्पादित करने के लिए एक तीन-चरणीय विधि है, जो उन फोन पर काम करेगी जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन का विकल्प नहीं है।
- फीचर फोन उपयोगकर्ता इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना भुगतान करने के लिए चार विकल्पों का लाभ उठा सकते हैं:
  - इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर)
  - ऐप-आधारित कार्यक्षमता
  - मिस्ड कॉल सुविधा
  - निकटता ध्वनि-आधारित भुगतान
- आईवीआर विकल्प का उपयोग करते हुए, उपयोगकर्ताओं को अपने फीचर फोन से एक पूर्व निर्धारित आईवीआर नंबर पर एक सुरक्षित कॉल शुरू करने और धन हस्तांतरण, मोबाइल रिचार्ज, ईएमआई पुनर्भुगतान, शेष राशि, चेक और अन्य जैसे वित्तीय लेनदेन शुरू करने में यूपीआई ऑन-बोर्डिंग औपचारिकताओं को पूरा करने की आवश्यकता होगी।
- मिस्ड कॉल सुविधा से उपयोगकर्ता अपने बैंक खाते तक पहुंच सकते हैं और मर्चेंट आउटलेट पर प्रदर्शित नंबर

	पर मिस्ड कॉल देकर नियमित लेनदेन जैसे प्राप्त करना, धन हस्तांतरित करना, नियमित खरीदारी, बिल भुगतान आदि कर सकते हैं। ग्राहक को UPI पिन डालकर लेनदेन को प्रमाणित करने के लिए एक इनकमिंग कॉल प्राप्त होगी। • वे अपने फीचर फोन पर एक ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसके माध्यम से स्मार्टफोन पर उपलब्ध कई यूपीआई फ़ंक्शन उनके फीचर फोन पर उपलब्ध होंगे, स्कैन और भुगतान सुविधा को छोड़कर, जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। • अंत में, वे निकटता ध्वनि-आधारित भुगतान विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, जो किसी भी डिवाइस पर संपर्क रहित, ऑफ़लाइन और निकटता डेटा संचार को सक्षम करने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है। • उपयोगकर्ता अपने दोस्तों और परिवार को भुगतान करने, अपने उपयोगी बिलों का भुगतान करने, फास्टैग्स को रिचार्ज करने, मोबाइल बिलों का भुगतान करने और अपने खाते की शेष राशि की जांच करने में सक्षम होंगे। **क्या अन्य देशों में भी कुछ ऐसा ही है?** • मोबाइल भुगतान प्रणालियाँ जो इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भर नहीं हैं जैसे यूएसएसडी या एसएमएस तकनीक पर आधारित हैं, ये कई साल पहले शुरू की गई थीं और अभी भी कुछ विकासशील देशों में उपयोग की जा रही हैं। • वास्तव में, विश्व स्तर पर प्रमुख मोबाइल भुगतान प्रणालियों में से एक को वोडाफोन के केन्याई सहयोगी, सफ़ारीकॉम द्वारा वर्ष 2007 में पेश किया गया था। • एम-पेसा, जो अफ्रीका की अग्रणी मोबाइल मनी सेवा है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मिस्र, घाना, केन्या, लेसोथो में संचालित होती है, वोडाफोन के अनुसार मोजाम्बिक और तंजानिया, 51 मिलियन ग्राहक सेवा के माध्यम से प्रति वर्ष लेनदेन में 314 बिलियन डॉलर से अधिक कमाते हैं। **निष्कर्ष** UPI123Pay का शुभारंभ UPI के तहत सुविधाओं को समाज के उस वर्ग के लिए सुलभ बनाता है जिसे अब तक डिजिटल भुगतान परिदृश्य से बाहर थे। इस तरह, यह हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे रहा है।
परमाणु ऊर्जा: गुमराह नीति (Nuclear Energy: Misguided Policy)	**संदर्भ:** 15 दिसंबर, 2021 को भारत सरकार ने संसद को सूचित किया कि वह "फ्लीट मोड में 10 स्वदेशी रिएक्टर" बनाने की योजना बना रही है और फ्रांस, अमेरिका एवं रूस से आयात किए जाने वाले 24 सहित 28 अतिरिक्त रिएक्टरों के लिए "सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन" प्रदान किया था। • फुकुशिमा के बाद परमाणु उद्योग में वैश्विक और राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को देखते हुए, ऐसी नीति दिशाहीन लगती है। **फुकुशिमा परमाणु आपदा क्या थी?** • फुकुशिमा पावर प्लांट के परमाणु रिएक्टर की इमारत 11 मार्च 2011 में आए भूकंप और सुनामी के बाद हुए हाइड्रोजन विस्फोट में तबाह हो गई थी। • सुनामी ने रिएक्टरों के कूलिंग सिस्टम को तहस-नहस कर दिया था जिससे तीन रिएक्टर पिघल गए थे। इसके बाद पिघले हुए रिएक्टरों को ठंडा करने के लिए दस लाख टन से ज़्यादा पानी का उपयोग किया गया था। **परमाणु ऊर्जा की ओर भारत का प्रयास पथभ्रष्ट क्यों है?** • **अधिक पूंजी :** परमाणु ऊर्जा संयंत्र में अधिक पूंजी की आवश्कता होगी हैं इसमें अरबों डॉलर के निवेश करने पड़ेंगे। • **लागत में वृद्धि:** हाल के परमाणु निर्माणों को बड़ी लागत का सामना करना पड़ा है। उदाहरण: वी.सी. दक्षिण कैरोलिना (यू.एस.) में ग्रीष्मकालीन परमाणु परियोजना जहां लागत इतनी तेजी से बढ़ी कि 9 अरब डॉलर से अधिक के खर्च के बाद परियोजना को छोड़ दिया गया। • **सस्ता विकल्प:** वैकल्पिक अक्षय-ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की लागत में भारी कमी आई है। ट्रांसमिशन लागत को छोड़कर परमाणु ऊर्जा की लागत कम से कम ₹15 प्रति यूनिट है। इसके विपरीत, सौर ऊर्जा अब ₹2.14 प्रति यूनिट की दर से उपलब्ध कराई जा रही है। (स्टोरेज के साथ ₹4.30 प्रति यूनिट)। ○ यदि परमाणु बिजली को प्रतिस्पर्धी दर पर बेचा जाना है, तो उसे भारत सरकार द्वारा बहुत अधिक सब्सिडी देनी होगी, जो भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम के माध्यम से सभी परमाणु संयंत्रों का संचालन करती है।

	• **वैश्विक प्रवृत्ति के विरुद्ध:** 1996 में, दुनिया की 17.5% बिजली परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से आती थी; 2020 तक यह आंकड़ा घटकर महज 10% रह गया था। ○ विदित हो कि वर्ष 2008 में, यू.एस. सरकार ने 2030 तक परमाणु क्षमता के 114.9 गीगावाट तक विस्तार का अनुमान लगाया था; और 2021 में इन्होनें भविष्यवाणी की कि क्षमता 83.3 गीगावाट हो जाएगी। • **भारत-अमेरिका परमाणु समझौते की विफलता:** वर्ष 2010 में सरकार ने भविष्यवाणी की थी कि वर्ष 2020 तक भारत में परमाणु क्षमता 35 गीगावाट तक पहुंच जाएगी (आज स्थापित क्षमता केवल 6.78 गीगावाट है)। इस तरह के लक्ष्य इस उम्मीद पर आधारित थे कि भारत-यू.एस. असैन्य परमाणु समझौता। लेकिन, इस सौदे से एक भी नए परमाणु संयंत्र की स्थापना नहीं हुई है। • **परमाणु आपदा की उच्च लागत:** एक परमाणु आपदा भूमि के बड़े हिस्से को निर्जन छोड़ सकती है - जैसे चेरनोबिल और फुकुशिमा में, जहां आई आपदा को हटाने के लिए लागत $ 600 बिलियन से अधिक हो सकती है। • **आपूर्तिकर्ता की देनदारियां:** परमाणु आपूर्तिकर्ताओं के आग्रह से सुरक्षा के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं कि उन्हें भारत में किसी भी दुर्घटना के परिणाम के लिए दायित्व की क्षतिपूर्ति की जाए। • **जलवायु संबंधी चिंताएं:** परमाणु ऊर्जा जलवायु परिवर्तन के लिए "अनुकूल" होने का सही विकल्प नहीं है, जिसके लिए विद्युत प्रणालियों में लचीलेपन की आवश्यकता होती है। वर्ष 2020 में, एक आंधी के कारण अमेरिका में डुआने अर्नोल्ड परमाणु संयंत्र का संचालन बंद हो गया। भविष्य में इस तरह की चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति बढ़ने की संभावना है। • यह भारत के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए भी उपयुक्त विकल्प नहीं है क्योंकि इसे आवश्यक पैमाने पर तैनात नहीं किया जा सकता है। • **स्थानीय विरोध:** फुकुशिमा दुर्घटना के बाद सुरक्षा चिंताओं ने प्रत्येक नियोजित रिएक्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। **निष्कर्ष** परमाणु रिएक्टरों की अंतर्निहित कमजोरियों और उनकी उच्च लागत को देखते हुए, सरकार के लिए यह सबसे अच्छा होगा कि वह परमाणु विस्तार के लिए अपनी योजनाओं को स्पष्ट रूप से रद्द कर दे।
रुपया-रूबल व्यापार व्यवस्था	**रुपया-रूबल व्यापार व्यवस्था क्या है?** • रुपया-रूबल व्यापार एक भुगतान तंत्र है जो भारतीय निर्यातकों को डॉलर या यूरो जैसी मानक अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के बजाय रूस को उनके निर्यात के लिए भारतीय रुपये में भुगतान करने की अनुमति देता है। • 'रुपया-रूबल व्यापार' एक भुगतान तंत्र है, जो भारतीय निर्यातकों को डॉलर या यूरो जैसी मानक अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के बजाय रूस को उनके निर्यात के लिये भारतीय रूपए में भुगतान करने की अनुमति दे सकता है। • इस व्यवस्था के तहत किसी रूसी बैंक को भारतीय बैंक में तथा भारतीय बैंक को रूस में अपना खाता खोलना होगा। • इसके लागू होने के पश्चात् दोनों पक्ष अपने-अपने खातों में स्थानीय मुद्राओं में एक निर्दिष्ट राशि की मुद्रा रखने के लिये पारस्परिक रूप से सहमत हो सकते हैं। • यदि निर्दिष्ट राशि 100 मिलियन डॉलर है, तो भारत में रूसी बैंक के खाते में उस राशि के रूपए होंगे जबकि रूस में भारतीय बैंक के खाते में उस राशि के रूबल होंगे। • एक बार भुगतान तंत्र लागू हो जाने पर, भारतीय निर्यातक को भारत में रूसी बैंक के खाते से रुपये में भुगतान किया जा सकता है और रूस से आयात का भुगतान रूस में भारतीय बैंक के खाते से रूबल के साथ किया जा सकता है। **क्या यह पहले प्रयास किया गया है?** • भारत ने रूस के साथ चाय जैसी कुछ वस्तुओं के लिये पहले बहुत छोटे पैमाने पर रूपया-रूबल भुगतान तंत्र का प्रयास किया है। किंतु यह सामान्य समय में हुआ है तथा बड़े व्यावसायिक स्तर पर कभी नहीं हुआ। • हालाँकि, रूपया-रियाल भुगतान तंत्र ने ईरान के साथ भारत के व्यापार में सफलता पूर्वक काम किया था, जब वर्ष

	2012 में पश्चिम द्वारा ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे। ○ भारत ने ईरान से अपनी तेल खरीद के लिये आंशिक रूप से भुगतान करने के लिये तंत्र का सफलतापूर्वक उपयोग किया था। ○ यह रणनीति कई वर्षों तक सफल रही, जब तक कि ट्रंप सरकार ने ईरान के साथ तेल व्यापार पर उत्पाद-विशिष्ट प्रतिबंध नहीं लगाया और भारत ने ईरान से इसकी खरीद बंद नहीं कर दी। **भारत के लिए रुपया-रूबल तंत्र कितना महत्वपूर्ण है?** ● भारत के लिये रूस के साथ एक वैकल्पिक भुगतान तंत्र होना महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका, यूरोपीय संघ और यू.के. ने कम से कम सात रूसी बैंकों की सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन (स्विफ्ट) तक पहुँच को अवरोधित किया है। ○ SWIFT एक वैश्विक सुरक्षित इंटरबैंक प्रणाली है, जो भुगतान निर्देशों को संप्रेषित करती है और दुनिया भर के सभी देशों के बैंकों के बीच लेनदेन को सक्षम बनाती है। ● भारतीय निर्यातकों द्वारा पहले से भेजे गए माल के लिये अनुमानित $500 मिलियन लंबित हैं तथा अब नियमित स्विफ्ट चैनल के माध्यम से भुगतान प्राप्त करना संभव नहीं है। ● चूँकि रूस के साथ लेनदेन अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं जैसे डॉलर या यूरो में नहीं किया जा सकता है, अतः रूपया भुगतान तंत्र भारतीय निर्यातकों को उनके भुगतान की स्थिति के साथ-साथ यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि रूस के साथ व्यापार जारी रहेगा या नहीं। **ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो सामने आ सकती हैं?** ● रूबल के मूल्य में उतार-चढ़ाव से रूपया-रूबल भुगतान तंत्र को लागू करना कठिन हो सकता है। ● सर्वप्रथम, रूपए और रूबल के बीच एक उचित विनिमय दर निर्धारित करना कठिन होगा। ● इसके अलावा, यदि रूबल का मूल्य तेज़ी से गिरता रहता है, तो भारत के साथ व्यापार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है क्योंकि भारतीय बैंक के रूसी खाते में रूबल का मूल्य कम हो जाएगा। ● ऐसी स्थिति में भारत को जोखिम उठाना पड़ सकता है। ● फिलहाल स्विफ्ट के इस्तेमाल के खिलाफ सिर्फ मंजूरी है। वस्तु विनिमय प्रणाली या रुपये-रूबल भुगतान तंत्र जैसे विकल्पों का उपयोग करके भारत को रूस के साथ व्यापार करने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। ● हालांकि, यदि प्रतिबंध उत्पाद-विशिष्ट हो जाते हैं, तो भारत के लिए इस व्यवस्था का उपयोग करना मुश्किल हो सकता है। **भारत के लिए रणनीतिक प्रभाव क्या हैं?** ● दुनिया इसे भारत द्वारा यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद प्रतिबंधों को दरकिनार करने की व्यवस्था के रूप में देखेगी। ● यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए रूस की आलोचना करने वाले सभी प्रस्तावों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में शामिल नहीं होने के कारण अमेरिका और यूरोपीय संघ पहले से ही भारत से नाखुश हैं। ● ऐसे में यदि भारत रूस को आर्थिक प्रतिबंधों के उल्लंघन करने में मदद करता है, तो उस पर रूस का पक्ष लेने का आरोप लग सकता है और यह पश्चिमी शक्तियों के साथ भारत के राजनयिक संबंधों को नुकसान पहुँचा सकता है।
करों का भुगतान करने के लिए नागरिकों की अनिच्छा को समझना	सरकार अपना पैसा कैसे खर्च करती है, इस पर धारणा करों का भुगतान करने के संबंध में नागरिकों के व्यवहार को प्रभावित करती है- ● लाभ-आधारित कराधान के शास्त्रीय सिद्धांत के समर्थकों ने लंबे समय से तर्क दिया है कि करों का भुगतान करने के लिए नागरिकों की इच्छा उन लाभों पर निर्भर करती है जो करदाताओं को अपने करों का भुगतान करने के बदले में प्राप्त होने की उम्मीद है। ● इस सिद्धांत के अनुसार, लोग करों का भुगतान करने के लिए अधिक इच्छुक हो सकते हैं यदि वे मानते हैं कि पैसा इस तरह से खर्च किया जाएगा जिससे उन्हें व्यक्तिगत रूप से लाभ हो। ● दूसरी ओर, यदि सरकारी खर्च से उन्हें सीधे लाभ होने की संभावना नहीं है, तो करदाताओं के अपने करों का भुगतान करने की संभावना कम होती है।

	• इसलिए कर जो विशुद्ध रूप से धन के पुनर्वितरण के उद्देश्य से हैं, वे बहुत से करदाताओं को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। **यूएस केस स्टडी** • एक शोध परियोजना में, चार अमेरिकी शोधकर्ताओं की एक टीम ने डलास काउंटी, यूएसए में 2,000 से अधिक घरों का अध्ययन किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि सरकार ने अपना पैसा कैसे खर्च किया, इस पर नई जानकारी के साथ संपत्ति करों का भुगतान करने की उनकी इच्छा कैसे बदलती है। • परिवार इस बारे में पूरी तरह से अवगत नहीं थे कि उनके द्वारा भुगतान किए गए संपत्ति कर उनके इलाकों में सार्वजनिक शिक्षा के वित्तपोषण के लिए कैसे गए। • जब परिवारों को सूचित किया गया कि उनकी सरकार ने सार्वजनिक शिक्षा के वित्तपोषण के लिए उनके करों का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया है, तो उनके व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। • यह पाया गया कि जिन नागरिकों के बच्चे पब्लिक स्कूलों में गए, वे अपने करों का भुगतान करने के लिए अधिक इच्छुक थे और अदालतों में अपने कराधान की अपील करने की संभावना कम थी। हालाँकि, सार्वजनिक शिक्षा का लाभ नहीं उठाने वाले नागरिकों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ। • इस अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि लोग करों का भुगतान करने के लिए तैयार थे जब उन्हें एहसास हुआ कि वे इससे व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित हो रहे थे। **यह अध्ययन भारत के लिए क्या सबक है?** • इस अध्ययन के निष्कर्ष भारत जैसे देशों के लिए सबक ले सकते हैं जहां कर चोरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस तथ्य के कारण है कि नागरिकों को यह नहीं लगता है कि वे करों के लिए सरकार से पर्याप्त लाभ प्राप्त करते हैं। • लोगों को करों का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक तरीका यह होगा कि यह जानकारी दी जाए कि सरकार द्वारा कर राजस्व कैसे खर्च किया जा रहा है और यह नागरिकों के लिए अधिक सुलभ है। • यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को विभिन्न उद्देश्यों (जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क आदि) के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करनी चाहिए, जिसके लिए कर संग्रह निर्धारित किया जाएगा।
राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम	**संदर्भ:** पिछले हफ्ते, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और अन्य सरकारी एजेंसियों की अधिशेष भूमि जोत का मुद्रीकरण करने के लिए एक राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के निर्माण को मंजूरी दी। **भूमि मुद्रीकरण निगम बनाने से क्या लाभ हैं?** • **भूमि का डेटाबेस:** देश भर में राज्य की भूमि जोत की एक विस्तृत और व्यापक सूची तैयार की जाएगी। • **निवेशक हितैषी:** भौगोलिक पहचानकर्ताओं के साथ उचित रूप से चिह्नित भूमि पार्सल, स्पष्ट रूप से सीमांकित सीमाएं, और अच्छी तरह से स्थापित शीर्षक की वैधता, निजी निवेशकों को अधिक स्पष्टता एवं निश्चितता प्रदान करेगी। इससे संभावित निवेशकों का डेटाबेस तैयार करने में मदद मिलेगी। • **परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग:** एक इकाई के तहत अप्रयुक्त/उपयोग की गई भूमि के बड़े हिस्से को मिलाने से अधिक कुशल मुद्रीकरण अभियान और इन परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग होगा। उदाहरण के लिए: रेलवे के पास उपलब्ध कुल खाली भूमि लगभग 1.25 लाख एकड़ अनुमानित है। • **सरकारी राजस्व में वृद्धि:** इन परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से होने वाली आय से अतिरिक्त संसाधन उत्पन्न करने में मदद मिलेगी, सरकारी खजाने को बढ़ावा मिलेगा। • **भूमि की कीमतों को कम करने में मदद करना :** अधिशेष भूमि की नीलामी से भूमि की आपूर्ति में वृद्धि होगी, जो कुछ क्षेत्रों में मौजूद भूमि की "कृत्रिम" कमी के मुद्दे को संबोधित करती है। यह कीमतों को कम कर सकता है और इस प्रकार परियोजनाओं की लागत पर एक मध्यम प्रभाव पड़ेगा। • **विशेष एजेंसी की आवश्यकता होना:** भूमि मुद्रीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए "बाजार अनुसंधान, कानूनी उचित परिश्रम, मूल्यांकन, मास्टर प्लानिंग, निवेश बैंकिंग और भूमि प्रबंधन" जैसे क्षेत्रों में "विशेष कौशल और विशेषज्ञता" की आवश्यकता होती है। विशेष कौशल वाली एक समर्पित संस्था इस कार्य के लिए बेहतर अनुकूल है। **इस निगम को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?**

	● **घोषित करने में अनिच्छा:** अधिशेष भूमि का अनुमान एक विवादास्पद मुद्दा हो सकता है। मंत्रालय, विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं भूमि पार्सल को "अधिशेष" के रूप में सीमांकित करने के लिए अनिच्छुक हो सकती हैं। ● **कानूनी-प्रशासनिक चुनौतियाँ:** निगम को स्पष्ट शीर्षकों की अनुपस्थिति, चल रहे मुकदमे, और शांत निवेशक हित जैसे मुद्दों से जूझना होगा। साथ ही सरकारी जमीन पर कब्जा करने का भी मामला सामने आया है। **निष्कर्ष** हालांकि इस मुद्रीकरण अभियान से अधिक कुशल परिणाम सामने आने चाहिए, लेकिन यह आम लोगों के प्रबंधन पर सवाल उठाता है, और क्या राज्य द्वारा सार्वजनिक भूमि के अधिक प्रभावी प्रबंधन द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य की बेहतर देखभाल की जा सकती है।
बेरोजगारी लाभ ढूँढना (Finding Unemployment Benefits)	**संदर्भ:** COVID-19 से पहले भी, बेरोजगारी दर 2017-18 में 6.1% पर चरम पर पहुंच गई थी। ● सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार, औसत शहरी बेरोजगारी दर वर्ष 2021 में 9.04% और जनवरी-फरवरी 2022 में 7% से अधिक रही। ● इस बीच, जून 2021 (8.75%) के बाद से लगभग 5-7% के मामूली उतार-चढ़ाव के बाद फरवरी 2022 में ग्रामीण बेरोजगारी दर बढ़कर 8.35% हो गई। **क्या बेरोजगारी राहत की संतोषजनक व्यवस्था मौजूद है?** ● चीन के विपरीत, श्रम कानून स्पष्ट रूप से बेरोजगारी लाभ प्रदान नहीं करते हैं। हालाँकि, भारत में विभिन्न पहल हैं जो बेरोजगारी राहत प्रदान करती हैं **1. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (ईएसआईए), 1948** ● उक्त अधिनियम के तहत, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना (आरजीएसकेवाई) अनैच्छिक रूप से बेरोजगार बीमित व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करती है जिन्होंने ईएसआई में दो साल के लिए योगदान दिया है। ● नकद राहत पहले 12 महीनों के लिए अंतिम औसत दैनिक मजदूरी के 50% और अगले 12 महीनों के लिए 25% की दर से है। ● इसमें छँटनी, बंद होने या स्थायी अपंगता के कारण होने वाली बेरोजगारी को कवर किया जाता है। ● इसमें छंटनी, बंद होने या स्थायी अमान्यता के कारण बेरोजगारी शामिल है। **2. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY)** ● इसे वर्ष 2018 में पेश किया गया था जिसके तहत बेरोजगार बीमित व्यक्तियों को दावेदार की औसत प्रतिदिन की कमाई के 50% की दर से भत्ता प्रदान किया जाता है। ● यह भत्ता 90 दिनों के लिए प्रदान किया जाता है। ● इसे दो साल के लिए पायलट आधार पर लॉन्च किया गया था लेकिन COVID-19 अवधि के दौरान इसे बढ़ा दिया गया। **3. औद्योगिक विवाद अधिनियम (आईडीए), 1947** ● 100 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बंद होने के कारण नौकरी खोने के मामले में श्रमिकों को सेवा के पूरे वर्षों के लिए औसत वेतन के 15 दिनों के छंटनी मुआवजे का भुगतान करना होगा। ● यहां बेरोजगारी भत्ते का भार नियोक्ता पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। निर्माण और सेवाओं जैसे रोजगार प्रधान उद्योगों को बाहर रखा गया है। **4. सामाजिक सुरक्षा संहिता (एसएससी), 2020** ● हालांकि एसएससी ने 'सामाजिक सुरक्षा' की अपनी परिभाषा में बेरोजगारी संरक्षण को शामिल किया, लेकिन इसके लिए कोई योजना प्रदान नहीं की। ● सरकार ने तर्क दिया कि ईएसआई अधिनियम के तहत पहले से ही बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है और इसलिए अलग योजना की कोई जरुरत नहीं है। ● एसएससी असंगठित श्रमिकों को योजनाओं का अस्पष्ट वादा प्रदान करता है। **क्या उपरोक्त योजनाएँ सफल रही हैं?** ● ईएसआईए, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम (20 या अधिक श्रमिकों) की तुलना में 10 या अधिक श्रमिकों के

	अधिक समावेशी कवरेज के बावजूद, भारत में जिलों के सीमित और धीमी गति से विस्तार के कारण कम श्रमिकों को कवर करता है। ● आरजीएसकेवाई के तहत, 2007-08 से 2019-20 के दौरान 0.043% (13,341/3,09,66,930) कर्मचारियों ने बेरोजगारी भत्ता प्राप्त किया ● इसके अलावा, ईएसआईसी के कुल नकद व्यय में बेरोजगारी भत्ते का हिस्सा 0.25% से 0.99% के बीच था। अविश्वसनीय रूप से कम उठान का मतलब है कि आरजीएसकेवाई सफल नहीं है। ● एबीवीकेवाई के तहत, 1 जुलाई, 2018 से 31 मार्च, 2020 तक 120 दावे किए गए, जिसका मतलब ₹73.33 की मामूली औसत दैनिक नकद राहत । **क्या वैकल्पिक उपाय किए जा सकते हैं?** ● नियोक्ताओं, श्रमिकों और सरकार द्वारा त्रिपक्षीय योगदान के साथ एक सार्वभौमिक बेरोजगारी भत्ता योजना प्रदान करने के लिए एसएससी में संशोधन किया जाना चाहिए। ● शहरी श्रम बाजार में श्रमिकों की पीड़ा को कम करने के लिए एक शहरी रोजगार गारंटी योजना तैयार की जानी चाहिए। कानून और कल्याणकारी योजनाओं को हाशिए पर पड़े कामगारों को राहत देनी चाहिए जो कई आघातों से जूझ रहे हैं।
वैश्विक अनिश्चितताएं, भारत की विकास संभावनाएं	**संदर्भ:** 28 फरवरी, 2022 को, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने 2021-22 की तीसरी तिमाही के लिए भारत का जीडीपी डेटा 2021-22 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान (एसएई) के साथ जारी किया। **भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास प्रदर्शन क्या रहा है?** ● 2020-21 के COVID-19 वर्ष में, वास्तविक जीडीपी और जीवीए दोनों में क्रमशः माइनस 6.6% और माइनस 4.8% की कमी आई। ● एनएसओ का एसएई यह दर्शाता है कि वर्ष 2021-22 में वास्तविक जीडीपी और जीवीए वृद्धि क्रमशः 8.9% और 8.3% तक ठीक होने का अनुमान है। ● इस सुधार के बावजूद, 2021-22 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का परिमाण ₹147.7 लाख करोड़ है, जो 2019-20 में ₹145.2 लाख करोड़ के इसी स्तर से थोड़ा अधिक है। ● मांग का पुनरुद्धार धीमा रहा है ○ 2021-22 में सभी मांग घटकों के परिमाण ने 2019-20 में अपने संबंधित स्तरों को पार कर लिया है। हालांकि, खपत और निवेश की मांग में वृद्धि – जैसा कि निजी अंतिम खपत व्यय (पीएफसीई) और सकल अचल पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) द्वारा 2021-22 में 2019-20 में मापा जाता है, क्रमशः केवल 1.2% और 2.6% है, जो देश में सुस्त पुनरुद्धार का सुझाव देता है। ○ 2021-22 में निर्माण क्षेत्र में विकास 2019-20 के मुकाबले केवल 1.9% था। ● पहली दो तिमाहियों में कुछ आधार प्रभावों को जारी रखने के लिए, 2022-23 में वार्षिक वृद्धि 7% से अधिक नहीं हो सकती है। **आने वाले दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या चुनौतियां हैं?** ● यूक्रेन में भू-राजनीतिक संघर्ष के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के प्रभाव के सटीक अनुमानों पर पहुंचना मुश्किल है, यह अनुमान लगाया गया है कि यूएस $ 10 / बैरल की वृद्धि से वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 0.27% की कमी आई है और सीपीआई मुद्रास्फीति में 0.40% की वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, 2022-23 के लिए विकास अनुमानों को घटाकर 6.3% कर दिया जाएगा (सीपीआई मुद्रास्फीति 6% के साथ)। ● साथ ही, पेट्रोलियम और उर्वरक सब्सिडी सहित पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों से जुड़े व्यय के कुछ घटकों में भी वृद्धि होगी। ● वैश्विक अनिश्चितताओं से उत्पन्न होने वाली अन्य आर्थिक चुनौतियों में रुपये के मूल्यह्रास के साथ उच्च आयात बिलों के कारण चालू खाते की शेष राशि का बिगड़ना शामिल हो सकता है। ○ 2019 में RBI के एक अध्ययन ने US$10/bbl के बाद चालू खाता घाटे (CAD) में वृद्धि का अनुमान लगाया था। वैश्विक कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.4%

	अंक। इस प्रकार, 2022-23 के लिए जीडीपी के 1.9% पर सीएडी के अनुमान को संशोधित करके 2.9% करना पड़ सकता है। • पेट्रोलियम उत्पादों जैसे उर्वरक, लोहा और इस्पात फाउंड्री, परिवहन, निर्माण और कोयले पर भारी मात्रा में आकर्षित करने वाले क्षेत्र प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे। • स्विफ्ट के माध्यम से लेन-देन बंद होने से रूस और यूक्रेन से आने-जाने वाले व्यापार में कुछ व्यवधान होगा। • वित्तीय प्रवाह के संबंध में कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी होंगे। अक्टूबर से दिसंबर 2021 के दौरान शुद्ध विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) बहिर्वाह बढ़कर 6.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। o इस अवधि के दौरान निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अंतर्वाह में भी गिरावट आई है, हालांकि वे सकारात्मक बने हुए हैं। • जैसे-जैसे विकसित देशों को अपनी ब्याज दरें बढ़ाने के लिए मजबूर किया जा रहा है (अपने स्वयं के मुद्रास्फीति के दबावों को नियंत्रित करने के लिए) यू.एस. डॉलर का बहिर्वाह बढ़ा है और इस प्रकार आरबीआई पर अपनी नीतिगत दर बढ़ाने का दबाव डाला जा रहा है। **आगे की राह** • नीति निर्माताओं को भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की ऊंची कीमतों का भार कौन वहन करता है, इस संबंध में एक महत्वपूर्ण विकल्प का प्रयोग करना पड़ सकता है o उपभोक्ता (ईंधन और मुद्रास्फीति की बढ़ी हुई लागत) o औद्योगिक उपयोगकर्ता (इनपुट लागत में वृद्धि) o तेल विपणन कंपनियाँ (कम लाभ) o सरकार (राजस्व में कमी और सब्सिडी का बोझ बढ़ा) • यदि विकास को पुनर्जीवित करना है, तो खपत वृद्धि को समर्थन देने और क्षमता उपयोग में सुधार लाने की दृष्टि से औद्योगिक आदानों की लागत को कम करने पर अधिकतम ध्यान दिया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी)	**संदर्भ:** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 मार्च को राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी), विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के निर्माण को मंजूरी दी, जिसे वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित किया था। **मुद्रीकरण का क्या अर्थ है?** • जब सरकार अपनी संपत्ति का मुद्रीकरण करती है, तो इसका मतलब है कि वह एक निर्दिष्ट अवधि के लिए एक निजी प्रतिनिधि को संपत्ति के राजस्व अधिकार (निष्क्रिय भूमि, बुनियादी ढांचा, सार्वजनिक उपक्रम हो सकता है) को हस्तांतरित कर रही है। • ऐसे लेनदेन में सरकार को बदले में मिलता है o निजी संस्था से अग्रिम भुगतान o संपत्ति से उत्पन्न राजस्व का नियमित हिस्सा o परिसंपत्ति में स्थिर निवेश का वादा o मुद्रीकृत संपत्ति पर शीर्षक अधिकार बनाए रखना। • सरकारी संपत्तियों का मुद्रीकरण करने के कई तरीके हैं; कार्यालयों जैसे कुछ स्थानों के भूमि मुद्रीकरण के मामले में, यह एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) के माध्यम से किया जा सकता है - एक कंपनी जो भूमि संपत्ति का मालिक है और इसे संचालित करती है और कभी-कभी, आय-उत्पादक अचल संपत्ति को धन देती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के जरिए सरकार की संपत्ति का मुद्रीकरण भी किया जा सकता है। • सरकार निम्नलिखित कारणों से अपनी संपत्ति का मुद्रीकरण करती है o सरकार के लिए राजस्व के नए स्रोत बनाना o संस्थागत निवेशकों या निजी खिलाड़ियों को शामिल करके अप्रयुक्त या कम उपयोग की गई संपत्ति की क्षमता को अनलॉक करना o भविष्य की संपत्ति के निर्माण के लिए संसाधन या पूंजी उत्पन्न करना, जैसे कि मुद्रीकरण से उत्पन्न धन का उपयोग नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बनाने के लिए करना।

NLMC क्या है और यह क्या करेगी?

- राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम, सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक फर्म होगी, जो अधिशेष, अप्रयुक्त या अप्रयुक्त भूमि संपत्ति के रूप में सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति का मुद्रीकरण करेगी।
- यह वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आएगा और इसे ₹5,000 करोड़ की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी और ₹150 करोड़ की चुकता पूंजी के साथ स्थापित किया जाएगा।
- निगम इन भूमि जोतों के मूल्य को अनलॉक करने के उद्देश्य से उन सार्वजनिक उपक्रमों की संपत्तियों के मुद्रीकरण की सुविधा भी प्रदान करेगा जो परिचालन बंद कर चुके हैं या रणनीतिक विनिवेश के लिए लाइन में हैं।
- ऐसे उद्यमों की अधिशेष भूमि और भवन संपत्ति एनएलएमसी को हस्तांतरित किए जाने की उम्मीद है, जो तब उन्हें धारण, प्रबंधन और मुद्रीकृत करेगी।
- प्रबंधन और मुद्रीकरण के अतिरिक्त एनएलएमसी एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगा और अन्य सरकारी संस्थाओं एवं सीपीएसई को उनकी अधिशेष गैर-प्रमुख संपत्तियों की पहचान करने और उनका मुद्रीकरण करने में सहायता करेगा।

NLMC होने के क्या गुण हैं?

- एनएलएमसी की स्थापना से सीपीएसई को बंद करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी और रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया आसान होगी।
- यह गति में स्थापित करके इन कम उपयोग की गई संपत्तियों के उत्पादक उपयोग को भी सक्षम करेगा
  - निजी क्षेत्र का निवेश
  - नई आर्थिक गतिविधियाँ जैसे औद्योगीकरण
  - रोजगार पैदा करके स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना
  - संभावित आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए वित्तीय संसाधन पैदा करना।

एनएलएमसी कैसे काम करेगा?

- फर्म राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष (एनआईआईएफ) एवं इन्वेस्ट इंडिया जैसी अन्य विशिष्ट सरकारी कंपनियों के समान योग्यता आधारित दृष्टिकोण के साथ निजी क्षेत्र के पेशेवरों को नियुक्त करेगी।
- ऐसा इसलिए है क्योंकि अचल संपत्ति के परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए संपत्ति के मूल्यांकन, बाजार अनुसंधान, निवेश बैंकिंग, भूमि प्रबंधन, कानूनी परिश्रम और अन्य संबंधित कौशल सेट में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
- एनएलएमसी एक एजेंसी के रूप में मुद्रीकरण करेगा और भूमि मुद्रीकरण में सर्वोत्तम प्रथाओं की निर्देशिका के रूप में कार्य करने की उम्मीद है।

मुद्रीकरण के लिए वर्तमान में कितनी भूमि उपलब्ध है?

- आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 के अनुसार, अब तक सीपीएसई ने संभावित मुद्रीकरण के लिए लगभग 3,400 एकड़ जमीन को टेबल पर रखा है। उन्होंने इस जमीन को निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) को भेज दिया है।
- सर्वेक्षण के अनुसार, एमटीएनएल, बीएसएनएल, बीपीसीएल, बी एंड आर, बीईएमएल, एचएमटी लिमिटेड, इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड आदि जैसे सार्वजनिक उपक्रमों की गैर-प्रमुख संपत्तियों का मुद्रीकरण विभिन्न चरणों में है।
- उदाहरण के लिए, मार्च 2020 में, बीएसएनएल ने मुद्रीकरण के लिए कुल ₹24,980 करोड़ मूल्य की संपत्तियों की पहचान की थी।
- रेलवे के पास 11 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन उपलब्ध है, जिसमें से 1.25 लाख एकड़ जमीन खाली है।
- रक्षा मंत्रालय के पास 17.95 लाख एकड़ जमीन है। इसमें से लगभग 1.6 लाख एकड़ 62 सैन्य छावनियों के अंदर आता है जबकि 16 लाख एकड़ से अधिक छावनी की सीमाओं के बाहर है।

NLMC के लिए संभावित चुनौतियाँ क्या हैं?

1. सरकारी विनिवेश प्रदर्शन पर निर्भर करता है

- एनएलएमसी का प्रदर्शन और उत्पादकता उसके विनिवेश लक्ष्यों पर सरकार के प्रदर्शन पर भी निर्भर करेगी।

	• वित्त वर्ष 2021-22 में, सरकार विनिवेश के विभिन्न रूपों के माध्यम से अभी तक 12,423.67 रुपये करोड़ जुटाने में सफल रही है। • बजट 2021-22 में, सरकार ने शुरू में 1.75 लाख करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य निर्धारित किया था जिसे बाद में घटाकर 78,000 करोड़ रुपये कर दिया गया था। • जीवन बीमा निगम का आईपीओ, जिसे 60,000 करोड़ रुपये जुटाना था, अब अनिश्चितता में डूबा हुआ है क्योंकि रूस-यूक्रेन संकट ने शेयर बाजारों को अस्थिर बना दिया है। • राज्य के स्वामित्व वाली वाहक एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया में भी काफी समय लगा और टाटा समूह के आने से पहले बातचीत हुई। **2. परिचालन चुनौतियां** • मुद्रीकृत भूमि संपत्तियों के लिए लाभदायक राजस्व धाराओं की पहचान करना, निजी खिलाड़ी द्वारा पर्याप्त निवेश सुनिश्चित करना और विवाद-समाधान तंत्र स्थापित करना भी महत्वपूर्ण कार्य हैं। • एक अन्य संभावित चुनौती के रूप में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) का मुद्रीकरण मॉडल के रूप में उपयोग करना होगा। • उदाहरण के लिए, रेलवे के लिए वर्ष 2020 में शुरू की गई केंद्र की पीपीपी पहल के परिणाम उत्साहजनक नहीं थे। • यह भारतीय रेलवे की 150 ट्रेनों को चलाने के लिए निजी पार्टियों को आमंत्रित किया था, लेकिन जब बोलियां लगाई गईं, तो ट्रेनों के नौ समूहों में कोई बोली लगाने वाला नहीं था, जबकि तीन समूहों के लिए केवल दो इच्छुक बोलीदाता थे। **4. प्रतिस्पर्धा की कमी** • कुछ गंभीर बोलीदाताओं की उपस्थिति भी कम प्रतिस्पर्धी स्थान की संभावना को जन्म देगी, जिसका अर्थ है कि कुछ निजी संस्थाएं अधिशेष सरकारी भूमि के संचालन में एकाधिकार बना सकती हैं। • उदाहरण के लिए, सवाल उठाए गए थे जब सरकार ने एक एकल इकाई के लिए बोली लगाने वाले हवाई अड्डों की संख्या को हटा दिया, जिसके परिणामस्वरूप अदानी समूह ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से ₹ 2,440 करोड़ के लिए छह शहर के हवाई अड्डों का कब्जा ले लिया।
$400 बिलियन डॉलर का निर्यात	**संदर्भ:** 21 मार्च को वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के आउटबाउंड शिपमेंट का मूल्य $400 बिलियन तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। • जब तक 31 मार्च को वर्ष समाप्त होता है, तब तक 10 अरब डॉलर मूल्य का अन्य माल बाहर भेज दिए जाने की उम्मीद है। • यह 2020-21 के महामारी-प्रभावित वर्ष से लगभग 41% की वृद्धि में बदल जाएगा, जिससे यह 2009-10 के बाद से भारत की सबसे तेज निर्यात वृद्धि दर बन जाएगी। **भारत के 400 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य की प्राप्ति कितनी महत्वपूर्ण है?** • आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, आउटबाउंड मर्चेंडाइज ट्रेड में गिरावट दर्ज की गई है o 2017-18 में $303.5 बिलियन o 2018-19 में $330.1 बिलियन o 2019-20 में $313.4 बिलियन • वर्ष 2021-22 कई वर्षों में पहली बार दर्शाता है कि देश ने की चुनौतियों के बावजूद अपने निर्यात लक्ष्य को पूरा किया है o महामारी के कारण आपूर्ति में व्यवधान o शिपिंग कंटेनरों की चुनौतीपूर्ण कमी o मालभाड़ा दरों में वृद्धि • वस्तुओं और तेल की ऊंची कीमतों ने निर्यात के मूल्य को बढ़ाने में मदद की। • उदाहरण के लिए, इंजीनियरिंग निर्यात 46.5% उछलकर पहली बार 100 बिलियन डॉलर को पार कर गया है,

यहां तक कि रसायन, सूती धागे, हथकरघा उत्पादों और परिधान उद्योग ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है।

- व्यापार में वृद्धि को दुनिया द्वारा COVID-19 वायरस के प्रकोप के बाद चीन पर अपनी निर्भरता में विविधता लाने के लिए अपनी वैश्विक खरीद प्राथमिकताओं को स्थानांतरित करने से समझाया जा सकता है।

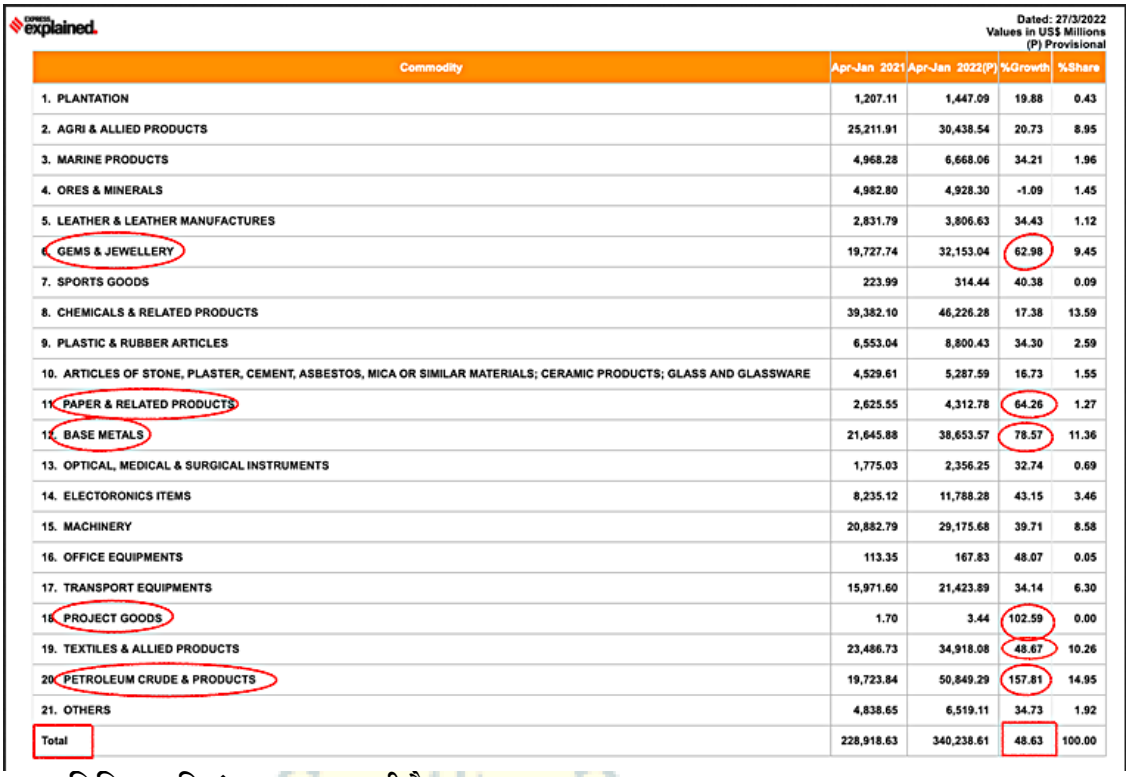

explained

Dated: 27/3/2022
Values in US$ Millions
(P) Provisional

Commodity	Apr-Jan 2021	Apr-Jan 2022(P)	%Growth	%Share
1. PLANTATION	1,207.11	1,447.09	19.88	0.43
2. AGRI & ALLIED PRODUCTS	25,211.91	30,438.54	20.73	8.95
3. MARINE PRODUCTS	4,968.28	6,668.06	34.21	1.96
4. ORES & MINERALS	4,982.80	4,928.30	-1.09	1.45
5. LEATHER & LEATHER MANUFACTURES	2,831.79	3,806.63	34.43	1.12
6. GEMS & JEWELLERY	19,727.74	32,153.04	62.98	9.45
7. SPORTS GOODS	223.99	314.44	40.38	0.09
8. CHEMICALS & RELATED PRODUCTS	39,382.10	46,226.28	17.38	13.59
9. PLASTIC & RUBBER ARTICLES	6,553.04	8,800.43	34.30	2.59
10. ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT, ASBESTOS, MICA OR SIMILAR MATERIALS; CERAMIC PRODUCTS; GLASS AND GLASSWARE	4,529.61	5,287.59	16.73	1.55
11. PAPER & RELATED PRODUCTS	2,625.55	4,312.78	64.26	1.27
12. BASE METALS	21,645.88	38,653.57	78.57	11.36
13. OPTICAL, MEDICAL & SURGICAL INSTRUMENTS	1,775.03	2,356.25	32.74	0.69
14. ELECTORONICS ITEMS	8,235.12	11,788.28	43.15	3.46
15. MACHINERY	20,882.79	29,175.68	39.71	8.58
16. OFFICE EQUIPMENTS	113.35	167.83	48.07	0.05
17. TRANSPORT EQUIPMENTS	15,971.60	21,423.89	34.14	6.30
18. PROJECT GOODS	1.70	3.44	102.59	0.00
19. TEXTILES & ALLIED PRODUCTS	23,486.73	34,918.08	48.67	10.26
20. PETROLEUM CRUDE & PRODUCTS	19,723.84	50,849.29	157.81	14.95
21. OTHERS	4,838.65	6,519.11	34.73	1.92
Total	228,918.63	340,238.61	48.63	100.00

$400 बिलियन की संख्या क्या छुपाती है?

- **सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निर्यात का निम्न स्तर:** लगभग 400 अरब डॉलर का व्यापारिक निर्यात होता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 13% (2011-12 में यह 305 अरब डॉलर था, जो सकल घरेलू उत्पाद का 17% था)। 400 अरब डॉलर का लक्ष्य बहुत पहले हासिल किया जा सकता था अगर भारत का निर्यात अपनी जीडीपी वृद्धि के साथ गति बनाए रखता।
- **व्यापक आधार पर रिकवरी न होना :** 20 कमोडिटी समूहों में से केवल छह (चार्ट में लाल घेरे द्वारा हाइलाइट किए गए) की वृद्धि दर समग्र औसत (49%) से अधिक थी।
  - रसायन और उत्पाद, जो दूसरी सबसे बड़ी निर्यात वस्तु है, में केवल 17% की वृद्धि हुई। इसी तरह, कृषि, 9% की हिस्सेदारी के साथ केवल 20% की दर से बढ़ी - समग्र विकास दर के आधे से भी कम है ।
- भारत का निर्यात या तो कीमतों में वृद्धि या मात्रा में वृद्धि या दोनों के संयोजन के कारण बढ़ सकता है। भारत की निर्यात वृद्धि काफी हद तक मूल्य वृद्धि के कारण थी। उदाहरण के लिए: पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य - कुल निर्यात का 15% - 158% की भारी वृद्धि हुई।
- **बढ़ता व्यापार घाटा:** वर्ष के लिए व्यापार घाटा लगभग 190 अरब डॉलर हो सकता है, जो महामारी वर्ष में दर्ज 102 अरब डॉलर से काफी अधिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस साल आयात भी तेजी से बढ़ा है (2020-21 के 393.6 अरब डॉलर के आयात के आंकड़े की तुलना में 200 अरब डॉलर बढ़ने का अनुमान है)

आने वाले वर्ष में भारतीय निर्यात के लिए जोखिम कारक क्या हैं?

- हालांकि रूस के साथ भारत का सीधा व्यापार उसके व्यापार टोकरी के लगभग 1% पर महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यूक्रेन-रूस संघर्ष भारतीय कृषि उत्पाद निर्यात के लिए कुछ और अवसर पैदा कर सकते हैं।
  - लेकिन यूक्रेन-रूस संघर्ष भारतीय कृषि उत्पाद निर्यात के लिए कुछ और अवसर पैदा कर सकते हैं, विशेष रूप से गेहूं और मक्का जैसी फसलों के लिए। लेकिन यह भारत के ऊर्जा आयात बिल में तेज वृद्धि के साथ-साथ सूरजमुखी तेल जैसे खाद्य तेलों के आयात की लागत में वृद्धि से ऑफसेट होगा।
- उच्च शिपिंग दरें, कंटेनर की कमी और काला सागर के आसपास व्यापार मार्गों का पुन: संरेखण भी एक चुनौती पेश करेगा।

	• विकसित देशों में आर्थिक सुधार (और मांग में कमी) के कारण निर्यात में भी वृद्धि हुई, जो सरकारी खर्च और ढीली मौद्रिक नीति से प्रेरित था। आने वाले वर्ष में वैश्विक विकास की संभावनाओं में नरमी देखी जा सकती है और इस प्रकार भारत की व्यापार संभावनाओं पर भी असर पड़ सकता है। **निष्कर्ष** भारत इन लाभों को मजबूत करने और चीन के एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में अपनी साख स्थापित करने की उम्मीद करेगा, भले ही उसे वियतनाम और बांग्लादेश जैसे एशियाई साथियों से कुछ क्षेत्रों में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है।
क्रिप्टोकरंसी	**संदर्भ:** केंद्रीय बजट में क्रिप्टो और अन्य आभासी डिजिटल संपत्ति के उपयोगकर्ताओं और व्यापारियों के लिए एक कठोर झटका था। इन संपत्तियों के सभी हस्तांतरण या बिक्री को कर के दायरे में लाया गया था। **इस कदम के पीछे क्या मंशा थी?** • केंद्र अनियमित क्रिप्टो-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे वज़ीरएक्स, कॉइनडीसीएक्स, ज़ेबपे आदि पर गतिविधि में वृद्धि के बारे में चिंतित है। • भोले-भाले निवेशकों को 2020 और 2021 में इन परिसंपत्तियों की कीमतों में भारी वृद्धि से आकर्षित हुए बिना संपत्ति के जोखिमों के बारे में पूरी तरह से अवगत हुए (अपने आप में कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं है)। • इन परिसंपत्तियों की अत्यंत अस्थिर और सट्टा प्रकृति निवेशकों के पैसे को बहुत जोखिम में डालती है। • इसके अलावा, किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कोई नियामक पर्यवेक्षण नहीं होने से, निवेशकों को अपना सारा पैसा खोने का जोखिम होता है यदि इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म डिफॉल्ट या बंद हो जाता है। ○ केंद्र अभी भी इस बात पर विचार कर रहा है कि इन व्यापारों को विनियमित किया जाए या उन सभी को एक साथ प्रतिबंधित किया जाए, जैसा कि चीन ने किया है। **क्या कराधान प्रस्तावित किया गया है?** **बजट में क्रिप्टो कराधान के पांच पहलू हैं।** • पहला, किसी भी आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। जब अधिभार और उपकर जोड़ दिए जाते हैं, तो कर की दर 33 से 42 प्रतिशत के बीच बढ़ जाती है। • दूसरा, आय की गणना करते समय कोई कटौती प्रदान नहीं की जाती है, केवल अधिग्रहण की लागत की अनुमति है, यदि कोई हो। इसलिए खनन की लागत या किसी अन्य लागत को लाभ कम करने के लिए व्यय के रूप में नहीं दिखाया जा सकता है। • तीसरा, वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर से होने वाले नुकसान को किसी अन्य स्रोत से किसी भी लाभ के खिलाफ सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। एक क्रिप्टोकुरेंसी में किए गए लाभ को किसी अन्य क्रिप्टोकुरेंसी में हुए नुकसान के खिलाफ सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। • चौथा, आभासी डिजिटल संपत्ति के उपहार पर प्राप्तकर्ता के हाथों कर लगाने का भी प्रस्ताव है। • अंत में, ऐसी संपत्तियों के हस्तांतरण पर 1 प्रतिशत की दर से टीडीएस लगाया जाना है। **विशेषज्ञ इसे दंडात्मक कराधान क्यों कह रहे हैं?** • केंद्र स्पष्ट है कि वह लॉटरी या जुए जैसी अन्य सट्टा गतिविधियों के साथ क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार को देख रहा है। • यही कारण है कि आय पर कर अन्य पूंजीगत संपत्तियों पर लगाए गए पूंजीगत लाभ कर की तुलना में बहुत अधिक है। • वित्त विधेयक में संशोधन ने आगे स्पष्ट किया कि क्रिप्टोकरेंसी को पूंजीगत संपत्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है। • घाटे के समायोजन को अस्वीकार करना, किसी भी खर्च में कटौती की अनुमति नहीं देना और उपहारों पर कर लगाना दंडात्मक है और निवेशकों को इन परिसंपत्तियों से दूर रहने के लिए कहने का एक और तरीका है। **क्रिप्टो खिलाड़ियों ने इस पर कैसे प्रतिक्रिया दी है?** • ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और वॉलेट प्रदाताओं सहित क्रिप्टोकुरेंसी स्पेस में हितधारक इस कदम से स्पष्ट रूप से नाखुश हैं। • प्रारंभ में, उन्होंने स्पिन देने की कोशिश की कि सरकार का उन पर कर लगाने का कदम इन संपत्तियों को कानूनी बनाता है।

	• लेकिन विभिन्न सरकारी अधिकारियों ने इस व्याख्या का खंडन करते हुए कहा है कि क्रिप्टोकरेंसी पर कर लगाने का मतलब उन्हें वैध बनाना नहीं है। • क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग ने करों को वापस लेने के लिए केंद्र के साथ पैरवी की। लेकिन अब जबकि शुक्रवार को वित्त विधेयक पारित हो गया है, ऐसे में इन खिलाड़ियों को बदली हुई परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। **क्रिप्टो एक्सचेंजों, निवेशकों के लिए आगे क्या?** • क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अब लगातार आयकर विभाग की नजर में रहेंगे, जिसके लिए अब इन प्लेटफार्मों को उन पर किए गए सभी लेनदेन के रिकॉर्ड बनाए रखने, बिक्री पर 1 प्रतिशत का टीडीएस एकत्र करने और आईटी प्राधिकरण को पैसा जमा करने की आवश्यकता होगी। • अनुपालन का बोझ कठिन होगा और कई एक्सचेंजों के दुकान बंद होने की संभावना है। • उच्च आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता के कारण निवेशक भारतीय क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफॉर्म पर खरीदना और बेचना नहीं चाहते हैं। • वे अपनी गतिविधि को अन्य अनियमित विदेशी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, व्यापारिक गतिविधि एक बार फिर भूमिगत हो सकती है। **क्या है सहारा, कैसे होगा ये सब खत्म?** • अमेरिका और यूरोपीय संघ सहित दुनिया भर की सरकारें निजी क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग को विनियमित करने के लिए एक रूपरेखा पर काम कर रही हैं। • एक वैश्विक ढांचा – जो जोखिम लेने के इच्छुक लोगों को इन परिसंपत्तियों में खेलना जारी रखता है, जबकि भोले निवेशकों की रक्षा करता है – एक या दो साल में तैयार हो सकता है। • तभी इन परिसंपत्तियों के नियमन में आगे की राह पर स्पष्टता सामने आएगी। • एक देश द्वारा इन ट्रेडों पर एकतरफा प्रतिबंध या विनियमन काम करने की संभावना नहीं है क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र आभासी है। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** • ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी • RBI की डिजिटल करेंसी
भारत में किफायती स्वास्थ्य सेवा की ओर: 'जन औषधि' से 'जन उपयोगी' तक	**संदर्भ:** भारत ने फरवरी के मध्य में जन औषधि दिवस 2022 को चिह्नित किया। • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भारत के नागरिकों को सस्ती और गुणवत्ता वाली दवा प्रदान करना है। • यह योजना केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के तहत स्थापित की गई थी। • वर्ष 2015 में इसकी स्थापना के बाद से, पूरे भारत में 8,000 से अधिक जनऔषधि केंद्र (केंद्र) संचालित हो चुके हैं। ये केंद्र हमारे देश के कोने-कोने में हमारे समाज के एक बड़े वर्ग को एक किफायती मूल्य पर 1,451 जेनेरिक दवाओं और 240 सर्जिकल वस्तुओं की पेशकश करके पूरा करते हैं। *लंबे समय में, पीएमबीजेपी का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा को वहनीय, सुलभ और स्वीकार्य बनाना है।* **किफायती स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता - भारत और स्वास्थ्य** हेल्थ किसी राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक (HDI) के केंद्रीय स्तंभों में से एक है जो इसकी समृद्धि को इंगित करता है। हेल्थ न केवल एक व्यक्ति के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है बल्कि राष्ट्र के लिए मानव-पूंजी का एक अभिन्न अंग भी है। • इसे देखते हुए, प्रत्येक राष्ट्र का लक्ष्य विभिन्न पहलों और योजनाओं के माध्यम से अपने नागरिकों को सस्ती कीमत पर अच्छी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। • पीएमबीजेपी भारत में सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा की सुविधा के लिए एक ऐसी नेक पहल है। • भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसके बावजूद स्वास्थ्य सेवा के लिए बजट आवंटन 3 फीसदी से भी कम है। • भारत की जनसंख्या में ग्रामीण अधिवास और मध्यम आय वर्ग का प्रभुत्व है।

- हमारे देश की लगभग एक तिहाई आबादी स्वास्थ्य बीमा से वंचित है। प्रचलित बीमारियां और महामारी का प्रकोप स्थिति के खतरों को बढ़ाता है। इन महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखते हुए, जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य सेवा को वहनीय बनाना महत्वपूर्ण है।

जन औषधि से जन-उपयोगी

स्वास्थ्य देखभाल में दवाओं (औषधि) और शल्य चिकित्सा उपकरणों का बड़ा हिस्सा है। उन्हें हमारे समाज के आम जन तक पहुँचाने से स्वास्थ्य सेवा में एक प्रमुख समस्या का समाधान होता है। यह 'जन औषधि' को जन-उपयोगी (जनता के लिए उपयोगी) बनाता है।

- पेटेंट दवाओं ने दवा उद्योग में निजीकरण, बाजार प्रतिस्पर्धा और लाभ की भूख के उदय के साथ जेनेरिक दवाओं पर कब्जा कर लिया है। इसके परिणामस्वरूप आवश्यक स्वास्थ्य स्वच्छता बनाए रखने के लिए व्यक्तियों की जेब में छेद हो गया।
- नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत का स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च 60 प्रतिशत से अधिक है। यह निम्न-मध्यम आय वाले देशों के औसत से काफी ऊपर है।

संक्षेप में, भारत के सामने एक भीषण स्वास्थ्य देखभाल चुनौती है जिसका समाधान करना है।

- पीएमबीजेपी का लक्ष्य इसकी बढ़ती पहुंच और सस्ती जेनेरिक दवाओं के माध्यम से है।
- पीएमबीजेपी फार्मा क्षेत्र में मानव संसाधन के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। यह जनऔषधि केंद्र खोलने और आय उत्पन्न करने के लिए योग्य कर्मियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर के अलावा, जनऔषधि केंद्र संबद्ध आपूर्ति श्रृंखला, परिवहन और रखरखाव क्षेत्रों में परिधीय रोजगार उत्पन्न करता है। इस प्रकार, पीएमबीजेपी न केवल स्वास्थ्य के लिए बल्कि देश की संपत्ति के लिए भी औषधि है। यह वास्तव में एक जन-उपयोगी है।

पिछले सात वर्षों में, पीएमबीजेपी ने देश में जनऔषधि केंद्र की व्यापक उपस्थिति और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के मामले में मील के पत्थर हासिल किए हैं। हालांकि, बढ़ती और उम्रदराज़ आबादी और महामारी के डर को देखते हुए, इसकी स्थिरता और विकास के लिए इस पहल को समर्थन और बढ़ावा देने की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जिन मुद्दों को हल करने की आवश्यकता है वे हैं -

- पहला, जनऔषधि केंद्र की पहुंच बढ़ाना।
- दूसरा, पीएमबीजेपी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रचार करना ।
- तीसरा, बढ़ती महंगाई और आपूर्ति लागत के बावजूद जेनेरिक दवाओं की सस्ती कीमत बनाए रखना।

आगे की राह

- पहला जनऔषधि केंद्र की पहुंच बढ़ाने के लिए
  - बुनियादी ढांचे और वित्तीय सहायता के लिए स्वास्थ्य देखभाल बजट में वृद्धि की आवश्यकता है।
  - इसके अलावा, अधिक निजी कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक भागीदारी बढ़ाने और आउटरीच का विस्तार करने के लिए जेनेरिक दवाओं के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर विचार किया जाना चाहिए।
  - जनऔषधि केंद्र के विस्तार के लिए फार्मास्युटिकल स्टाफ के प्रशिक्षण और विकास की भी आवश्यकता होगी।
- दूसरा, पीएमबीजेपी और जनऔषधि केंद्र के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए: स्थानीय अस्पतालों, क्लीनिकों और डॉक्टरों के साथ सहयोग की आवश्यकता है - जेनेरिक दवाओं की प्रभावकारिता पर स्थानीय लोगों का विश्वास बनाने का यह एक बहुत प्रभावी तरीका है। मरीज डॉक्टर के नुस्खे पर विश्वास करते हैं, विज्ञापन के विवरण में नहीं।
- अंत में, मुद्रास्फीति से बचाव के लिए और जेनेरिक दवाओं की वहनीय कीमतों को बनाए रखने के लिए, आपूर्ति-पक्ष हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
  - इसमें मुख्य रूप से दवाओं का अनुसंधान और विकास शामिल है ताकि कम कीमत पर जेनेरिक दवाओं की प्रभावशीलता को पेटेंट दवाओं के बराबर लाया जा सके।
  - o उत्पादन, भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला में दक्षता भी इनपुट लागत को कम करने में मदद करेगी और इस प्रकार, हितधारकों के लाभ ब्याज से समझौता किए बिना सस्ती कीमतों को बनाए रखेगी।

	निष्कर्ष सस्ती, सुलभ और स्वीकार्य दवाएं हर नागरिक का अधिकार हैं। स्वास्थ्य केवल व्यक्तियों की पसंद नहीं बल्कि राष्ट्र की आवश्यकता है। पीएमबीजेपी 'स्वस्थ भारत' की दिशा में एक नेक पहल है। भविष्य के भारत के लिए इस पहल को टिकाऊ बनाना महत्वपूर्ण है।
सीए, सीडब्ल्यूए और सीएस (संशोधन विधेयक), 2021	**संदर्भ:** चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज (संशोधन) विधेयक, 2021, लोकसभा द्वारा पारित किया गया था जो संशोधन करता है ● सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 ● लागत और कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959 ● कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 **प्रसंग:** ● उपरोक्त तीन अधिनियम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की स्थापना का प्रावधान करते हैं। ● इन संस्थानों के मामलों का प्रबंधन उनकी संबंधित परिषदों द्वारा किया जाता है। ● परिषदों में निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं। ● ये निकाय अकादमिक पाठ्यक्रमों को मंजूरी देना, उम्मीदवारों की परीक्षा आयोजित करना, सदस्यों के रजिस्टर में नाम दर्ज करने के लिए योग्यता निर्धारित करना और अपने सदस्यों की व्यावसायिक योग्यता के मानकों को विनियमित करना हैं। ● यह अधिनियम उन संस्थानों के सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए तंत्र भी प्रदान करता है जो पेशेवर या अन्य कदाचार में लिप्त हैं। ● यह तंत्र मोटे तौर पर स्व-नियामक प्रकृति का है जिसमें संस्थानों के सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित कुछ बाहरी सदस्यों के साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही में भाग लेते हैं। ● हाल के वर्षों में, भारत ने कई धोखाधड़ी और घोटालों को देखा है, जिन्होंने स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षा की भूमिका और प्रभावशीलता को ध्यान में लाया है। ● वर्ष 2018 में पंजाब नेशनल बैंक में एक बड़ी धोखाधड़ी की पृष्ठभूमि में, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) की स्थापना की। ● एनएफआरए को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा पेशेवर या अन्य कदाचार के मामलों की जांच करने का अधिकार है। यह चार्टर्ड एकाउंटेंसी के पेशे के स्व-नियमन से दूर एक कदम था जैसा कि अब तक पालन किया गया था। **प्रस्तावित नए विधेयक का उद्देश्य क्या है?** ● सीए, सीडब्ल्यूए और सीएस (संशोधन विधेयक), 2021 अनुशासनात्मक तंत्र को अधिक स्वतंत्र बनाकर, फर्मों को पंजीकृत करने और दंड में वृद्धि करके चिकित्सकों और फर्मों की जवाबदेही को मजबूत करने का प्रयास करता है। विधेयक में प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार हैं: ● **अनुशासन:** ○ आईसीएआई की अनुशासन समिति और अनुशासन बोर्ड की अध्यक्षता गैर-चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (सीए) करेंगे, और इसके निर्वाचित परिषद सदस्य अब बहुमत में नहीं होंगे। ○ यह सदस्यों के खिलाफ मामलों के समयबद्ध निपटान का भी प्रावधान करता है। ● **शासन और प्रशासन:** ○ ICAI की परिषद का कार्यकाल तीन से बढ़ाकर चार वर्ष किया जाएगा। ○ इसके निर्वाचित सदस्यों के लिए लगातार कार्यकाल की अधिकतम संख्या वर्तमान तीन से घटाकर दो कर दी जाएगी; ○ ICAI के सचिव, ICAI के अध्यक्ष को मुख्य कार्यकारी के रूप में प्रतिस्थापित करेंगे और निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्यों का निष्पादन करेंगे; ○ ICAI भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के CA फर्मों के पैनल से अपने लेखा परीक्षक की

नियुक्ति करेगा;

- **समन्वय समिति**
    - विधेयक कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति के गठन का प्रावधान करता है।
    - इसके कार्यों में शामिल होंगे: (i) शिक्षाविदों की गुणवत्ता में सुधार, (ii) व्यवसायों के बीच समन्वय और सहयोग करना, और (iii) व्यवसायों के लिए नियामक नीतियों पर सिफारिशें करना।
- **फर्मों का पंजीकरण:** फर्मों को अब संस्थानों के साथ पंजीकरण करना होगा। परिषदों को किसी भी कार्रवाई योग्य शिकायत के लंबित होने या जुर्माना लगाने सहित विवरण वाली फर्मों का एक रजिस्टर बनाए रखना चाहिए।
- **दंड:** यह बिल तीन अधिनियमों के तहत कुछ जुर्माने को बढ़ाता है। यदि पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी फर्म का भागीदार या मालिक बार-बार कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो फर्म के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

विधेयक द्वारा लाए गए परिवर्तनों का महत्व

- यह आईसीएआई की जवाबदेही, शासन और प्रशासन को मजबूत करेगा।
- वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने इन परिवर्तनों का समर्थन किया है और प्रमाणन में आईसीएआई के एकाधिकार को समाप्त करने की सिफारिश की है।
- लगातार शिकायतें मिलती रही हैं कि आईसीएआई गलत सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने में ढिलाई बरत रहा है। आईसीएआई की अनुशासन समिति में सरकार की बढ़ती भूमिका को देखते हुए प्रस्तावित परिवर्तनों से शिकायतों के त्वरित निपटान में वृद्धि होगी।

बिल की आलोचना

- आईसीएआई की अनुशासनात्मक शाखाओं की संरचना में प्रस्तावित परिवर्तन इसकी भूमिका को और सीमित कर देंगे। परिणामस्वरूप आईसीएआई प्रभावी रूप से एक परीक्षा बोर्ड के रूप में कम हो जाएगा।
- इस बिल का उद्देश्य इन व्यवसायों में अनुशासन लाना है, लेकिन अनुशासनिक प्राधिकरण का नेतृत्व एक गैर-चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया जाएगा, जिसके पास डोमेन ज्ञान की कमी हो सकती है।
    - बार काउंसिल के लिए, अध्यक्ष एक वकील होता है। मेडिकल काउंसिल के लिए चेयरमैन डॉक्टर होता है, लेकिन आईसीएआई कमेटी के लिए चेयरमैन नॉन-सीए होगा।
- विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि यह संस्थानों के प्रशासनिक और अनुशासनात्मक हथियारों के बीच हितों के टकराव को दूर करने का प्रयास करता है। इसे प्राप्त करने के लिए, विधेयक में दो अनुशासनात्मक संस्थाओं की संरचना को बदलने का प्रस्ताव है ताकि अधिक बाहरी प्रतिनिधित्व की अनुमति मिल सके। हालाँकि, इन बाहरी सदस्यों का चयन तीन परिषदों द्वारा तैयार किए गए व्यक्तियों के एक पैनल से किया जाएगा।
- चूंकि तीनों संस्थानों में आपस में समन्वय के लिए समितियां भी हैं, यह स्पष्ट नहीं है कि विधेयक के तहत प्रस्तावित एक अन्य समन्वय परिषद की स्थापना की आवश्यकता क्यों है।

आगे की राह

- IIT और IIM की तर्ज पर भारतीय लेखा संस्थान (IIAs) की एक स्ट्रिंग स्थापित करने के लिए संसदीय समिति का सुझाव अभिनव है।
- IIA लेखांकन, लेखा परीक्षा और संबंधित क्षेत्रों और उनके स्नातकों में पांच वर्षीय पूर्णकालिक और व्यापक-आधारित डिग्री प्रदान करेगा।
- एक स्तर पर, वे प्रमाणन पर ICAI के वैधानिक एकाधिकार को समाप्त कर देंगे। और अधिक प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप बेहतर गुणवत्ता एवं आचरण के उच्च मानक होंगे।

डाउन टू अर्थ की स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2022 रिपोर्ट

प्रसंग: पिछले दो सालों में हमने सामान्य जीवन में जिस स्तर का व्यवधान देखा है, उतना इससे पहले कभी नहीं देखा। कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन दोनों प्रकृति के साथ हमारे 'डायस्टोपियन' संबंधों का नतीजा हैं, जिसे प्रकृति का बदला कहा जाना चाहिए।

- कोविड-19 इसलिए क्योंकि हम जंगली जानवरों और इंसान के बीच की दरार को तोड़ रहे हैं और अपने खाने के उत्पादन की तरीका भी बर्बाद कर रहे हैं। जबकि जलवायु परिवर्तन, उस उत्सर्जन का परिणाम है, जो हमारी आर्थिक वृद्धि के लिए जरूरी है - जीवाश्म ईंधन टिकाऊ नहीं हैं और हमारी जीवन शैली अब एक समस्या है।
- वर्तमान समय में भारत के सामने तीन अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं- जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण और टिकाऊपन-क्षमता संबंध।

भारत ऐसे कम से कम 17 प्रमुख सरकारी लक्ष्यों को पाने की दिशा में पीछे है, जिनकी समय-सीमा 2022 है। डाउन टू अर्थ की स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2022 रिपोर्ट के अनुसार, इस धीमी गति के चलते भारत समय-सीमा में इन लक्ष्यों को हासिल करने से चूक सकता है।

रिपोर्ट कार्ड

- **अर्थव्यवस्था:** अर्थव्यवस्था का लक्ष्य 2022-23 तक जीडीपी चार ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब पहुंचाना है लेकिन 2020 तक, अर्थव्यवस्था केवल 2.48 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ी है। यही नहीं, महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था काफी हद तक सिकुड़ गई है, जिससे समय-सीमा को पूरा करना और भी मुश्किल हो गया है।
- **रोजगार:** कार्यक्षेत्रों में महिलाओं के श्रम-बल को 2022-23 तक कम से कम तीस फीसदी तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है लेकिन जनवरी से मार्च 2020 के बीच यह महज 17.3 फीसदी ही रहा।
- **आवास:** 'सबको आवास' देने के लक्ष्य के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 29.5 मिलियन और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में 12 मिलियन आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन दोनों योजनाओं में क्रमशः 46.8 फीसदी और 38 फीसदी काम ही पूरा हो सका है।
- **पीने के पानी का इंतजाम :** सरकार ने 2022-23 तक सभी को पाइप से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य बनाया है लेकिन अभी तक इसका केवल 45 फीसदी ही हासिल किया जा सका है।
- **खेती :** 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया था। हालांकि किसानों की मासिक आय 6426 रुपये से बढ़कर 10,218 रुपये हो गई है लेकिन इस बढ़त में ज्यादा हिस्सेदारी मजदूरी और पशुओं से होने वाली आय की है। जहा तक फसलों से होने वाली मासिक आमदनी का सवाल है तो वह बढ़ने की बजाय कम हो गई है। 2012-13 में यह 48 फीसदी थी, जो 2018-19 में 37.3 फीसदी हो गई थी।
- **भूमि-रिकार्डों का डिजिटलीकरण:** सरकार का एक और लक्ष्य 2022 तक सभी भूमि-रिकार्डों को डिजिटलाइज करना है। इस दिशा में मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों ने अच्छी प्रगति की है, जबकि जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और सिक्किम जैसे राज्यों में इसमें क्रमशः 5 फीसदी, 2 फीसदी और 8.8 फीसदी की दर से गिरावट आई है। कुल मिलाकर, इस लक्ष्य को पूरा करने की संभावना नहीं है, क्योंकि 14 राज्यों में 2019-20 के बाद से भूमि रिकॉर्ड की गुणवत्ता में गिरावट पाई गई है।
- **वायु प्रदूषण:** 2022 तक देश के शहरों में पीएम 2.5 का स्तर, 50 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से नीचे लाने का है। हालांकि 2020 में जबकि महामारी के चलते लॉकडाउन लगा हुआ था, तब भी देश के 121 में से 23 शहरों में पीएम 2.5 का स्तर 50 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा पाया गया था।
- **ठोस कचरा प्रबंधन:** इसका लक्ष्य सभी घरों में सौ फीसद स्रोत पृथक्करण हासिल करना है। इस दिशा में समग्र प्रगति 78 फीसद है - केरल जैसे राज्यों और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों ने लक्ष्य हासिल कर लिया है जबकि पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे अन्य राज्य इसमें बहुत पीछे हैं। 2022 के अंत तक देश में मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने का लक्ष्य भी रखा गया है , हालांकि अपने यहां अभी भी हाथ से मैला ढोने वाले 66,692 लोग हैं।
- **वन क्षेत्र को बढ़ाना:** राष्ट्रीय वन नीति, 1988 की परिकल्पना के अनुसार वन-क्षेत्र को देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33.3 फीसदी तक बढ़ाने का लक्ष्य है। हालांकि 2019 तक, देश का केवल 21.67 फीसद क्षेत्र ही वनों से आच्छादित था।
- **ऊर्जा:** इस दिशा मे जो लक्ष्य हासिल किया जाना है, वह 2022 तक 175 जीगावाट नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता है। इसका अभी तक केवल 56 फीसद ही हासिल किया जा सका है।

	राज्यों की स्थिति • सतत विकास लक्ष्यों (एसीडीजी) की समय-सीमा 2030 है। इन्हें हासिल करने में अब एक दशक से भी कम का वक्त बचा है। देश के दो राज्य, उत्तर प्रदेश और बिहार का एसडीजी क्रमशः 11 और 14 है, जो राष्ट्रीय औसत से नीचे है। वहीं, केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश बेहतर काम कर रहे हैं। • एसीडीजी 1, जो गरीबी दूर करने से जुड़ा है, उसमें सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों छह राज्यों में बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। इन राज्यों को मेघालय, असम, गुजरात, महाराष्ट्र के साथ भूख और कुपोषण दूर करने (एसीडीजी 2) वालों राज्यों की सूची में भी सबसे खराब प्रदर्शन वालों की श्रेणी में रखा गया है। • जल और स्वच्छता (एसडीजी 6) में, दिल्ली, राजस्थान, असम, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश का प्रदर्शन चिंताजनक है। • स्वच्छ और किफायती ऊर्जा से संबंधित एसडीजी 7 में राज्यों का प्रदर्शन औसत से ऊपर है और अधिकांश राज्यों ने लक्ष्य हासिल कर लिया है। • जलवायु कार्रवाई (एसडीजी 13) में, 13 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों का स्कोर राष्ट्रीय औसत से कम है। अच्छे प्रदर्शन के मामले में ओडिशा सबसे ऊपर है, उसके बाद केरल है। झारखंड और बिहार का प्रदर्शन इस दिशा में सबसे खराब है। **निष्कर्ष** लक्ष्यों और उपलब्धियों के बीच का अंतर एक बार फिर से हमारे देश की शासन व्यवस्था की उन खामियों को उजागर करता है, जो स्थायी तौर पर अपनी जड़े जमाए हैं। हम बड़ी उम्मीदों के साथ लक्ष्य निधारित करते हैं और कुछ मौकों पर महत्वूपर्ण नीतिगत फैसले भी लेते हैं लेकिन जब सवाल नीतियों को लागू करने और नतीजे देने का आता है तो हम इंतजार करते रह जाते हैं। यह स्थिति बदलनी चाहिए। ● इनमें से कई लक्ष्य वास्तविक हैं। हालांकि कई जीडीपी में वृद्धि जैसे कई लक्ष्यों में समय-सीमाओं को चूकने का दोष महामारी पर मढ़ा जा सकता है, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के चलते वायु प्रदूषण में कमी आई थी और हमें इस दिशा में निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लेना चाहिए था। हमें इस बात पर आत्ममंथन करना चाहिए कि हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल क्यों हैं जो इस देश के लिए एक स्थायी भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हैं।' ● भारत को अपने स्वार्थ में कार्य करने की आवश्यकता है। हमारी जलवायु परिवर्तन रणनीति सह-लाभ के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए - हम जलवायु परिवर्तन के लिए कुछ करेंगे क्योंकि यह दुनिया के लिए अच्छा है, बल्कि इसलिए भी कि यह हमारे लिए अच्छा है। हमें हर क्षेत्र के लिए कम कार्बन वाली रणनीति की जरूरत है; हमें विकसित दुनिया से भी भुगतान करने के लिए कहना चाहिए और हमें उच्च लागत वाले विकल्प देने चाहिए ताकि हम छलांग लगा सकें। **क्या आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं?** 1. जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण और स्थिरता-सहनशीलता लिंकेज आज भारत के सामने तीन अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इन मुद्दों के समाधान के लिए सुझाव साझा कीजिए।
नो वाइल्ड, नो लाइफ (No Wild, No Life)	**संदर्भ:** हर जगह लोग भोजन से लेकर ईंधन, दवाओं, आवास और कपड़ों तक हमारी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए वन्य जीवन और जैव विविधता-आधारित संसाधनों पर निर्भर हैं। लाखों लोग अपनी आजीविका और आर्थिक अवसरों के स्रोत के रूप में प्रकृति पर भी भरोसा करते हैं। • इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) रेड लिस्ट, खतरे वाली प्रजातियों के आंकड़ों के अनुसार, जंगली जीवों और वनस्पतियों की 8,400 से अधिक प्रजातियां गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। जबकि 30,000 से अधिक को लुप्तप्राय या खतरे में है। • इस डेटा के अनुसार 239 जीव प्रजातियां जो भारत में पाई जाती हैं उन्हें लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसमें स्तनधारियों की 45 प्रजातियां, पक्षियों की 23 प्रजातियां, सरीसृप की 18 प्रजातियां, उभयचरों की 39 प्रजातियां और मछलियों की 114 प्रजातियां शामिल हैं। • भारत में 733 संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क है जिसमें 103 राष्ट्रीय उद्यान, 537 वन्यजीव अभयारण्य, 67 संरक्षण रिजर्व और 26 सामुदायिक रिजर्व शामिल हैं, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 4.89 प्रतिशत को कवर करते हैं।

मानव-वन्यजीव संघर्ष के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं:

- जंगली जानवरों द्वारा पशुधन या घरेलू पशुओं का शिकार
- फसलों और बाड़ों को नुकसान
- रिहायशी कचरे के बारे में वन्यजीवों का जमावड़ा
- वाहन/वन्यजीव टकराव, विमान/पक्षी टक्कर
- गिलहरियों या चमगादड़ों से फलों और फलों के पेड़ों को होने वाली क्षति
- अवांछनीय आवासीय स्थानों में पक्षियों का घोंसला बनाना

मानव-पशु संघर्ष के कारण:

- वनों में मानव बस्तियों का विस्तार - शहरों, औद्योगिक क्षेत्रों, रेलवे/सड़क के बुनियादी ढांचे, पर्यटन आदि का विस्तार
- वन क्षेत्रों में पशुओं को चरने देना
- भूमि उपयोग परिवर्तन जैसे संरक्षित वन क्षेत्रों से कृषि और बागवानी भूमि में परिवर्तन और मोनोकल्चर वृक्षारोपण वन्यजीवों के आवासों को और नष्ट करना
- देश में वन प्रबंधन की अवैज्ञानिक संरचनाएं और प्रथाएं
- वन्यजीवों के स्थानिक आवास में आक्रामक विदेशी खरपतवारों के संक्रमण से शाकाहारी वन्य जीवों के लिये खाद्य सामग्री (जैसे- घास, पत्ती, फल आदि) की उपलब्धता कम हो जाती है।
- पशुओं के अवैध शिकार के कारण मांसाहारी पशुओं के भोजन (शिकार) आधार में कमी आ रही है, परिणामस्वरूप जंगली पशु शिकार की तलाश में आवासीय बस्तियों में प्रवेश कर रहे हैं।

भारत की संरक्षण संस्कृति

- एक अरब लोगों के बावजूद वर्तमान में भारत में अधिकांश बड़ी वन्यजीव प्रजातियां, जैसे- बाघ, एशियाई हाथी, तेंदुआ, स्लॉथ भालू, गौर आदि की सबसे बड़ी आबादी मौजूद हैं।
- संस्कृति का हिस्सा: भारतीय संस्कृति मानव और जीवों के सह-अस्तित्व को स्वीकार करता है। यहाँ देवताओं के साथ पशु एवं जीव जुड़े हुए हैं।
- गोवा में वेलिप समुदाय द्वारा बाघों की पूजा और राजस्थान में विश्नोई समुदाय द्वारा काले हिरन की पूजा की प्रथा आज भी प्रचलित है।
- जानवरों को अक्षय संसाधन भी माना जाता है: खनन जैसी गतिविधियों के विपरीत, बाघ एक अक्षय संसाधन हैं। वे हमेशा वहाँ रहने वाले हैं, और इसी तरह नदियाँ और जंगल, स्थानीय लोगों को आय और विकास दे रहे हैं - जब तक बाघ हैं।

मानव-पशु संघर्ष को कम करने के लिए इनोवेटिव अभ्यास

- भारत के पश्चिमी घाटों में, एक नई संरक्षण पहल ने मानव-हाथी संघर्ष को रोकने के लिये प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में 'टेक्स्टिंग' (Texting) का उपयोग किया गया है। एसएमएस चिप्स के साथ एम्बेडेड हाथी ट्रैकिंग कॉलर स्वचालित रूप से हाथियों की गतिविधियों की चेतावनी आस-पास के निवासियों को प्रदान करता है।
- कनाडा में भी स्थानीय स्तर पर अधिकारियों ने वन्यजीव गलियारों का निर्माण किया है। अधिक मानव आबादी वाले क्षेत्रों में इस प्रकार का संरक्षण वन्यजीवों को एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करता है।
- हाथियों को उनके खेतों और घरों से सुरक्षित दूरी पर रखने के लिए, कुछ अफ्रीकी ग्रामीणों ने दो असंभावित, सभी प्राकृतिक समाधानों की ओर रुख किया है: मधुमक्खियां और गर्म मिर्च। मिर्च में पाए जाने वाले रासायनिक कैप्साइसिन को हाथी नापसंद करते हैं, जिससे तंजानिया के किसानों को तेल और मिर्च मिर्च के मिश्रण से अपने बाड़ को बुझाने के लिए प्रेरित किया जाता है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के प्रयास

- **अनियोजित शहरीकरण को हतोत्साहित करना:** इसके लिये शहरी नियोजन को योजनाबद्ध तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। वन्यजीवों के आवास को यथासंभव कम से कम बाधित करने का प्रयास किया जाना चाहिये।
- **संपूर्ण परिदृश्य को ध्यान में रखना:** केवल संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय अभयारण्यों या बायोस्फीयर रिजर्व के समुदायों की रक्षा करने के बजाय हमें परिदृश्य पर संपूर्णता से विचार करने की आवश्यकता है। इससे न केवल

मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने में मदद मिलेगी बल्कि व्यापक जैव विविधता को भी संरक्षित किया जा सकेगा।

- **सड़क पारिस्थितिकी को बनाए रखना:** खंडित आवासों को सड़कों पर जानवरों की सुरक्षित आवाजाही की अनुमति देने वाले ओवर या अंडर पास के माध्यम से पुनः जोड़ने की आवश्यकता है। उच्चतम जोखिम वाले क्षेत्रों में वन्यजीव और वाहनों के टक्कर को रोकने के लिए जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर निर्देशित करने के लिए बाड़ लगाने का भी उपयोग किया जा सकता है।

वन्यजीव संरक्षण- आवश्यक कदम:

वन्यजीव संरक्षण और वन्य जीवन का आनंद लेना हमारे लोकाचार का हिस्सा होना चाहिए।

- **जागरूकता का स्तर बढ़ाना:** राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाना। ऐसे लोगों में जागरूकता कम है जो इतने शिक्षित नहीं हैं जो दूरदराज के क्षेत्रों में रह रहे हैं क्योंकि उनके पास किसी भी ज्ञान प्रणाली तक पहुंच नहीं है, इसलिए हमें ऐसे अभियानों की आवश्यकता है जिनके माध्यम से वे सीख सकें, समझ सकें कि जैव विविधता क्या है, हमें इसकी रक्षा करने की आवश्यकता क्यों है उनको हमारे कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में जैव विविधता के महत्व के बारे में समझ हो। विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने में नागरिक समाज की भूमिका बहुत बड़ी है।
- स्कूल में पर्यावरण और वन्य जीवन के बारे में बात अधिक गंभीरता से की जानी चाहिए। हमें वास्तव में बच्चों को जैव विविधता वाले स्थानों के केंद्र में ले जाने की जरूरत है ताकि उन्हें संवेदनशील बनाया जा सके। स्कूली पाठ्यक्रम में वन्यजीव और जैव विविधता के महत्व पर पाठ और उनके संरक्षण के लिए आवश्यक कदम भी शामिल करना चाहिए।
- **WPA में संशोधन, 1972:** वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो कई वर्षों से संशोधन के अधीन है। वन्य जीवों और वनस्पतियों (उद्धरणों) की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कन्वेंशन के प्रावधानों को शामिल करके और अवैध शिकार जैसे अपराधों के लिए दंड को बढ़ाकर इसे संशोधित किया जाना चाहिए।
- **वन्यजीव गलियारों की रक्षा करना:** महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाएं जो प्रसिद्ध जंगली जानवरों के मार्ग को काटती हैं - जैसे कि एक नया राजमार्ग, ट्रेन लाइन या बिजली संयंत्र का निर्माण - पूरी तरह से जांच के बाद स्वीकृत किया जाना चाहिए।
- **परिदृश्य संरक्षण दृष्टिकोण अपनाना:** चूंकि देश के 60 फीसदी वन्यजीव इन संरक्षित क्षेत्रों के बाहर मौजूद हैं, इसलिए भारत सरकार को केवल राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक परिदृश्य संरक्षण दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

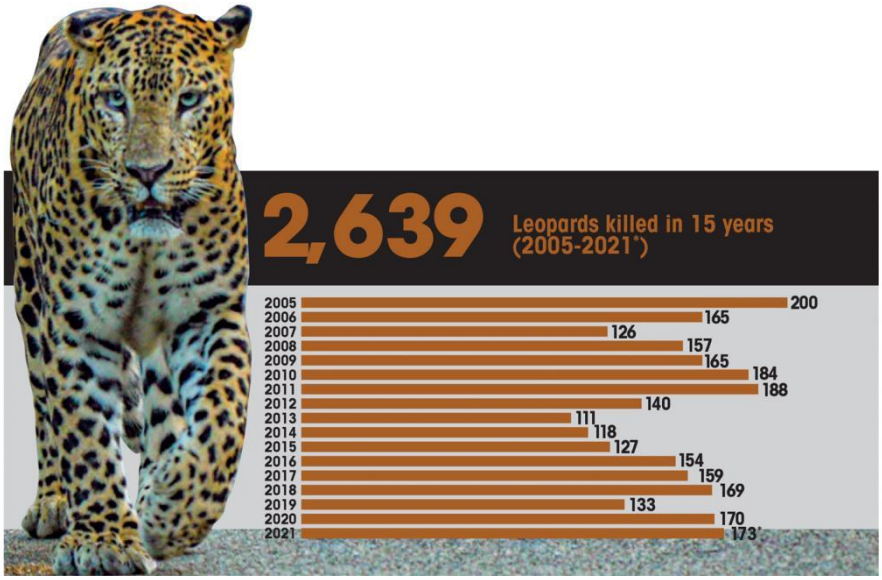

As of December 15, 2021 | Source: Wildlife Protection Society of India

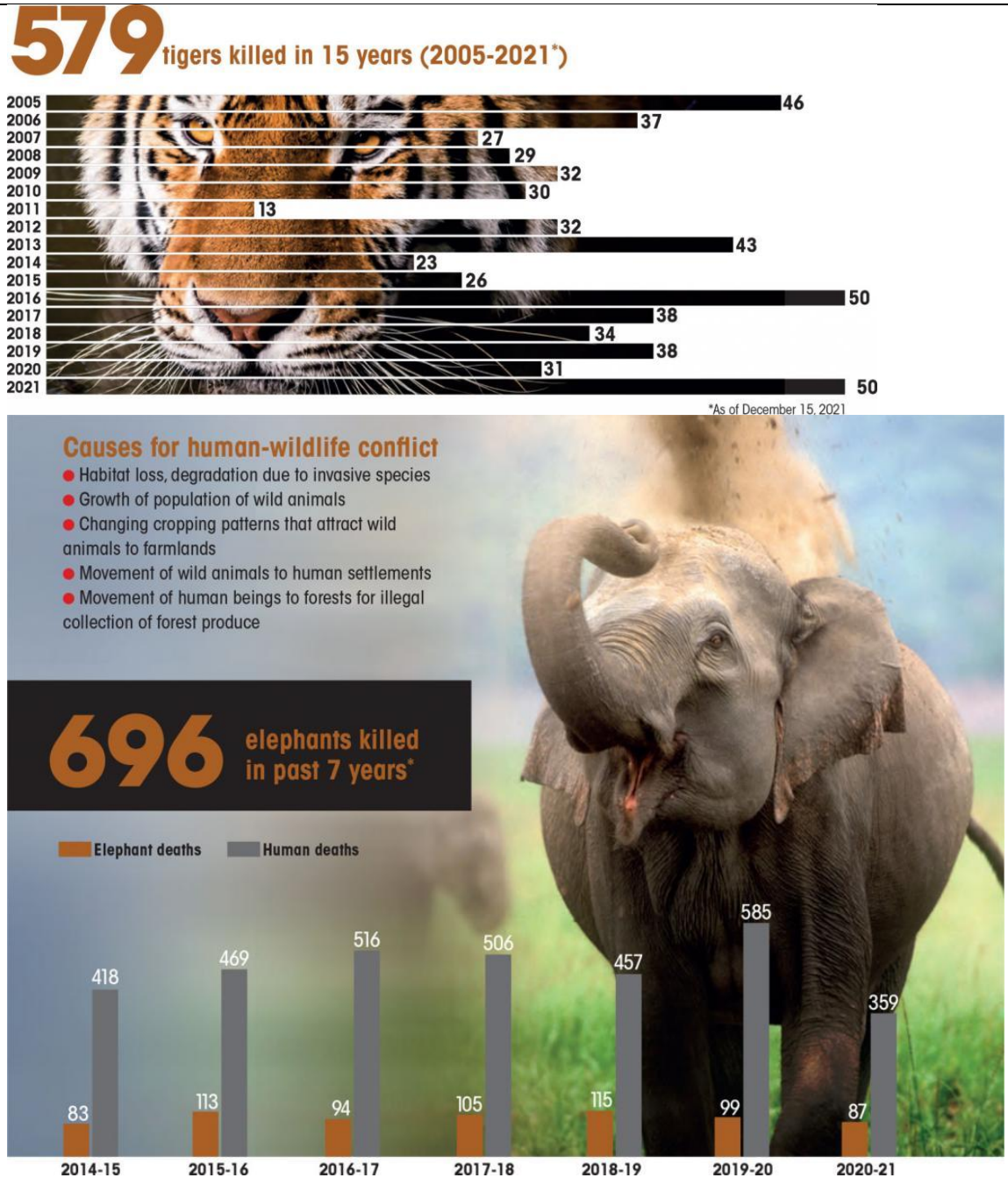

**up to December 2020*

स्रोत: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; अगस्त 9, 2021

निष्कर्ष

हमें नागरिकता के स्तर से जैविक विविधता, इसके संरक्षण, वन्य जीवन की सुरक्षा और मानव के लिए स्वस्थ कल्याण के प्रश्न को एक साथ मिलाने की जरूरत है। संरक्षण एक परियोजना नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और एक परिदृश्य के साथ संबंध है। यह न केवल विज्ञान और कानूनों पर आधारित है, बल्कि समाज में इसका मजबूत आधार है। वन्यजीवों की गुणवत्ता में न केवल उनकी रक्षा करके बल्कि यह सुनिश्चित करके भी सुधार किया जा सकता है कि नागरिक वास्तव में वन्य जीवन का आनंद लेते हैं जो कि उनकी विरासत है।

भारत की सौर क्षमता: महत्त्वपूर्ण उपलब्धि और चुनौतियाँ

संदर्भ: वर्ष 2021 में भारत ने अपनी संचयी स्थापित क्षमता में रिकॉर्ड 10 गीगावाट (GW) सौर ऊर्जा की वृद्धि की।

- अब 28 फरवरी, 2022 तक भारत 50 GW संचयी स्थापित सौर क्षमता से आगे निकल गया है।
- वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा से 500 गीगावाट उत्पादन की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसमें से 300 गीगावाट सौर ऊर्जा से आने की उम्मीद है।

क्या आप जानते हैं?

- 50 GW स्थापित सौर क्षमता में से
    - 42 GW ग्राउंड-माउंटेड सोलर फोटोवोल्टिक (PV) सिस्टम से प्राप्त होती है
    - केवल 6.48 GW रूफ-टॉप सोलर (RTS) से
    - 1.48 GW सोलर PV के अन्य तरीकों से प्राप्त होती है
- भारत की क्षमता वृद्धि सौर ऊर्जा परिनियोजन में देश में पांचवें स्थान पर है, जो 709.68 GW की वैश्विक संचयी क्षमता में लगभग 6.5% का योगदान करती है।

भारत की सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के लिए क्या चुनौतियाँ हैं?

- **विकास की धीमी गति:** स्थापित सौर क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद देश के बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान उसी गति से नहीं बढ़ा है। उदाहरण के लिये वर्ष 2019-20 में सौर ऊर्जा ने भारत की कुल 1390 BU बिजली उत्पादन में केवल 3.6% (50 बिलियन यूनिट) का योगदान दिया।
- **अक्षमताएं:** उपयोगिता-पैमाने पर सोलर PV क्षेत्र को भूमि लागत, उच्च T&D नुकसान और अन्य अक्षमताओं तथा ग्रिड एकीकरण जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- पर्यावरण संबंधी चिंताएं: स्थानीय समुदायों और जैवविविधता संरक्षण मानदंडों के बीच भी टकराव की स्थिति रही है।
- **विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण की उपेक्षा:** सौर पीवी प्रौद्योगिकी के प्राथमिक लाभों में से एक यह है कि इसे खपत के बिंदु पर स्थापित किया जा सकता है, जिससे बड़े पूंजी-गहन संचरण बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को काफी कम किया जा सकता है। हालाँकि, नीति ने रूफ टॉप सोलर (RTS) खंड की उपेक्षा की है।
    - आवासीय उपभोक्ताओं और लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए सीमित वित्तपोषण है जो आरटीएस स्थापित करना चाहते हैं।
    - बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMS) की ओर से RTS के लिए नेट मीटरिंग का समर्थन करने पर भी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है।
- सौर मूल्य श्रृंखला में पिछड़ा एकीकरण अनुपस्थित है: भारत में सौर वेफर्स और पॉलीसिलिकॉन के निर्माण की कोई क्षमता नहीं है। वर्ष 2021-22 में भारत ने अकेले चीन से लगभग 76.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के सौर सेल और मॉड्यूल आयात किये, जो उस वर्ष भारत के कुल आयात का 78.6% था।
- **उपभोक्ताओं की लागत में कोई बदलाव नहीं आया:** इसके अलावा, भारत ने उपयोगिता पैमाने के खंड में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए रिकॉर्ड कम टैरिफ हासिल किया है, यह अंतिम उपभोक्ताओं के लिए सस्ती बिजली में तब्दील नहीं हुआ है।

भारत की घरेलू सौर मॉड्यूल निर्माण क्षमता की स्थिति क्या है?

- कम विनिर्माण क्षमता और चीन से सस्ते आयात ने भारतीय उत्पादों को घरेलू बाज़ार में गैर-प्रतिस्पर्द्धी बना दिया है।
- हालाँकि यदि भारत सौर प्रणालियों के लिये एक 'सर्कुलर अर्थव्यवस्था मॉडल' को अपनाता है, तो इस स्थिति में आसानी से सुधार किया जा सकता है।
- यह सौर पीवी कचरे को सौर पीवी आपूर्ति श्रृंखला में पुनर्नवीनीकरण और पुन: उपयोग करने की अनुमति देगा।
- वर्ष 2030 के अंत तक, भारत में लगभग 34,600 मीट्रिक टन सौर पीवी कचरे का उत्पादन होने की संभावना है।
- अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) का अनुमान है कि सौर PV अपशिष्ट से पुनर्प्राप्त करने योग्य सामग्री का वैश्विक मूल्य $15 बिलियन से अधिक हो सकता है। वर्तमान में केवल यूरोपीय संघ ने सोलर PV अपशिष्ट के प्रबंधन में निर्णायक कदम उठाए हैं।
- भारत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) के आसपास उपयुक्त दिशा-निर्देश विकसित करने पर विचार कर सकता है, जिसका अर्थ है कि सौर पीवी उत्पादों के समग्र जीवन चक्र के लिये निर्माताओं को उत्तरदायी बनाया जाएगा और अपशिष्ट पुनर्चक्रण हेतु मानक विकसित किये जाएंगे।
- यह घरेलू निर्माताओं को प्रतिस्पर्द्धा में बढ़त दे सकता है और अपशिष्ट प्रबंधन एवं आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को दूर करने में महत्त्वपूर्ण हो सकता है।

	आगे की राह • सरकारों, विभिन्न इकाइयों और बैंकों को ऐसे नवीन वित्तीय तंत्रों की तलाश करने की आवश्यकता होगी जो ऋण की लागत में कमी और उधारदाताओं के लिये निवेश के जोखिम को कम करते हों। • जागरूकता में वृद्धि और RTS परियोजनाओं के लिये किफायती वित्त संभावित रूप से देश भर में एसएमईऔर घरों में आरटीएस का प्रसार सुनिश्चित कर सकता है। • छत के रिक्त स्थान का उपयोग करने से RTS स्थापित करने की समग्र लागत को कम करने और अर्थव्यवस्था के परिमाणात्मक विकास को सक्षम करने में मदद मिल सकती है। • अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) निवेश जुटाने, क्षमता निर्माण, कार्यक्रम का समर्थन करने और विश्लेषण जैसी सहयोग की सुविधा के लिए देशों को एक साथ लाने हेतु एक वैश्विक मंच भी उपलब्ध है। • भविष्य में प्रौद्योगिकी साझाकरण और वित्त भी ISA के महत्त्वपूर्ण पहलू बन सकते हैं, जिससे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देशों के बीच सार्थक सहयोग की अनुमति मिल सकती है।
प्लास्टिक प्रदूषण पर प्रस्तावित वैश्विक संधि	**संदर्भ:** 2 मार्च, 2022 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) ने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए वर्ष 2024 तक एक अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी कानूनी साधन की ओर को अपनाने के लिए मतदान किया। • यह निर्णय केन्या के नैरोबी में UNEA के पांचवें सत्र में लिया गया है और 175 देशों के प्रतिनिधियों ने इस पर सहमति व्यक्त की है। **प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभाव** • 1950 के बाद से प्लास्टिक का सालाना उत्पादन तेजी से बढ़ा है और वैश्विक उत्पादन की बात करें तो पहले ये 2 मिलियन टन हुआ फिर 2017 में ये आंकड़ा 348 मिलियन टन हुआ और अब 2040 तक इस आंकड़े के दो गुना बढ़त का अनुमान है। • प्लास्टिक का एक्सपोजर मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है, संभावित रूप से प्रजनन क्षमता, हार्मोनल, चयापचय और तंत्रिका संबंधी गतिविधि को प्रभावित कर सकता है, और प्लास्टिक को खुले में जलाने से वायु प्रदूषण में योगदान होता है। • वर्ष 2050 तक प्लास्टिक उत्पादन, उपयोग और निपटान से जुड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस (34.7 डिग्री फारेनहाइट) तक सीमित करने के लक्ष्य के तहत अनुमानित उत्सर्जन का 15 प्रतिशत होगा। • अंतर्ग्रहण, उलझाव और अन्य खतरों से इस प्रदूषण से 800 से अधिक समुद्री और तटीय प्रजातियां प्रभावित हुई हैं। • लगभग 11 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रतिवर्ष महासागरों में प्रवाहित होता है।यह 2040 तक तीन गुना हो सकता है। **संकल्प (resolution) क्या है?** • प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए UNEA के प्रस्ताव ने एक अंतर सरकारी वार्ता समिति (INC) की स्थापना की, यह वर्ष 2024 तक अपना मसौदा समझौता प्रस्तुत करेगा। • इस उपकरण की प्रकृति में कानूनी रूप से बाध्यकारी होने की उम्मीद है और इसमें प्लास्टिक के पूर्ण जीवन चक्र के साथ-साथ पुन: प्रयोज्य और पुन: प्रयोज्य उत्पादों तथा सामग्रियों के डिजाइन के विकल्प शामिल होंगे। • इस प्रस्ताव में संधि के कार्यान्वयन में निजी क्षेत्र और हितधारकों की भूमिका को भी मान्यता दी गई है और समाज के लिए प्लास्टिक के महत्व को ध्यान में रखते हुए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर कार्रवाई को बढ़ावा दिया गया है। **नई संधि के पीछे क्या विचार हैं?** • वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने की संधि, उत्पाद डिजाइन से लेकर अपशिष्ट प्रबंधन तक, प्लास्टिक के पूरे जीवनचक्र में विश्वव्यापी दायित्वों और उपायों जैसे तत्वों पर ध्यान केंद्रित करेगी। • प्लास्टिक प्रदूषण संधि में संकल्प की नीतियों के लिए प्रासंगिक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने और इसके कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता में मदद करने के लिए तंत्र भी शामिल होंगे। • यह पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए स्वदेशी समुदायों और उनकी सदियों पुरानी प्रथाओं के महत्व की भी पहचान करता है और इन समुदायों के ज्ञान को आईएनसी द्वारा ध्यान में रखने का आह्वान करता है। • यह संधि प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में राष्ट्रीय कार्य योजनाओं और

	राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहकारी उपायों को ध्यान में रखेगी।
	• इन विचारों के अलावा, जिनमें से अधिकांश कार्यान्वयन पूर्व चरणों में हैं, संकल्प सदस्य राज्यों के लिए प्रगति मूल्यांकन सहित विचार भी करेगा।
	निष्कर्ष
	• वृत्ताकार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है
	  ○ वर्ष 2040 तक महासागरों में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक की मात्रा को 80 फीसदी से अधिक कम करना;
	  ○ वर्ष 2040 तक सरकारों को 70 अरब अमेरिकी डॉलर बचाना;
	  ○ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 25 प्रतिशत तक कम करना;
	  ○ मुख्य रूप से वैश्विक दक्षिण में 700,000 अतिरिक्त रोजगार सृजित करना

मुंबई जलवायु कार्य योजना (एमसीएपी)	**संदर्भ:** महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों राज्य की राजधानी में एक कार्यक्रम में मुंबई जलवायु कार्य योजना (एमसीएपी) का शुभारंभ किया।
	• यह योजना अनिवार्य रूप से उत्सर्जन को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए पेरिस समझौते में उल्लिखित जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
	• विश्व संसाधन संस्थान (डब्ल्यूआरआई) भारत के समर्थन से ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) द्वारा योजना का मसौदा तैयार किया गया है।
	• इस पहल में महाराष्ट्र सरकार के साथ भागीदारी करने वाले अन्य संगठन C40 सिटीज नेटवर्क, क्लाइमेट वॉयस महाराष्ट्र और वातावरण (Waatavaran) हैं। मुंबई वर्ष 2020 में C40 सिटीज नेटवर्क में शामिल हुआ था।
	C40 शहरों का नेटवर्क क्या है?
	• C40 सिटीज क्लाइमेट लीडरशिप ग्रुप दुनिया भर के 97 शहरों का एक संघ है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से लड़ना और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है।
	• यह समूह विश्व की आबादी के बारहवें हिस्से और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के एक चौथाई का प्रतिनिधित्व करता है।
	• C40 की पहल का लक्ष्य अपने सदस्य शहरों के उत्सर्जन को एक दशक के भीतर आधा करना है।
	• समूह की सदस्यता प्रदर्शन-आधारित आवश्यकताओं से आती है।
	• वर्तमान में पांच भारतीय शहर C40 नेटवर्क का हिस्सा हैं। ये दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और मुंबई है।
	एमसीएपी के प्रमुख कार्य क्षेत्र क्या हैं?
	• **सतत अपशिष्ट प्रबंधन:** एमसीएपी का उद्देश्य स्रोत पर पृथक्करण, जैविक अपशिष्ट खाद आदि जैसे कार्यों को लागू करके नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन का विकेंद्रीकरण करना है। यह 4R दृष्टिकोण पर जोर देता है, जैसे कम करें, पुन: उपयोग करें, पुनर्प्राप्त करें, रीसायकल करें, और अपशिष्ट जल के उपचार के लिए भी कॉल करें।
	• **शहरी हरियाली और जैव विविधता:** मुंबई में देश में प्रति व्यक्ति ग्रीन स्पेस अनुपात सबसे कम है।
	  ○ जैव विविधता की बहाली और वृद्धि एमसीएपी की कुछ प्राथमिक चिंताएं हैं।
	  ○ इसमें तापमान में वृद्धि को कम करने, गर्मी की लहरों के प्रभाव को कम करने और शहरी बाढ़ को रोकने के लिए वनस्पति आवरण बढ़ाना शामिल है। इस नीति में सभी नागरिकों के लिए हरित स्थान का उपयोग करने का भी आह्वान किया गया है।
	• **शहरी बाढ़ और जल संसाधन प्रबंधन:** एमसीएपी सुरक्षित और किफायती पेयजल की कमी से निपटने के साथ-साथ जलभराव और बाढ़ के कारण होने वाली समस्याओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
	  ○ जलवायु कार्य योजना का उद्देश्य शहर में जल निकासी नेटवर्क में और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली में सुधार करके एवं कमजोर तथा तटीय समुदायों को संवेदनशील बनाकर शहर में बाढ़ प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है।
	  ○ यह उन नीतियों को भी बढ़ावा देता है जो पानी के पुन: उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बढ़े हुए रिसाव और वर्षा जल संचयन जैसे उपायों के माध्यम से पानी के पुन: उपयोग को बढ़ावा देते हैं।
	• **ऊर्जा और भवन:** मुंबई को उत्सर्जन मुक्त बनाने की रणनीति में बिजली ग्रिड में कार्बन की भूमिका को कम करना और स्वच्छ ईंधन संसाधनों के संक्रमण को बढ़ावा देना शामिल है।
	  ○ MCAP का लक्ष्य नए और मौजूदा दोनों बुनियादी ढांचे में ऊर्जा दक्षता में सुधार और हरित भवनों को बढ़ावा देकर इस लक्ष्य को प्राप्त करना है।

	• **वायु गुणवत्ता:** इस कार्य योजना के अनुसार, वायु गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक कदम प्रदूषण के स्तर को कम करना है। मुंबई को भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में स्थान दिया गया है। • **सतत गतिशीलता:** इस कार्य योजना के अनुसार, मुंबई में ईंधन से चलने वाले वाहनों के विपरीत इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने के लिए जोर देना होगा। नीति सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के उपयोग को भी प्रोत्साहित करती है, जो बदले में, स्वच्छ हवा, यात्रा में समय कम लग्न और सड़कों पर भीड़भाड़ को कम करेगी। **मुंबई को जलवायु योजना की आवश्यकता क्यों है?** • 1973 के बाद से, मुंबई में प्रति दशक औसतन 0.25 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ लगातार गर्म जलवायु की प्रवृत्ति देखी गई है। • 1973 और 2020 के बीच, शहर को 10 हीटवेव और दो अत्यधिक हीटवेव का सामना करना पड़ा। • मुंबई में भी हाल के वर्षों में बाढ़ में वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2005, 2014 और 2017 की बाढ़ से शहर में जान-माल का काफी नुकसान हुआ। • मुंबई की आबादी भी वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील है, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में जहां खराब वेंटिलेशन, गैर-एलपीजी खाना पकाने के ईंधन के उपयोग या व्यावसायिक खतरों के कारण वायु प्रदूषकों की सांद्रता बढ़ जाती है। इन सभी कारकों ने मुंबई के निवासियों के लिए जलवायु जोखिम को कम करने हेतु एमसीएपी के विकास में योगदान दिया है।

जल प्रबंधन को एक जल-सामाजिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है

संदर्भ: ताज़े जल स्रोत के संसाधन तनाव में हैं, प्रमुख चालक उनके विभिन्न रूपों में मानवीय गतिविधियाँ हैं।

जल प्रबंधन के लिए किस दृष्टिकोण की आवश्यकता है?

- विश्व स्तर पर यह अनुमान लगाया गया है कि यदि वर्तमान पद्धति जारी रहती है तो ताजे पानी की मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर वर्ष 2030 तक 40% तक पहुंच सकता है।
- नवीनतम संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट, 2021, जिसका शीर्षक 'पानी का मूल्यांकन' है, ने पांच परस्पर संबंधित दृष्टिकोणों पर विचार करके पानी के उचित मूल्यांकन का आह्वान किया है:
  - जल स्रोत
  - जल अवसंरचना
  - जल सेवाएं
  - उत्पादन और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक इनपुट के रूप में पानी
  - पानी के सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्य

मीठे पानी की व्यवस्था को प्रभावित करने वाले मानवजनित कारक क्या हैं?

मीठे पानी की व्यवस्था को सीधे प्रभावित करने वाले मानवजनित कारक हैं:

- नदी चैनलों की इंजीनियरिंग (engineering of river channels)
- सिंचाई और पानी का अन्य उपभोग्य उपयोग
- व्यापक भूमि उपयोग/भूमि आवरण परिवर्तन
- जलीय आवास में परिवर्तन
- बिंदु और गैर-बिंदु स्रोत प्रदूषण पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करता है
- सभी क्षेत्रों में जल संसाधनों का अकुशल उपयोग
- प्राकृतिक भंडारण क्षमता में कमी
- जलग्रहण क्षमता में गिरावट

जल असंतुलन को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

- किसी दिए गए क्षेत्र के भीतर जल संसाधनों के प्राकृतिक रूप से प्रचलित असमान वितरण के कारण पानी की उपलब्धता में असंतुलन को दूर करने के लिए पानी का इंट्रा- और इंटर-बेसिन ट्रांसफर (IBT) एक प्रमुख हाइड्रोलॉजिकल हस्तक्षेप है।
- दुनिया भर में लगभग 110 जल अंतरण मेगा परियोजनाएं हैं जिन्हें या तो क्रियान्वित किया गया है (34 परियोजनाएं) या योजना बनाई जा रही है/निर्माणाधीन (76 परियोजनाएं)।
- भारत की राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना (1970 में प्रस्तावित और 1999 में पुनर्जीवित) निर्माणाधीन परियोजनाओं में से एक है।

जल दृष्टिकोण के आईबीटी के साथ कुछ मुद्दे क्या हैं?

- सरप्लस और डेफिसिट बेसिन का मुकाबला: आईबीटी का मूल आधार अधिशेष बेसिन से घाटे वाले बेसिन में पानी का निर्यात करना है। हालाँकि, अधिशेष और घाटे के बेसिन की अवधारणा पर ही विवाद है क्योंकि यह अभ्यास काफी हद तक हाइड्रोलॉजिकल है। जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, औद्योगीकरण और घटती वर्षा एक बेसिन के अधिशेष चरित्र पर चिंता बढ़ा रही है।
- दूषित जल के उपयोग में कमी: यह अनुमान लगाया गया है कि घरेलू जल का 55% से 75% उपयोग दूषित जल में परिवर्तित हो जाता है।
- जल के बुनियादी ढांचे का क्षमता उपयोग: वर्ष 2016 तक, भारत ने 112 मिलियन हेक्टेयर के लिए एक सिंचाई क्षमता बनाई, लेकिन सकल सिंचित क्षेत्र 93 मिलियन हेक्टेयर था। यह 19% का अंतर है, जो नहर सिंचाई के मामले में अधिक है।
  - 1950-51 में, नहर सिंचाई कुल सिंचित क्षेत्र का 40% योगदान करती थी, लेकिन 2014-15 तक, नहर सिंचाई के तहत शुद्ध सिंचित क्षेत्र 24% से कम हो गया।
  - भूजल सिंचाई अब शुद्ध सिंचित क्षेत्र के 62.8% को कवर करती है।
  - भारत में सिंचाई परियोजनाओं की औसत जल उपयोग दक्षता विकसित देशों के मामले में 50% - 60% के मुकाबले केवल 38% है।

	○ चावल और गेहूँ, जो कृषि उत्पादन के 75% से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं, ये क्रमशः 2,850 m3/टन और 1,654 m3/टन पानी का उपयोग करते हैं। इसी क्रम में वैश्विक औसत 2,291m3/टन और 1,334m3/टन है। ○ भारत में कृषि क्षेत्र कुल जल उपयोग का लगभग 90% उपयोग करता है। ○ औद्योगिक संयंत्रों में, अन्य देशों में समरूप संयंत्रों के उत्पादन की प्रति इकाई खपत से 2 गुना से 3.5 गुना अधिक है। ○ इसी तरह, घरेलू क्षेत्र में रिसाव के कारण पानी की 30% से 40% का नुकसान होता है। • मुद्दे की संवेदनशील प्रकृति: जल परियोजनाएं राजनीतिक रूप से चार्ज और सामाजिक संबंधों, सामाजिक शक्ति और प्रौद्योगिकी के परस्पर क्रिया को प्रकट करती हैं। **आगे की राह** समय की मांग है • स्रोत स्थिरता • पारंपरिक जल संचयन संरचनाओं का नवीनीकरण और रखरखाव • भूजल प्रबंधन बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना • भूजल पुनर्भरण • जल उपयोग दक्षता बढ़ाना और पानी का पुन: उपयोग करना • निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में गैर-राज्य अभिनेताओं को शामिल करना **निष्कर्ष** • एक हाइब्रिड जल प्रबंधन प्रणाली आवश्यक है, जहां (पेशेवरों और नीति निर्माताओं के साथ) मूल्य श्रृंखला में व्यक्ति, समुदाय और समाज की निश्चित भूमिका होती है। चुनौती तकनीकी केंद्रित नहीं बल्कि मानवजनित होने की है। **क्या आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं?** 1. क्या आपको लगता है कि भारत में जल प्रबंधन के लिए नदी को आपस में जोड़ना सबसे उपयुक्त तरीका है? समालोचनात्मक जाँच करें। 2. देश के विभिन्न हिस्सों में सूखे और बाढ़ से लड़ने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने का विचार आर्थिक रूप से विवेकपूर्ण हो सकता है लेकिन इसके पारिस्थितिक परिणाम अन्य लाभों से कहीं अधिक हैं। आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए।
अमेज़ॅन वर्षावन का 75% से अधिक एक अस्थिर बिंदु (टिपिंग पॉइंट) के पास, शुष्क सवाना में बदल सकता है: अध्ययन	**चर्चा में:** नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार, अमेज़ॅन वर्षावन का 75% से अधिक भाग 2000 के दशक से एक अस्थिर बिंदु (टिपिंग पॉइंट) की ओर बढ़ रहा है। • शोधकर्ताओं ने पाया कि वन सूखे या आग जैसी चरम घटनाओं से स्थिति में सुधार की अपनी क्षमता खो रहा है, जिससे शुष्क सवाना जैसा पारिस्थितिकी तंत्र बनने का संकट है। यह संक्रमण अमेज़ॅन की समृद्ध जैव विविधता, कार्बन-भंडारण क्षमता और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। • शोधकर्ताओं ने इन निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए उपग्रह डेटा और सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग किया। अमेज़ॅन के वर्षावन में विश्व की लगभग 30 प्रतिशत प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें 40,000 पौधों की प्रजातियाँ, 16,000 वृक्षों की प्रजातियाँ, 1,300 पक्षियों तथा स्तनधारियों की 430 से अधिक प्रजातियां सम्मिलित हैं। **अमेज़ॅन बेसिन** • 60 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला, यह भारत के आकार से लगभग दुगना है। • अमेज़ॅन वर्षावन बेसिन के लगभग 80 प्रतिशत हिस्से को कवर करते हैं। • इसके अलावा, यह दुनिया की लगभग पांचवीं भूमि प्रजातियों और सैकड़ों स्वदेशी समूहों एवं कई अलग-अलग जनजातियों सहित लगभग 30 मिलियन लोगों का घर है। • बेसिन दुनिया के ताजे पानी के प्रवाह का लगभग 20% महासागरों में पैदा करता है **यह पहली बार नहीं है** • एक पिछले अध्ययन ने भविष्यवाणी की थी कि जब वर्षावन में लगभग 20-25 प्रतिशत वनों की कटाई होती है, तो एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा। • वनों की कटाई बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जनवरी 2022 में इसका कुल क्षेत्रफल 430 वर्ग किलोमीटर था,

	जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में पांच गुना ज्यादा है। **अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा?** ● यह नुकसान वर्षा की मात्रा को प्रभावित करेगा। पेड़ जड़ों के माध्यम से पानी ग्रहण करते हैं, इसे वातावरण में योगदान करते हैं, दक्षिण अमेरिका में वर्षा को प्रभावित करते हैं, बोअर्स ने समझाया। ● वर्षावन भी एक कार्बन सिंक है - एक ऐसा स्थान जो जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है उससे अधिक अवशोषित करता है। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई के कारण बढ़ते तापमान वर्षावन को कार्बन स्रोत में बदलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं: वे स्थान जो अवशोषित होने से अधिक CO_2 छोड़ते हैं। ● शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि वन आंशिक रूप से शुष्क आवासों में परिवर्तित हो जाते हैं तो वे भारी मात्रा में CO_2 छोड़ सकते हैं। ● विश्लेषण से पता चला है कि कम वर्षा वाले और मानव भूमि उपयोग के करीब वाले क्षेत्रों में टिपिंग पॉइंट के संकेतक तेजी से ऊपर जाते हैं। ● इससे पता चलता है कि सुखाने की स्थिति में लचीलापन हानि हो सकती है। ● शोधकर्ताओं के अनुसार मानव भूमि-उपयोग गतिविधियाँ - पेड़ों को सीधे हटाना, सड़कों का निर्माण और आग - एक अन्य योगदानकर्ता हो सकता है। यह 2010 से बढ़ रहा है। **निष्कर्ष** कार्रवाई करने में देरन करके प्राथमिकता देनी चाहिए - ● वनों की कटाई को कम करने से जंगल के खतरे वाले हिस्सों की रक्षा होगी और अमेज़ॅन वर्षावन के लचीलेपन को बढ़ावा मिलेगा। ● अमेज़न की सुरक्षा के लिए वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करना भी आवश्यक है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

प्रसवोत्तर रक्तस्राव केरल में मातृ मृत्यु का प्रमुख कारण बना हुआ है: रिपोर्ट	**चर्चा में:** केरल फेडरेशन ऑफ ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रसवोत्तर रक्तस्राव (पीपीएच) पिछले दशक के बेहतर हिस्से के लिए केरल में मातृ मृत्यु का एक प्रमुख कारण रहा है। मातृ मृत्यु की गोपनीय समीक्षा शीर्षक से रिपोर्ट पिछले साल जारी की गई थी। ● वर्ष 2019-2020 में दर्ज 133 मातृ मृत्यु में से 17 पीपीएच के कारण और 19 आत्महत्या के कारण थे। ● भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल के अनुसार, सभी मातृ मृत्यु में पीपीएच का हिस्सा 35 प्रतिशत है। **प्रसवोत्तर रक्तस्राव (पीपीएच)** PPH को आमतौर पर जन्म के 24 घंटे के भीतर 500 मिलीलीटर या उससे अधिक के रक्त के नुकसान के रूप में परिभाषित किया जाता है, जबकि गंभीर PPH को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार एक ही समय सीमा के भीतर 1000 मिलीलीटर या उससे अधिक के रक्त नुकसान के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रसवोत्तर रक्तस्राव की घटनाएं 1-5 प्रतिशत ही हैं। यह ज्यादातर प्लेसेंटा के डिलीवर होने के बाद होता है, लेकिन यह बाद में भी हो सकता है। **प्रसवोत्तर रक्तस्राव का क्या कारण है?** ● एक बार प्रसव होने के बाद, गर्भाशय फिर से अपरा और उसकी झिल्ली को बाहर निकालने के लिए सिकुड़ता है। यह रक्त वाहिकाओं पर भी दबाव डालता है जो अपरा से भी जुड़ी होती हैं और रक्तस्राव का कारण बनती हैं। इसलिए यदि गर्भाशय ठीक से सिकुड़ता नहीं है, तो रक्त वाहिकाओं से स्वतंत्र रूप से रक्तस्राव होता रहता है। ● यदि अपरा के छोटे-छोटे टुकड़े जुड़े रहते हैं, तो रक्तस्राव होने की भी संभावना होती है। **प्रसवोत्तर रक्तस्राव के कारण भी हो सकते हैं:** ● गर्भाशय ग्रीवा के ऊतकों में टीअर ● गर्भाशय में रक्त वाहिका में टीअर ● हेमेटोमा फार्मेशन ● गर्भाशय का उलटा होना

	● खून का थक्का जमने से संबंधित विकार ● प्लेसेंटा की समस्या **आगे की राह** पीपीएच मातृ मृत्यु का एक प्रमुख कारण होने के कारण न केवल एक देशव्यापी प्रवृत्ति है बल्कि अन्य कम आय वाले देशों में भी देखी गई है। ● पीपीएच की घटनाओं को उचित प्रबंधन, एनीमिया को ठीक करके, प्रसव के लिए एक प्रशिक्षित डॉक्टर को शामिल करके और गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच के बारे में जागरूक करके रोका जा सकता है। ● गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल, श्रम के तीसरे चरण के सक्रिय प्रबंधन द्वारा जन्म के समय कुशल देखभाल, उच्च गुणवत्ता वाली आपातकालीन प्रसूति देखभाल (प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों और पर्याप्त बुनियादी ढांचे के साथ) की उपलब्धता और इन सेवाओं तक बेहतर पहुंच कई मातृ जीवन को बचाने के लिए आवश्यक है। ● सरकार को गर्भवती महिलाओं के लिए समर्थन नेटवर्क की एक विस्तृत श्रृंखला बनाने की आवश्यकता है - ○ अच्छी गुणवत्ता वाले पोषण तक पहुंच - अधिक प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम युक्त भोजन जटिलताओं से निपटने के लिए उनकी सहनशक्ति का निर्माण करता है। ○ एनीमिया के मामलों को कम करना ○ अच्छी प्रसवपूर्व देखभाल तक पहुंच का प्रावधान ○ दूसरे बच्चों के लिए 2-3 साल का अंतर रखने के लिए परामर्श ○ सभी सरकारी अस्पतालों में तृतीयक देखभाल का प्रावधान ○ गर्भवती महिलाओं को मासिक जांच के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए और उनकी डिलीवरी नजदीकी अस्पतालों में होनी चाहिए। ○ महिलाओं को इस बारे में शिक्षित करने के लिए ग्राम स्तर पर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जानी चाहिए। **क्या आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं?** 1. प्रसवोत्तर रक्तस्राव से हर 5 मिनट में एक भारतीय महिला की मृत्यु हो जाती है। इस देशव्यापी प्रवृत्ति को रोकने के उपाय सुझाएं।
मैन-पोर्टेबल एयर-डिफेंस सिस्टम (MANPADS)	**संदर्भ:** 13 मार्च को, संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति जो बिडेन ने यूक्रेन के लिए $200 मिलियन के हथियारों के पैकेज को मंजूरी दी, जिसमें यूएस निर्मित स्टिंगर मिसाइलें शामिल होंगी, जो एक प्रकार की कंधे से चलने वाली मैन-पोर्टेबल एयर-डिफेंस सिस्टम (MANPADS) हैं। ● मार्च के पहले सप्ताह में ही अमेरिका और नाटो द्वारा 17,000 से अधिक टैंक रोधी हथियार और 2,000 स्टिंगर मिसाइलें भेजी जा चुकी हैं। **MANPADS क्या हैं?** ● मैन-पोर्टेबल एयर-डिफेंस सिस्टम कम दूरी की हल्की और पोर्टेबल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं

जिन्हें विमान या हेलीकॉप्टर को नष्ट करने के लिये प्रयोग किया जा सकता है।

- ये हवाई हमलों से सैनिकों की सुरक्षा करने में मदद करते हैं और कम उड़ान वाले विमानों को निशाना बनाने में सबसे प्रभावी होते हैं।
- 'मैन-पोर्टेबल एंटी-टैंक सिस्टम' (MANPAT) भी इसी प्रकार कार्य करते हैं लेकिन इसका उपयोग सैन्य टैंकों को नष्ट या अक्षम करने हेतु किया जाता है।
- MANPADS को कंधे से फायर किया जा सकता है, एक जमीनी वाहन के ऊपर से लॉन्च किया जा सकता है, एक तिपाई या स्टैंड से और एक हेलीकॉप्टर या नाव से दागा जा सकता है।
- इनका वज़न 10 से 20 किलोग्राम के बीच होता है और इनकी ऊँचाई 1.8 मीटर से अधिक नहीं होती है। ये अन्य हथियार प्रणालियों की तुलना में काफी हल्के होते हैं, जिससे उन्हें सैनिकों द्वारा संचालित करना आसान होता है।
- MANPADS के संचालन के लिए काफी कम प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।
- MANPADS की अधिकतम सीमा 8 किलोमीटर है और यह 4.5 किमी की ऊंचाई पर लक्ष्य को भेद सकती है।
- इनमें से अधिकांश में निष्क्रिय या 'फायर एंड फॉरगेट' मार्गदर्शन प्रणाली मौज़ूद है, जिसका अर्थ है कि ऑपरेटर द्वारा मिसाइल को अपने लक्ष्य तक ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है, इससे उन्हें फायरिंग के तुरंत बाद चलाने और स्थानांतरित करने में मदद मिलती है।
- मिसाइल लक्षित वस्तु पर लॉक-ऑन रहती है, सैनिक से सक्रिय मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है।
- मिसाइलों में इन्फ्रारेड (IR) अन्वेषक लगे होते हैं जो वायुवाहित वाहन को उत्सर्जित ऊष्मा विकिरण के माध्यम से पहचानते हैं और लक्षित करते हैं।

पहले MANPADS का उपयोग कब किया जाता था?

- पहला MANPADS 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वियतनाम युद्ध के दौरान रूसी और यू.एस. MANPADS का भी उपयोग किया गया था।
- अमेरिका ने 1980 के दशक में अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को MANPADS की आपूर्ति की, जिसे बाद में सोवियत सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया गया।
- भारत, पाकिस्तान, जर्मनी, यू.के., तुर्की और इज़राइल जैसे देशों ने भी अपने रक्षा प्रयासों में MANPADS का उपयोग किया है।
- वर्ष 2019 तक 20 देशों ने MANPADS के निर्माण के लिए साधन विकसित किए थे और रक्षा एवं निर्यात उद्देश्यों के लिए मिलकर 1 मिलियन ऐसी प्रणालियाँ बनाई हैं।
- समय के साथ, विद्रोही और आतंकवादी समूहों जैसे गैर-राज्य अभिनेताओं ने भी अवैध रूप से MANPADS हासिल कर लिया है, उनका उपयोग गृह युद्धों और अन्य उच्च-तीव्रता वाले संघर्षों के दौरान किया जाता है।
    - MANPADS का उपयोग सीरियाई युद्ध और लीबिया में किया गया है। सूडान, दक्षिण सूडान, अंगोला, सोमालिया और कांगो जैसे अफ्रीकी देशों में गैर-राज्य समूहों ने भी MANPADS का अधिग्रहण और उपयोग किया है।
- अब तक रूस MANPADS का सबसे बड़ा निर्यातक है, जो 2010 और 2018 के बीच इराक, कतर, कजाकिस्तान, वेनेजुएला और लीबिया सहित विभिन्न देशों को 10,000 से अधिक ऐसे सिस्टम बेचे हैं।

MANPADS के सामान्य रूप क्या हैं?

- MANPADS का सबसे आम निर्माण यू.एस. निर्मित स्टिंगर मिसाइल है। इनका वजन लगभग 15 किलोग्राम है, इनकी सीमा 4,800 मीटर या 4.8 किमी है, और ये 3,800 मीटर की ऊंचाई पर कम-उड़ान वाले विमानों को शामिल कर सकते हैं। उनके पास एक निष्क्रिय मार्गदर्शन प्रणाली है, जो इन्फ्रारेड तकनीक का उपयोग करती है।
- स्टिंगर के रूसी या सोवियत निर्मित समकक्ष इग्ला MANPADS हैं, जो इन्फ्रारेड तकनीक का भी उपयोग करते हैं। वर्ष 2003 में जब अमेरिका द्वारा आक्रमण किया तब इराक में उनका उपयोग किया गया था। उदाहरण के लिए, भारत द्वारा सियाचिन संघर्ष के दौरान 1992 के ऑपरेशन त्रिशूल शक्ति के हिस्से के रूप में भी उनका उपयोग किया गया है।

	• Starstreak, ब्रिटिश सेना के स्टिंगर मिसाइलों के समकक्ष और U.K. यूक्रेन को Starstreaks के शिपमेंट के साथ प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार कर रहा है। • स्वीडन RBS-70 MANPADS सीरीज बनाता है जबकि चीन का संस्करण, FN-6, स्टिंगर के समान है। **यूक्रेन संकट में MANPADS कितने प्रभावी हैं?** • अभी भी यूक्रेन में सोवियत काल की कुछ लंबी दूरी की वायु-रक्षा प्रणालियाँ हैं जो रूसी विमानों को निशाना बना सकती हैं, यही वजह है कि रूस उन्हें कम ऊंचाई पर उड़ा रहा है, जो बदले में उन्हें MANPADS जैसी छोटी दूरी की प्रणालियों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। • रिपोर्टों से पता चलता है कि कम से कम 20 रूसी विमान - हेलीकॉप्टर और जेट यूक्रेन में वर्तमान संघर्ष शुरू होने के बाद से नीचे गिराए गए हैं। इस बीच, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने 48 रूसी विमानों और 80 हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है। • कीव स्थित राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान, सुरक्षा मुद्दों पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की को सलाह देने वाला एक संस्थान, ने कहा कि टैंक-रोधी और विमान-रोधी प्रणालियाँ "ठीक" हैं जिनकी यूक्रेन को अभी आवश्यकता है। **MANPADS के बारे में क्या चिंताएँ हैं?** • कई पर्यवेक्षकों ने बताया है कि यूक्रेन को MANPADS भेजने का इतना सकारात्मक प्रभाव नहीं हो सकता है। यू.एस. ने यूक्रेन को ऐसे हथियार भेजने में शामिल 'जोखिमों' का भी उल्लेख किया है। • माना जाता है कि यूक्रेन यूरोप में हथियारों की तस्करी के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। • वर्ष 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद, यूक्रेन की सहायता के लिए अन्य देशों द्वारा आपूर्ति किए गए हथियार कई मामलों में गलत हाथों में चले गए। • रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि राज्य के शस्त्रागार में हथियार अवैध रूप से प्राप्त किए गए थे और आपराधिक एवं गैर-राज्य विद्रोही समूहों द्वारा तस्करी की गई थी। • इस बीच, 2017 के स्मॉल आर्म्स सर्वे ने बताया कि यूक्रेन के पास 1.2 मिलियन कानूनी आग्नेयास्त्र और लगभग 4 मिलियन अवैध हथियार हैं, उनमें से बहुत सारे पूरी तरह से स्वचालित सैन्य हथियार हैं। • इस प्रकार, पर्यवेक्षकों को भय है कि यूक्रेन को हल्के जमीन आधारित MANPADS भेजने से अवैध हथियार व्यापार के नेटवर्क को तेज करने में योगदान हो सकता है। • अन्य संघर्ष-प्रभावित राज्यों में भी, MANPADS के गैर-राज्य और आतंकवादी समूहों के साथ समाप्त होने के व्यापक प्रमाण हैं; सबसे प्रमुख मामले सीरिया, लीबिया और अफगानिस्तान हैं। • MANPADS के आसपास एक और चिंता नागरिक हमले हैं, ऊपर उल्लिखित 2019 के अध्ययन के अनुसार, 1970 के दशक से MANPADS द्वारा 60 से अधिक नागरिक विमान प्रभावित हुए हैं, जिसमें 1,000 से अधिक नागरिकों के जीवन का दावा किया गया है।
भारत की मसौदा चिकित्सा उपकरण नीति	**संदर्भ:** सरकार उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरणों के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए एक नई नीति का प्रस्ताव कर रही है। **क्या आप जानते हैं?** • 2047 तक, हमारा देश मेडटेक में 25 सर्वोत्तम फ्यूचरिस्टिक तकनीकों का केंद्र और जननी होगा। और 10-12% की वैश्विक बाजार हिस्सेदारी के साथ 100-300 अरब डॉलर की आकार का मेडटेक उद्योग होगा। • विश्व स्तर पर, बाजार के 2025 तक $433 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है और वर्तमान में 40 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी (यूरोप में 25% और जापान 15% हिस्सेदारी) के साथ अमेरिका का वर्चस्व है। • चीन में, इस क्षेत्र का मूल्य लगभग 96 बिलियन डॉलर है और यह कई वर्षों से 20 प्रतिशत से अधिक की गति से बढ़ रहा है। **ऐसी नीति की क्या जरूरत है?** • वर्तमान में 80 प्रतिशत से अधिक चिकित्सा उपकरण भारत में आयात किए जाते हैं। • अंतरिक्ष में भारतीय प्रतिनिधियों ने अब तक आमतौर पर कम लागत वाले और कम तकनीक वाले उत्पादों, जैसे

उपभोग्य सामग्रियों और डिस्पोजेबल पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे विदेशी कंपनियों को उच्च मूल्य का हिस्सा मिल रहा है।

- नई नीति के तहत सरकार का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत की आयात निर्भरता को 80 प्रतिशत से घटाकर लगभग 30 प्रतिशत करना है, और वर्ष 2047 तक चिकित्सा उपकरणों के लिए शीर्ष पांच वैश्विक विनिर्माण केंद्रों में से एक बनना है।
- भारत के चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को अब तक औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया गया है, और चिकित्सा उपकरणों पर एक विशिष्ट नीति उद्योग की लंबे समय से मांग रही है।
    - जॉनसन एंड जॉनसन विवाद में भारत सरकार द्वारा कड़ा रुख अख्तियार करने के बाद कंपनी ने कहा है कि वह हिप इम्प्लांट से परेशान हुए भारतीय मरीजों के मुआवजे के मामले पर भारत सरकार के साथ काम करेगी।
- इस नीति का उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों पर भारत के प्रति व्यक्ति खर्च को बढ़ाना भी है। 47 डॉलर प्रति व्यक्ति खपत के वैश्विक औसत की तुलना में भारत में चिकित्सा उपकरणों पर सबसे कम प्रति व्यक्ति खर्च 3 डॉलर है।
- भारत प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में विनिर्माण अक्षमता की काफी लागत से ग्रस्त है, जिसे सुधारने की आवश्यकता है ताकि इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके।

वे कौन से कारक हैं जिनके कारण चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में घरेलू विकलांगता हुई है?

- पर्याप्त बुनियादी ढांचे का अभाव
- अक्षम घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और रसद
- वित्त की उच्च लागत
- बिजली की अपर्याप्त उपलब्धता
- सीमित डिजाइन क्षमताएं
- अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) और कौशल विकास पर कम फोकस
- अन्य देशों से सस्ता आयात उपलब्ध

मसौदा नीति के प्रमुख फोकस क्षेत्र क्या हैं?

- मसौदा नीति के मुख्य फोकस क्षेत्रों में मुख्य प्रौद्योगिकी परियोजनाओं और निर्यात को प्रोत्साहित करना शामिल है
    - टैक्स रिफंड और छूट
    - चिकित्सा उपकरणों को लाइसेंस देने के लिए सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम बनाना
    - महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करना
    - आपूर्ति श्रृंखला को जोखिम से मुक्त और डी-कार्बोनाइज़ करना
    - स्थानीय सोर्सिंग को बढ़ावा देना
    - क्रॉस-इंडस्ट्री सहयोग को प्रोत्साहित करना
    - विक्रेताओं और श्रमिकों का एक केंद्रीय पूल बनाना
    - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
    - अन्य बातों के अलावा, अनुसंधान और विकास में चिकित्सा प्रौद्योगिकी कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ाकर लगभग 50 प्रतिशत करना।
- यह मौजूदा उद्योग के खिलाड़ियों, प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों और स्टार्टअप्स को शामिल करते हुए संयुक्त अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए एक समर्पित फंड आवंटित करने का भी प्रस्ताव करता है।
- यह सभी नागरिकों को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए एक सुसंगत मूल्य निर्धारण विनियमन के लिए एक रूपरेखा भी शामिल करेगा। इस उद्देश्य के लिए एनपीपीए (नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी) को अधिकार दिया जाएगा।
- औषध विभाग, चिकित्सा उपकरण विपणन प्रथाओं (यूसीएमडीएमपी) के लिए एक समान कोड लागू करने के

	लिए उद्योग के साथ भी काम करेगा। **निष्कर्ष** ● भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग है, विशेष रूप से सभी चिकित्सा स्थितियों, बीमारियों, बीमारियों और विकलांगों की रोकथाम, निदान, उपचार और प्रबंधन के लिए। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** ● चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई योजना) ● स्टेंट पर सरकारी मूल्य नियंत्रण
सौर तूफान	**सौर तूफान क्या हैं?** ● जैसे सूर्य हमें प्रकाश और ऊष्मा भेजता रहता है, वैसे ही यह पृथ्वी सहित सभी दिशाओं में बहुत सी अन्य सामग्री को बाहर फेंकता है। ● सौर हवा सभी दिशाओं में सूर्य या किसी भी तारे से निकलने वाले आवेशित कणों की एक धारा है। सौर हवा ज्यादातर मुक्त प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों (प्लाज्मा) से बनी होती है, जिसमें लगभग 1 केवी (किलो-इलेक्ट्रॉन-वोल्ट) की ऊर्जा होती है। ● हम अपने चुंबकीय क्षेत्र द्वारा सौर हवा से सुरक्षित हैं, जो कणों को दूर कर देता है। **कोरोनल मास इजेक्शन क्या है?** ● कभी-कभी सूर्य से गैस का बुलबुला फट जाता है। इसे साबुन के पानी की बाल्टी से निकलने वाले बुलबुले की तरह कल्पना करें। ● यह बुलबुला, जिसमें आमतौर पर अरबों टन पदार्थ होता है, सौर हवा के माध्यम से हल करता है और कई मिलियन किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक यादृच्छिक दिशा में यात्रा करता है। ● ऐसा बुलबुला जो सूर्य के कोरोना से अलग हो गया है, उसे 'कोरोनल मास इजेक्शन' (CME) या 'सौर तूफान' कहा जाता है। ● यदि कोई सीएमई पृथ्वी की दिशा में आ रहा है, तो यह चिंता का विषय है। ● वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कुछ समय से ज्ञात है कि सूर्य उच्च (अधिकतम) और निम्न (न्यूनतम) सीएमई गतिविधि के चक्र से गुजरता है। अभी, एक उछाल है और यह कुछ वर्षों में अधिकतम तक पहुंच जाएगा। **वे क्यों होते हैं?** ● जिस प्रकार अलाव से चिंगारी निकलती है, उसी प्रकार सूर्य से पदार्थ का बाहर निकलना एक सामान्य घटना है। ● यह उतना ही स्वाभाविक है जितना कि पानी के कण कताई, गीली टेनिस बॉल से बाहर निकल रहे हैं। ● सूरज तेजी से घूम रहा है और यह स्पिन जटिल भंवर और एडी बनाता है। कभी-कभी पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के लूपों में फंस जाता है, जो हिंसक रूप से बाहर निकल जाता है। **सौर तूफान का क्या असर होगा?** ● यह सब व्यक्तिगत सौर तूफान पर निर्भर करता है। ● आमतौर पर, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र - मैग्नेटोस्फीयर - खतरनाक घुसपैठ को दूर करेगा; सीएमई तभी खतरा पैदा कर सकता है जब चुंबकीय क्षेत्र अभिभूत हो। ● पृथ्वी के सूर्य की ओर स्थित चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के उपग्रहों की सीमा के भीतर, लगभग 65,000 किमी तक फैला हुआ है। (वास्तव में, दिन की ओर चुंबकीय क्षेत्र सौर हवाओं द्वारा 65,000 किमी तक संकुचित हो जाता है, रात की तरफ, मैग्नेटोस्फीयर बहुत बड़ा होता है)। ● यदि एक बड़ा सीएमई होता है, तो कुछ उपग्रह खो सकते हैं; हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ● जहां तक पावर ग्रिड और टेलीकॉम नेटवर्क जैसी पृथ्वी-आधारित प्रणालियों का सवाल है, भले ही कोई बड़ा सीएमई धरती से टकराए, केवल ऊपरी और निचले अक्षांशों के देशों के प्रभावित होने का खतरा है। भूमध्य रेखा के पास होने के कारण भारत अपेक्षाकृत सुरक्षित है। **कितनी बड़ी समस्या है?**

	• यह व्यक्तिगत सीएमई पर निर्भर करता है। कभी-कभी, एक बड़ा सौर तूफान ढीला हो सकता है और पृथ्वी की ओर गिर सकता है; और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। • अगर हम इसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं, तो हम उपग्रह प्रक्षेपणों को फिर से निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन सीएमई के लिए उनकी घटना से पहले पर्याप्त भविष्यवाणी करना मुश्किल है। • यदि हम इसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं, तो हम उपग्रह प्रक्षेपणों को पुनर्निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन सीएमई के लिए उनकी घटना से पहले पर्याप्त भविष्यवाणी करना मुश्किल है। • पृथ्वी से टकराने वाला एक बड़ा सौर तूफान सदी में एक बार आ सकता है। • आखिरी बड़ा 1859 में था। 'कैरिंगटन इवेंट' ने कई दिनों तक टेलीग्राफ और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को बंद कर दिया। • अगर आज 1859 प्रकार का सौर तूफान पृथ्वी से टकराता, तो अकेले अमेरिका को 2.6 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता था।
COVID की तरह, TB एक महामारी है और इसे एक आपात स्थिति के रूप में माना जाना चाहिए	**संदर्भ:** वर्ष 1993 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने तपेदिक (टीबी) को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। यह राष्ट्रों से लाखों मौतों को रोकने के प्रयासों में समन्वय करने का आग्रह किया। जनवरी 2020 में, WHO ने COVID-19, एयरबोर्न नाम की एक दूसरी बीमारी अंतरराष्ट्रीय चिंता को बढ़ा दिया जिससे राष्ट्रों को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करना पड़ा। इन दो महामारियों के लिए वैश्विक प्रतिक्रियाओं के बीच समानता वहीं समाप्त होती है। पिछले दो वर्षों में COVID-19 के प्रति वैज्ञानिक, सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा और दवा समुदायों की प्रतिक्रियाएँ शानदार रही हैं। • COVID-19 को वैश्विक आपातकाल घोषित करने के दो सप्ताह के भीतर, WHO ने विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाई थी और एक शोध रोडमैप जारी किया था। राष्ट्रीय सरकारों ने बुनियादी वायरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी से लेकर क्लीनिकल देखभाल और रोकथाम तक सभी स्तरों पर अनुसंधान के लिए बड़ी मात्रा में धन की प्रतिबद्धता की। दवा कंपनियों ने COVID-19 के निदान, उपचार और रोकथाम के लिए नए उत्पादों के लिए विकास कार्यक्रम शुरू किए। नतीजतन, निदान, चिकित्सीय और टीके तेज गति से बनाये गए, जो SARS-CoV-2 महामारी को नियंत्रित करने और समाप्त करने के लिए उपकरणों की एक सारणी प्रदान करते हैं। उन उपकरणों की प्रभावी और न्यायसंगत तैनाती एक चुनौती है। लेकिन कोई यह नहीं कह सकता कि वैश्विक संकट से निपटने में विज्ञान को अभावग्रस्त पाया गया है। • दूसरी ओर, टीबी को वास्तविक आपात स्थिति के रूप में नहीं माना गया है। फिर भी इसका विश्वव्यापी वितरण, स्वास्थ्य पर प्रभाव और मृत्यु दर का बोझ उतना ही भयानक था। प्रति वर्ष 10 मिलियन मामलों में टीबी की घटनाएं रुकी हुई हैं। • वर्ष 2020 में इस मामले का पता लगाने में लगभग 20 प्रतिशत की गिरावट आई और एक दशक में पहली बार मृत्यु दर बढ़कर 1.5 मिलियन हो गई। ये झटके सीधे तौर पर COVID-19 महामारी के लिए जिम्मेदार हैं। COVID-19 महामारी कई मायनों में टीबी महामारी से अलग है, इसके अचानक से होने, दुनिया भर में तेजी से फैलने और व्यक्तियों और समुदायों पर व्यापक प्रभाव पड़ने के साथ। फिर भी, टीबी एक प्रमुख घातक बीमारी बनी हुई है। **लंबी समय सीमा के बावजूद कामयाबी** सीमित धन के साथ भी पिछले एक दशक में टीबी अनुसंधान में कुछ सफलताएँ मिली हैं: A. आणविक परीक्षण 2 घंटे से भी कम समय में निदान को संभव बनाना B. बहुऔषध प्रतिरोधी टीबी के उपचार को कम कर दिया गया है और इसे आसान बना दिया गया है C. दवा के प्रति संवेदनशील टीबी के उपचार को कम कर दिया गया है D. सुरक्षित और बेहतर सहनशील आहार के साथ टीबी संक्रमण के उपचार में कटौती की गई है। लेकिन इन सभी परिवर्तनकारी प्रगतियों में उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक समय लगा। • टीबी जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिए वित्त पोषण के अवसर कम हैं और टीबी अनुप्रयोगों की समीक्षा धीमी है। • अधिकांश अध्ययन अनावश्यक रूप से लंबी प्रशासनिक और नियामक समीक्षा प्रक्रियाओं द्वारा लंबे समय तक चलते हैं। हालाँकि, व्यापक समस्या व्यक्तिगत फंडिंग एजेंसियों या नियामक निकायों के यांत्रिकी से बहुत बड़ी है।

- पहला, कोई भी टीबी को वास्तविक आपात स्थिति नहीं माना। जैसा कि हम लोग COVID-19 के साथ देखे, जब हर कोई सोचता है कि यह एक आपात स्थिति है, लोग अलग तरह से कार्य करते हैं, और चीजें तेजी से आगे बढ़ती हैं।
- दूसरा, नैदानिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान अवसंरचना बहुत कम समर्थित है। COVID-19 ने एहसास कराया है कि जब शोधकर्ता, फंडर्स और नियामक एजेंसियां एक संकट का सामना करने के लिए एकजुट होती हैं तो क्या संभव है। गेम-चेंजिंग ट्रायल रिकॉर्ड समय में कोनों को काटे बिना और प्रतिभागी सुरक्षा और वैज्ञानिक अखंडता से समझौता किए बिना आयोजित किया जा सकता है, अगर हर कोई ऐसा व्यवहार करता है जैसे यह एक आपात स्थिति है। लेकिन ऐसा करने के लिए मानव और वित्तीय संसाधनों के अलावा मानसिकता में मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता है।

प्रगति कैसे तेज करें - आगे की राह

COVID-19, TB, या किसी अन्य स्वास्थ्य आपदा के लिए संकट समय में संचालन करना मुश्किल है। लेकिन COVID-19 महामारी ने दिखाया है कि वैश्विक खतरे के खिलाफ प्रगति में तेजी लाने के लिए क्या काम करता है।

- सबसे पहले, प्राथमिकता वाले शोध के लिए पर्याप्त वित्त पोषण नवाचार और प्रगति को बढ़ाता है। एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में, सरकारों, फार्मा / बायोटेक कंपनियों और फाउंडेशनों को टीबी अनुसंधान में निवेश बढ़ाना चाहिए, कम से कम संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक रिपोर्ट में निर्धारित स्तर तक और वैश्विक महामारी प्रतिक्रिया रणनीतियों में टीबी को एक केंद्रीय एलिमेंट बनाना चाहिए। वर्ष 2030 तक सरकारों और अन्य फंडर्स को टीबी को समाप्त करने के लिए और अधिक प्रतिबद्ध होना चाहिए।
- दूसरा, फंडिंग टाइमलाइन को बहुत कम किया जा सकता है। अगर एचआईवी और कोविड-19 में बायोमेडिकल रिसर्च की तेजी से समीक्षा करने का कारण यह था कि ये संक्रमण तेजी से फैलेंगे और मारे जाएंगे, तो टीबी अनुदान की भी तेजी से समीक्षा की जानी चाहिए।
- तीसरा, नियामक अड़चन को दूर किया जाना चाहिए। नियामक और नैतिकता के बुनियादी ढांचे (प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय सहित) में अधिक निवेश होना चाहिए ताकि इन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं से नवीन अनुसंधान का दम न घुटे।
- अंत में, सरकारों को वैश्विक महामारी प्रतिक्रिया रणनीतियों में टीबी को एक केंद्रीय एलिमेंट के रूप में मानना चाहिए। महामारी को विशेष रूप से ध्यान देकर डब्ल्यूएचओ में कानूनी रूप से बाध्यकारी महामारी संधि या इसी तरह के तंत्र को बनाने के लिए बातचीत की शुरुआत करके टीबी जैसी महामारी को समाप्त करने की प्रतिबद्धता शामिल होनी चाहिए। यदि टीबी से होने वाली सालाना 1.5 मिलियन मौतें महामारी नहीं हैं, तो क्या है?
- सामाजिक स्टिग्मा को समाप्त करना: टीबी अकेले स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है। यह एक व्यापक सामाजिक चुनौती है। इसके रोगी अक्सर उपचार करने में हिचकिचाते हैं या सामाजिक प्रतिष्ठा खोने के डर से अपनी स्थिति को पूरी तरह से नकार देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि टीबी पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी होने के बावजूद कई लोगों के लिए मौत की सजा बन जाती है। इस क्रम में महिलाएं अनुपातहीन रूप से प्रभावित हैं, यह सुझाव देते हुए कि टीबी से निदान होने के बाद हर साल 100,000 भारतीय महिलाओं को अपना घर छोड़ने के लिए कहा जाता है।

निष्कर्ष

टीबी निदान, उपचार और रोकथाम के क्षेत्र में प्रगति को आगे बढ़ाने की जरूरत है और इसे तात्कालिकता के साथ बढ़ाया जाना चाहिए जिसके वे हकदार हैं। यदि हम ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं कि टीबी एक वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल है और हम एक ऐसी बीमारी से अस्वीकार्य पीड़ा का अनुभव करेंगे, जिसने अकेले इस सदी में 20 मिलियन से अधिक लोगों की जान ले ली है।

अन्य संबंधित तथ्य :

A. **A. टीबी को खत्म करने की दिशा में भारत का योगदान**
   - **2025 तक टीबी को खत्म करना:** भारत वर्ष 2030 के वैश्विक लक्ष्य से पांच साल पहले 2025 तक तपेदिक को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।
   - **राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम:** महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ संरेखित करने के लिए, कार्यक्रम का नाम संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) से बदलकर राष्ट्रीय क्षय रोग

	उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) कर दिया गया है। ▪ निदान और उपचार के लिए होने वाली बाधाओं को कम करते हुए टीबी के सामाजिक निर्धारकों से निपटने हेतु सभी सह-रुग्णताओं को संबोधित करना और चिकित्सा हस्तक्षेप से परे जाना। ▪ निक्षय पोषण योजना के माध्यम से, सभी टीबी रोगियों को उनके उपचार की पूरी अवधि के लिए पोषण सहायता प्रदान की जाती है। ▪ अस्पताल के वार्डों और आउट पेशेंट प्रतीक्षा क्षेत्रों में वायुजनित संक्रमण नियंत्रण की दिशा में सख्ती से काम करना। ▪ टीबी रोगियों और पीएलएचआईवी रोगियों के बाल चिकित्सा संपर्कों में टीबी रोग के खिलाफ कीमोप्रोफिलैक्सिस का प्रावधान है। ▪ वयस्क संपर्कों के लिए भी टीबी निवारक उपचार के विस्तार के लिए प्रक्रिया जारी है। ● 'टीबी मुक्त भारत अभियान' भारत में टीबी उन्मूलन के लिए एक जन आंदोलन के रूप में शुरू किया गया है। ● भारत संभावित तकनीकी सहायता और इसके साथ अपने पड़ोस के देशों को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। **B. क्षय रोग एक सामाजिक रोग है -** ● यह भीड़भाड़ और कुपोषण के कारण, यह अनुपातहीन रूप से गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों को प्रभावित करता है। ● इस बीमारी से जुड़े मिथक और भ्रांतियां कम रिपोर्टिंग और कम निदान की ओर ले जाती हैं। ● लंबे समय तक चलने वाले दवा उपचार से खराब अनुपालन और दवा-प्रतिरोध होता है, जो रिकवरी होने में समय लगता है। ● मधुमेह या एचआईवी के साथ सह-संक्रमण जैसी पहले से मौजूद बीमारी से जटिलताएं बढ़ जाती हैं। ● अंत में, रोग की पुरानी प्रकृति और कई अंगों को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति मृत्यु दर को बढ़ा देती है। **क्या आप निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं?** 1. यदि हम ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं कि टीबी एक वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल है, और हम एक ऐसी बीमारी से अस्वीकार्य पीड़ा का अनुभव करना जारी रखेंगे, जो अकेले इस सदी में 20 मिलियन से अधिक लोगों की जान ले ली है। टिप्पणी कीजिए।
पहली बार मानव रक्त में मिला माइक्रोप्लास्टिक	**संदर्भ:** प्लास्टिक प्रदूषण हमारे समय की सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। शहरी क्षेत्रों में प्लास्टिक का कचरा एक आम दृश्य है लेकिन यह जंगलों में भी अपना रास्ता बना चुका है। यह प्रत्येक प्राकृतिक आवास (जंगल, रेगिस्तान, नदियाँ, मिट्टी) में कल्पना योग्य है। यहां तक कि हमारे सबसे ऊंचे पहाड़ों और गहरे समुद्रों को भी नहीं छोड़ा गया है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर ट्रेकर्स ने प्लास्टिक कचरे को पीछे छोड़ दिया है। 2019 में, प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच जो दुनिया का सबसे गहरा स्थान है उसमें एक पनडुब्बी, प्लास्टिक बैग और मिठाई के खाली डिब्बे मिले। हम हजारों उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करा रहे हैं; इनमें प्लास्टिक सहित इन अंतरिक्ष यान से मलबा इधर-उधर बह रहा है। ***किसी ऐसे पारितंत्र का नाम बताइए जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। अगर इंसान वहां (या आस-पास) रहे हैं, तो प्लास्टिक भी होगी।*** **माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण** मानव रक्त में पहली बार माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण का पता चला है। एनवायरनमेंट इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में 22 रक्तदाताओं के रक्त के नमूनों का विश्लेषण किया और 17 नमूनों में प्लास्टिक के कण पाए। परीक्षण किए गए लगभग 80 प्रतिशत लोगों में वैज्ञानिकों को माइक्रोप्लास्टिक के छोटे कण मिले। खोज से पता चलता है कि कण शरीर के चारों ओर भ्रमण कर सकते हैं और अंगों में रह सकते हैं। ● आधे से अधिक नमूनों में PET प्लास्टिक मौजूद था, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर पेयजल की बोतलों में किया जाता है। ● एक-तिहाई में पॉलीस्टाइनिन मौजूद था, जिसका उपयोग भोजन एवं अन्य उत्पादों की पैकेजिंग के लिये किया

जाता है।

- कुछ रक्त के नमूनों में दो या तीन प्रकार के प्लास्टिक थे।

माइक्रोप्लास्टिक्स को प्रयोगशाला में मानव कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए भी देखा गया। लोग पहले से ही भोजन और पानी के माध्यम से छोटे कणों का उपभोग करने के लिए जाने जाते थे। शोधकर्ताओं ने पहले शिशुओं और वयस्कों के मल में माइक्रोप्लास्टिक पाया है।

माइक्रोप्लास्टिक क्या है?

- ये पाँच मिलीमीटर से कम व्यास वाले प्लास्टिक कण होते हैं जो कि प्रायः गहनों में इस्तेमाल होने वाले मानक मोती की तुलना में भी छोटे होते हैं।
- माइक्रोप्लास्टिक प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों से उत्पन्न होता है।
  - प्राथमिक स्रोत वे हैं जहां प्लास्टिक को छोटे टुकड़ों में तैयार किया गया है - जैसे प्लास्टिक के छर्रों या छोटे मोती जो 2-5 मिमी चौड़े होते हैं। वे पॉलिएस्टर से बने होते हैं। प्लास्टिक उद्योग में छर्रा एक आम कच्चा माल है क्योंकि प्लास्टिक बैग और कंटेनर जैसे कई अन्य बड़े प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण के लिए उन्हें पिघलाया जा सकता है। माइक्रोप्लास्टिक के अन्य प्राथमिक स्रोतों में माइक्रोबीड्स शामिल हैं, जो फेस स्क्रब और पेंट सहित कई दैनिक देखभाल उत्पादों में पाए जाते हैं।
  - माइक्रोप्लास्टिक के द्वितीयक स्रोतों में प्लास्टिक बैग, बोतलें और लगभग हर दूसरी प्लास्टिक वस्तु शामिल है जो समय के साथ छोटे टुकड़ों में टूट जाती है।
- ऐसे टुकड़े मनुष्य देख नहीं पाता हैं। नए अध्ययन में, माइक्रोप्लास्टिक्स का आकार लगभग 700 एनएम व्यास का था। यह एक इंसान के बाल की चौड़ाई से लगभग 140 गुना छोटा है।

चूंकि माइक्रोप्लास्टिक बहुत छोटे होते हैं, इसलिए यह पता लगाना मुश्किल है कि उन्होंने हमारे ग्रह और उसके जीवों के शरीर पर किस हद तक आक्रमण किया है।

आगे की राह

पर्यावरणविद, नीति निर्माता और सरकारें पर्यावरण में माइक्रोप्लास्टिक के खतरों पर ध्यान देती दिख रही हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में, 170 से अधिक देशों ने वर्ष 2024 तक प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय, कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि विकसित करने का संकल्प लिया। यह मसौदा प्रस्ताव में एक प्रकार के प्रदूषक के रूप में माइक्रोप्लास्टिक शामिल है।

- जबकि हम हर जगह माइक्रोप्लास्टिक पाया है, तो ठीक से नहीं जानते कि वे मनुष्यों को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हैं, उदाहरण के लिए, स्टाइरीन - माइक्रोप्लास्टिक्स में से एक मानव कार्सिनोजेन हो सकता है जिसे वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव रक्त में खोजा है।
- लेकिन जैसे-जैसे हम और अध्ययन करते हैं, एक बात निश्चित होती है कि हमको तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर्राष्ट्रीय संधि महत्वपूर्ण हो सकती है। प्लास्टिक प्रदूषण पर कुछ प्रतिबंध माइक्रोप्लास्टिक के आक्रमण को रोकने के लिए एक लंबा रास्ता तय कर सकते हैं।

लेखक लिखते हैं कि रक्तप्रवाह में प्लास्टिक से जुड़े मानव स्वास्थ्य जोखिमों को निर्धारित करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है।

- "यह आपके शरीर में कहाँ जा रहा है? क्या इसे समाप्त किया जा सकता है?उत्सर्जित? या यह कुछ अंगों में जमा हो सकता है, या यह रक्त-मस्तिष्क की बाधा को पार करने में भी सक्षम है?"
- प्लास्टिक प्रदूषण पर एक अंतरराष्ट्रीय संधि तैयार है - यह माइक्रोप्लास्टिक, और प्लास्टिक, खतरे के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

क्या आप निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं?

1. कोई प्लान बी नहीं है क्योंकि हमारे पास प्लेनेट बी नहीं है। चर्चा कीजिए।
2. क्या आपको लगता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध से प्रदूषण की समस्या का स्थायी तरीके से समाधान हो सकता है? क्या प्रदूषण को कम करने, पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण 'के माध्यम से प्लास्टिक के उपयोग का स्थायी प्रबंधन प्रदूषण से निपटने का एक बेहतर तरीका नहीं है? समालोचनात्मक जाँच कीजिए।

मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन (MCC): नेपाल, यूएसए और इंडो-पैसिफिक

संदर्भ: 2 नेपाल की संसद में 2019 से लटके पड़े मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन नेपाल कॉम्पेक्ट (Millennium Challenge Corporation Nepal Compact) को आखिरकार 27 फरवरी को मंजूरी दे दी गई, जिसमें 500 मिलियन यूएस डॉलर का अनुदान शामिल है।

- एक महत्वपूर्ण घोषणा के साथ अनुदान की पुष्टि की गई थी।
- इस घोषणा में कहा गया है कि यू.एस. अनुदान इंडो-पैसिफिक रणनीति का हिस्सा नहीं है और नेपाल का संविधान अनुदान समझौते के प्रावधानों से ऊपर होगा।
- इसमें यह भी उल्लेख है कि अनुदान को केवल एक आर्थिक सहायता के रूप में माना जाएगा।
- राजनीतिक दलों और नागरिक समाज को विभिन्न कारणों से यू.एस. अनुदान पर विभाजित किया गया है।
- अनुदान समझौता, जिसे 20 फरवरी को काठमांडू में संसद में पेश किया गया था, इसके खिलाफ प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा, जो हिंसक हो गया, इस दंगे में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी पथराव किया और दोनों पक्षों के कई लोगों के घायल होने की सूचना है।

मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन क्या है?

- **यूएसए की विदेशी सहायता एजेंसी:** मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन (एमसीसी) जो कि एक द्विपक्षीय अमेरिकी विदेश अनुदान एजेंसी है, इसकी स्थापना वर्ष 2004 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा की गई थी। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य यह रहा है कि वे निम्न और मध्यमवर्गीय देशों में ग़रीबी और आर्थिक विपन्नता को काम करने हेतु, यथोचित सहायता प्रदान करें। इसके लिए, विभिन्न क्षेत्रों को लक्षित किया गया है, जैसे शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य, सड़क और परिवहन की आधारभूत संरचना, ईंधन और कृषि जो कि विकास के सबसे मज़बूत स्तम्भ रहे हैं, और जिन्हें आर्थिक सहायता के लिए सबसे मज़बूत पात्र माना गया है।
- **आतंकवाद और गरीबी:** यह सहायता निकाय की वर्तमान आधिकारिक परिभाषा है, एमसीसी को जॉर्ज बुश प्रशासन द्वारा 9/11 के आतंकवादी हमले के बाद, वैश्विक गरीबी और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रस्तावित किया गया था, इस तर्क का हवाला देते हुए कि गरीबी और आतंकवाद जुड़े हुए हैं।
- एमसीसी तीन रूपों में सहायता प्रदान करता है।
    - कॉम्पैक्ट बड़े पैमाने पर, उन देशों के लिए पांच-वर्षीय अनुदान हैं जो MCC के पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं;
    - थ्रेशहोल्ड प्रोग्राम उन देशों को दिए जाने वाले छोटे अनुदान हैं जो इन मानदंडों को पूरा करने के करीब हैं और अपनी नीतियों में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं
- एमसीसी ने अब तक 29 देशों के लिए लगभग 37 कॉम्पेक्ट को मंजूरी दी है, जिनकी कुल कीमत 13 अरब डॉलर से अधिक है।

एमसीसी नेपाल कॉम्पैक्ट क्या है?

- वर्ष 2014 में, 20 नीति संकेतकों में से 16 को पूरा करने के बाद, जिन पर एमसीसी देशों का चयन करता है, नेपाल ने एक समझौते के लिए अर्हता प्राप्त कर ली थी, जिसके लिए उसने बाद में 2017 में हस्ताक्षर किए थे।
- समझौते के तहत, यू.एस. सरकार, एमसीसी के माध्यम से, नेपाल को ऊर्जा संचरण और सड़क विकास परियोजनाओं के लिए $500 मिलियन का अनुदान प्रदान करेगी, साथ ही नेपाल को भी 130 मिलियन डॉलर का अनुदान मिलेगा।
- काठमांडू के उत्तर-पूर्व से शुरू होने वाले और भारत के साथ नेपाल की सीमा के पास समाप्त होने वाले एक बिजली गलियारे के साथ, कॉम्पैक्ट में प्रस्तावित बिजली परियोजना 400 किलोवोल्ट की क्षमता वाली 300-400 किमी लंबी ऊर्जा संचरण लाइन है।
- इस परियोजना में लाइन के साथ तीन बिजली सबस्टेशनों का निर्माण भी शामिल है।
- इसके अलावा, अनुदान राशि एक 'सड़क रखरखाव परियोजना' के लिए भी है जो 300 किलोमीटर में फैले पूर्व-

	पश्चिम राजमार्ग पर सड़कों का उन्नयन करेगी। • जबकि काम्पैक्ट का कहना है कि ऊर्जा परियोजना नेपाल के लिए बिजली उत्पादन और आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए है, इसमें यह भी कहा गया है कि यह भारत के साथ सीमा पार बिजली व्यापार की सुविधा प्रदान करेगा। • परियोजनाओं पर काम शुरू होने से पहले, बिल को नेपाल की संसद में औपचारिक रूप से स्वीकार या अनुमोदित किया जाना चाहिए। • यू.एस. और नेपाल दोनों सरकारों ने कहा है कि यह एक 'नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड' अनुदान है, जिसकी कोई शर्त नहीं होगी, या इसके लिए पुनर्भुगतान और ब्याज भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी। • हालांकि, समझौते की धारा 7.1 कहती है कि यह नेपाल के घरेलू कानूनों पर "प्रचलित" होगा और धारा 6.8 "नेपाल के सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों" में एमसीसी कर्मचारियों को छूट प्रदान करती है। **एमसीसी अनुदान को लेकर क्या विवाद है?** • प्रारंभिक समझौते के अनुसार, यह समझौता 2019 तक प्रभावी हो जाना चाहिए था, लेकिन संशयवाद, राजनीति और अब विरोध ने इसके पाठ्यक्रम को रॉकी () बना दिया। • यू.एस. नेपाल पर समय सीमा देते हुए समझौते की पुष्टि करने के लिए अपना दबाव बढ़ा रहा था, या यू.एस. को "नेपाल के साथ अपने संबंधों की समीक्षा करनी होगी।" ○ अतीत में ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां यू.एस. ने विभिन्न कारणों से देशों के साथ इस तरह के समझौते को समाप्त कर दिया है। • नेपाली राजनीतिक दलों को एमसीसी समझौते पर इस डर से विभाजित किया गया है कि यह नेपाल की संप्रभुता को अमेरिका की इंडो-पैसिफिक स्ट्रैटेजी (आईपीएस) में खींचकर कमजोर कर देगा, जो चीन का मुकाबला करने पर केंद्रित है- जिस देश के साथ नेपाल के घनिष्ठ संबंध होंगे। • इस समझौते को कुछ पर्यवेक्षक चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के प्रति अमेरिका के जवाब के रूप में भी देखते हैं, यह एक सड़क विकास कार्यक्रम है जिस पर नेपाल सरकार ने 2016 में हस्ताक्षर किए थे। • इस बात की भी चिंता है कि यह समझौता अपने संविधान के खिलाफ जाएगा, जो देश को गुटनिरपेक्षता के एक मजबूत सिद्धांत से बांधता है। • नेपाल के लोग भी डरते हैं कि एमसीसी भारत को ऊर्जा निर्यात करके बिजली परियोजना से लाभ कमाएगा। • समय सीमा के बारे में व्हाइट हाउस से नेपाल को कॉल मिलने के बाद, चीन ने कहा कि वह "जबरदस्ती कूटनीति और कार्यों का विरोध करता है जो नेपाल की संप्रभुता और हितों की कीमत पर स्वार्थी एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं।" • गठबंधन सहयोगियों के बीच अस्थिरता की इस राजनीतिक पृष्ठभूमि में, आगामी चुनावों में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए पार्टियों द्वारा एमसीसी समझौते का राजनीतिकरण किया गया। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** • भारत-नेपाल संबंधों को रीसेट करने की आवश्यकता है • भारत-नेपाल संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या हैं? उनके नतीजे क्या हैं? जांच कीजिए।
बालाकोट हवाई हमला	**संदर्भ:** 26 फरवरी को बालाकोट हवाई हमले की तीसरी वर्षगांठ है, जो भारतीय वायु सेना द्वारा पाकिस्तान के खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट शहर में चल रहे आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाकर किया गया था। ED से लदी एक एसयूवी ने उनके काफिले को टक्कर मार दी, इस हमले में सीपीआरएफ के चालीस जवानों की जान चली गई। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली थी। बालाकोट हवाई हमले को पुलवामा बमबारी की सीधी प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया। • 26 फरवरी, 2019 को तड़के, भारत ने जम्मू के पुलवामा जिले में जैश-ए-मोहम्मद द्वारा रचित एक आत्मघाती हमलावर द्वारा सीआरपीएफ कर्मियों को ले जा रहे वाहनों के काफिले पर हमला किए जाने के 12 दिन बाद हवाई हमले किए। • पिछले साल 14 फरवरी को हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 40 जवान शहीद हो गए थे। जवाबी कार्रवाई में, भारतीय वायु सेना ने 26 फरवरी, 2019 को बालाकोट में JeM के सबसे बड़े आतंकी

प्रशिक्षण शिविर को नष्ट कर दिया।

- IAF के एक दर्जन मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने आतंकी शिविर पर हमला करने के लिए भारत-पाकिस्तान सीमा पार की।
- मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बालाकोट में आतंकवादी शिविरों में भारतीय वायुसेना के बम विस्फोटों की पहली बरसी से पहले सुधार किया गया है।

ऑपरेशन बंदर

- पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादी ठिकाने पर बमबारी करने के भारतीय वायुसेना के मिशन को 'ऑपरेशन बंदर' कोडनेम दिया गया था। यह एक दुर्लभ ऑपरेशन था जिसमें भारतीय वायुसेना ने जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) को पार किया और पाकिस्तानी क्षेत्र में जाकर अपने लक्ष्य पर बम गिराए। बालाकोट पाकिस्तान के खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित एक छोटा सा शहर है।
- 26 फरवरी, 2019 को, भारतीय वायु सेना के मिराज-2000 फाइटर जेट्स ने पूरे भारत में एयरबेस से उड़ान भरी। भारतीय वायु सेना के जेट विमानों ने जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा को पार किया और बालाकोट में जैश के आतंकी शिविरों पर सटीक-निर्देशित मिसाइलों से बमबारी की।
- पाकिस्तान ने एक दिन बाद जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान वायु सेना ने भारतीय धरती पर हवाई हमले का प्रयास किया। भारतीय वायु सेना ने जवाब में अपने लड़ाकू जेट विमानों को लॉन्च किया, जिससे भारतीय और पाकिस्तानी जेट विमानों के बीच एक दुर्लभ हवाई लड़ाई हुई। इस झड़प में, एक IAF मिग -21 बाइसन फाइटर जेट ने संघर्ष के दौरान एक पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया। वहीं विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान द्वारा उड़ाए जा रहे भारतीय मिग-21 को भी मार गिराया गया जो पाकिस्तान में जा गिरा और उसे पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया। काफी विचार-विमर्श के बाद विंग कमांडर अभिनंदन को दो दिन बाद पाकिस्तान के कब्जे से रिहा कर दिया गया। इस विकास ने दो सप्ताह के बढ़े हुए संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच तनाव को शांत किया।

दुनिया के लिए विचार और संदेश

बालाकोट भारत के खिलाफ कम लागत वाले विकल्प के रूप में आतंकवाद के रोजगार के खिलाफ भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है।

- इसने यह संकेत दिया कि एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से परे के क्षेत्रों में आतंकवादी, आतंकवादी बुनियादी ढांचे और आतंकवादी प्रशिक्षण सुविधाएं जब भारत के खिलाफ नियोजित होती हैं, तो वे अब सुरक्षित ठिकाने नहीं रहेंगे।
- आतंकवाद एक कम लागत वाला विकल्प नहीं रहेगा जो सीमा पार से गैर-जिम्मेदार नेताओं द्वारा बार-बार आवाज उठाए जाने वाले छिपे खतरों और बोगी के तहत बढ़ सकता है।
- बालाकोट प्रयास के एक अभिन्न अंग के रूप में अप्रत्याशितता और नवाचार के तत्व के साथ, इच्छित प्रभाव के लिए सबसे उपयुक्त संसाधनों को नियोजित करने के लिए भारत के इरादे को दोहराना जारी रखेगा। यह वह कारक है जो हमारे दिमाग में सबसे ऊपर रहना चाहिए।

भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल के साथ उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो दुश्मन के इलाके में हमला कर सकते हैं और अपने सैनिकों की मौत का बदला ले सकते हैं। इसने विरोधियों को संकेत दिया कि उकसावे पर भारत की प्रतिक्रिया अब 'नरम' नहीं होगी और केवल कूटनीतिक होगी। सारे विकल्प मेज पर थे।

आगे की राह

- एनएसजी द्वारा सरकार के समक्ष रखे गए अनुरोधों को पूरा करने की आवश्यकता है। एनएसजी को एक संपूर्ण कमांडो फोर्स बनाया जाना चाहिए, चाहे वह प्रशिक्षण हो, आधुनिक हथियार हों, परिवार के सदस्यों की सुविधाएं हों। एनएसजी को दुनिया की अन्य ताकतों से कम से कम दो कदम आगे रखने का विचार है।
- भारतीय सेना को सेना के पुनर्गठन के साथ आगे बढ़ना होगा ताकि जमीन पर तेजी से गतिशीलता और सीमित भूमि-आधारित सैन्य अभियानों में अधिक लचीलेपन की अनुमति मिल सके।
- **नौसैनिक शक्ति पर भी काम:** अल्पावधि में, भारत पाकिस्तान के साथ टकराव के दौरान अपने नौसैनिक बलों को आक्रामक तरीके से तैनात करने की संभावना रखता है, जैसा कि इस संकट के दौरान और पिछले संकटों में कथित तौर पर किया गया था। लंबी अवधि में, यह एक नौसैनिक नाकाबंदी या भूमि हमले के विकल्पों का पता लगा सकता है, हालांकि पाकिस्तान की नौसैनिक परमाणु महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए अपने विरोधी के क्षेत्रीय जल में निर्णायक मिशन को अंजाम देने की भारत की क्षमता सीमित और संभावित रूप से बढ़ जाएगी। इस प्रकार, अरब सागर में भारतीय दबाव अभी के लिए सबसे अच्छा विकल्प रहेगा।

	• इस ऑपरेशन के बाद अपनाए गए संयमित दृष्टिकोण को जारी रखने और सितंबर 2016 के 'सर्जिकल स्ट्राइक' पर छाए विजयवाद से बचने की आवश्यकता है। लंबी अवधि में, मजबूत आतंकवाद विरोधी सुरक्षा का निर्माण करना, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपने नागरिकों के साथ साझेदारी करना और निवारक बनाना महत्वपूर्ण होगा। **क्या आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं?** 1. बालाकोट हवाई हमले ने पाकिस्तान को अपनी नियम पुस्तिका बदलने के लिए मजबूर कर दिया। टिप्पणी कीजिए। 2. भारत के लंबे समय से चले आ रहे संयम के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया है, जिससे पुलवामा जैसे आतंकी हमलों के खिलाफ अधिक जोखिम भरे भारतीय जवाबी कदमों के लिए जगह खुल गई है। चर्चा कीजिए।
भारत और यूएनएससी ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण पर मतदान किया (India and UNSC Vote over Russia's Invasion of Ukraine)	**संदर्भ:** भारत (India) ने अमेरिका द्वारा प्रायोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UN Security Council) के उस प्रस्ताव (UN resolution) से दूरी बनाए रखी जिसमें यूक्रेन के खिलाफ रूस की "आक्रामकता" की निंदा की गई थी और पड़ोसी देश से रूसी सेना (Russian forces) की "तत्काल, पूर्ण और बिना शर्त" वापसी की मांग की गई थी। **संकल्प किस बारे में है?** • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका और अल्बानिया द्वारा प्रस्तुत मसौदा प्रस्ताव 8979 पर मतदान किया, और कई अन्य देशों द्वारा सह-प्रायोजित किया गया। • यह प्रस्ताव यूक्रेन के खिलाफ रूस के आक्रमण की निंदा करता है और निर्णय लेता है कि ○ रूस यूक्रेन के खिलाफ अपने बल प्रयोग को तुरंत बंद कर देगा ○ रूस संयुक्त राष्ट्र के किसी भी सदस्य देश के खिलाफ किसी भी तरह की गैरकानूनी धमकी या बल प्रयोग से बचना चाहिए। ○ रूस अपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर यूक्रेन के क्षेत्र से अपने सभी सैन्य बलों को तुरंत हटा ले ○ रूस यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहान्स्क क्षेत्रों के कुछ क्षेत्रों की स्थिति से संबंधित निर्णय को तुरंत उलट दे • परिषद के संकल्प ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर यूक्रेन की संप्रभुता, स्वतंत्रता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। • भारत मसौदा प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहा। • रूस - जिसने यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता की क्योंकि यह फरवरी के महीने के लिए राष्ट्रपति पद धारण करता है - ने प्रस्ताव को वीटो कर दिया • चीन ने पिछले वोट में रूस के समर्थन से दूर रहने के लिए स्थानांतरित कर दिया, जब अमेरिका और अल्बानिया, संकल्प के दो "पेनहोल्डर", अध्याय VII (रूसी सैनिकों के खिलाफ बल के उपयोग का प्राधिकरण) के संदर्भ को छोड़ने के लिए सहमत हुए। • यूएनएससी के शेष 11 सदस्यों, जिनमें यूएस, यूके, फ्रांस शामिल हैं, ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने के बावजूद, रूस द्वारा वीटो किए जाने के बाद से यह पारित नहीं हुआ। ○ रूस ने पहले UNSC के प्रस्तावों को वीटो कर दिया था जो जॉर्जिया (2008), और क्रीमिया (2014) में सेना भेजने के उसके निर्णय की आलोचना करते थे। **भारत ने परहेज क्यों किया?** • भारत चार संभावित विकल्प चुन सकता/सकती है: ○ रूसी आक्रमण की निंदा करना - यह भारत को रूस के खिलाफ खड़ा करेगा ○ रूसी आक्रमण का समर्थन करना - यह यू.एस. और उसके सहयोगियों के विरुद्ध खड़ा करेगा ○ रूसी आक्रमण पर चुप रहना - इसे रूस समर्थक के रूप में पढ़ा जाएगा ○ नाराजगी व्यक्त करना (निंदा करने की कमी) और कूटनीति का आह्वान करना - जो उसने लिया है - कम से कम हानिकारक है। • साथ ही, भारत अमेरिका और रूस के नेतृत्व वाले पश्चिमी ब्लॉक के बीच संतुलन बनाए रखना चाहता है, क्योंकि उसके दोनों के साथ रणनीतिक संबंध हैं। • भारत-रूस रक्षा और रणनीतिक साझेदारी के अलावा, रूस भारत का सबसे भरोसेमंद P-5 सहयोगी है, जब कश्मीर पर घुसपैठ के प्रस्तावों को रोकने की बात आती है।

	• रूस भारत के प्रति चीनी दुश्मनी को नियंत्रित करने में सक्षम हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी एक मित्रविहीन क्षेत्र में भारत के बढ़ते अलगाव को कम करने में सक्षम हो सकती है।
	• नई दिल्ली को रक्षा आपूर्ति के माध्यम से अपनी महाद्वीपीय कठिनाइयों का प्रबंधन करने, मध्य एशिया में लौटने में मदद करने, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में एक साथ काम करने या अफगानिस्तान में सहयोग के अवसरों की खोज करने के लिए मास्को की सहायता की आवश्यकता है।
	• दूसरी ओर, QUAD जैसे अनौपचारिक समूह बनाने के साथ भारत के अमेरिका के साथ संबंध सबसे अच्छे हैं, जो चीन को नियंत्रित करने में रणनीतिक रुचि रखते हैं। इसलिए, नई दिल्ली सक्रिय रूप से रूस का समर्थन नहीं कर सका।
	  ○ नैतिक आधार पर भी, आक्रमण को अंतरराष्ट्रीय कानून और यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन के रूप में माना जाता है।
	• भारत की समस्या चीन है, और उसे "चीन समस्या" से निपटने के लिए यू.एस./पश्चिम और रूस दोनों की आवश्यकता है।
	  ○ एक आक्रामक रूस अमेरिका के लिए एक समस्या है जबकि पश्चिम, भारत के लिए नहीं है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) का विस्तार रूस की समस्या है, भारत का नहीं।
	• भारत के पास संवाद और कूटनीति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर को पाटने और बीच का रास्ता खोजने के प्रयास में प्रासंगिक पक्षों तक पहुंचने का विकल्प बरकरार है।
	भारत का स्टैंड
	• भारत ने कहा कि यूक्रेन में हाल के घटनाक्रम से वह बहुत परेशान है।
	• भारत ने हिंसा की समाप्ति के लिए अपनी अपील दोहराई और कूटनीति की वकालत की और संबंधित पक्षों से बातचीत की मेज पर लौटने का आग्रह किया।
	• इसने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों के बारे में अपनी मूल चिंता को हरी झंडी दिखाई, जिनमें से अधिकांश छात्र हैं।
	• भारत ने "प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता" को छुआ जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर निर्मित समकालीन वैश्विक व्यवस्था थी।
	• यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का भारत के रणनीतिक गणित पर प्रमुख प्रभाव कैसे पड़ता है?
	• पहली बात तो यह है कि यूक्रेन में रूसी कार्रवाई निस्संदेह चीन और उसकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देगी।
	• दूसरा, नई प्रतिबंध व्यवस्था का मॉस्को के साथ भारत के रक्षा सहयोग पर प्रभाव पड़ सकता है।
	• तीसरा, गतिरोध जितना लंबा चलेगा, चीन और रूस उतने ही करीब हो सकते हैं, जो निश्चित रूप से भारत के लिए सही नहीं होगा।
	• अंत में, यू.एस.-रूस प्रतिद्वंद्विता जितनी अधिक गंभीर होगी, उतना ही कम ध्यान भारत-प्रशांत और चीन पर होगा, जो भारत के हित में निहित हैं।
	निष्कर्ष
	• अब इस पर नई दिल्ली को विचार करना चाहिए कि क्या वैश्विक सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले संघर्ष पर स्पष्ट स्थिति के बिना "अग्रणी शक्ति" बनने की उसकी आकांक्षाओं को प्राप्त किया जा सकता है।
	बिंदुओं को कनेक्ट करना
	• अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
	• अफगानिस्तान पर अमेरिकी आक्रमण और 2021 में वापसी

ऑस्ट्रेलिया-भारत द्विपक्षीय संबंधों में 'नया अध्याय' लिख रहे हैं	**संदर्भ:** ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंध दिन पर दिन बदल रहे हैं, बहुपक्षीय मंचों और क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच भागीदारी बढ़ गई है। इस भागीदारी का लक्ष्य दोनों देशों के लिए लाभदायक साझेदारी के उद्देश्य से असली प्रतिबद्धताओं और प्रक्रियाओं को बनाना है। अगर वर्ष 2020 ऑस्ट्रेलिया-भारत के द्विपक्षीय संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी (सीएसपी) तक बढ़ाने का साल था तो 2021 द्विपक्षीय संबंधों को रफ़्तार और ऊर्जा देकर द्विपक्षीय आर्थिक हिस्सेदारी को मज़बूत करने का साल रहा। इसी तरह 2022 एक नई और प्रतिबद्ध हिस्सेदारी की सोच को केंद्रित शुरुआत देने का साल है और द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से फरवरी का महीना बेहद व्यस्त और भरोसा देने वाला महीना रहा। **वैश्विक भू-रणनीतिक और भू-आर्थिक परिदृश्य**

- क्वॉड के सदस्य देश "पूरे क्षेत्र में कोविड-19 वैक्सीन पहुंचाने में तेज़ी लाने के अलावा मानवीय सहायता और आपदा के दौरान जवाब देने, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का मुक़ाबला, दुष्प्रचार के जवाब और साइबर सुरक्षा समेत क्षेत्रीय चुनौतियों के समाधान" को लेकर सहमत हुए।
- ऑस्ट्रेलिया ने 2022 के मध्य में इंडो-पैसिफिक क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन फोरम की मेज़बानी की पेशकश भी की है।
- इंडो-पैसिफिक आर्थिक एकीकरण: ऑस्ट्रेलिया पांच वर्षों में 36.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर मुहैया कराएगा, इसमें से 11.4 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर समुद्री जहाज़, आपदा सामर्थ्य और सूचना साझाकरण पर क्षेत्रीय सुधार करने पर खर्च किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रीय आर्थिक चुनौतियों में भागीदारी बढ़ाने और बांग्लादेश के डिजिटल सेक्टर में नये अवसरों की तलाश करने पर 10.2 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का निवेश करेगा।
- इसके साथ ही, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ऑस्ट्रेलिया के कारोबारियों के लिए क्षेत्र में बुनियादी ढांचें के निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 5.8 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का निवेश करेगी, ऑस्ट्रेलियाई संसाधनों और खनन उपकरणों, तकनीक एवं सेवाओं को बेहतर करने और दक्षिण एशियाई बाज़ारों को समझने पर 4.8 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का निवेश करेगी,
- ऑस्ट्रेलिया, भारत और बांग्लादेश के बीच एलएनजी सप्लाई चेन को समर्थन देने के लिए 4.3 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और खर्च किया जाएगा।

ये सभी क़दम उत्तर-पूर्व हिंद महासागर में व्यापार, निवेश और संपर्क के लिए अवसर पैदा करेंगे। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को लेकर बदलती सोच भू-रणनीतिक और भू-आर्थिक परिकल्पना और माहौल में उभरते संरचनात्मक बदलाव को दर्शाता है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया

A. चौथी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के साथ आविष्कार, डिजिटल अर्थव्यवस्था और साइबर एवं महत्वपूर्ण तकनीक में सहयोग भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी का अहम हिस्सा बन गए हैं जो न्यू सेंटर ऑफ एक्सिलेंस फॉर क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी पॉलिसी के ज़रिए सुरक्षा मानक, सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली और नैतिक रूप-रेखा बनाने के लिए उद्योग, शिक्षा क्षेत्र और विषय के जानकारों के बीच सहयोग का एक माहौल बनाते हैं।
B. ऑस्ट्रेलिया-भारत के विदेश मंत्रियों के बीच शुरुआती साइबर संवाद में निवेश के लिए मज़बूत अवसरों और साइबर, महत्वपूर्ण एवं उभरती तकनीकों में अत्याधुनिक आविष्कार को और बढ़ावा देने पर ध्यान दिया गया।
C. व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए): ऑस्ट्रेलिया में संघीय चुनाव होने वाला है, जिस आर्थिक संदर्भ में सीसीईए पर बातचीत हो रही है, वो बदल गया है। दो साल पहले के हालात से ये अब पूरी तरह अलग है, जिस तरह से आपूर्ति, लोगों और संसाधनों के संकट ने कारोबार में ख़ुद को स्पष्ट किया है, उससे तरीक़ों की पूरी तरह जांच-पड़ताल करने की ज़रूरत है। सीईसीए की संभावना है -
    - कम टैरिफ
    - सीईसीए के लागू होने से शुल्क कम होंगे और कपड़ों, दवाई, जूते-चप्पल, डेयरी उत्पादों, दूध, महंगी शराबों और कई अन्य क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया और भारतीय निर्यातकों को ज़्यादा पहुंच का अवसर प्रदान करेगा। सीईसीए कोविड के बाद आर्थिक रिकवरी पर ध्यान केंद्रित करेगा, साथ ही ऑस्ट्रेलिया में भारतीय कंपनियों की ऑफशोर (अपने देश के बाहर) आमदनी पर कर के मौजूदा मुद्दे का जल्द समाधान करेगा।
D. पर्यटन सहयोग पर समझौता ज्ञापन: ये समझौता दोनों देशों के कारोबारियों के आने-जाने को प्रोत्साहित करेगा और पर्यटन नीति, डाटा साझा करने, प्रशिक्षण और उद्योग भागीदारी के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगा। महामारी से पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के मामले में सबसे तेज़ी से बढ़ता देश था। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय प्रवासियों की बड़ी संख्या और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का दस्ता भारतीय जनसंख्या के बड़े हिस्से के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दरवाज़े खोलना जारी रखेगा। ये भारत में 'ब्रैंड ऑस्ट्रेलिया' को बनाने में भी मददगार हैं, इससे व्यापक द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी के दृष्टिकोण से सांस्कृतिक साक्षरता और एक-दूसरे के बारे में सोच में और सुधार होगा।
E. **ऑस्ट्रेलिया-भारत इन्फ्रास्ट्रक्चर फोरम:** भारत में ऑस्ट्रेलिया के लिए शहरी बुनियादी ढांचे, परिवहन और पानी के क्षेत्र में अवसर ध्यान देने के मुख्य क्षेत्र हैं। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े रिटायरमेंट फंड ऑस्ट्रेलियन सुपर, जिसके पास 200 अरब अमेरिकी डॉलर का फंड प्रबंधन के लिए है, ने वर्तमान में 1.5 अरब डॉलर का निवेश

भारत में किया है. बड़े सॉवरेन फंड, पेंशन फंड और प्राइवेट इक्विटी के भारत में निवेश और भारत सरकार के राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 2025 तक 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के खर्च की योजना के साथ परस्पर क्षमताओं को मिलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ज़बरदस्त अवसर हैं।

F. ऑस्ट्रेलिया-भारत के बीच सामुदायिक सहयोग, रचनात्मकता, समझ और आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भी 20.8 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के कुल निवेश के साथ तीन मैत्री पहल की शुरुआत की है।
    a. 11.2 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के मैत्री छात्रवृत्ति कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के प्रतिभावान विद्यार्थियों को ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए मदद देना है, ये छात्र विशेष तौर पर विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग, गणित और स्वास्थ्य के होने चाहिए।
    b. 3.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का मैत्री अनुदान और फेलोशिप कार्यक्रम भविष्य के नेताओं के बीच संपर्क बनाएगा। ये कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया और भारत के जो लोग पेशेवर करियर के मध्य में है, उनको सामरिक अनुसंधान और साझा प्राथमिकता पर सहयोग के लिए समर्थन देग।
    c. 6.1 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की ऑस्ट्रेलिया-भारत मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी आर्थिक क्षेत्र में रचनात्मकता की भूमिका को बढ़ावा देगी। इसके साथ ही विज़ुअल एवं परफॉर्मिंग आर्ट, साहित्य, फिल्म, टेलीविज़न और संगीत उद्योग में कलाकारों की प्रतिभा एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देने के लिए लोगों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ावा देगी।

G. **चौथा भारत-ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा संवाद:** दोनों देशों ने तकनीक की लागत कम करने का निर्णय लिया है जिससे वैश्विक उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य बेहद कम क़ीमत में सौर ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और उसके इस्तेमाल समेत वास्तविक गतिविधियों और परियोजनाओं पर ध्यान देना है।
    a. नई और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की लागत को कम करने की दिशा में काम करने का मार्ग प्रशस्त करना
    b. वैश्विक उत्सर्जन में कमी लाने के लिए तैनाती को बढ़ाना।
    c. इस एलओआई का फोकस: अल्ट्रा-लो-कॉस्ट सोलर और क्लीन हाइड्रोजन के निर्माण और तैनाती को बढ़ाना
    d. **सहयोग के अन्य क्षेत्र:** प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण पर ध्यान देने की तत्काल आवश्यकता है। ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियां
        - ग्रिड प्रबंधन
        - ग्रिप गैस डिसल्फराइजेशन, बायोमास या हाइड्रोजन को-फायरिंग पर अनुसंधान एवं विकास सहयोग
        - जल चक्र अनुकूलन
        - नवीकरणीय एकीकरण
        - बैटरी
        - विद्युत गतिशीलता
        - विद्युत क्षेत्र के अलावा, सहयोग के कई वांछनीय क्षेत्र हैं जिन पर सहमति बनी है
        - ग्रीन हाइड्रोजन की लागत कम करना
        - कोयला आधारित ऊर्जा सुरक्षा और संसाधन परिनियोजन के क्षेत्र में सहयोग
        - खनिज क्षेत्र में निवेश के अवसर
        - एलएनजी साझेदारी की संभावना तलाशना

निष्कर्ष

ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच साझेदारी अब ऊपरी स्तर पर नहीं है, आज हम जो देख रहे हैं वो वास्तव में एक सच्ची व्यापक द्विपक्षीय विकास की कहानी है जो निरंतरता, प्रतिबद्धता और क्रियाशीलता से प्रेरित है। मुख्य बात ये है कि भारत में ऑस्ट्रेलिया से इस संबंध को बढ़ाया जाए और ऑस्ट्रेलिया में भारत से इस संबंध को बढ़ाया जाए, इसके लिए एक सर्वांगीण बहुपक्षीय रणनीति और दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो एक-दूसरे के लिए समझ और सराहना को और गहरा करते हैं।

क्या आप निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं?

1. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग इंडो-पैसिफिक में बढ़ते भू-राजनीतिक असंतुलन के खतरों को सीमित कर सकता है। टिप्पणी कीजिए।

'मानवीय गलियारे'(Humanitarian Corridors)	**मानवीय गलियारे क्या हैं?** • वे एक विशिष्ट क्षेत्र में और एक विशिष्ट समय के लिए विसैन्यीकृत क्षेत्र हैं – और एक सशस्त्र संघर्ष के दोनों पक्ष उनसे सहमत हैं। • संयुक्त राष्ट्र(UN) मानवीय गलियारों को सशस्त्र संघर्ष के अस्थायी विराम के कई संभावित रूपों में से एक मानता है। **इस कॉरिडोर की आवश्यकता क्यों होती है?** • इन गलियारों के माध्यम से, संघर्ष के क्षेत्रों में भोजन और चिकित्सा सहायता लाई जा सकती है, या नागरिकों को निकाला जा सकता है। • मानवीय गलियारे (Humanitarian Corridors) तब आवश्यक होते हैं जब शहरों की घेराबंदी की जाती है और आबादी बुनियादी खाद्य आपूर्ति, बिजली और पानी से कट जाती है। • ऐसे मामलों में जहां मानवीय आपदा सामने आती है क्योंकि युद्ध के अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया जा रहा है – उदाहरण के लिए नागरिक लक्ष्यों पर बड़े पैमाने पर बमबारी के माध्यम से – मानवीय गलियारे महत्वपूर्ण राहत प्रदान कर सकते हैं। **मानवीय गलियारे किसके द्वारा स्थापित किये जाते है?** • ज्यादातर मामलों में, मानवीय गलियारों(Humanitarian Corridors) पर संयुक्त राष्ट्र(UN) द्वारा बातचीत की जाती है। कभी-कभी वे स्थानीय समूहों द्वारा भी स्थापित किए जाते हैं। • चूंकि सभी पक्षों को गलियारों को स्थापित करने के लिए सहमत होने की आवश्यकता है, इसलिए सैन्य या राजनीतिक दुरुपयोग का खतरा है। उदाहरण के लिए, गलियारों का इस्तेमाल हथियारों और ईंधन की तस्करी के लिए घिरे शहरों में किया जा सकता है। • इसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों, गैर सरकारी संगठनों और पत्रकारों द्वारा उन विवादित क्षेत्रों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है जहां युद्ध अपराध किए जा रहे हैं। **यूक्रेन में कौन से कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं?** • पूर्वी यूक्रेन में, 5 मार्च को पांच घंटे का संघर्ष विराम होना था, जिससे लगभग 200,000 को मारियुपोल और वोल्नोवाखा शहर से छोड़ने की अनुमति मिल सके। • लेकिन यह पहल कुछ घंटों के बाद विफल हो गई जहां प्रशासन ने कहा कि निकासी को "सुरक्षा कारणों से स्थगित कर दिया गया था" क्योंकि रूसी सैनिकों ने आसपास बमबारी जारी रखी थी। • लेकिन रूस ने कहा कि मारियुपोल और वोल्नोवाखा के पास स्थापित गलियारों का उपयोग नहीं किया गया था। • यूक्रेन ने कहा कि रूस ने गलियारे के वादे को पूरा नहीं किया और मानवीय सहायता वाले 19 वाहनों को अंदर नहीं जाने दिया गया है।

	कौन पहुँचता है? • मानवीय गलियारों तक पहुंच संघर्ष के पक्षों द्वारा निर्धारित की जाती है। • यह आमतौर पर तटस्थ अभिनेताओं, संयुक्त राष्ट्र या रेड क्रॉस जैसे सहायता संगठनों तक सीमित है। • वे समय सीमा , क्षेत्र और परिवहन के साधन जैसे ट्रक, बस या विमान को गलियारे का उपयोग करने की अनुमति भी निर्धारित करते हैं। • दुर्लभ मामलों में, मानवीय गलियारों का आयोजन केवल संघर्ष के पक्षों में से एक द्वारा किया जाता है। वर्ष 1948-1949 में सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी के बाद अमेरिकी एयरलिफ्ट के साथ ऐसा हुआ था। **उनका उपयोग और कहाँ किया गया है?** • 20वीं सदी के मध्य से मानवीय गलियारों को स्थापित किया गया है। उदाहरण के लिए, 1938 से 1939 तक तथाकथित किंडरट्रांसपोर्ट के दौरान, यहूदी बच्चों को नाजी नियंत्रण वाले क्षेत्रों से यूनाइटेड किंगडम में निकाला गया था। • इसके अलावां 1992-1995 के दौरान साराजेवो, बोस्निया की घेराबंदी और 2018 में घोउटा, सीरिया की निकासी के दौरान मानवीय गलियारे (Humanitarian Corridors) भी बनाए गए थे। • हालाँकि, ऐसे कई युद्ध और संघर्ष हैं जहाँ नागरिक गलियारों के आह्वान या लड़ाई में विराम व्यर्थ किया गया है। उदाहरण के लिए, यमन में चल रहे युद्ध में, संयुक्त राष्ट्र अब तक अपनी वार्ताओं में विफल रहा है।
भारत-चीन संबंधों और नई वैश्विक धाराओं पर: स्पष्ट संकेत	**मुख्य उपाय:** भारत और चीन को उन वैश्विक धाराओं से जुड़ना चाहिए जो संबंधों को नया आकार दे सकती हैं। **चीन का दावा** चीन का यह दावा कि यू.एस. इंडो-पैसिफिक रणनीति "नाटो का एक इंडो-पैसिफिक संस्करण" बनाने का लक्ष्य बना रही है, नया नहीं है। • चीन ने "विशिष्ट क्लब बनाकर" अमेरिका पर "भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भड़काने" का आरोप लगाया। "फाइव आईज" इंटेलिजेंस गठबंधन को मजबूत करके और "क्वाड को पैडल करना, AUKUS को एक साथ जोड़ना और द्विपक्षीय सैन्य गठबंधनों को मजबूत करना", यू.एस. इस क्षेत्र में "पांच-चार-तीन-दो" गठन का नेतृत्व कर रहा है। • व्यापक लक्ष्य, चीन सोचता है कि "नाटो का एक इंडो-पैसिफिक संस्करण स्थापित करना" है। **रूस के साथ चीन के वर्तमान संबंध** • यूक्रेन में संकट के लिए बीजिंग ने बार-बार नाटो को जिम्मेदार ठहराया है। • तटस्थ रहने का दावा करते हुए, यह रूस के साथ संबंधों की पुष्टि करने के लिए आगे बढ़ा है, जिसे बीजिंग ने "रॉक सॉलिड" के रूप में वर्णित किया है। • जब दोनों देशों के नेताओं ने 4 फरवरी को शिखर सम्मेलन के लिए मुलाकात की, तो चीन ने यूरोप में नाटो के पूर्व की ओर विस्तार पर अपनी चिंताओं पर रूस का समर्थन किया, और रूस ने यू.एस. इंडो-पैसिफिक रणनीति की आलोचना करते हुए दोनों पक्षों के पक्ष में वापसी की। • पहले से ही गहरे राजनीतिक और आर्थिक संबंधों से परे, अमेरिकी गठबंधनों पर ये प्रतिबिंबित चिंताएं चीन-रूस अक्ष में एक शक्तिशाली बाध्यकारी गोंद के रूप में उभर रही हैं। **भारत का स्टैंड** *रूस के साथ संबंधों पर* • नई दिल्ली को यह विचार करने की आवश्यकता होगी कि यह रूस के साथ उसके घनिष्ठ संबंधों को कैसे प्रभावित करेगा। • भारत ने अमेरिका द्वारा प्रायोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव से परहेज किया है जो यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता की निंदा करता है, नई दिल्ली ने कहा कि बातचीत ही मतभेदों और विवादों को सुलझाने का एकमात्र जवाब है। **यूएसए के साथ संबंधों पर** • स्पष्ट रूप से क्वाड, जो एक सैन्य समझौता नहीं है, को अन्य सुरक्षा समझौतों के साथ तुलना करके, चीन अब स्पष्ट रूप से भारत को यू.एस. नई दिल्ली ने इस धारणा को खारिज कर दिया है। पिछले महीने ही, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा था कि "इच्छुक पक्ष" एक "एशियाई नाटो का आलसी सादृश्य" बना रहे थे और भारत

	एक अमेरिकी संधि सहयोगी नहीं था। *चीन के साथ संबंधों पर* ● भारत की ओर से दूसरा संदेश यह रहा है कि सरोकारों के प्रति संवेदनशीलता परस्पर होनी चाहिए, और दूसरे पक्ष द्वारा अनदेखी किए जाने पर एक तरफ से इसकी मांग नहीं की जा सकती; पाकिस्तान के साथ चीन के संबंध इसका उदाहरण हैं। ● चीन ने स्वीकार किया है कि संबंधों में हाल के "झटके" न तो भारत के अनुकूल हैं और न ही चीन के लिए यह एक विचार नई दिल्ली साझा करता है। ● एलएसी को अलग करने को आगे बढ़ाने के लिए अगले दौर की सैन्य वार्ता के लिए दोनों पक्ष 11 मार्च को मिलेंगे। **निष्कर्ष** जैसा कि भारत और चीन दशकों में सबसे निचले बिंदु से संबंधों को बहाल करने और सीमा पर शांति सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत जरूरी तौर-तरीके की तलाश जारी रखे हुए हैं, उन्हें वैश्विक धाराओं के बारे में व्यापक बातचीत करने की भी आवश्यकता होगी जो उनके द्विपक्षीय संबंधों को फिर से आकार दे रही हैं।
यूक्रेन युद्ध में तुर्की का दांव (Turkey's Stakes in Ukraine War)	**संदर्भ:** यूक्रेन और रूस के विदेश मंत्रियों को अंताल्या डिप्लोमैटिक फोरम के इतर बातचीत के लिए मिलना है। ● यह वार्ता "त्रिपक्षीय प्रारूप" में आयोजित की जाएगी: अर्थात तुर्की मध्यस्थ के रूप में वहाँ मौजूद रहेगा। ● यूक्रेन ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि वह इसमें भाग लेगा। चाहे बैठक हो या न हो, इस संकट में तुर्की की दिलचस्पी, विशेष रूप से मध्यस्थ की भूमिका निभाने में महत्वपूर्ण रहेगी। **तुर्की और रूस के बीच संबंध कैसे हैं?** ● तुर्की, यूरोप और एशिया के बीच प्रवेश द्वार के रूप में, कई भागों का देश है। यह नाटो का सदस्य है, और एक समय में यूरोपीय संघ में सदस्यता के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त माना जाता था। ● तुर्की भी तेजी से एक धार्मिक रूढ़िवादी राज्य है, जिसका सत्तावादी नेता घड़ी को इस्लामवाद की ओर मोड़ना चाहता है। **तुर्की और रूस के बीच तनाव** ● रूस तुर्की का मित्र है, लेकिन रूस-ओटोमन युद्धों में वापस जाने वाला एक सदियों पुराना भूराजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भी है। ● तुर्की के लिए, क्रीमिया पर मास्को का कब्जा चिंता का विषय रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि तुर्की इस "अवैध" कार्रवाई को कभी मान्यता नहीं देगा। ● सोवियत संघ के दिनों से तुर्की कुर्द विद्रोही समूह पीकेके से रूस की निकटता तुर्की के लिए एक प्रमुख अड़चन है। ● सीरिया में, रूस और तुर्की ने विपरीत पक्षों पर लड़ाई लड़ी, रूस ने बशर अल-असद की अध्यक्षता को बनाए रखने के लिए, और तुर्की ने उससे लड़ने वाले समूहों के पक्ष में था। ○ इस क्षेत्र में वर्चस्व के लिए रूस-तुर्की की लड़ाई तुर्की के साथ सीमा पर उत्तर-पश्चिमी सीरिया में इदलिब के छोटे से क्षेत्र में लड़ी गई थी। **बढ़ती साझेदारी** ● रूस अब तुर्की के मुख्य व्यापार भागीदारों में से एक है। तुर्की की अर्थव्यवस्था रूस से आयात पर बहुत अधिक निर्भर करती है। वर्ष 2019 में उनका द्विपक्षीय व्यापार करीब 16.4 अरब डॉलर का था और रूस से आयातित सबसे बड़ी वस्तु रिफाइंड पेट्रोलियम थी। ● रूस से तुर्की तक काला सागर के नीचे अब एक गैस पाइपलाइन है। ● वर्ष 2020 में, तुर्की ने रूस से एस 400 ट्रायम्फ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदी और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपने CAATSA कानून के तहत स्वीकृत किया गया था। ● रूस, दक्षिणी तुर्की के आयुक्कू में परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कर रहा है। **तुर्की और यूक्रेन के बीच संबंध कैसे हैं?** ● तुर्की यूक्रेन का करीबी व्यापारिक और रणनीतिक साझेदार भी है। ● वर्ष 2019 में उनका द्विपक्षीय व्यापार लगभग 2.15 बिलियन डॉलर का था, जिसमें तुर्की यूक्रेन का एक प्रमुख

	निर्यातक था। और इसी वर्ष सबसे बड़ा निर्यात रिफाइंड पेट्रोलियम भी था। ● तुर्की यूक्रेन को एक घातक मिसाइल वाहक ड्रोन भी प्रदान किया था, जिसका उपयोग यूक्रेन मौजूदा संघर्ष के दौरान रूसी टैंकों के खिलाफ करता रहा है। ● फरवरी 2022 में, जब यूक्रेन और रूस के बीच मामले उच्च बिंदु पर पहुंच रहे थे, तब तुर्की के राष्ट्रपति ने यूक्रेन का दौरा किया, और एक मुक्त व्यापार समझौते एवं यूक्रेन में सशस्त्र लंबी दूरी की बेराकथर ड्रोन के सह-निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ● यूक्रेन को हथियार देने को लेकर रूस तुर्की से नाराज़ है। **रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष में तुर्की की क्या स्थिति है?** ● तुर्की ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को अस्वीकार्य और क्षेत्रीय शांति के लिए एक सदमा बताया है। ● तुर्की ने लुहान्स्क और डोनेट्स्क के "गणराज्यों" की रूस की मान्यता को खारिज कर दिया है। ● तुर्की "यूक्रेन में रूसी आक्रमण" नामक महासभा के प्रस्ताव के 80 प्रायोजकों में से एक था। ● तुर्की ने 1936 के मॉन्ट्रो कन्वेंशन के प्रावधानों को भी लागू किया, यह एक ऐसा सम्मेलन था जिसने तुर्की को बोस्फोरस और डार्डानेल्स जलडमरूमध्य के प्रभारी के रूप में रखा, ताकि बोस्फोरस जलडमरूमध्य के माध्यम से युद्धपोतों के पारित होने पर रोक लगाई जा सके। ● लेकिन तुर्की ने यह भी कहा है कि सम्मेलन की शर्तों के तहत, वह काला सागर के तटवर्ती देशों के युद्धपोतों को नहीं रोक सकता है - रूस उनमें से एक है। ● तुर्की रूस के खिलाफ प्रतिबंधों में शामिल नहीं हुआ है। ● इसके अलावा, तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि तुर्की यूक्रेन या रूस के साथ संबंधों को नहीं छोड़ सकता है। **तुर्की क्यों मध्यस्थता करना चाहता है?** ● मध्यस्थता के अपने प्रयासों में, तुर्की क्षेत्रीय नेता की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। ● यह एर्दोगन को पश्चिम में अपनी खराब नेता की छवि को हटाने में भी मदद कर सकता है, जहां उन्हें दुनिया के सत्तावादी नेताओं के साथ स्थान दिया गया है। ● यह इस क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण आर्थिक हितों, काला सागर और तुर्की जलडमरूमध्य की स्थिरता, दोनों देशों के साथ अपने रक्षा संबंधों और रूस से तेल एवं गैस की आपूर्ति की रक्षा करने की भी मांग करना।
रूस-यूक्रेन संघर्ष वैश्विक खाद्य संकट को जन्म दे सकता है	**संदर्भ:** रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण विश्व में खाद्य अर्थव्यवस्था चिंता का विषय बना हुआ है। **वैश्विक खाद्य अर्थव्यवस्था में रूस और यूक्रेन का महत्व** ● रूस (18%) और यूक्रेन (8%) वैश्विक गेहूं निर्यात में लगभग एक चौथाई योगदान करते हैं। ● रूस और यूक्रेन मक्का उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हैं और वर्ष 2020 में वैश्विक मक्का निर्यात में उनकी 14 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। ● इसके अलावा, ये दोनों देश सूरजमुखी के तेल उत्पादन में अग्रणी हैं और निर्यात में उनकी 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है, रूस के साथ वैश्विक सूरजमुखी तेल निर्यात का 18 प्रतिशत हिस्सा है। **यूक्रेन संकट से वैश्विक खाद्य अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित होगी?** ● **वैश्विक कमोडिटी कीमतों में वृद्धि:** युद्ध के कारण वस्तुओं और कृषि उत्पादों में उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यवधान से कीमतों में वृद्धि होती है। मक्के (21 फीसदी), गेहूं (35 फीसदी), सोयाबीन (20 फीसदी) और सूरजमुखी तेल (11 फीसदी) की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। ● **खाद्य सुरक्षा:** खाद्य सुरक्षा के छह आयाम-उपलब्धता, पहुंच, उपयोग, स्थिरता, एजेंसी और स्थिरता, जो इस संकट से प्रभावित होने की उम्मीद है। ○ **उदाहरण के लिए:** यह पहले ही खाद्य सुरक्षा अफ्रीका पर चिंता व्यक्त कर चुका है। वर्ष 2020 में, अफ्रीकी देशों ने रूस से 4 बिलियन डॉलर की कृषि उपज (यूक्रेन से 2.9 बिलियन डॉलर) का आयात किया। 90% रूसी आयात में गेहूं और 6% सूरजमुखी तेल शामिल थे (यूक्रेन के आयात में 48% गेहूं, 31% मक्का और शेष सूरजमुखी तेल के रूप में शामिल थे) ● **खाद्य मुद्रास्फीति:** यह संकट खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगा जो COVID-19 प्रेरित मंदी के बाद

	अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए उपाय करने (ब्याज दर को कम करने) के लिए सरकार की क्षमताओं को और बाधित कर सकता है। ● **अन्य कारक स्थिति को खराब कर सकते हैं:** दक्षिण अमेरिका और इंडोनेशिया में शुष्क मौसम के कारण खराब फसल और चीन एवं भारत में गेहूं और तिलहन की बढ़ती मांग से स्थिति और खराब हो सकती है। ● **अन्य देशों के लिए अवसर:** कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे गेहूं निर्यातक देशों को अनाज की मांग में किसी भी संभावित निकट अवधि में वृद्धि से लाभ होने की संभावना है। ● इसके अलावा, चीन, यूरोपीय संघ के देशों, कनाडा और भारत जैसे तिलहन उत्पादक देश रूस और यूक्रेन के प्रभुत्व वाले बाजार में कदम रख सकते हैं। ● **उर्वरक मूल्य में वृद्धि:** यह युद्ध तेल और उर्वरक की कीमतों में वृद्धि, विकासशील और कम विकसित देशों में किसानों को प्रभावित करने और सरकारी वित्त पर दबाव डालने पर एक लहर प्रभाव पड़ सकता है। **आगे की राह** ● अनाज भंडार और खाद्य तेल की आपूर्ति निकट भविष्य में गरीबों की भुखमरी को पूरा करने में मदद कर सकती है। ● राज्य व्यापार निगम, भारतीय खाद्य निगम और बहुराष्ट्रीय तिलहन व्यापार फर्म जैसी एजेंसियां अपनी खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लचीला और कुशल बनाने के लिए अद्यतन करके संकट से निपटने में मदद कर सकती हैं। ● इसके अलावा, मजबूत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देने से उन देशों के गरीबों को मदद मिल सकती है जो संकट से बुरी तरह प्रभावित हैं (उदा: अफ्रीकी देश)
रक्षा कूटनीति के क्षेत्र में भारत के बढ़ते क़दम और उसके पदचिन्ह	**संदर्भ:** हाल ही में भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 'मिलन' को पूरा किया है, ये पहली बार था जब अमेरिकी नौसेना के साथ-साथ दुनिया के 40 देशों की नौसेनाएं इस युद्धाभ्यास में शामिल हुई हैं। ● नौसैनिक अभ्यास 'मिलन' की शुरुआत 1995 से हुई थी. इस साल ये युद्धाभ्यास दो चरणों में किया गया- बंदरगाह वाला चरण (25-28 फ़रवरी) और समुद्री चरण (1-4 मार्च) वाला अभ्यास। इस अहम नौसैनिक अभ्यास ने न केवल भारतीय नौसेना को पेशेवर संबंध विकसित करने का मौक़ा दिया, बल्कि भारत की नरम सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण भी बन गया है। ● मिलान युद्धाभ्यास में प्रतिभागियों का बढ़ता आकार और अभ्यासों की जटिलता भारत के पश्चिम से दक्षिण पूर्व एशिया तक विस्तारित रक्षा कूटनीति छाप का प्रतीक है। ● इस कूटनीति में अधिक उन्नत नौसैनिक जुड़ाव, अधिक सैन्य अभ्यास और रक्षा निर्यात के लिए उन्नत प्रयास शामिल हैं। ● परिणामस्वरूप, भारतीय सेनाएं ने साझीदार देशों की सेनाओं के साथ मिलकर काम करने में सुधार ला रही हैं, नई साझेदारियां बना रही हैं और इनके भारत की कूटनीति को भी शक्ति मिल रही है। **दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ बढ़ते संबंध** भारत की रक्षा कूटनीति के लिए एक प्रमुख चालक इस क्षेत्र में, विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में चीन की लगातार आक्रामक उपस्थिति रही है। हाल के वर्षों में भारत ने दक्षिणी पूर्वी एशिया के कई देशों के साथ सहयोग बढाया है। वे भी चीन को संतुलित करने और अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत के साथ अपने सुरक्षा संबंधों का विस्तार करने के इच्छुक हैं। ● अधिकांश दक्षिण पूर्व एशियाई राज्यों- इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, सिंगापुर, कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार ने इस वर्ष के मिलान अभ्यास में भाग लिया। ● भारत इस सहयोगी दृष्टिकोण का उपयोग रक्षा निर्यात को प्रोत्साहित करने और चीन का मुकाबला करने के लिए कर रहा है, जिसने अपनी रक्षा आपूर्ति का लाभ इस क्षेत्र में खुद को स्थापित करने के लिए दिया है। **रक्षा निर्यात** भारत ने हाल ही में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलें बेचने का सौदा 37.5 करोड़ डॉलर में किया है। ये सौदा भारत के रक्षा उद्योग का हौसला बढ़ाने वाला है। अनुबंध के तहत, भारत, फिलीपींस की नौसेना को मिसाइलों की तीन बैटरी देगा। ● वर्ष 2024 तक पांच अरब अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत ने दक्षिणी पूर्वी

एशिया और अफ्रीका में अपने हथियारों को बेचने के प्रयास तेज़ कर दिए हैं, जहां चीनी रक्षा कंपनियां हावी हैं।

- सरकार ने विदेशों में भारतीय दूतावासों में स्थित रक्षा संलग्नकों की भूमिका को सुदृढ़ किया है। सरकार ने उन्हें अपने संबंधित बाजारों में भारतीय रक्षा उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए 50,000 अमेरिकी डॉलर तक का वार्षिक बजट आवंटित किया है। इसके अलावा, उनकी बिक्री पिच को मजबूत करने के लिए, सरकार ने कई 'मेड-इन-इंडिया' उपकरण को मंजूरी दे दी है, जिसमें तेजस लड़ाकू विमान और मित्र देशों को निर्यात के लिए एस्ट्रा मिसाइल शामिल हैं।
- निर्यात से परे, भारत ने भी अपने निकटतम पड़ोसियों को उपकरण दान और स्थानांतरित करके अपनी नौसैनिक क्षमता का निर्माण करने में मदद की है। इसमें मॉरीशस (2015), श्रीलंका (2018), मालदीव (2019), और सेशेल्स (2021), साथ ही सेशेल्स (2013 और 2018) के लिए दो डोर्नियर विमान शामिल हैं।
- इस तरह के प्रयासों के कारण, निर्यात 2018-19 में बढ़कर 10,745 करोड़ रुपये हो गया, जो 2014-15 में सिर्फ 1,940.64 रुपये था, हालांकि अभी एक लंबा रास्ता तय करना है।

तालिका 1: भारत का रक्षा निर्यात

वर्ष	रक्षा निर्यात (करोड़ रुपये में)
2014-15	1,940.64
2015-16	2,059.18
2016-17	1,521.91
2017-18	4,682.36
2018-19	10,745.77
2019-20	9,115.55
2020-21	8,434.84

स्रोत: *रक्षा मंत्रालय, लोकसभा*

मानवीय सहायता

'शुद्ध सुरक्षा प्रदाता' होने का एक प्रमुख तत्व इस क्षेत्र में मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) संचालन शुरू करने की क्षमता है।

- लंबे समय से, भारत एचएडीआर संचालन के मोर्चे पर अग्रणी रहा है, जैसा कि 2004 के हिंद महासागर में सुनामी, 2015 के नेपाल भूकंप और 2020 में मेडागास्कर में बाढ़ के दौरान देखा गया था। इसके अलावा, पिछले एक दशक में आईएनएस जलाश्व ट्रांसपोर्ट डॉक (INS Jalashwa transport dock) और C17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे उपकरणों के अधिग्रहण ने भारतीय सेना को इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने का अधिकार दिया है।
- भारत, विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया तंत्र को बढ़ाने के लिए भागीदार देशों के साथ समन्वय कर रहा है।
- एचएडीआर क्वाड के भीतर एक महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र बना हुआ है, लेकिन भारत ने महामारी की पृष्ठभूमि में इस तरह के संचालन के लिए आकस्मिकताओं की परिकल्पना करने के लिए बिम्सटेक (बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन) देशों के साथ पैनेक्स -21 अभ्यास जैसी पहल की है।

भारत के पश्चिम में संबंधों का विकास

भारत ने अब पश्चिम एशियाई राजतंत्रों के साथ एक अलग साझेदारी तैयार की है और रक्षा कूटनीति ने इस रिश्ते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया है। जब इस क्षेत्र में अब्राहम समझौते के साथ युगांतरकारी बदलाव और चीन की बढ़ती प्रोफ़ाइल देखी जा रही है, तो भारत ने नौसैनिक जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करके अपने सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाया है।

	• अगस्त 2021 में, भारत ने संयुक्त अरब अमीरात (ज़ायद तलवार अभ्यास), बहरीन (समुद्री भागीदारी अभ्यास), और सऊदी अरब (अल-मोहद अल-हिंदी अभ्यास) के साथ बैक-टू-बैक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। • विशेष रूप से यह भारत-सऊदी अरब अभ्यास दोनों के बीच पहला संयुक्त अभ्यास था। दोनों देशों के अपने-अपने सेना प्रमुखों के साथ उच्च स्तरीय सैन्य आदान-प्रदान भी हुआ है, जो पहली बार अभ्यास में शामिल हो रहे थे। • ओमान ने इस क्षेत्र में भारत की सैन्य भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण एंकर के रूप में कार्य किया है। दोनों सेनाओं के बीच नियमित सैन्य आदान-प्रदान के अलावा, ओमान ने भारतीय नौसेना को रसद और समर्थन के लिए डुकम बंदरगाह तक पहुंच प्रदान की है। इसने पश्चिमी हिंद महासागर में नौसेना की निरंतर दीर्घकालिक उपस्थिति की सुविधा प्रदान की है, जो वर्षों से समुद्री डकैती के लिए एक हॉटस्पॉट के रूप में कार्य किया था। • लेकिन हाल ही में समुद्री डकैती की घटनाओं में कमी आई है और अन्य चुनौतियां सामने आई हैं, जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध मछली पकड़ना जो समुद्री सतर्कता की मांग करती हैं। • **अफगान चुनौती से निपटना:** जनवरी 2022 के उद्घाटन भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन और नवंबर 2021 की क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता ने आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अफगान चुनौती के प्रति भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। इस दिशा में, भारत रुचि रखने वाले मध्य एशियाई राज्यों के साथ संयुक्त आतंकवाद-रोधी अभ्यास आयोजित करने की संभावना तलाश रहा है, जो संभावित आतंकवादी हिंसा से निपटने के लिए उनके संबंधित सुरक्षा बलों को तैयार करेगा। **निष्कर्ष** भारत-प्रशांत में बढ़ती चीनी समुद्री दृढ़ता से निपटने के साथ-साथ अफगानिस्तान में सामने आ रही सुरक्षा स्थिति के प्रतिकूल क्षेत्रीय नतीजों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, भारत ने क्षेत्रीय कूटनीति को आकार देने के लिए अपने रक्षा बलों का तेजी से लाभ उठाया है। ये पहलें भारत को एक सतत सहकारी जुड़ाव बनाने और पूरे क्षेत्र में साझेदारी का एक वेब बनाने में मदद कर रही हैं। इन साझेदारियों को बनाए रखने के लिए भारत को अपनी नौसेना, अभियान और रसद क्षमताओं में अधिक निवेश करने की आवश्यकता होगी। **क्या आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं?** 1. भारत की बढ़ती रक्षा कूटनीति पर विचार कीजिए।
नई यूएस इंडो-पैसिफिक स्ट्रैटेजी: नए और विकसित पर्यावरण के साथ निरंतरता को संतुलित करना	**संदर्भ:** 22 फ़रवरी 2022 को जारी नई यूएस इंडो-पैसिफिक स्ट्रैटेजी को लेकर सीमित दिलचस्पी देखी जा रही है। इनमें से प्रमुख हैं- रूस-यूक्रेन संकट जो 24 फरवरी 2022 को एक आक्रमण और युद्ध में बदल गया। हालांकि अमेरिका निरंतर ऐसे संकेत दे रहा है कि इस इलाक़े से उसका जुड़ाव और उसकी रणनीति टिकाऊ हैं, अमेरिका जताना चाहता है कि संसार के किसी दूसरे हिस्से के टकरावों और संकटों का यहां की रणनीतियों पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका की पिछली हिंद-प्रशांत रणनीतिक रिपोर्ट 1 जून 2019 को जारी हुई थी। हालांकि कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में थोड़े-बहुत बदलाव देखने को मिले हैं। इसे उभरते भू-सामरिक वातावरण के हिसाब से अनुकूलन के रूप में देखा जा सकता है। **नई रणनीति** ***भौगोलिक विस्तार*** • पिछली रणनीति में मुख्य उद्देश्य के तौर पर "क्षेत्रीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अमेरिकी प्रभाव को बरकरार रखने" की पहचान की गई थी। नई रणनीति में भी इस इलाक़े में "प्रभाव का संतुलन तैयार करने" को एक लक्ष्य के तौर पर रेखांकित किया गया है। • हालांकि, ताज़ा रणनीति में कुछ और बिंदुओं को जोड़ा गया है, जिनके ज़रिए चीन के साथ प्रतिस्पर्धा से ज़िम्मेदार तरीक़े से निपटने पर ज़ोर दिया गया है, शायद ऐसे कम भड़काऊ या अपेक्षाकृत नरम रुख़ का मक़सद महाशक्तियों के बीच की रस्साकशी और प्रतिस्पर्धा को लेकर इस इलाक़े की चिंताओं को दूर करना है। • नई रिपोर्ट में इसे "प्रशांत महासागर में अमेरिकी समुद्री तट से लेकर हिंद महासागर तक" के इलाक़े के तौर पर देखा गया है। इसके तहत उत्तर पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया और ओशिनिया (प्रशांत महासागर के द्वीपों समेत) को तवज्जो दी गई है। दोनों ही रणनीतियों में पश्चिमी हिंद महासागर को शामिल नहीं किया गया। हालांकि नई रणनीति में भारत के पश्चिमी समुद्री तट के दायरे को ख़त्म कर पूरे दक्षिण एशिया को ही शामिल कर लिया गया है, नतीजतन अरब सागर का व्यापक इलाक़ा अब अमेरिका की नज़र में हिंद-प्रशांत क्षेत्र का हिस्सा हो गया है।

मौजूदा क्षेत्रीय संधि गठबंधनों के विशिष्ट संदर्भ में 'गठबंधन और भागीदारी' पर जोर देता है।

- यह उभरती भागीदारियों को मज़बूत बनाने के साथ-साथ मौजूदा गठजोड़ों (ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस, कोरियाई गणराज्य, ताइवान और थाईलैंड) को आधुनिक बनाने और उन्हें बदलते वक़्त की ज़रूरतों के हिसाब से ढालने की अनुकूल की गई है। साझेदारियों के बीच, क्वाड को रणनीति में विशेष जोर और बार-बार उल्लेख मिलता है।
- यह क्वाड को मजबूत करने और आसियान के साथ काम करने वाले क्वाड का पता लगाने का प्रयास करता है। 2019 के विपरीत, नई रणनीति यूरोपीय संघ और नाटो के साथ दृष्टिकोण को संरेखित करना चाहती है। यह इस मान्यता के कारण है कि इस क्षेत्र के लिए यूरोपीय संघ और अमेरिकी रणनीतियाँ विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न हैं।
- यह भी उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र के लिए ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका (AUKUS) की नई सुरक्षा भागीदारी (15 सितंबर 2021 से शुरू हुई) की इस ताज़ा रणनीति के आख़िरी हिस्से में केवल संक्षेप में चर्चा की गई है। इस हिस्से में कार्य योजनाओं का ब्योरा दिया गया है। इस संक्षिप्त ब्योरे में भी ऑकस का गठन करते वक़्त जारी साझा बयान की सामग्रियों को ही बस दोहरा दिया गया है। ताज़ा रणनीति में AUKUS को ज़्यादा महत्व नहीं दिए जाने की वजह शायद इसके संभावित दायरों को लेकर कुछ साथी देशों द्वारा ज़ाहिर की गई चिंताएं हैं। दरअसल अमेरिका ये सुनिश्चित करना चाहता है कि इस इलाक़े के भीतर और यहां से परे भागीदारियां और संपर्क तैयार करने के रास्ते में किसी भी सूरत में ऑकस के चलते कोई रुकावट न आए।

2022 की शुरुआत में, नई रणनीति में एक 'हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचे' के साथ आर्थिक और व्यापारिक भागीदारी का एजेंडा पेश किया गया है।

- इसके तहत लोकतांत्रिक मूल्यों, तकनीक, डिजिटल, जलवायु, पर्यावरण और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों का भी शामिल किया गया है। इससे ये रणनीति एक व्यापक स्वरूप लेती दिखाई देती है, हालांकि इसका मुख्य ज़ोर 'सुरक्षा' पर ही है।
- इस क्षेत्र में संसाधनों को चलाने की नई योजना में नए दूतावास/वाणिज्य दूतावास खोलने, भागीदारों को सुरक्षा सहायता प्रदान करने और क्षेत्र में यूएस कोस्टगार्ड की उपस्थिति का विस्तार करने पर जोर दिया गया है। यह साझेदारी नए जोर और दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में चीन के ग्रे ज़ोन संचालन द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त चुनौतियों से जुड़ा है।

भारत के निरंतर उत्थान और क्षेत्रीय नेतृत्व का समर्थन करना एक अलग कार्य एजेंडा आइटम के रूप में इंगित किया गया है, जो क्वाड को और अधिक प्रभावी बनाने से भी जुड़ा हुआ है। रूस-यूक्रेन युद्ध पर भारत की अब तक की तटस्थ स्थिति को देखते हुए, रणनीति के इस हिस्से को आगे ले जाने पर अलग-अलग विचार निकट भविष्य में उभरने की संभावना है।

चीन की संभावित प्रतिक्रिया

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में पर्यावरण, चुनौतियां और अवसर पूर्वी यूरोप के लोगों से काफी अलग हैं। फिर भी, रूस-यूक्रेन युद्ध और इससे संबंधित, चल रहे घटनाक्रम हिंद-प्रशांत के बारे में ड्रामा को दृढ़ता से प्रभावित करने के लिए बाध्य हैं।

- चीन और रूस, जो भारत-प्रशांत क्षेत्र की अवधारणा के विरोधी हैं, ने इस क्षेत्र के लिए अमेरिकी रणनीतियों की समानताएं और आलोचना करना शुरू कर दिया।
- चीन के इस बात पर जोर देना जारी रखने की संभावना है कि पूर्वी यूरोप में अमेरिका और नाटो के दृष्टिकोण को इंडो-पैसिफिक में दोहराया जा सकता है, जिसके संभावित परिणाम यूक्रेन में देखी गई तबाही और पीड़ा के समान हैं।
- युद्ध की समाप्ति की विधि, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बाद के समझौते का दायरा, और यूरोपीय सुरक्षा वास्तुकला में बदलाव इंडो-पैसिफिक सहित अन्य क्षेत्रों में दृष्टिकोण को प्रभावित करेंगे।
- चीन से यह भी उम्मीद की जा सकती है कि वह भारत-प्रशांत के लिए चीनी और यूरोपीय संघ के दृष्टिकोण के बीच आम आधार पर जोर दे, विशेष रूप से समावेशिता पर, जो नई अमेरिकी रणनीति का हिस्सा नहीं है।
- यह चीन-यूरोप सहयोग पर प्रतिकूल प्रभाव को सीमित करने का भी प्रयास करेगा, क्योंकि चीन को यूरोप में विशाल बहुमत द्वारा रूस के पक्ष में देखा गया है। युद्ध की समाप्ति की विधि, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बाद के समझौते का दायरा, और यूरोपीय सुरक्षा वास्तुकला में बदलाव इंडो-पैसिफिक सहित अन्य क्षेत्रों में दृष्टिकोण को प्रभावित करेंगे।

निष्कर्ष

	नई रणनीति भारत-प्रशांत से संबंधित अमेरिका में नीति स्तर पर द्विदलीय समर्थन और निरंतरता को इंगित करती है। इसे वर्ष 2019 की रणनीति में बदलाव के साथ वर्तमान परिवेश में अनुकूलित किया गया है, लेकिन यह अभी भी इरादे के बयान की तरह है। ● चूंकि यह अपने कार्यान्वयन से संबंधित कई विवरणों पर कम है, इसलिए यह अपने कार्य एजेंडे के संबंध में विभिन्न आकलनों और अनुमानों के लिए कई पहलुओं को खुला छोड़ देता है। ● यह सुरक्षा से परे अपने दायरे का विस्तार करने की मांग की है, लेकिन एक बार फिर सीमित विवरण के साथ। भारत-प्रशांत क्षेत्र की अमेरिका की प्राथमिकता और इस रणनीति की रिहाई पर रूस-यूक्रेन युद्ध भी छाया हुआ है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद से सबसे बड़ा पारंपरिक सैन्य हमला है। ● युद्ध और अंतिम समझौता हिंद-प्रशांत के लिए नई अमेरिकी रणनीति सहित अन्य क्षेत्रों में रणनीतियों के कार्यान्वयन को प्रभावित करेगा। **क्या आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं?** **1.** संयुक्त राज्य अमेरिका की इंडो-पैसिफिक रणनीति अपनी सुरक्षा को मजबूत करने और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। टिप्पणी कीजिए।
वन रैंक वन पेंशन केस	**संदर्भ:** सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए लागू वन रैंक वन पेंशन (OROP) की नीति को सही ठहराया। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसमें कोई संवैधानिक कमी नहीं है। ● याचिकाकर्ता भारतीय भूतपूर्व सैनिक आंदोलन (आईईएसएम) ने 7 नवंबर 2015 के OROP नीति के फैसले को चुनौती दी थी। **वन रैंक वन पेंशन क्या है?** ● 'वन रैंक, वन पेंशन' (OROP) का अर्थ है कि सेवानिवृत्त होने की तारीख से इतर समान सेवा अवधि और समान रैंक पर सेवानिवृत्त हो रहे सशस्त्र सैन्यकर्मियों को एक समान पेंशन दी जाएगी। ○ वर्ष 2011 में कोश्यारी समिति ने ओआरओपी को एक समान पेंशन के रूप में परिभाषित किया, जो समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक में सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को भुगतान किया जाना था, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि कुछ भी हो। ● हालांकि यह लगभग स्पष्ट प्रतीत हो सकता है, ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से पहले ऐसा नहीं था। ● तीनों सेवाओं में सैन्य कर्मी दो श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, अधिकारी और अन्य रैंक जैसा उनकी पोस्ट हो। ● अन्य रैंक वाले जो सैनिक हैं, ये आमतौर पर 35 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। अर्थात देश को एक युवा सेना की जरूरत है। ● 60 वर्ष के करीब सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के विपरीत, सैनिक रैंक वाले कर्मचारी वेतन आयोगों के लाभों से वंचित हो जाते हैं। इस प्रकार केवल पेंशन ही उनका अंतिम जीविका का स्रोत रहता है, इसलिए पेंशन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ● इसलिए, यह तर्क दिया गया कि बाद में सेवानिवृत्त होने वालों की तुलना में एक सैनिक पेंशन के रूप में जो कमाता है, उसके लिए समय से पहले सेवानिवृत्ति एक प्रतिकूल तत्व नहीं बनना चाहिए। **ओआरओपी की मांग कब शुरू हुई?** ● 1950 से 1973 तक, पेंशन की मानक दर के रूप में जानी जाने वाली एक अवधारणा थी, जो ओआरओपी के समान थी। ● 1974 में, जब तीसरा वेतन आयोग लागू हुआ, तो कुछ बदलाव किए गए जिन्हें चौथे वेतन आयोग में और संशोधित किया गया। ● अंतत: क्या हुआ कि क्रमिक वेतन आयोगों का लाभ उन सैनिकों को नहीं दिया गया जो पहले सेवानिवृत्त हो चुके थे। ● उन लोगों के लिए पेंशन अलग-अलग थी जो समान रैंक पर, समान सेवा के वर्षों के साथ, लेकिन वर्षों के अंतर से सेवानिवृत्त हुए थे। ● पूर्व सैनिकों ने इस विसंगति को दूर करने के लिए ओआरओपी की मांग की। और दशकों से, कई समितियों ने इस

	पर ध्यान दिया। • 1983 में ब्रिगेडियर के पी सिंह देव समिति ने पेंशन की मानक दर के समान एक प्रणाली की सिफारिश की, जैसा कि रक्षा संबंधी संसदीय समितियों ने किया था। **ओआरओपी के वित्तीय निहितार्थ क्या हैं?** • मांग को पूरा करना आर्थिक रूप से अस्थिर होने का तर्क दिया गया क्योंकि सैनिक जल्दी सेवानिवृत्त हो जाते हैं और अन्य कर्मचारियों की तुलना में अधिक समय तक पेंशन के लिए पात्र रहते हैं। • इससे रक्षा मंत्रालय का पेंशन बजट (कुल रक्षा बजट के पांचवें हिस्से से अधिक) बढ़ जाएगा, जो मंत्रालय के पूंजीगत व्यय को और अधिक प्रभावित करेगा। • कुल रक्षा पेंशनभोगी 32.9 लाख हैं, लेकिन इसमें 6.14 लाख रक्षा नागरिक पेंशनभोगी शामिल हैं। • पेंशन पर रक्षा मंत्रालय का वास्तविक खर्च 2019-2020 में 1.18 लाख करोड़ रुपये और 2020-2021 में 1.28 लाख करोड़ रुपये था • जब मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री थे, तो अनुमान लगाया गया था कि पिछले सभी मुद्दों को दूर करने के लिए 83,000 करोड़ रुपये के एकमुश्त भुगतान की आवश्यकता होगी। • लेकिन हर बार जब कोई नया वेतन आयोग आया, तो इससे समता लाने के लिए पर्याप्त भुगतान मिलेगा। **सरकार द्वारा 2015 से ओआरओपी लागू करने के बाद भी क्या चिंता थी?** • याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया कि सरकार ने ओआरओपी की प्रारंभिक परिभाषा को बदल दिया है और पेंशन की दरों के स्वत: संशोधन के बजाय, संशोधन अब आवधिक अंतराल पर होगा। • याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मनमाना और असंवैधानिक था। **क्या था न्यायालय का फैसला?** • न्यायालय इस तर्क से सहमत नहीं थी कि सरकार की 2015 की नीति ओआरओपी को लागू करने के मूल निर्णय का खंडन करती है। • न्यायालय ने यह भी कहा कि जबकि कोश्यारी समिति की रिपोर्ट मांग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उस पर अपने स्वयं के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है, इसे "सरकारी नीति के एक बयान के रूप में नहीं माना जा सकता है"। • सरकार की नीति का मूल्यांकन करने के बाद, इसने "7 नवंबर 2015 के सरकारी संचार द्वारा परिभाषित ओआरओपी सिद्धांत में कोई संवैधानिक दोष नहीं पाया"। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** • केंद्रीय सशस्त्र पुलिस सेवाएं • आत्मानिर्भर भारत
रूस-यूक्रेन संघर्ष: आईसीजे की भूमिका	**संदर्भ:** यूरोप में यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे संघर्ष ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे गंभीर मानवीय संकटों में से एक को जन्म दिया है। • रूस ने डोनेट्स्क और लुहान्स्क (क्रेन के पूर्वी भाग) के क्षेत्रों में रूसी भाषी लोगों के नरसंहार के कथित कृत्य के जवाब के रूप में अपने "विशेष सैन्य अभियान" को सही ठहराने की मांग की है। • यूक्रेन ने 26 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) से संपर्क किया, जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि रूस द्वारा दावा किए गए नरसंहार (नरसंहार सम्मेलन, 1948 के तहत परिभाषित) का कोई भी कार्य यूक्रेन द्वारा नहीं किया गया है और अदालत से रूस को निर्देश देने का भी अनुरोध किया है। यूक्रेन में "तुरंत सैन्य अभियानों को निलंबित करें"। • आईसीजे ने 16 मार्च को रूसी संघ को निर्देश दिया कि वह अन्य बातों के साथ-साथ यूक्रेन में सभी सैन्य अभियानों को तुरंत निलंबित कर दे। **ICJ का अधिकार क्षेत्र कहाँ है?** • ICJ के क़ानून के अनुच्छेद 36(1) में प्रावधान है कि ICJ के पास संयुक्त राष्ट्र चार्टर, या अन्य संधियों या सम्मेलनों से संबंधित सभी मामलों में अधिकार क्षेत्र होगा।

- अनुच्छेद IX के तहत नरसंहार सम्मेलन 1948 में यह प्रावधान है कि नरसंहार सम्मेलन की व्याख्या, आवेदन या पूर्ति से संबंधित राज्यों के बीच विवाद, साथ ही साथ नरसंहार के लिए एक राज्य की जिम्मेदारी से संबंधित विवादों को किसी के अनुरोध पर आईसीजे को प्रस्तुत किया जाएगा।
- ICJ ने माना कि यूक्रेन और रूस के बीच इस सवाल पर प्रथम दृष्टया विवाद है कि क्या यूक्रेन में नरसंहार के कृत्य किए गए हैं, और तदनुसार इसका अधिकार क्षेत्र है।

अनंतिम उपायों को इंगित करने के लिए ICJ की शक्तियों में क्या शामिल है?

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क़ानून, अनुच्छेद 41 के तहत, ICJ को किसी भी मामले में शामिल पक्षों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए अनंतिम उपायों को इंगित करने का अधिकार देता है।
- जब ICJ ऐसे अनंतिम उपायों को इंगित करता है, तो विवाद के पक्षों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सूचित करना होगा।
- 2001 तक, इस बात को लेकर अनिश्चितता थी कि क्या ICJ द्वारा इंगित अनंतिम उपाय बाध्यकारी थे।
- हालांकि, जर्मनी और अमेरिका के बीच लाग्रैंड (2001) के मामले में अमेरिका में एक जर्मन नागरिक को कांसुलर एक्सेस से इनकार करने से संबंधित, आईसीजे ने स्पष्ट किया कि अनंतिम उपाय चरित्र में बाध्यकारी हैं और अंतरराष्ट्रीय कानूनी दायित्वों को बनाते हैं।
- इसके अलावा, आईसीजे द्वारा या तो किसी राज्य पार्टी के अनुरोध पर या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर अनंतिम उपायों का संकेत दिया जा सकता है।
- आईसीजे ने तेहरान बंधकों के मामले (1980) में यह भी माना है कि संबंधित पक्षों में से किसी एक की गैर-मौजूदगी स्वयं अस्थायी उपायों के संकेत के लिए एक बाधा नहीं हो सकती है।
    - वर्तमान मामले में, रूसी संघ ने अदालत के समक्ष मौखिक कार्यवाही में उपस्थित नहीं होने का विकल्प चुना। इसके बावजूद, ICJ मामले का फैसला करने के लिए आगे बढ़ा।

ICJ की शक्तियों का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जा सकता है?

- अनंतिम उपायों को इंगित करने की शक्ति कुछ शर्तों के अधीन है।
- रोहिंग्याओं के नरसंहार से निपटने वाले गाम्बिया बनाम म्यांमार (2020) मामले में, ICJ ने कहा कि यह अनंतिम उपायों को इंगित करने की शक्ति का प्रयोग तभी कर सकता है जब वह संतुष्ट हो कि अस्थायी उपायों का अनुरोध करने वाली पार्टी द्वारा दावा किए जा रहे अधिकार "कम से कम प्रशंसनीय" हैं।
- वर्तमान मामले में आईसीजे ने माना कि यूक्रेन के पास वास्तव में "नरसंहार के कथित कृत्यों को दंडित करने और रोकने के उद्देश्य से रूसी संघ द्वारा सैन्य अभियानों के अधीन नहीं होने का अधिकार है।"
- ICJ ने नरसंहार कन्वेंशन 1948 के तहत एक साधन के रूप में नरसंहार को रोकने और दंडित करने के लिए दूसरे राज्य के खिलाफ एकतरफा सैन्य बल के उपयोग के बारे में संदेह व्यक्त किया।
- इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि नरसंहार कन्वेंशन अन्य साधनों के लिए प्रदान करता है जैसे कि अनुच्छेद VIII के तहत अन्य संयुक्त राष्ट्र अंगों का सहारा लेना, और अनुच्छेद IX के तहत ICJ द्वारा शांतिपूर्ण विवाद समाधान के लिए।
- यहां यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि अनंतिम उपायों के चरण में आईसीजे इस बात का निश्चित विश्लेषण नहीं करता है कि आवेदक द्वारा दावा किए गए अधिकार वास्तव में मौजूद हैं या नहीं। वह विश्लेषण गुण चरण के लिए है।

आगे क्या छिपा है?

- ICJ द्वारा इंगित अनंतिम उपाय बाध्यकारी हैं, और गैर-अनुपालन निश्चित रूप से एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी दायित्व के उल्लंघन पर जोर देता है।
- हालाँकि, ICJ के पास स्वयं निर्णय के प्रवर्तन को सुरक्षित करने के लिए साधन या तंत्र नहीं है।
- दरअसल, अनुच्छेद 94(2) के तहत संयुक्त राष्ट्र चार्टर में यह प्रावधान है कि यदि कोई राज्य आईसीजे के फैसले के अनुसार दायित्वों को निभाने में विफल रहता है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) फैसले को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक उपाय कर सकती है।

	• हालाँकि, वर्तमान मामले में संभावना धूमिल है क्योंकि रूस के पास UNSC में वीटो पावर है। • इसके अतिरिक्त, यदि सुरक्षा परिषद में कोई गतिरोध है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 14 के तहत किसी भी स्थिति के शांतिपूर्ण समायोजन के उपायों की सिफारिश करने का अधिकार है। • निकारागुआ बनाम यूएस (1984) जब अमेरिका ने आईसीजे के फैसले का पालन करने से इनकार कर दिया और सुरक्षा परिषद में गतिरोध पैदा हो गया, तो यूएनजीए ने अमेरिका के व्यवहार की निंदा करते हुए कई प्रस्तावों को अपनाया।
अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन	**संदर्भ:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पिछले अगस्त में तालिबान के अधिग्रहण के बाद अफगानिस्तान में अपने राजनीतिक मिशन के लिए एक मजबूत जनादेश को मंजूरी दी है। **नया जनादेश (new mandate) क्या है?** • नया जनादेश संयुक्त राष्ट्र मिशन को अधिकृत करता है, जिसे UNAMA के नाम से जाना जाता है, लैंगिक समानता, महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण, सभी अफगानों के मानवाधिकारों और एक समावेशी और प्रतिनिधि सरकार को बढ़ावा देने के लिए। • नॉर्वेजियन-मसौदा संकल्प को 14-0 के वोट से अपनाया गया, जिसमें रूस ने भाग नहीं लिया। • रूस ने संयुक्त राष्ट्र की उपस्थिति पर मेजबान देश (अफगानिस्तान) से परामर्श नहीं करने के लिए परिषद की आलोचना करते हुए कहा कि UNAMA और तालिबान के बीच "पर्याप्त सहयोग" संयुक्त राष्ट्र को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। • संयुक्त राष्ट्र मिशन के जनादेश में अति आवश्यक सहायता का समन्वय और वितरण भी शामिल है। • परिषद ने UNAMA को "सभी प्रासंगिक अफगान राजनीतिक अभिनेताओं और हितधारकों, क्षेत्र और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच संवाद की सुविधा के लिए" अधिकृत किया। • सुरक्षा परिषद ने एक स्पष्ट संदेश भेजा कि UNAMA "अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने और अफगान लोगों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि वे अभूतपूर्व चुनौतियों और अनिश्चितता का सामना करते हैं।" **अफगानिस्तान में वर्तमान चुनौतियां क्या हैं?** • **लड़कियों के लिए शिक्षा तक पहुंच:** 20 साल के युद्ध (2001-2021) के बाद अमेरिका की वापसी के साथ, तालिबान ने देश पर कब्जा कर लिया। सत्ता में बैठे तालिबान ने लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया है। तालिबान अब लड़कियों को प्राथमिक विद्यालय में जाने की अनुमति दे रहा है लेकिन बड़ी लड़कियों को अभी भी शिक्षा से वंचित रखा गया है। • **कामकाजी महिलाओं पर प्रतिबंध:** स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसे कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, अफगानिस्तान की बड़ी संख्या में कामकाजी महिलाओं को अपने कार्यस्थलों पर जाने की अनुमति नहीं है। • **अल्पसंख्यकों के प्रति असहिष्णुता:** पूर्व सरकारी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिशोध के साथ-साथ अल्पसंख्यक समूहों और नागरिक समाज के खिलाफ हमलों, धमकी , नजरबंदी और जबरन गायब होने की खबरें हैं। • चरमपंथी समूह का समर्थन करने का डर तालिबान ने अभी तक यह प्रदर्शित नहीं किया है कि चरमपंथी समूह अब देश में पनपने में सक्षम नहीं हैं। • **सत्ता का बंटवारा:** तालिबान के नए शासकों ने एक समावेशी सरकार का वादा किया था। हालाँकि, तालिबान द्वारा नियुक्त मंत्रिमंडल भारी पश्तून और महिलाओं के बिना बना हुआ है। तालिबान सत्ता साझा करने या अफगानों के मूल अधिकारों का सम्मान करने के कोई संकेत नहीं दिखाता है। • **आर्थिक संकट:** तालिबान के अधिग्रहण से पहले, अफगान सरकार के खर्च का दो-तिहाई हिस्सा दान के माध्यम से आता था। चूंकि किसी भी देश ने तालिबान को अफगानिस्तान के वैध शासकों के रूप में मान्यता नहीं दी है, अगस्त महीने से ये दान सरकार के कामकाज में बाधा डाल रहे हैं। • **बड़े पैमाने पर भुखमरी:** विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार, अफगानिस्तान के 38 मिलियन लोगों में से केवल 2% फीसदी पर्याप्त भोजन है।

	● **बढ़ती गरीबी:** संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था के इस वर्ष 30% तक सिकुड़ने की उम्मीद है और वर्ष 2022 के मध्य तक लगभग हर अफगान नागरिक गरीबी में रह सकता है। ● **अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं की अनिच्छा:** अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस डर से कदम उठाने के लिए अनिच्छुक है कि तालिबान अपनी शक्ति को मजबूत करने और सुधारों के मांगों का विरोध करने के लिए सहायता का उपयोग करेगा। **आगे की राह** ● जब अफगान बड़े पैमाने पर भुखमरी का सामना करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दूर नहीं देख सकता। ● नए जनादेश के साथ, जिसे लगभग सभी प्रमुख शक्तियों का समर्थन मिला, संयुक्त राष्ट्र मिशन को तालिबान को शामिल करना शुरू कर देना चाहिए। ● इसका अर्थ यह नहीं है कि सदस्य देशों को तालिबान शासन को शीघ्र मान्यता प्रदान करनी चाहिए। ● उन्हें मुल्लाओं (Mullahs) के परामर्श से अफगानों को मानवीय सहायता की पेशकश करनी चाहिए, साथ ही उन पर कम से कम अल्पकालिक सुधारों को स्वीकार करने और बुनियादी मानवाधिकारों का सम्मान करने के उपाय करने का दबाव डालना चाहिए।
नाटो के ब्लंडर्स से क्वाड क्या सीख सकता है (What Quad can learn from NATO's Blunders)	**संदर्भ:** हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया। ● रूसी राष्ट्रपति पुतिन का संस्करण यह है कि यह एक "विशेष सैन्य अभियान" था, जो 1948 में हैदराबाद के खिलाफ भारत की पुलिस कार्रवाई के समान था। **पश्चिम क्या पहचानने में असफल रहा?** ● पुतिन ने मॉस्को के राजनीतिक पदानुक्रम में नाटकीय रूप से बढ़ोत्तरी की है और उनकी पहली दो उपलब्धियों को पश्चिम ने अनदेखा कर दिया था ○ तेल उत्पादन और निर्यात में स्थिरीकरण और वृद्धि जिसने रूसी सकल घरेलू उत्पाद में अत्यधिक वृद्धि की ○ चेचन्या विद्रोह का उनका सफल दमन ● पश्चिम नाटो को सिविलियन बनाने और सैन्य रूप से डाउनग्रेड करने में व्यस्त था। ● जैसा कि पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रों ने यूरोपीय संघ में शामिल होने की मांग की, पश्चिमी नेताओं ने नाटो मुख्यालय की सैन्य बौद्धिक सामग्री को नष्ट कर दिया, नाटो बलों को एक नागरिक महासचिव के राजनीतिक नियंत्रण के तहत एक तीव्र प्रतिक्रिया बल में कम कर दिया। ● इसलिए, वर्ष 2015 में पश्चिम पुतिन के जॉर्जिया पर आक्रमण को यूक्रेन में शासन परिवर्तन से लड़ने के लिए उनकी सतत दृष्टि से जोड़ने में विफल रहा। **क्वाड नाटो से क्या सीख सकता है?** ● इंडो-पैसिफिक महाद्वीपीय यूरोप नहीं है और इंडो-पैसिफिक में युद्ध समुद्री रणनीति और अंतरिक्ष संपत्ति के अनुसार लड़ा जाने वाला समुद्री युद्ध होगा। ● क्वाड को "राजनयिक समूह" कहना एक समान त्रुटि है जो नाटो ने 1991 के बाद नागरिकीकरण और सैन्य रूप से डाउनग्रेड करके किया था। ● बीजिंग को राजनयिक समूह कहकर भ्रमित करने से निश्चित रूप से क्वाड राष्ट्रों के संकल्प और संभावित चीनी दुस्साहसवाद की गलतफहमी पैदा होगी। **क्वाड को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किन उपायों की आवश्यकता है?** ● क्वाड समुद्री डोमेन जागरूकता, पानी के भीतर डोमेन जागरूकता और सूचना साझाकरण के बारे में है - ये सभी विशुद्ध रूप से नौसैनिक गतिविधियाँ हैं, जिन्हें निरंतर संचार की आवश्यकता होती है। ● समुद्री क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण क्वाड को एक कमांड संगठन और एक सचिवालय की आवश्यकता होती है, जिसमें से कोई भी नहीं है क्योंकि यह एक राजनयिक समूह है। ● डोमेन जागरूकता और कमांड संचार एवं बौद्धिक योजना की गहराई वाले कर्मचारियों को प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली समुद्री संपत्तियों के मालिकों द्वारा क्वाड का प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता है। ● राजनयिक समर्थन के साथ नौसेना के अधिकारियों की अध्यक्षता में क्वाड बैठकें होनी चाहिए, ताकि वे फरवरी

	2022 में कोविड, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की बात करने वाले अप्रासंगिक विज्ञप्ति का उत्पादन न करें।
भारत-जापान संबंध	**संदर्भ:** जापानी पीएम फुमियो किशिदा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए आपस बातचीत की। स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून के शासन जैसे सार्वभौमिक मूल्यों से जुड़े हुए हैं, जिन्हें विनिमय के लंबे इतिहास के माध्यम से साझा किया गया है, जापान और भारत विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदार हैं, रणनीतिक हितों को साझा करते हैं। इस मील के पत्थर अर्थात वर्ष 2022 (28 अप्रैल 1952) में, यह जापान और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70 वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। **पृष्ठिभूमि** जापान और भारत के बीच औपचारिक संबंध 1952 में शुरू हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, बहुपक्षीय सैन फ्रांसिस्को शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के बजाय, भारत ने जापान के साथ एक द्विपक्षीय शांति संधि का समापन करने का विकल्प चुना, यह देखते हुए कि जापान को अंतरराष्ट्रीय समुदाय में फिर से शामिल होने के लिए सम्मान और समानता सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह हमारी लंबे समय से चली आ रही दोस्ती की आधारशिला है। लेकिन राजनयिक संबंधों की स्थापना से पहले भी, दोनों देशों के लोगों के बीच सद्भावना व्यापार, शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से गहराई से निहित थी। 1951 में, जब भारत ने नई दिल्ली में पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की, तो इसने जापानी एथलीटों को आमंत्रित किया। यह उन पहले अवसरों में से एक था जहां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापानी ध्वज फहराया गया था। इस अनुभव ने उन जापानी लोगों के मन को सुकून दिया जो अपने देश के पुनर्निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे थे। विदित है कि 70 वर्षों के बहुस्तरीय आदान-प्रदान के बाद, हमारे दोनों देशों के बीच संबंध "विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी" में विकसित हुए। **दोनों देशों के बीच संबंध** *सामरिक घटक* ● मुक्त, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक पर अभिसरण, ● रक्षा और सुरक्षा एवं क्षेत्रीय संदर्भ में प्रगति। ● भारत और जापान ने आपूर्ति और सेवा समझौते के पारस्परिक प्रावधान (RPSS) पर हस्ताक्षर किए। ● वर्ष 2019 में उद्घाटन 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक नवंबर आयोजित की गई थी। ● **एक्ट ईस्ट फोरम:** 2017 में शुरू किया गया एक्ट ईस्ट फोरम भारत के "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" और जापान के एफओआईपी के बीच भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्र के आर्थिक आधुनिकीकरण हेतु परियोजनाओं की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उद्देश्य कनेक्टिविटी, वन प्रबंधन, आपदा जोखिम में कमी और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में पूर्वोत्तर भारत में विकास परियोजनाओं का समन्वय करना है। ● मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में राजमार्गों के उन्नयन सहित कई परियोजनाएं चल रही हैं। पीएम ने पिछले साल असम और मेघालय के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर 20 किलोमीटर लंबे पुल की आधारशिला रखी थी। ● आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (एससीआरआई) - भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और अर्थव्यवस्था मंत्रियों ने 27 अप्रैल 2021 को (एससीआरआई) लॉन्च किया। यह पहल भारत-प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखलाओं के लचीलेपन को बढ़ाने और भरोसेमंद विकसित करने का प्रयास करती है। आपूर्ति के स्रोत और निवेश आकर्षित करने के लिए, प्रारंभिक परियोजनाओं के रूप में (i) आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना; और (ii) मैचिंग इवेंट का आयोजन पूरा करना । *आर्थिक घटक* दोनों देशों ने भारत में सार्वजनिक और निजी निवेश में 3.5 ट्रिलियन जापानी येन का लक्ष्य हासिल कर किया। • वर्तमान में भारत में 1,455 जापानी कंपनियां हैं। 11 जापान औद्योगिक टाउनशिप (जेआईटी) की स्थापना की गई है, जिसमें राजस्थान में नीमराना और आंध्र प्रदेश में श्री सिटी में सबसे अधिक कंपनियां हैं। • जापान एफडीआई का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है; ओडीए का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता (भारत का विकास भागीदार) • मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मेट्रो परियोजनाओं, डीएमआईसी आदि सहित जापानी सहायता के माध्यम से कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं चल रही हैं। • पिछले साल पीएम मोदी ने वाराणसी कन्वेंशन सेंटर (रुद्राक्ष) का उद्घाटन किया था, जबकि तत्कालीन पीएम योशीहिदे सुगा ने एक वीडियो संदेश भेजा था। • अक्टूबर 2018 में दोनों पक्षों ने एक डिजिटल साझेदारी पर हस्ताक्षर किए थे। इस साझेदारी के तहत स्टार्टअप्स में

सहयोग एक जीवंत पहलू के रूप में उभरा है। अब तक भारतीय स्टार्टअप ने जापानी वीसी से 10 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक की राशि जुटाई है। भारत और जापान ने भारत में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप में निवेश करने के लिए एक निजी क्षेत्र द्वारा संचालित फंड-ऑफ-फंड भी लॉन्च किया है, जिसने अब तक 100 मिलियन अमरीकी डालर जुटाए हैं।

- दोनों देशों का आईसीटी के क्षेत्र में, 5जी, अंडर-सी केबल, दूरसंचार और नेटवर्क सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग है। 5जी पर वर्कशॉप भी आयोजित की गई।
- कौशल विकास के क्षेत्र में भी प्रगति हुई है। जापान-भारत विनिर्माण संस्थान (JIM) की कुल संख्या अब 19 हो गई है (2018 में यह 8 थी)। ये संस्थान कुशल कामगारों को प्रशिक्षण देने के लिए भारत में स्थित जापानी कंपनियों द्वारा स्थापित किए गए हैं। जापानी कंपनियों ने विभिन्न कॉलेजों में 7 जापानी एंडेड कोर्स (जेईसी) भी स्थापित किए हैं।
- 220 भारतीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीआईटीपी) के तहत जापान में प्रशिक्षु के रूप में रखा गया है। पिछले साल भारत ने एक विशिष्ट कुशल श्रमिक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। जापानी पक्ष ने इस साल जनवरी से इस कार्यक्रम के तहत नर्सिंग देखभाल के लिए परीक्षाएं शुरू की हैं।

शिखर सम्मेलन के दौरान

- **आतंकी हमलों के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी भाषा:** आतंकवाद पर, दोनों नेताओं ने "भारत में 26/11 के मुंबई और पठानकोट हमलों सहित आतंकवादी हमलों की निंदा की और पाकिस्तान से अपने क्षेत्र से बाहर चल रहे आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ दृढ़ और अपरिवर्तनीय कार्रवाई करने एवं एफएटीएफ सहित अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पूरी तरह से पालन करने का आह्वान किया।
- **अफगानिस्तान में मानवीय संकट:** "अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता का एहसास करने के लिए निकटता से सहयोग करने की उनकी मंशा व्यक्त की, और मानवीय संकट को संबोधित करने, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और एक प्रतिनिधि और समावेशी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया"। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जो स्पष्ट रूप से मांग करता है कि "अफगान क्षेत्र का उपयोग आतंकवादी कृत्यों को आश्रय, प्रशिक्षण, योजना या वित्तपोषण के लिए नहीं किया जाना चाहिए"।
- **परमाणु अप्रसार:** चूंकि किशिदा हिरोशिमा से हैं, उन्होंने "व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) के बल में शीघ्र प्रवेश के महत्व पर जोर दिया"। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि किशिदा जापानी संसद में निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है।
- **5जी में सहयोग पर समझौता, साइबर सुरक्षा:** आईओटी, एआई और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन और सहयोग के लिए संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ावा देने के माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के उद्देश्य से "भारत-जापान डिजिटल साझेदारी" पर चर्चा की।
- **उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विकास:** "भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए सतत विकास पहल" शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसमें चल रही परियोजनाओं और कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य देखभाल, नई और नवीकरणीय ऊर्जा में संभावित भविष्य के सहयोग के साथ-साथ बांस मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने की पहल शामिल है।
- **जापानी सेब का आयात और भारतीय आमों का निर्यात:** जापानी सेबों के आयात के लिए भारत की मंजूरी और जापान को भारतीय आम के निर्यात के लिए प्रक्रियाओं में छूट को हरी झंडी दिखाई।

घोषणा: भारत में विनिर्माण को प्रोत्साहित करने, इन क्षेत्रों में लचीला और भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला बनाने के साथ-साथ अनुसंधान एवं विकास में सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की गई थी। इसे एनर्जी डायलॉग के मौजूदा मैकेनिज्म के जरिए लागू किया जाएगा।

मौजूद अपार संभावनाएं

- साइबर सुरक्षा, बाह्य अंतरिक्ष और आर्थिक सुरक्षा सहित सुरक्षा मुद्दों में सहयोग करने के लिए ढेर सारे क्षेत्र।
- हमारे आर्थिक संबंधों को और बढ़ाया जा सकता है: लंबे समय से, जापान भारत के लिए सबसे बड़ा ओडीए (आधिकारिक विकास सहायता) दाता रहा है। हमारे सहयोग के सबसे हालिया और चल रहे उदाहरणों में से एक मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना है। जापान भी भारत के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। दोनों देशों ने सामाजिक बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अन्य देशों में आर्थिक सहयोग को भी बढ़ावा

	दिया है। हमारी आर्थिक साझेदारी हिंद-प्रशांत की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ विश्व अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर सकती है। ● हमारे संबंधों के लिए साहित्य, चलचित्र, संगीत, खेल और शिक्षाविदों सहित सांस्कृतिक आदान-प्रदान आवश्यक हैं, जिससे बेहतर समझ हो सके। **क्या आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं?** 1. हाल के वर्षों में भारत-जापान संबंधों ने अधिक सामरिक ऊंचाइयों को हासिल किया है। क्या आप सहमत हैं? चर्चा करना। 2. जापान आर्थिक मजबूती की दिशा में भारत की यात्रा में न केवल एक विश्वसनीय भागीदार रहा है बल्कि एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी के रूप में भी उभरा है। क्या आप सहमत हैं? समालोचनात्मक जाँच करें।
भारत और इज़राइल, एक स्थिर रिश्ते की परिपक्वता	**संदर्भ:** इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30 वीं वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए 2 अप्रैल से भारत का दौरा करेंगे। ● इज़राइल ने 1 फरवरी 1992 को नई दिल्ली में अपना दूतावास खोला। जबकि तेल अवीव में भारतीय दूतावास 15 मई 1992 को खोला गया। **भारत-इजरायल संबंधों का इतिहास** ● भारत ने इजराइल को 1950 में ही मान्यता दे दी थी लेकिन सामान्य होने में चार दशक और लग गए। ● भारत इस्राइल के साथ अपने संबंधों को लेकर अनिच्छुक था क्योंकि ○ भारत ने फिलीस्तीनी उद्देश्य के लिए अपने ऐतिहासिक समर्थन के साथ इसे संतुलित किया, ○ तेल के लिए भारत की अरब देशों पर निर्भरता, ○ देश के मुस्लिम नागरिकों की फिलिस्तीन समर्थक भावनाएं। ● ● वर्ष 1992 से संबंधों ने एक अलग भूमिका निभाई जहां रक्षा सौदे, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कृषि में सहयोग थे ● प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए -1 के बाद ही पहली उच्च स्तरीय यात्राएं हुई। 2000 में, लालकृष्ण आडवाणी इजरायल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय मंत्री बने। उस वर्ष, दोनों देशों ने एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी आयोग का गठन किया। ● वर्ष 2003 में, एरियल शेरोन भारत की यात्रा करने वाले पहले इजरायली प्रधानमंत्री बने। ● वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी की इज़राइल यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पहली थी, और इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसे रिश्ते का पूर्ण स्वामित्व लिया जो ज्यादातर एक चौथाई सदी से अधिक समय तक रडार के नीचे विकसित हुआ था। ● वर्ष 2020 के अब्राहमिक समझौते के साथ, जिसमें यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को ने इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य किया है, और भारत के यूएई और सऊदी अरब के साथ अपने नए मजबूत संबंधों के साथ, भारत अब किसी भी अन्य समय की तुलना में पश्चिम एशिया में अपने प्रमुख संबंधों के बारे में अधिक आश्वस्त है। **पिछले कुछ वर्षों में फिलिस्तीन के साथ भारत के संबंध कैसे विकसित हुए हैं?** ● इससे पहले, फ़िलिस्तीन के साथ संबंध लगभग चार दशकों से अधिक समय से भारतीय विदेश नीति में आस्था का विषय थे। ● भारत ने आत्मनिर्णय के फिलिस्तीनी अधिकार का समर्थन किया और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (पीएलओ) और उसके नेता यासर अराफात के पीछे रैली की। ● वर्ष 1975 में, भारत ने पीएलओ को दिल्ली में एक कार्यालय खोलने के लिए आमंत्रित किया, इसे पांच साल बाद राजनयिक दर्जा दिया। ● वर्ष 1988 में, जब पीएलओ ने पूर्वी यरुशलम में अपनी राजधानी के साथ फ़िलिस्तीन के एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा की, तो भारत ने तुरंत मान्यता प्रदान की। ● यूपीए के 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान, वेस्ट बैंक का प्रशासन करने वाले फिलिस्तीनी प्राधिकरण के प्रमुख महमूद अब्बास ने वर्ष वर्ष 2005, 2008, 2010 और 2012 में चार बार दौरा किया। ● वर्ष 2011 में भारत ने फिलिस्तीन को यूनेस्को का पूर्ण सदस्य बनने के लिए वोट दिया।

	• वर्ष 2012 में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव को सह-प्रायोजित किया जिसने फिलिस्तीन को मतदान के अधिकार के बिना संयुक्त राष्ट्र में "गैर-सदस्य" पर्यवेक्षक राज्य बनने में सक्षम बनाया। • भारत ने मोदी के प्रधानमंत्री बनने के एक साल बाद सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र परिसर में फिलिस्तीनी ध्वज की स्थापना का भी समर्थन किया। • वर्ष 2021 में इजराइल-फिलिस्तीन हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की चर्चा में भारत के बयान ने वस्तुतः इस्राइल को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया, और दो-राज्य समाधान के लिए "न्यायसंगत" और "अटूट" समर्थन के लिए भारत के "मजबूत" समर्थन को व्यक्त किया। • वर्ष 2021की शुरुआत में जिनेवा में UNHRC के 46वें सत्र में, भारत ने तीन प्रस्तावों में इजरायल के खिलाफ मतदान किया था - ○ फिलीस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार पर; ○ इस्राइली बंदोबस्त नीति पर; और ○ गोलान हाइट्स में मानवाधिकार की स्थिति पर। **क्या भारत-फिलिस्तीन संबंधों में कोई बदलाव आया है?** • भारत और इस्राइल के बीच बढ़ते संबंधों ने फ़िलिस्तीन के लिए नई दिल्ली के स्पष्ट समर्थन को हटा दिया है। • वर्ष 2017 में भारत की नीति में पहला बड़ा बदलाव महमूदअब्बास की यात्रा के दौरान आया जब भारत ने एक बयान में एक फिलिस्तीनी राज्य की राजधानी के रूप में पूर्वी यरुशलम के समर्थन में प्रथागत लाइन को छोड़ दिया। • जब मोदी ने इज़राइल का दौरा किया, तो उनके यात्रा कार्यक्रम में रामल्लाह शामिल नहीं थे, जैसा कि अन्य आने वाले गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया जाता था। ○ लेकिन संतुलन बनाने का कार्य जारी रहा। मोदी ने फरवरी 2018 में रामल्लाह की एक अलग यात्रा की और एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य का आह्वान किया। **निष्कर्ष** भारत ने फ़िलिस्तीन के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों और इस्राइल के लिए अपने हालिया स्नेह के बीच एक कड़ी (tightrope) चलना जारी रखा है
श्रीलंका की बिगड़ती अर्थव्यवस्था	**संदर्भ:** श्रीलंका इतिहास में अपने सबसे खराब आर्थिक मंदी की चपेट में है। **कारकों ने संकट का कारण क्यों बनाया है?** • महामारी के कारण नौकरी छूटना और आय में कमी आई। पर्यटन के साथ-साथ निर्यात और प्रेषण जैसे सभी प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जन क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित किया । • **घटती विदेशी मुद्रा भंडार:** वर्ष 2021 के अंत तक देश का विदेशी भंडार घटकर 1.6 बिलियन डॉलर हो जाने के साथ एक संप्रभु चूक की आशंका बढ़ गई। लेकिन श्रीलंका अपना पूरा विदेशी कर्ज चुकाने का रिकॉर्ड रखने में कामयाब रहा। • **सरकार की निष्क्रियता:** इस संकट को बढ़ाने में कुछ कारको का महत्वपूर्ण योगदान है जैसे एक व्यापक रणनीति की कमी, कुछ नीतिगत निर्णयों के साथ-साथ सरकार के अचानक जैविक खेती पर स्विच करना आदि शामिल है। ○ अगस्त 2021 में, सरकार ने डॉलर बचाने के लिए आयात प्रतिबंधों के साथ-साथ आवश्यक खाद्य पदार्थों के वितरण के लिए आपातकालीन नियमों की घोषणा की। हालांकि, इन उपायों के कारण बाजार में अनियमितताएं और जमाखोरी हुई। **जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है?** • **गिरती मुद्रा:** श्रीलंकाई रुपया जिसको अधिकारियों ने इस महीने जारी किया था, यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लुढ़कर लगभग 265 हो गया है। • उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 16.8% पर है • **बढ़ता हुआ कर्ज:** श्रीलंका को इस साल लगभग 7 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज चुकाना होगा और अपने घटते डॉलर खाते से जरूरी चीजों का आयात जारी रखना होगा।

- **व्यापार घाटा:** राष्ट्रपति राजपक्षे ने कहा कि श्रीलंका इस साल 22 अरब डॉलर का आयात बिल लेगा, जिसके परिणामस्वरूप 10 अरब डॉलर का व्यापार घाटा होगा।
- नागरिकों के लिए जीवन कठिन हो गया है
    - ईंधन खरीदने के लिए लंबी कतारें
    - रसोई गैस की कीमत बढ़कर 4,199 (लगभग ₹ 1,150) हो गई और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले दूध पाउडर की कीमत में LKR 600 प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई, जिससे इन उत्पादों की खपत में कमी आई।
    - कई इलाकों में लंबे समय तक बिजली कटौती।
    - रोगियों के लिए दवा खोजने के लिए संघर्ष।
    - पेपर की कमी के कारण, अधिकारियों को लाखों छात्रों के लिए स्कूल परीक्षा रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

क्या कोई प्रतिरोध है?

- हां, नागरिक और राजनीतिक विरोध के विभिन्न वर्ग राष्ट्रपति राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं।
- कई मीडिया के लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया पर सरकार पर तीखी टिप्पणियों की बाढ़ सी आ गई है।

क्या है सरकार की प्रतिक्रिया?

- श्रीलंकाई सरकार ने बिगड़ती स्थिति के अपने स्वयं के कुप्रबंधन को छिपाते हुए महामारी से उत्पन्न संकट की ओर इशारा करते हुए आलोचना से ध्यान हटाने की कोशिश की।
- सरकार शुरू में संकट से निपटने के लिए आईएमएफ का समर्थन लेने से हिचक रही थी लेकिन अब सरकार आईएमएफ के साथ बातचीत कर रही है।
- यह देखा जाना बाकी है कि आईएमएफ इस समय श्रीलंका को कैसे समर्थन देगा, और किस हद तक इसका समर्थन देश को संकट से निपटने में मदद कर सकता है।
- श्रीलंकाई सरकार ने भारत सहित विभिन्न द्विपक्षीय भागीदारों से ऋण, मुद्रा अदला-बदली और आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए क्रेडिट लाइनों के माध्यम से समर्थन मांगा है।

भारत कैसे मदद कर रहा है?

- जनवरी 2022 से, भारत ने कुल 2.4 बिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है - जिसमें एक
  o $400 मिलियन RBI मुद्रा स्वैप
  o $500 मिलियन का ऋण स्थगन
  o भोजन, ईंधन और दवाओं के आयात के लिए क्रेडिट लाइन। इसमें से हाल ही में एक अरब डॉलर की क्रेडिट लाइन को अंतिम रूप दिया गया।
- इस बीच, हाल ही में चीन श्रीलंका द्वारा 2.5 बिलियन डॉलर की सहायता के अनुरोध पर विचार कर रहा है, इसके अलावा बीजिंग ने महामारी फैलने के बाद से 2.8 बिलियन डॉलर की सहायता दी है।

श्रीलंका में भारत की सहायता को किस रूप में देखा जा रहा है?

- बढ़ती संशयवाद: श्रीलंका की नेतृत्व वाली सरकार ने समय पर सहायता के लिए भारत को धन्यवाद दिया है, लेकिन श्रीलंकाई मीडिया और कुछ वर्गों में भारत के लिए "बंधे" होने पर संदेह बढ़ रहा है, जैसे देश में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शामिल करना -
    - सामरिक त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म परियोजना
    - श्रीलंका के पूर्वी त्रिंकोमाली जिले के समपुर में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सीलोन विद्युत बोर्ड के साथ राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का हालिया समझौता
    - भारत के अदानी समूह के निवेश के साथ उत्तरी श्रीलंका में दो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं। राजनीतिक विपक्ष ने अडानी समूह पर प्रतिस्पर्धी बोली और उचित प्रक्रिया से बचते हुए "बैक दूर " से श्रीलंका में प्रवेश करने का आरोप लगाया है।

	• ऐसी भी आलोचनाएं हैं कि भारत इस द्वीपीय देश में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए "राजनयिक ब्लैकमेल" का सहारा ले रहा है। कार्टूनिस्टों ने भारत से आपातकालीन वित्तीय सहायता के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा परियोजनाओं का व्यापार करने वाले श्रीलंकाई नेताओं को चित्रित किया है।
यूरोपीय संघ का डिजिटल बाजार अधिनियम (डीएमए)	**संदर्भ:** यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के वार्ताकार बिग टेक दिग्गजों के बाजार प्रभुत्व को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक कानून (डीएमए) पर सहमत हुए हैं। • यह कानून पारित नहीं हुआ है। एक अंतिम संस्करण अभी तक यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ बनाने वाले 27 देशों द्वारा आधिकारिक रूप से अपनाया जाना बाकी है। • ये नियम 1 जनवरी, 2023 से लागू हो सकते हैं, हालांकि तकनीकी कंपनियां कानून को लागू करने के लिए और समय मांग रही हैं। **डीएमए के निशाने पर कौन हैं?** डीएमए का फोकस 'गेटकीपर्स' नाम की कंपनियों पर है, जिसमें एप्पल, फेसबुक, गूगल आदि शामिल हैं। इन कंपनियों को नए नियमों का पालन करना होगा। 'गेटकीपर्स' कंपनियों की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मीट्रिक निम्नलिखित हैं: • **डिजिटल इकोसिस्टम में प्रमुख भूमिका:** कानून इन कंपनियों को गेटकीपर्स के रूप में संदर्भित करता है क्योंकि वे अक्सर वितरण को नियंत्रित करते हैं, चाहे वह प्लेटफॉर्म पर ऐप्स या विज्ञापनों या संचार के लिए। • **राजस्व और मूल्यांकन:** एक कंपनी को गेटकीपर के रूप में कहा जाएगा यदि उसका पिछले तीन वर्षों में यूरोपीय संघ के भीतर कम से कम € 7.5 बिलियन का वार्षिक कारोबार या कम से कम € 75 बिलियन का बाजार मूल्यांकन है। • **उपयोगकर्ता आधार:** 45 मिलियन से अधिक मासिक अंतिम-उपयोगकर्ताओं वाला कोई भी प्रतिनिधि और यूरोपीय संघ में स्थापित कम से कम 10,000 व्यावसायिक उपयोगकर्ता, गेटकीपर के रूप में भी योग्य हैं। • **छूट:** लघु और मध्यम उद्यमों को गेटकीपर के रूप में पहचाने जाने से छूट दी गई है। • **प्लेटफ़ॉर्म सेवाएँ:** कंपनी को कम से कम तीन यूरोपीय संघ के राज्यों में एक या अधिक कोर प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं को नियंत्रित करना चाहिए। इन सेवाओं में मार्केटप्लेस और ऐप स्टोर, सर्च इंजन, सोशल नेटवर्किंग, क्लाउड सर्विसेज, विज्ञापन सेवाएं, वॉयस असिस्टेंट और वेब ब्राउजर शामिल हैं। • 'उभरते गेटकीपर' की एक श्रेणी की पहचान की गई है, जिसका लक्ष्य "कंपनियां जिनकी प्रतिस्पर्धी स्थिति सिद्ध है लेकिन अभी तक टिकाऊ नहीं है"। • भले ही गेटकीपरों की सूची अभी तक जारी नहीं की गई है, "बिग टेक" - GAFAM (गूगल, अमेज़ॅन, फेसबुक, ऐप्पल, माइक्रोसॉफ्ट) - अधिनियम के मुख्य विषय होने की संभावना है, लेकिन केवल वही नहीं हैं। **डीएमए के प्रस्ताव क्या हैं?** • **प्री-लोडेड ऐप्स:** आम तौर पर यह ऐप्पल, गूगल और अन्य में पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप्स पर भारी पड़ता है। उपयोगकर्ताओं को अपने ऐप्स चुनने और इंस्टॉल करने का अधिकार होगा। इसलिए, भविष्य के आईफ़ोन सफारी, या आईमैसेज या सिरी (Siri) , प्री-लोडेड के साथ नहीं आ सकते हैं। • **मैसेजिंग सेवाओं में इंटरऑपरेबिलिटी:** इसका मतलब यह है कि व्हाट्सएप पर एक उपयोगकर्ता और आईमैसेज पर एक दूसरे से बात करने में सक्षम होना चाहिए। ○ बड़ी इंटरनेट कंपनियों की अक्सर “वॉल्ड गार्डन्स (walled gardens)” के संचालन के लिए आलोचना की जाती है, बंद सिस्टम जो एक उपयोगकर्ता के लिए एक प्रदाता को दूसरे के लिए खोदना कठिन बना देता है। • **थर्ड-पार्टी ऐप स्टोर:** गेटकीपर्स को थर्ड पार्टी ऐप और ऐप स्टोर के इंस्टालेशन और प्रभावी उपयोग की अनुमति देनी चाहिए, भले ही वे सुरक्षा के लिए "आनुपातिक उपाय" कर सकें। ○ Apple जैसी कंपनियों ने सुरक्षा को कारण बताते हुए लंबे समय से थर्ड-पार्टी ऐप स्टोर का विरोध किया है। • **डेवलपर्स के लिए उचित पहुंच:** यूरोपीय संघ चाहता है कि ऐप डेवलपर्स स्मार्टफोन की पूरक कार्यात्मकताओं तक उचित पहुंच प्राप्त करें, उदाहरण के लिए नियर फील्ड कम्युनिकेशंस चिप।

	○ इसके अलावा, गेटकीपर्स व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के लिए अनुचित स्थितियाँ स्थापित नहीं कर सकते हैं या ऐप स्टोर में सूचीबद्ध होने के लिए ऐप डेवलपर्स को कुछ सेवाओं (जैसे भुगतान प्रणाली या पहचान प्रदाता) का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। ○ ऐप डेवलपर्स जैसे एपिक गेम्स, स्पॉटिफाई, आदि ने लंबे समय से Google और Apple पर उनके भुगतान प्रणालियों को बंधक बनाने का आरोप लगाया है। ● **विज्ञापन प्रदर्शन डेटा में पारदर्शिता:** गेटकीपर्स को प्लेटफ़ॉर्म पर विक्रेताओं को उनके मार्केटिंग या विज्ञापन प्रदर्शन डेटा तक पहुंच प्रदान करनी होगी। ● **विलय और अधिग्रहण:** गेटकीपर्स को अपने अधिग्रहण और विलय के बारे में यूरोपीय आयोग को सूचित करना होगा। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़े प्लेयर अपनी आने वाली प्रतियोगिता में से कुछ को खरीद लेते हैं। ● **रैंकिंग में निष्पक्षता:** नए नियम गेटकीपर्स को अपने स्वयं के उत्पादों या सेवाओं को दूसरों की तुलना में उच्च रैंकिंग से और किसी अन्य सेवा के प्रयोजनों के लिए सेवा के दौरान एकत्र किए गए निजी डेटा का पुन: उपयोग करने से भी मना करते हैं। ○ नया कानून इन दिग्गजों को उनके साथ बेहतर प्रतिस्पर्धा करने के लिए व्यावसायिक ग्राहकों द्वारा उनकी साइट पर उत्पन्न डेटा का उपयोग करने से रोकता है, जैसा कि अमेज़ॅन पर करने का आरोप लगाया गया है। ● **दंडात्मक प्रावधान:** कानून केशुरुआती उल्लंघन के लिए उल्लंघनकर्ताओं पर कंपनी की वैश्विक वार्षिक बिक्री का 10% तक जुर्माना लगाया जा सकता है, जो बार-बार उल्लंघन के लिए 20% तक बढ़ जाता है। सबसे खराब स्थिति में, उन्हें आगे किसी भी अधिग्रहण से प्रतिबंधित भी किया जा सकता है **डीएमए का महत्व क्या है?** ● कानून यूरोपीय संघ के बाजार में डिजिटल क्षेत्र को निष्पक्ष और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है। ● यह बड़े प्लेटफार्मों के अपमानजनक व्यापार प्रथाओं को रोकने में मदद करता है और इसकी तुलना बैंकिंग, ऊर्जा और दूरसंचार क्षेत्रों में ऐतिहासिक अविश्वास सुधारों से की जाती है। ● यह उपभोक्ता की पसंद को बढ़ाता है। ● यह प्रतिद्वंद्वियों को दुनिया की शक्तिशाली टेक कंपनियों के खिलाफ जीवित रहने का बेहतर मौका देता है ● एक बार लागू होने के बाद यह दुनिया भर में तकनीकी विनियमन के लिए एक नई मिसाल कायम करता है। ● यह बिग टेक के एकाधिकारवादी व्यवहार को दंडित करने के लिए यूरोपीय संघ द्वारा आवश्यक प्रक्रियाओं और अदालती लड़ाइयों को टाल देता है जहां मामले भारी जुर्माना के साथ समाप्त हो सकते हैं, लेकिन इन दिग्गजों के व्यापार करने के तरीके में थोड़ा बदलाव होता है। ● कानून ब्रसेल्स को दिग्गजों के फैसलों पर नजर रखने का अभूतपूर्व अधिकार देगा **निष्कर्ष** टेक कंपनियों ने आरोप लगाया है कि कुछ नियम उनके उपयोगकर्ताओं के लिए अनावश्यक गोपनीयता और सुरक्षा कमजोरियां पैदा कर सकते हैं। फिर भी, अधिनियम सही दिशा में एक कदम है।
श्रीलंका का आर्थिक संकट	**संदर्भ:** भुगतान संतुलन (Balance of Payments- BoP) की गंभीर समस्या के कारण श्रीलंका की अर्थव्यवस्था इन दिनों संकट में है। ● उसका विदेशी मुद्रा भंडार तेज़ी से घटता जा रहा है और देश के लिये आवश्यक उपभोग की वस्तुओं का आयात करना कठिन होता जा रहा है। ● देश भी पिछले कर्ज को चुकाने में असमर्थ है। **वर्तमान संकट के कारण क्या हैं?** **1. आर्थिक संरचना में ऐतिहासिक असंतुलन** ● 21वीं सदी में भी, श्रीलंका की आर्थिक स्थिति चाय और रबर जैसी प्राथमिक वस्तुओं और कपड़ों के निर्यात से जुड़ी रही। ● इसने प्राथमिक वस्तु निर्यात, पर्यटन और प्रेषण के माध्यम से विदेशी मुद्रा भंडार जुटाया, और इसका उपयोग

भोजन सहित आवश्यक उपभोग की वस्तुओं के आयात के लिए किया।

2. महामारी से बहुत पहले मंदी

- 2009 में श्रीलंका जब 26 वर्षों से जारी गृहयुद्ध से उभरा तो युद्ध के बाद की उसकी जीडीपी वृद्धि 2012 तक प्रति वर्ष 8-9% के उपयुक्त उच्च स्तर पर बनी रही थी।
- हालांकि, वैश्विक कमोडिटी मूल्यों में गिरावट, निर्यात की मंदी और आयात में वृद्धि के साथ वर्ष 2013 के बाद उसकी औसत जीडीपी विकास दर घटकर लगभग आधी रह गई।

3. विदेशी मुद्रा भंडार की निरंतर निकासी

- गृहयुद्ध के दौरान श्रीलंका का बजट घाटा बहुत अधिक था और वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने उसके विदेशी मुद्रा भंडार को समाप्त कर दिया था।
- जिसके कारण देश को वर्ष 2009 में IMF से 2.6 बिलियन डॉलर का ऋण लेने के लिये विवश होना पड़ा था।
- इस प्रतिबद्धता ने सरकार के हाथों को प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति के लिए जाने के लिए बाध्य कर दिया जब 2013 के बाद अर्थव्यवस्था धीमी हो गई।

4. आईएमएफ की ऋण संबंधी शर्तें

- विकास या निर्यात में कोई तेजी नहीं आने और विदेशी मुद्रा भंडार के निरंतर निकास के साथ, वर्ष 2016 में श्रीलंका एक बार फिर 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण के लिये IMF के पास पहुँचा, लेकिन IMF की शर्तों ने श्रीलंका के आर्थिक स्वास्थ्य को और बदतर कर दिया।
- IMF की शर्त थी कि 2020 तक राजकोषीय घाटे को 3.5% तक कम किया जाना चाहिए। अन्य शर्तें शामिल हैं
    - कर नीति और कर प्रशासन में सुधार;
    - व्यय पर नियंत्रण;
    - सार्वजनिक उद्यमों का व्यावसायीकरण;
    - विनिमय दरों में लचीलापन;
    - विदेशी निवेश के लिए मुक्त वातावरण।
- आईएमएफ पैकेज के कारण श्रीलंका की आर्थिक स्थिति खराब हुई।
    - जीडीपी विकास दर 2015 में 5% से घटकर 2019 में 2.9% हो गई।
    - निवेश दर 2015 में 31.2% से गिरकर 2019 में 26.8% हो गई।
    - सकल सरकारी ऋण 2015 में सकल घरेलू उत्पाद के 78.5% से बढ़कर 2019 में सकल घरेलू उत्पाद का 86.8% हो गया।

5. अर्थव्यवस्था को नए झटके

- सबसे पहले अप्रैल 2019 के ईस्टर बम विस्फोटों में 253 लोगों के मारे जाने की खबर कोलंबो में चर्चा का विषय बना रहा, जिसके परिणामस्वरूप पर्यटकों की संख्या में तेजी से गिरावट आई जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट दर्ज की गई।
- वर्ष 2019 में सत्ता में आई गोटाबाया राजपक्षे की सरकार ने अपने चुनावी अभियानों में निम्न कर दरों और किसानों के लिये व्यापक रियायतों का वादा किया था। वैट की दरों को 15% से घटाकर 8% कर दिया गया। राष्ट्र निर्माण कर, भुगतान कर और आर्थिक सेवा शुल्क समाप्त कर दिए गए।
- इस नीति के परिणामस्वरूप, सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2% इस प्रकार छोड़े गए करों में नहीं था। 2019 और 2020 के बीच GST/VAT राजस्व आधा कर दिया गया।
- वर्ष 2020 में COVID-19 महामारी ने इस स्थिति को और खराब कर दिया। चाय, रबर, मसालों और कपड़ों के निर्यात को नुकसान हुआ। पर्यटन आगमन और राजस्व में और गिरावट आई।
- महामारी ने सरकारी व्यय में और वृद्धि की: राजकोषीय घाटा 2020 और 2021 में 10% से अधिक हो गया, और सकल घरेलू उत्पाद के लिए सार्वजनिक ऋण का अनुपात 2019 में 94% से बढ़कर 2021 में 119% हो गया।

6. गुमराह करने वाली नीतियां: रासायनिक उर्वरक प्रतिबंध

- श्रीलंका ने उर्वरक सब्सिडी पर सालाना लगभग $260 मिलियन (या अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग

	0.3%) खर्च किया। अधिकांश उर्वरक आयात किए जाते हैं। ● विदेशी मुद्रा भंडार की निकासी को रोकने के लिए, सरकार ने मई 2021 से सभी उर्वरक आयातों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विचित्र समाधान निकाला और घोषणा की कि श्रीलंका रातोंरात 100% जैविक खेती वाला देश बन गया। ● यह नीति नवंबर 2021 में किसानों के विरोध के बाद वापस ले लिया गया, इस नीति के कारण श्रीलंका एक आपदा की तरफ चला गया । ● हालाँकि, इस नीति ने कृषि उपज पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जिससे कृषि उत्पादन में गिरावट आई जिससे खाद्य पदार्थों के आयात की आवश्यकता हुई। ● लेकिन विदेशी मुद्रा की कमी के कारण आयात बढ़ाना मुश्किल था। इस प्रकार, फरवरी 2022 में मुद्रास्फीति बढ़कर 17.5 प्रतिशत हो गई। ● साथ ही, चाय और रबर की उत्पादकता में गिरावट के कारण निर्यात आय कम हुई। इस प्रकार, जैविक कृषि नीति, जिसका उद्देश्य भंडार पर दबाव को कम करना था, ने और अधिक तनावपूर्ण बना दिया। **निष्कर्ष** ● सरकार नई शर्तों के साथ नए ऋण के लिए एक बार फिर आईएमएफ से संपर्क कर सकती है। वैश्विक दृष्टिकोण के मंद दिखने के साथ, इस तरह की अपस्फीति नीति के लिए एक नए सिरे से धक्का न केवल आर्थिक पुनरुद्धार की संभावनाओं को सीमित करेगा, बल्कि श्रीलंका के लोगों की पीड़ा को भी बढ़ा देगा। **बिंदुओं को कनेक्ट करना** ● भारत का 1991 का बीओपी संकट ● 2008 वैश्विक वित्तीय संकट

Q.1 जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा 1988 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है।
2. आईपीसीसी की सदस्यता डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी के सभी सदस्यों के लिए खुली है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.2 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?

a) इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय
b) वित्त मंत्रालय
c) रक्षा मंत्रालय
d) गृह मंत्रालय

Q.3 करकट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है?

a) कर्नाटक
b) केरल
c) तमिलनाडु
d) तेलंगाना

Q.4 वेफ्स (waifs) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसमें आम तौर पर मुस्लिम धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के इरादे से एक इमारत, भूखंड या अन्य संपत्ति दान करना शामिल है।
2. भारत में "बोर्डों के कामकाज और वक्फ के उचित प्रशासन से संबंधित मामलों पर" सरकार को सलाह देने के लिए एक केंद्रीय वक्फ परिषद भी है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.5 निम्नलिखित में से कौन भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोविड -19 वैक्सीन है?

a) कोविशील्ड
b) कोवैक्सिन
c) स्पुतनिक-वी
d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Q.6 ऑपरेशन गंगा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

a) अफगानिस्तान से हिंदुओं और सिखों को भगाने में मदद करना।
b) जम्मू और कश्मीर के कश्मीर क्षेत्र से आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए
c) भारतीय सेना द्वारा भारत-म्यांमार सीमा पर नागा आतंकी संगठन NSCN-खापलांग का लगातार पीछा करना।
d) यूक्रेन से भारतीयों को बचाने के लिए

Q.7 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. पिछले कुछ वर्षों में भारत का व्यापार घाटा घट रहा है।
2. एक व्यापार घाटा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक आर्थिक उपाय है जिसमें किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.8 'सरायघाट का युद्ध' निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था?

a) मुगल और राजपूत
b) राजपूत और अहोम
c) मुगल और अहोम
d) राजपूत और मराठा

Q.9 3डी प्रिंटिंग में निम्नलिखित में से किसमें अनुप्रयोग होते हैं?

a) चिकित्सा उपकरण
b) औद्योगिक कला और आभूषण
c) निर्माण
d) उपरोक्त सभी

Q.10 जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वर्ष 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है।
2. यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.11 अर्धचालक निम्नलिखित में से किसमें उपयोगी हैं?

a) ऑटोमोबाइल
b) मोबाइल फोन
c) उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स
d) उपरोक्त सभी

Q.12 यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है?

a) रूस
b) फ्रांस
c) यूक्रेन
d) पोलैंड

Q.13 भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका प्रबंधन वित्त मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है।
2. यह मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित भारत का प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.14 निम्नलिखित में से कौन टोही उपग्रह का उपयोग करता है?

a) बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण का पता लगाकर हमले की चेतावनी प्रदान करता है।
b) अंतरिक्ष से परमाणु विस्फोट का पता लगाता है।
a) ऑप्टिकल इमेजिंग जहां सैटेलाइट इमेज एक सर्वेक्षण या नज़दीकी टेलीफोटो हो सकती है।
b) उपरोक्त सभी

Q.15 निम्नलिखित में से कौन हंसा-नई पीढ़ी (HANSA-New Generation) के बारे में सही नहीं है?

a) यह भारत का अपनी तरह का पहला स्वदेशी विमान प्रशिक्षक है।
a) यह कथित तौर पर सबसे उन्नत उड़ान प्रशिक्षकों में से एक है।
b) विमान को प्रशिक्षक विमान के लिए भारत में फ्लाइंग क्लब की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
c) यह अपनी उच्च लागत और उच्च ईंधन खपत के कारण वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस के लिए एक आदर्श विमान है।

Q.16 प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है?

a) श्रम और रोजगार मंत्रालय
b) ग्रामीण विकास मंत्रालय
c) सामाजिक न्याय मंत्रालय
d) एमएसएमई मंत्रालय

Q.17 हाल ही में "समर्थ" पहल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी?

a) ग्रामीण विकास मंत्रालय
b) श्रम और रोजगार मंत्रालय
c) एमएसएमई मंत्रालय
d) सामाजिक न्याय मंत्रालय

Q.18 क्या SLINEX सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश के बीच किया जाता है?

a) श्रीलंका और थाईलैंड
b) ऑस्ट्रेलिया और जापान
c) श्रीलंका और भारत
d) ऑस्ट्रेलिया और भारत

Q.19 निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है?

a) फ्रांस
b) इटली
c) मोंटेनेग्रो
d) रूस

Q.20 निम्नलिखित में से कौन उत्तरी नदी टेरापिन की IUCN स्थिति है?

a) विलुप्त
b) गंभीर रूप से संकटग्रस्त
c) कमजोर
d) थ्रीटेंडेड

Q.21 BBIN पहल में निम्नलिखित में से कौन-सा देश शामिल है?

a) बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और भारत
b) बांग्लादेश, ब्राजील, नेपाल और भारत
c) बांग्लादेश, भूटान, नीदरलैंड और भारत
d) बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और इंडोनेशिया

Q.22 राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एनएलएमसी का नेतृत्व एक अध्यक्ष करेगा जिसका चयन योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।
2. एनएलएमसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और सरकारी एजेंसियों की अधिशेष भूमि और भवन संपत्ति का मुद्रीकरण करेगा।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.23 हाल ही में भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित किया गया था जो दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र ग्लोबल आउटपोस्टेड सेंटर (कार्यालय) बनने जा रहा है। यह केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था?

a) मुंबई
b) जामनगर
c) भोपाल
d) भुवनेश्वर

Q.24 श्रीमान दीपक धर बोल्ट्जमान पदक के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। बोल्ट्जमान पदक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

a) वैमानिकी
b) जीन थेरेपी
c) सांख्यिकीय भौतिकी
d) जैव रसायन

Q.25 राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) 33 सदस्यों का एक भारतीय नियामक निकाय है जो चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा पेशेवरों को नियंत्रित करता है।

2. यह 25 सितंबर, 1995 को भारतीय चिकित्सा परिषद का स्थान लिया।

उपरोक्त में से कौन सा सही हैया सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.26 अभ्यास धर्म संरक्षक-2022 निम्नलिखित में से किसके बीच आयोजित किया गया था?

a) भारत और नेपाल
b) भारत और मालदीव
c) भारत और जापान
d) भारत और वियतनाम

Q.27 वेडेल सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का हिस्सा है?

a) अटलांटिक महासागर
b) हिंद महासागर
c) दक्षिणी महासागर
d) आर्कटिक महासागर

Q.28 जैविक और विषाक्त हथियार सम्मेलन (BTWC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक निरस्त्रीकरण संधि है जो जैविक और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण, भंडारण और उपयोग को प्रतिबंधित करके प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करती है।

2. BWC सामूहिक विनाश के हथियारों की एक पूरी श्रेणी के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि थी।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.29 'पैंगोंग त्सो' झील कहाँ स्थित है?

a) नेपाल
b) तिब्बत
c) लद्दाख
d) जम्मू

Q.30 निम्नलिखित में से किसे 'पृथ्वी गृह के फेफड़े (lungs of the planet)' के रूप में जाना जाता है?

a) कांगो वर्षा वन
b) सवाना घास के मैदान
c) अमेज़न वर्षावन
d) उत्तर-पूर्वी भारत के वर्षा वन

Q.31 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत चलाया जा रहा है।

2. जनऔषधि सुगम, पीएमबीजेपी के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन जनता को अपनी उंगलियों की नोक पर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करके सुविधा प्रदान करता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.32 निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है?

a) अष्टमुडी झील
b) चिल्का झील
c) वुलर झील
d) लोकतक झील

Q.33 'सफेद फास्फोरस' के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?

a) यह पायरोफोरिक है
b) यह भयंकर रूप से जलता है
c) यह कपड़े, ईंधन और गोला-बारूद को प्रज्वलित कर सकता है
d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Q.34 माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. माइक्रोफाइनेंस छोटे व्यवसाय के मालिकों के लिए एक समाधान प्रदान करता है, जिनके पास बैंकिंग और संबंधित सेवाओं तक पहुंच नहीं है।

2. वे ऋण पर ब्याज लेते हैं लेकिन ब्याज दर देश के अधिकांश बैंकों द्वारा वसूले जाने वाले ब्याज से कम है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.35 जिस नदी पर इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय बनाया गया है वह है-

a) रवि
b) चंद्रमा
c) झेलम
d) सूक्ष्म

Q.36 PM-डिवाइन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

a) भारत के तीर्थ स्थलों के लिए विकास पहल
b) उत्तर-पूर्व के लिए विकास पहल
c) भारत में आध्यात्मिक केंद्रों के लिए विकास पहल
d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Q.37 डिजिटल मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक भुगतान विधि है जो केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद है और मूर्त नहीं है।
2. इसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन और इंटरनेट जैसी तकनीक की मदद से संस्थाओं या उपयोगकर्ताओं के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.38 निम्नलिखित में से कौन G7 का सदस्य नहीं है?

a) इटली
b) कनाडा
c) फ्रांस
d) रूस

Q.39 वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए भारत का पहला मध्यस्थता केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में है?

a) हैदराबाद
b) कोच्चि
c) गोरखपुर
d) मुंबई

Q.40 इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एक इलेक्ट्रिक वाहन प्रणोदन के लिए एक या अधिक इलेक्ट्रिक मोटर या ट्रैक्शन मोटर का उपयोग करता है।
2. ईंधन को बिजली में परिवर्तित करने के लिए एक इलेक्ट्रिक वाहन को स्वयं निहित बैटरी, सौर पैनलों या विद्युत जनरेटर के माध्यम से संचालित किया जा सकता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.41 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?

a) ग्रामीण विकास मंत्रालय
b) आवास मंत्रालय
c) सामाजिक न्याय मंत्रालय
d) पर्यावरण मंत्रालय

Q.42 नो-फ्लाई ज़ोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. नो-फ्लाई ज़ोन एक सैन्य शक्ति द्वारा स्थापित एक क्षेत्र है जिस पर अनधिकृत विमानों को उड़ान भरने की अनुमति नहीं है।
2. केवल सैन्य संदर्भ में नो-फ्लाई जोन की अनुमति है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.43 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एक क्रेडिट सुविधा उधार लेने वाले पक्ष को हर बार धन की आवश्यकता होने पर ऋण के लिए पुन: आवेदन करने के बजाय विस्तारित अवधि में धन निकालने की अनुमति देती है।
2. लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी) के तहत, कर्जदार जरूरत के मुताबिक पैसे निकाल सकता है, जब तक कि लिमिट खत्म न हो जाए, और जैसे ही पैसा चुका दिया जाता है, क्रेडिट की खुली लाइन के मामले में इसे फिर से उधार लिया जा सकता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.44 अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है?

a) एमएफआई
b) डब्ल्यूएचओ
c) ओईसीडी
d) डब्ल्यूईएफ

Q.45 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. रोसालिंड फ्रैंकलिन नाम के मार्स रोवर को एक रूसी रॉकेट पर नियोजित प्रक्षेपण के लिए यूके में इकट्ठा किया गया था।
2. रोजालिंड फ्रैंकलिन संयुक्त यूरोपीय-रूसी मिशन का दूसरा चरण है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.46 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक संवैधानिक निकाय है।
2. इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q.47 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन (DOM) किया जा रहा है?

a) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
b) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
c) जल शक्ति मंत्रालय
d) उपरोक्त में से नौ

Q.48 हिमालयन ग्रिफॉन की IUCN स्थिति है-

a) कमजोर
b) संकटग्रस्त
c) निकट संकटग्रस्त
d) विलुप्त

Q.49 क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह इतिहास का सबसे बड़ा व्यापार ब्लॉक है।
2. इसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और न्यूजीलैंड एवं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) के 10 सदस्य इसके सदस्य हैं।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.50 निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है?

a) वस्तु के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 भारत में जीआई माल का पंजीकरण और सुरक्षा प्रदान करता है।
b) भारत के लिए भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री दिल्ली में स्थित है।
c) एक पंजीकृत जीआई टैग किसी तीसरे पक्ष को ऐसे उत्पादों का उपयोग करने से रोकता है।
d) जीआई एक सामूहिक बौद्धिक संपदा अधिकार है और इस प्रकार परिभाषित जीआई क्षेत्र के भीतर सभी उत्पादकों के स्वामित्व में है।

Q.51 निम्नलिखित में से कौन आर्कटिक परिषद का सदस्य नहीं है?

a) कनाडा
b) डेनमार्क
c) फिनलैंड
d) ऑस्ट्रिया

Q.52 न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम (NILP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसमें स्कूली छात्रों, उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के पूर्व-सेवा छात्रों, स्कूल शिक्षकों, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं, एनवाईकेएस, एनएसएस, एनसीसी स्वयंसेवकों की भागीदारी शामिल है।
2. इस योजना के क्रियान्वयन के लिए विद्यालय एक इकाई होगा।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.53 पद्म पुरस्कारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है?

a) इसकी स्थापना 1954 में हुई थी।
b) जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेद के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं।
c) यह पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता हैं।
d) पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिसका गठन हर साल प्रधानमंत्री पुरस्कार द्वारा किया जाता है।

Q.54 क्या 'फिनलैंडाइजेशन' के तहत तटस्थता का सिद्धांत मित्रता, सहयोग और पारस्परिक सहायता के समझौते में निहित था, जिस पर फिनलैंड ने अप्रैल 1948 में निम्नलिखित में से किसके साथ हस्ताक्षर किए थे?

a) यूएसएसआर
b) जर्मनी
c) यूएसए
d) ब्रिटेन

Q.55 हाइपरसोनिक मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाइपरसोनिक मिसाइल एक हथियार प्रणाली है जो कम से कम मैक 5 की गति से उड़सकती है, अर्थात ध्वनि की गति से पांच गुना।
2. बैलिस्टिक मिसाइलों के विपरीत, हाइपरसोनिक मिसाइलें बैलिस्टिक प्रक्षेपवक्र का पालन नहीं करती हैं और उन्हें इच्छित लक्ष्य तक ले जा सकती है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.56 न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है?

a) एमएसपी बंपर उत्पादन वर्षों के दौरान किसानों को कीमतों में अत्यधिक गिरावट से बचाने के लिए निर्धारित मूल्य है।
b) कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर कुछ फसलों के लिए बुवाई के मौसम की शुरुआत में भारत सरकार द्वारा एमएसपी की घोषणा की जाती है।
c) सरकार 22 अनिवार्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और कच्चे जूट के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) की घोषणा करती है।
d) हाल ही में कच्चे जूट के लिए एमएसपी में वृद्धि की गई थी।

Q.57 निम्न में से किस प्रकार के सूक्ष्मजीव के कारण क्षय रोग होता है?

a) कवक
b) वायरस
c) प्रोटोजोआ
d) बैक्टीरिया

58. वर्ष 2022 के एबेल पुरस्कार के विजेता कौन है?

a) डेनिस पी. सुलिवन
b) हिलेल फुरस्टेनबर्ग
c) ग्रेगरी मार्गुलिस
d) एंड्रयू विल्स

59. भारत में पहली जाति आधारित जनगणना कब हुई थी?

a) 2011
b) 2021
c) 1931
d) 1881

60. संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करना केंद्र का कर्तव्य होगा?

a) अनुच्छेद 235
b) अनुच्छेद 72
c) अनुच्छेद 355
d) अनुच्छेद 263

Q.61 केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
2. सीबीआई को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से छूट दी गई है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.62 निम्नलिखित में से किस देश के पास अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है?

a) फ्रांस
b) रूस
c) भारत
d) पाकिस्तान

Q.63 सोलोमन द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है?

a) प्रशांत महासागर
b) अटलांटिक महासागर
c) हिंद महासागर
d) आर्कटिक महासागर

Q.64 अनिवासी भारतीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 (फेमा) के अनुसार, एनआरआई एक भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का विदेशी नागरिक है जो रोजगार के उद्देश्य से भारत से बाहर रहता है, ऐसी परिस्थितियों में एक अनिश्चित काल व्यवसाय करता है जो भारत से बाहर रहने के इरादे का संकेत देता है।
2. उन अनिवासी भारतीयों का दौरा करना जिनकी भारत में कुल आय रुपये तक है। वित्तीय वर्ष के दौरान 15 लाख एनआरआई बने रहेंगे यदि उनका प्रवास 181 दिनों से अधिक नहीं है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) ग) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.65 निर्यात तैयारी सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है?

a) नीति आयोग
b) वित्त मंत्रालय
c) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
d) उपरोक्त सभी

Q.66 प्रेसिडेंट्स कलर निम्नलिखित में से किसके लिए दिया जाता है?

a) शिक्षाविदों में उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड
b) संकट के समय असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए
c) शांति और युद्ध दोनों में राष्ट्र को असाधारण सेवा प्रदान करने वाली एक सैन्य इकाई
d) अनुकरणीय समाज सेवा

Q.67 अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था रॉकेट और उपग्रह, दूरसंचार, जलवायु परिवर्तन शोधकर्ताओं सहित आदि उद्योगों से बनी है। जो आधुनिक दिन, डिजिटल जीवन को संभव बनाने के लिए अंतरिक्ष में ट्रिलियन डॉलर का पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं।
2. अगले दशक के अंत तक, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का मूल्य 4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगा।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.68 निम्नलिखित में से कौन बिम्सटेक का सदस्य नहीं है?

a) भारत
b) पाकिस्तान
c) भूटान
d) श्रीलंका

Q.69 दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र वैश्विक केंद्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है?

a) यूएसए
b) जर्मनी
c) नेपाल
d) भारत

Q.70 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. दुनिया की 60% से अधिक हाथी आबादी भारत में है।
2. एशियाई हाथी की IUCN रेड लिस्ट स्थिति संकटग्रस्त है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.71 डार्लोंग समुदाय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है?

a) गुजरात
b) अरुणाचल प्रदेश
c) त्रिपुरा
d) मिजोरम

Q.72 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र/क्षेत्र के बीच जोजिला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है?

a) श्रीनगर और लेह
b) मेरठ और चोपता
c) जम्मू और कश्मीर
d) कश्मीर और लेह

Q.73 ग्रेटर एक-सींग वाले गैंडे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह राइनो प्रजाति में सबसे बड़ा है।
2. विश्व में भारत सबसे बड़ी संख्या में एक सींग वाले गैंडे का घर है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.74 भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य असम के साथ सीमा साझा नहीं करता है?

a) त्रिपुरा
b) अरुणाचल प्रदेश
c) सिक्किम
d) मिजोरम

Q.75 निम्न में से कौन G7 समूह का हिस्सा नहीं है?

a) कनाडा
b) चीन
c) फ्रांस
d) जर्मनी

Q.76 हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. आईओएनएस एक स्वैच्छिक और समावेशी पहल है जो समुद्री सहयोग बढ़ाने और क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) के तटवर्ती राज्यों के जहाजों को एक साथ लाता है।
2. IONS में 24 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं जो IOR के भीतर स्पर्श करते हैं या झूठ बोलते हैं, और 8 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं ?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.77 यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था?

a) नीति आयोग
b) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)
c) वित्त मंत्रालय
d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Q.78 सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है?

a) राजस्थान
b) अरुणाचल प्रदेश
c) मध्य प्रदेश
d) दिल्ली

1 C	27 C	53 C
2 A	28 C	54 A
3 B	29 C	55 C
4 C	30 C	56 C
5 B	31 B	57 D
6 D	32 B	58 A
7 C	33 D	59 C
8 C	34 C	60 C
9 D	35 D	61 C
10 A	36 B	62 D
11 D	37 C	63 A
12 C	38 D	64 C
13 B	39 A	65 A
14 D	40 C	66 C
15 D	41 A	67 C
16 A	42 A	68 B
17 C	43 C	69 D
18 C	44 C	70 C
19 D	45 C	71 C
20 B	46 C	72 A
21 A	47 A	73 C
22 C	48 C	74 C
23 B	49 C	75 B
24 C	50 B	76 C
25 A	51 D	77 B
26 C	52 C	78 A

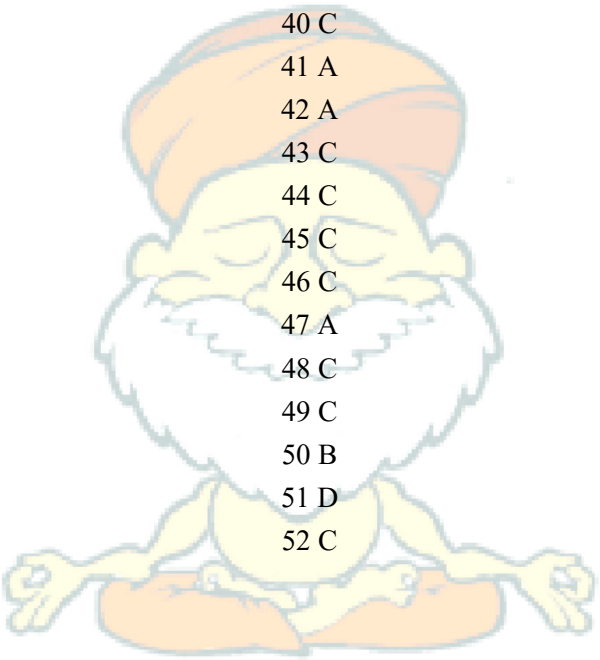

IAS BABA

Baba's Foundation Course (FC) - 2023

Baba's 8 fold path to crack IAS in 1st Attempt!

"The Most Comprehensive **CLASSROOM** & **MENTORSHIP** Based Program for UPSC / IAS"

OFFLINE CLASSES @ Delhi | Bengaluru | Lucknow

LIVE Online Classes

15% OFF Early Bird Offer!

REGISTER NOW

Scan Here to Know More

www.iasbaba.com support@iasbaba.com 91691 91888